उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना

OCCUPATIONAL STRUCTURE OF CLASS I AND II TOWNS OF UTTAR PRADESH

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० राम नगीना सिंह, एम० ए०, डी० फिल्०

रीडर, भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रस्तुतकर्त्री

श्रीमती गायत्री देवी, एम० ए०

भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

१९९०

आमुख

नगरीय केन्द्र सदैव मानव सभ्यता एवं संस्कृति के केन्द्र माने जाते रहे हैं। इनका उद्भव एवं विकास इनके द्वारा सम्पादित उन प्रकार्यों के कारण होता है जिन्हें ये अपने चतुर्दिक व्याप्त क्षेत्रों के लिए करते हैं। इस प्रकार नगरीय केन्द्र किसी क्षेत्र के विकास की धुरी होते हैं। अतः प्रादेशिक नियोजन में नगरीय नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश भारत का एक विकासशील तथा कृषि-प्रधान प्रान्त है जहाँ नगरीकरण का विकास देश के अनेक भागों की अपेक्षा कम हुआ है। प्रदेश के अधिकांश लघु एवं मध्यम नगरीय केन्द्रों का उद्भव अतिवर्धित ग्रामों के परिणामस्वरूप हुआ है जहाँ कृषि जैसी अनगरीय क्रियाओं का वर्चस्व पाया जाता है किन्तु वृहन्नगरों में नगरीय पर्यावरण का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है जहाँ विविध प्रकार की नगरीय क्रियायें सम्पन्न होती हैं। किन्तु कतिपय वृहन्नगरों में भी कृषि कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें नगरीय जनसंख्या का उल्लेखनीय प्रभाग संलग्न है। वास्तव में नगरीय केन्द्रों को मूलतः व्यवसायों की प्रकृति एवं प्रकार के आधार पर ही ग्रामीण क्षेत्रों से पृथक किया जाता है। ग्रामों में पशुपालन, कृषि आदि प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता पायी जाती है जबकि नगरों में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आदि क्रियायें विकसित होती हैं जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासन एवं शिक्षा आदि। आधारभूत खनिजों के अभाव, कृषि की प्रधानता, शक्ति संसाधनों की अपर्याप्तता आदि कारणों से उत्तर प्रदेश में वृहत् पैमाने के उद्योग-धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। इस प्रकार नगरीय व्यवसायों का सर्वप्रथम प्रतिनिधि तथा नगरीकरण का समवर्ती मानें जाने वाले विनिर्माण उद्योग का प्रदेश के नगरीय इकाइयों में समुचित विकास नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि इस प्रदेश में नगरीकरण आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि मात्र जनांकिकीय तथ्य रहा है जिसका योगदान आर्थिक विकास तथा पर्याप्त रोजगार-अवसरों की वृद्धि में अत्यल्प रहा है। इसके विपरीत, नगरीकरण के विकास-नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से नगरीय बेरोजगारी जैसी भीषण समस्यायें बलवती होती जा रही हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य "उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना" को इसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। इस अध्ययन का मौलिक उद्देश्य व्यवसायों की प्रकृति एवं प्रकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा उत्तर प्रदेश के

50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में विभिन्न व्यवसायों के वितरण एवं उनके बहु-मुखी प्रतिरूपों का स्पष्टीकरण करना है । उनका समुचित आकलन विभिन्न नगरीय क्रियाओं के अपूर्ण एवं असन्तुलित विकास के लिए उत्तरदायी कारणों के निदान में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा । साथ ही, इसके आधार पर प्रदेश के मानव संसाधनों के अपेक्षा-कृत अधिक लाभदायक उपयोग तथा विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किया जा सकेगा ।

भारत में नगरीय जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से प्रत्यक्षत: सम्बन्धित विस्तृत अध्ययनों की संख्या अत्यन्त सीमित रही है । अधिकांश नगरीय अध्ययन नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यात्मक क्षेत्रों एवं प्रभाव क्षेत्रों के निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में नगरीकरण की प्रवृत्तियों एवं लक्षणों आदि से सम्बन्धित रहे हैं । केवल जन-संख्या भूगोल में कतिपय अध्ययन ही हुए हैं जिनसे जनसंख्या के व्यावसायिक संघटन पर आंशिक प्रकाश पड़ता है । इसके साथ ही देश के विभिन्न शोध-पत्रिकाओं में व्यावसा-यिक संदर्भ में जनसंख्या संघटन तथा व्यवसायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों से इसके सम्बन्धों को व्यक्त करने वाले अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं । जन-संख्या की व्यावसायिक संरचना पर कतिपय स्वतंत्र कार्य भी हुए हैं जो कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या से सम्बन्धित हैं जिनका संदर्भ शोध-प्रबन्ध में यथो-चित स्थान पर दिया गया है । इस सन्दर्भ में महामाया मुखर्जी (1966), शीला राय (1972), हर्षदेव सिंह (1978) और साहबदीन (1981) के कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं । पुनरावृत्ति से बचने के लिए ही यहाँ विभिन्न व्यावसायिक कार्यों की समीक्षा नहीं प्रस्तुत की जा रही है ।

जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना द्वारा सम्बन्धित प्रदेश के आर्थिक अभिलक्षणों की अभिव्यक्ति होती है । किसी प्रदेश की व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन सामान्य-तया उसके आर्थिक विकास का सूचक होता है । उल्लेखनीय है कि अग्रांकित तथ्य किसी प्रदेश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं : 1. कार्यशील जनसंख्या का आकार एवं उसका संघटन, 2. नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं स्तर, 3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का स्तर, 4, व्यवसाय के प्रकार एवं उनका सापेक्ष महत्व और 5. आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता । किसी प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को उसके आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक माना जाता है । कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात

में वृद्धि से आश्रित या निर्भर जनसंख्या के अनुपात में प्रकृत्या ह्रास होता है । इस प्रकार आर्थिक उत्पादकों की वृद्धि तथा आश्रितों के आनुपातिक ह्रास से अमुक प्रदेश में आर्थिक सम्पन्नता एवं समृद्धि आती है । आयु के अनुसार बच्चे और वृद्ध प्राय: आश्रित होते हैं और आर्थिक क्रियाओं में उनका योगदान अत्यल्प होता है । श्रमशक्ति का प्रधान स्रोत युवा एवं प्रौढ़ जनसंख्या (15-60 वर्ष) होती है जिसे सक्रिय जनसंख्या भी कहा जाता है। किन्तु सक्रिय जनसंख्या वर्ग में भी विभिन्न वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से कतिपय व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं होते और वे अपनी जीविका हेतु अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होते हैं । भारत के अन्य भागों की ही भाँति उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता अत्यल्प है । अधिकांश महिलाओं की क्रियायें घरेलू कार्यों तक ही सीमित होती हैं जिन्हें आर्थिक नहीं माना जाता । इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में अप्रभावी जनसंख्या (बच्चों एवं वृद्धों) तथा महिलाओं का योगदान प्रभावी जनसंख्या (युवाओं एवं प्रौढ़ों) तथा पुरुषों की तुलना में अल्पतर होता है ।

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में उल्लेखनीय भिन्नता पायी जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य प्राय: परम्परागत और प्राथमिक प्रकार के होते हैं जबकि नगरीय क्रियाओं में अधिक विविधता मिलती है । सर्वविदित है कि ग्रामीण व्यवसाय में कृषि और इससे सम्बद्ध क्रियाओं की प्रमुखता होती है जबकि नगरीय केन्द्रों की मुख्य क्रियायें विनिर्माण, प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, शिक्षा तथा अन्य अनेक वैयक्तिक, व्यावसायिक एवं संस्थागत सेवायें हैं । नगरीय व्यावसायिक संरचना में बहुधा प्राथमिक क्रियाओं की क्षीणता तथा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आदि क्रियाओं की अधिकता पायी जाती है ।

जनसंख्या के अधिकांश प्रभाग की प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता को अमुक प्रदेश के पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है जबकि आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश की श्रमशक्ति का वृहत् प्रभाग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं में संलग्न होता है , जो नगरीय प्रकृति की हैं । इस प्रकार जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अध्ययन से विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों में श्रमशक्ति की प्रकृति एवं आकार का स्पष्टीकरण हो जाता है । व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा अवस्था की भी द्योतक होती है । पारिश्रमिक तथा सुविधाओं की दृष्टि से सभी व्यवसाय एक से नहीं होते हैं बल्कि उनमें

पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । यह भिन्नता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी मिलती है जिस पर अन्यान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का प्रभाव होता है । किसी प्रदेश में आय प्रतिरूप भी विशिष्ट व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षमता पर आधारित होता है । सामान्यतया कुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होता है । इसी प्रकार विनिर्माण उद्योग में संलग्न कर्मियों को कृषि मजदूरों की तुलना में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है । विभिन्न व्यवसायों में पारिश्रमिक-संरचना में भिन्नता प्राय: सभी प्रदेशों में कमोवेश मात्रा में परिलक्षित होती है ।

नगरीय केन्द्र प्राय: बहु-कार्यात्मक होते हैं जहाँ विविध प्रकार की क्रियाओं तथा सेवाओं का विकास होता है किन्तु पृथक-पृथक नगरों में एक अथवा कुछ क्रियाओं का विकास अधिक हो जाता है जबकि अन्य क्रियायें अल्पविकसित रह जाती हैं । किसी नगर की अधिकांश श्रमशक्ति का किसी विशिष्ट क्रिया में संलग्न होना वहाँ उक्त क्रिया के विशिष्टीकरण का सूचक होता है और इस क्रिया का नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि इसका सम्बन्ध अनेक सामाजिक-आर्थिक तथ्यों से भी होता है । अत: नगरीय केन्द्रों में कार्यात्मक विशिष्टीकरण की गहनता और इसके विभिन्न सहचरों के मध्य पाये जाने वाले सहसम्बन्धों द्वारा विशिष्ट क्रियाओं के प्रभुत्व के मौलिक कारणों को समझने में सहायता मिलती है । किसी नगरीय केन्द्र में वहाँ की जनसंख्या की माँग एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुएँ एवं सेवायें बाह्य-नगरीय क्षेत्रों को प्राप्त होती हैं । नगर में इन अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में संलग्न श्रमशक्ति को आधारभूत या बेसिक श्रम माना जाता है जिसके द्वारा नगर को आय प्राप्त होती है और नगर का विकास होता है । अत: नगर में किसी क्रिया का औसत से अधिक मात्रा में पाया जाना नगरीय अर्थव्यवस्था में उसके विशिष्ट योगदान का प्रतीक होता है । उल्लेखनीय है कि नगर में 'बेसिक' श्रम की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वहाँ आर्थिक विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी । नगरीय श्रमशक्ति में बेसिक श्रम वहाँ की विशिष्टीकृत क्रियाओं में संलग्न होता है । अत: नगरों की व्यावसायिक संरचना में विशिष्टीकृत क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रतिरूप तथा उसमें संलग्न श्रमिकों की कार्यक्षमता और सामाजिक आर्थिक दशाओं आदि के अध्ययन द्वारा अधिक उपयोगी एवं सार्थक तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश हमारे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है जहाँ जनाधिक्य के साथ ही अशिक्षा, अकुशल श्रम, सामूहिक बेरोजगारी, अध:रोजगार, परम्परागत व्यवसाय, निर्धनता आदि का प्रभुत्व हो गया है जो प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। इसकी तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने इसके आर्थिक विकास के मार्ग में अनेक भयंकर अवरोध उत्पन्न किया है। प्रदेश की वर्तमान आर्थिक संरचना प्रदेशवासियों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने तथा बेरोजगारी में ह्रास लाने में सर्वथा असमर्थ है। विगत वर्षों में जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में रोजगार-वृद्धि में अत्यल्प बढ़ोत्तरी हो पायी है जिससे बेरोजगारों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ भिन्न है क्योंकि यहाँ बेरोजगार व्यक्ति प्राय: साक्षर, शिक्षित और यहाँ तक कि विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में प्रशिक्षित भी होते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बेरोजगार व्यक्ति अकुशल और अशिक्षित होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी एवं विभिन्न आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का मौलिक कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों का नगरोन्मुख पलायन एवं स्थानान्तरण है। अत: विभिन्न नगरीय समस्याओं के निदान हेतु नगरीय व्यावसायिक संरचना की विस्तृत जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के 30 नगरों और द्वितीय श्रेणी के 36 नगरों (कुल 66 नगरों) का चयन किया गया है। नगरीय समूह को एकल नगरीय इकाई माना गया है जिनकी कुल संख्या 21 है। यह अध्ययन अपने विषय एवं उपागम दोनों ही दृष्टिकोणों से मूलत: जनांकिकीय है न कि सामाजिक या आर्थिक। यह प्रधानत: उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध भारतीय जनगणना अभिलेखों एवं समंकों पर आधारित है। यद्यपि किसी व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की आर्थिक दशाओं के आकलन हेतु उक्त व्यवसाय द्वारा प्राप्त प्रति व्यक्ति आय का ज्ञान अधिक उपयोगी तथा सहायक होगा किन्तु दुर्भाग्यवश अध्ययन क्षेत्र के नगरों के विषय में इस प्रकार के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण यह व्यावसायिक अध्ययन मुख्यत: जनांकिकीय ही रह गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वृहत् नगरों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत करना है जिसके लिए अद्यतन समंक भारतीय जनगणना 1981 द्वारा ही उपलब्ध हैं। अत: नगरीय जनसंख्या का व्यावसायिक विवरण मूलत: जनगणना 1981 के समंकों पर

आधारित है। यद्यपि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जनपदों की कुल संख्या 62 हो गयी है किन्तु जनगणना 1981 द्वारा कुल 56 जनपदों के अनुसार ही आँकड़े उपलब्ध हैं अत: इस अध्ययन में 56 जनपदों के अनुसार ही विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

जनगणना 1981 में कार्यशील जनसंख्या को चार उपविभागों-कृषक, कृषि श्रमिक, गृह उद्योग में कार्यरत और अन्य श्रमिक में विभक्त किया गया है जो ग्रामीण व्यावसायिक संरचना की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है किन्तु इससे नगरीय व्यावसायिक संरचना का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता क्योंकि उक्त वर्गीकरण नगरीय क्रियाओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त नगरीय क्रियाओं को अन्तिम वर्ग - 'अन्य श्रमिक' के अन्तर्गत कर दिया गया है जिसमें पशुचारण, वनोद्योग आदि अनगरीय क्रियायें भी सम्मिलित हैं। इसके विपरीत जनगणना 1971 में समस्त कार्यशील जनसंख्या को 9 वृहत् कार्यात्मक वर्गों में विभक्त किया था जिसमें अन्तिम 5 कार्यात्मक वर्ग नगरीय प्रकृति के हैं। अत: नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु जनगणना 1971 के समंकों का उपयोग किया गया है और इससे प्राप्त तथ्यों का प्रयोग आगामी अध्यायों में नगरों की व्यावसायिक संरचना में विभिन्न नगरीय क्रियाओं के महत्व एवं प्रकृति के विश्लेषण हेतु किया गया है।

नगरों की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन मुख्यतया 1981 जनगणना के आँकड़े पर आधारित है और व्यावसायिक परिवर्तन के स्पष्टीकरण हेतु 1971 से 1981 के मध्य हुए परिवर्तनों की भी व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। 'श्रमिक' की परिभाषा तथा कार्यात्मक वर्गों में प्रतिदशक भिन्नता मिलने के कारण 1971 से पूर्व में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण नहीं किया गया है, यद्यपि नगरीय विकास को 1901 से लेकर 1981 तक प्रदर्शित किया गया है। जनगणना 1981 में प्रयुक्त 4 कार्यात्मक-वर्गों को पुनर्संगठित करके तीन वर्गों में रखा गया है। प्रथम दो वर्गों - कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को उनकी प्रकृति एवं कार्यदशाओं में समानता के आधार पर संयुक्त करके एक ही साथ 'कृषि' के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। तृतीय वर्ग 'गृह उद्योग' को यथावत रखा गया है जबकि चतुर्थ वर्ग 'अन्य श्रमिकों' के नाम में परिवर्तन करके 'विविध क्रियायें' नामक कार्यात्मक-वर्ग बनाया गया है। इस प्रकार समस्त आर्थिक क्रियाओं को तीन प्रधान वर्गों - 1. कृषि, 2. गृह उद्योग, और 3. विविध क्रियाओं में विभक्त किया गया है और प्रत्येक

की व्याख्या पृथक-पृथक अध्यायों में की गयी है ।

नगरों की व्यावसायिक संरचना की व्याख्या हेतु प्रयुक्त व्यावसायिक आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या में लेखिका ने अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षणों और अनुभवों का भी सहारा लिया है जिससे अनेक रुचिकर, सार्थक तथा महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित साहित्य और सन्दर्भों का समुचित अध्ययन एवं उपयोग किया गया है जिनका यथोचित स्थलों पर उल्लेख भी किया गया है । उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की जनसंख्या के व्यावसायिक प्रतिरूपों के सम्मिश्र जनांकिकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय-कालिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण हेतु अनेक मानचित्र और आरेख भी तैयार किये गये हैं जिन्हें उपयुक्त स्थलों पर प्रदर्शित किया गया है । नगरों के व्यावसायिक विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को अधिक यथार्थ तथा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से कतिपय मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग भी किया गया है । इस प्रकार यदि व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन या कथन अध्ययन के उद्देश्य और दिशा को अभिव्यक्त करते हैं तो मात्रात्मक मापदण्ड इसे आवश्यक शुद्धता, विश्वसनीयता एवं गहराई प्रदान करते हैं ।

शोध-प्रबन्ध में नगरों की व्यावसायिक संरचना के सम्पूर्ण तथ्यों को आठ अध्यायों में संगठित किया गया है । अध्यायों का निर्धारण किसी आधारभूत सिद्धान्त या सूत्र के अनुसार नहीं बल्कि सामान्य क्रमानुसार किया गया है और व्यवसायों को जनगणना 1981 की व्यवस्थानुसार रखा गया है । अध्याय एक में अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण भौगोलिक ‡भौतिक एवं सांस्कृतिक‡ पृष्ठभूमि का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो व्यावसायिक विश्लेषण में सहायक होगा । द्वितीय अध्याय में व्यवसाय की संकल्पना और उसके निर्धारक तत्वों के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । अध्याय तीन में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की कार्यात्मक जनसंख्या की प्रकृति एवं आकार तथा उसका वृहत् क्रिया-वर्गों में वितरण आदि का मात्रात्मक विश्लेषण किया गया है और साथ ही सीमान्त कर्मियों एवं अकर्मियों के सामान्य लक्षणों पर भी प्रकाश डाला गया है । अध्याय चार का निर्धारण नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु किया गया है जिसमें कार्यात्मक वर्गीकरण की विधियों की विस्तृत व्याख्या के साथ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । अध्याय पाँच, छः और सात में तीन क्रिया-

वर्गों का पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है । पाँचवें अध्याय में कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या के विविध पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें कृषि में विशिष्टीकृत नगरों की विशेष चर्चा की गयी है । अध्याय छ: में गृह उद्योग में कार्यरत जनसंख्या की प्रकृति एवं मात्रा का विश्लेषण विशिष्टीकृत नगरों के संदर्भ में किया गया है । इसी क्रम में सातवाँ अध्याय भी आता है जिसमें विविध क्रियाओं में संलग्न श्रम शक्ति के लक्षणों एवं आकार का विश्लेषण इस क्रिया-वर्ग में विशिष्टीकृत नगरों के विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । आठवें तथा अन्तिम अध्याय में अध्ययन क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की जनसंख्या की सामान्य सामाजिक-आर्थिक प्रकृति से सम्बद्ध कतिपय प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा की गयी है और साथ ही वर्तमान नगरीय व्यावसायिक संरचना में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधारों हेतु कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये हैं ।

पाठ में उल्लिखित संदर्भों को प्रत्येक अध्याय के अन्त में क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है । शोध-प्रबन्ध का अन्त तीन परिशिष्टियों से होता है । प्रथम परिशिष्ट में शब्दावली, द्वितीय में जनांकिकीय आँकड़े और तृतीय में ग्रंथ-सूची का प्रदर्शन किया गया है ।

सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धेय गुरु डॉ0 रामनगीना सिंह, रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनके सुयोग्य निर्देशन में मुझे कार्य करने और शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । उनके सतत् प्रोत्साहन, विद्वतापूर्ण सुझावों तथा पाण्डुलिपि के आद्योपान्त परिमार्जन के फलस्वरूप ही प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अन्तिम स्वरूप सम्भव हो सका है । मैं प्रोफेसर रामनाथ तिवारी, अध्यक्ष, भूगोल विभाग की विशेषरूप से आभारी हूँ जिन्होंने कार्यविधि में विभिन्न स्तरों पर बहुमूल्य सुझाव एवं सहायता प्रदान किया है । प्रेरणा के परम स्रोत अपने पूज्य पिता श्री रामलोचन प्रसाद सिंह की मैं आजीवन ऋणी रहूँगी जिनसे मुझे अध्ययन हेतु प्रेरणा और मूल्यवान सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं । मैं अपने पति डॉ0 साहबदीन मौर्य की हार्दिक आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा, सुझाव एवं सहयोग के परिणामस्वरूप ही मैं इस शोध कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सकी हूँ ।

शोध-कार्य में विविध प्रकार से सहायता प्रदान करने के लिए मैं डॉ0 रामप्यारे

चतुर्वेदी, भूगोल विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद, श्री राजमणि त्रिपाठी शोध सहायक, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद और श्री रमाशंकर मौर्य, शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी आभारी हूँ । मैं उन समस्त व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनसे इस कार्य के पूर्ण होने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त हुई है । अन्त में मैं श्री रामबरन यादव को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने तत्परता एवं कुशलतापूर्वक अत्यन्त सीमित अवधि में समस्त पाण्डुलिपि को टंकित करने का सराहनीय कार्य किया है ।

गायत्री देवी
(गायत्री देवी)

भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद ।

16 मार्च 1990.

विषय-सूची

तालिकाओं की सूची

5.4 कृषि में विशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं कृषि में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत भिन्नता

6.1 उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में गृह उद्योग में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

6.2 गृह उद्योग में विशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं गृह उद्योग में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत भिन्नता

7.1 उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

7.2 विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत भिन्नता

अध्याय एक

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि

1.1 स्थिति, विस्तार एवं प्रादेशिक उपविभाग

उत्तर प्रदेश $23^0 52' 15"$ से $30^0 27' 22"$ उत्तरी अक्षांश तथा $77^0 5' 36"$ से $84^0 38' 10"$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 294,411 वर्ग किलोमीटर है ।[1] इसकी अधिकतम लम्बाई उत्तर से दक्षिण 840.5 किमी० और अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 742 किमी० है ।[2] भारत के उत्तरी भाग में स्थित इस राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है जिसके उत्तर में चीन एवं नेपाल देश स्थित हैं । उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार राज्य की स्थिति है । क्षेत्रीय विस्तार के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के पश्चात् इसका देश में चतुर्थ स्थान है (चित्र 1.1) ।

उत्तर प्रदेश कुल 12 प्रशासनिक मण्डलों तथा 62 जनपदों में विभक्त है (1981 में जनपदों की संख्या 56 थी) । जनपदों को तहसीलों में विभक्त किया गया है जिनका उपविभाजन पुनः परगनों तथा विकास-खण्डों में किया गया है ।

1.2 भौतिक स्वरूप

उत्तर प्रदेश का दक्षिणी अंचल पठारी है जो प्राचीनतम शैलों द्वारा निर्मित प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर बढ़ा हुआ भाग है । इसके विपरीत इसके उत्तरी भाग में तृतीय कल्प में निर्मित हिमालय की विशाल वलित श्रृंखलाएं फैली हुई हैं । इन दोनों भूखण्डों के मध्य में नदियों के अवसादों के निक्षेपों से निर्मित मैदानी भूभाग है जो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग है । धरातलीय रचना की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को चार प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया जाता है : 1. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, 2. भाबर एवं तराई प्रदेश, 3. समतल मैदान और 4. दक्षिणी पठार (चित्र 1.2) ।

उत्तर प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में वृहद् एवं लघु हिमालय की श्रेणियाँ स्थित हैं जिनकी पूर्व-पश्चिम लम्बाई लगभग 625 किमी० है । इन्हें कुमायूँ हिमालय के नाम से जाना जाता है । इस क्षेत्र के सर्वाधिक ऊँचे शिखर वृहद् हिमालय श्रेणी में स्थित हैं जिनमें अनेक शिखर वर्ष के अधिकांश महीनों में हिमाच्छादित रहते हैं । नन्दादेवी (7816 मीटर), कामेत (7756 मीटर), चौखम्बा (7138 मीटर), त्रिशूल (7120 मीटर), बद्रीनाथ (7038 मीटर), द्रोणगिरि (7066 मीटर), केदारनाथ (6940 मीटर) तथा गंगोत्री, कोसी, पिण्डारी आदि विशाल हिमनद इसी क्षेत्र में मिलते हैं जो नदियों के लिए जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं । उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियों - गंगा एवं यमुना के उद्गम स्थल क्रमश: गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद यहीं हैं। वृहत् या आन्तरिक हिमालय श्रेणी के दक्षिण में लघु हिमालय की श्रेणियाँ स्थित हैं जिनकी ऊँचाई 2000 मीटर से 2500 मीटर के मध्य पायी जाती है । मंसूरी, अलमोड़ा, चकराता, नैनीताल आदि स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी नगर इन्हीं श्रेणियों के निचले भागों में स्थित हैं जहाँ ग्रीष्मकाल में मैदानी भागों से हजारों लोग स्वास्थ्य-लाभ तथा मनोरंजन हेतु आते रहते हैं । लघु हिमालय के दक्षिण में व्यास तथा गंगानदी के ऊपरी छोरों के मध्य शिवालिक की निचली पहाड़ियाँ स्थित हैं जो विछिन्न रूप में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं । वास्तव में ये हिमालय के पाद-प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊँचाई सामान्यतया 1000 मीटर से अधिक नहीं है । शिवालिक श्रेणी का निर्माण नदियों द्वारा संग्रहीत कंकड़, बालुका प्रस्तर तथा चिकनी मिट्टी के साथ कांग्लोमरेट आदि शैलों द्वारा हुआ है । इस श्रेणी की पहाड़ियाँ कतिपय स्थलों पर चौरस क्षैतिज घाटियों द्वारा मुख्य हिमालय से पृथक हो गयी हैं जिन्हें 'दून' के नाम से जाना जाता है । इन घाटियों में देहरादून की घाटी अधिक महत्वपूर्ण है ।

हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिण पर्वतीय तलहटी में कंकड़ीली तथा पथरीली मिट्टियों द्वारा निर्मित एक संकीर्ण पेटी (15 से 20 किमी० चौड़ी) मिलती है जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है । उत्तर से आने वाली नदियों एवं स्रोतों का जल इस क्षेत्र में अदृश्य हो जाता है और धरातल के ऊपर न बहकर कंकड़-पत्थरों के नीचे-नीचे बहता रहता है । इस प्रकार धरातल के नीचे प्रवाहित जल धारायें आगे दक्षिण

में पुनः प्रकट होती हैं। भाबर प्रदेश के दक्षिण में और उसके समानान्तर एक संकीर्ण पट्टी में तराई का समतल मैदानी एवं दल-दली क्षेत्र विस्तृत है जहाँ उत्तर में भाबर प्रदेश में लुप्त जल धारायें पुनः धरातल पर प्रवाहित होने लगती हैं। अपेक्षाकृत निचला भाग होने एवं जलाधिक्य के परिणामस्वरूप यहाँ की भूमि प्रायः दलदली हो जाती है। तराई का निर्माण बारीक मिट्टी के निक्षेप से हुआ है जो दक्षिण में मुख्य मैदानी भाग में विलीन हो जाता है।

भाबर एवं तराई के दक्षिण में तथा दक्षिणी पठार के उत्तर में गंगा के विशाल समतल मैदान का विस्तार है जो राज्य के आधे से अधिक क्षेत्रफल को समाहित करता है। हिमालय के निर्माण के पश्चात् उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में गोण्डवाना लैण्ड (वर्तमान प्रायद्वीपीय पठार) के मध्य उत्पन्न निम्न गर्त में मुख्यरूप से उत्तर से आने वाली नदियों द्वारा किये गये निक्षेपों से इस विस्तृत समतल मैदान की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इस मैदान की ऊँचाई कहीं भी 300 मीटर से अधिक नहीं है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। यद्यपि उत्तर-पश्चिम में ऊँचाई सागरतल से 250 मीटर से अधिक मिलती है किन्तु पूर्व में यह 80 मीटर से भी कम हो गयी है। इस मैदान में संचित काँप मिट्टी की गहराई 400 मीटर से भी अधिक होने का अनुमान है। मिट्टी की मोटाई उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इस विशाल मैदान को उसके निक्षेपों की भूगर्भिक रचना के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जाता है - 1. बाँगर और 2. खादर भूमि। प्राचीन काँप द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत ऊँची भूमि जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता 'बाँगर' कहलाती है। नवीन काँप के निक्षेप से निर्मित भूमि को 'खादर' कहा जाता है जिसके ऊपर नदियों के बाढ़ का जल प्रायः प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है और नवीन मिट्टी का निक्षेप होता रहता है। बाँगर भूमि में अपेक्षाकृत कंकड़ एवं बड़ी कणों वाली मिट्टी की अधिकता मिलती है जबकि खादर भूमि में चिकनी मिट्टी के साथ रेत की अधिकता पायी जाती है। बाँगर भूमि की अपेक्षा खादर भूमि अधिक उपजाऊ होती है।

समतल मैदान के दक्षिण में संकीर्ण पठारी भाग स्थित है जिसके दक्षिण में विन्ध्या

चल की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं । यह दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है जिन्हें क्रमशः बुन्देलखण्ड पठार और विन्ध्य पठार के नाम से जाना जाता है । यह पठार प्राचीन शैलों द्वारा निर्मित है जिसमें चूना पत्थर की प्रधानता है और भूमि प्रायः कंकड़ीली, पथरीली एवं अनुपजाऊ है ।

1.3 अपवाह-तन्त्र

उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग का अपवाह प्रतिरूप सामान्यतया उत्तर पश्चिम से दक्षिण-पूर्व ढाल के अनुरूप है । उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तथा दक्षिणी उच्च भूमि में अपेक्षाकृत समिश्र भूमभिंक संरचना तथा उच्चावचन के परिणामस्वरूप यह प्रतिरूप अधिक उलझा हुआ है । गंगा इस प्रदेश की प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर प्रदेश के मध्य से गुजरती है । गंगा की सहायक नदियाँ - रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती एवं गण्डक उत्तर से तथा यमुना, टोंस तथा सोन दक्षिण से अपनी अपनी सहायक नदियों के साथ आकर इसमें मिलती हैं । प्रदेश की सभी प्रमुख नदियाँ सामान्यतया समानान्तर प्रवाहित होती हैं (चित्र 1.3) ।

इन नदियों के तीन उद्‌गम क्षेत्र हैं - उत्तर में हिमालय पर्वत, मध्य में मैदानी झीलें एवं दलदली निम्न क्षेत्र तथा दक्षिण में दक्षिणी पठारी क्षेत्र । गंगा, यमुना, काली, शारदा तथा गण्डक नदियाँ वृहत् हिमालय के दक्षिणी ढाल से निकलती हैं । रामगंगा तथा राप्ती नदियाँ लघु हिमालय श्रेणी से तथा हिण्डन एवं सेलानी नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं । हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेशों के हिमद्रवण तथा पर्याप्त वर्षा से इन नदियों का प्रवाह वर्ष भर बना रहता है । उत्तर प्रदेश की कतिपय नदियाँ मैदानी भाग में स्थित झीलों एवं दलदली क्षेत्रों से उद्‌भूत हुई हैं जो वर्षा ऋतु के अतिरिक्त शेष मासों में प्रायः शुष्क रहती हैं जैसे गोमती, सई, बरूण, पाण्डों, ईसन आदि । चम्बल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहन्द, कन्हर आदि नदियाँ दक्षिणी पठार से उद्‌भूत होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई अन्ततः गंगा-क्रम में विलीन हो जाती हैं । हिमालय प्रदेश से उद्‌भूत नदियाँ विन्ध्य श्रेणी से उद्‌भूत नदियों की तुलना में अधिक जलपूर्ण तथा सक्रिय रहती हैं जिन्हें हिम प्रवण के साथ ही मानसून का पर्याप्त वर्षा जल भी प्राप्त होता रहता है ।

1.4 जलवायु

उत्तर प्रदेश भूमध्य रेखा से दूर भारतीय उपमहाद्वीप के आन्तरिक भाग में स्थित है जहाँ मानसूनी जलवायु पायी जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने चार मौसमों को निर्धारण किया है जो इस राज्य में भी सामान्य रूप से पाया जाता है। ये हैं - 1. वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल (जून से सितम्बर), 2. परावर्तित दक्षिणी-पश्चिमी मानसून काल (अक्टूबर-नवम्बर) 3. शीत ऋतु या उत्तरी पूर्वी मानसून काल (दिसम्बर-फरवरी) 4. ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई)।

वर्षा ऋतु का आरम्भ सामान्यतया जून के द्वितीय सप्ताह के पश्चात् ग्रीष्म कालीन वर्षा के साथ होता है। इस ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता में तीव्र वृद्धि होने लगती है जो 70 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी या उत्तरी-पश्चिमी वायु की दिशा परिवर्तित होकर पूर्वी अथवा दक्षिणी-पूर्वी हो जाती है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत वार्षिक वर्षा इसी ऋतु में प्राप्त होती है।

मध्य सितम्बर के पश्चात् दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का परावर्तन आरम्भ हो जाता है। यद्यपि दिन का तापमान सामान्यतया मध्यम प्रकार का होता है किन्तु रात्रि के तापमान में तीव्रता से पतन होता है। इस काल में वायु की विविधता अपेक्षाकृत अधिक किन्तु शक्ति क्षीण होती है। पूर्वी पवन की प्रवाह दिशा का परिवर्तन दक्षिण, दक्षिण-पूर्व अथवा पूर्व की ओर हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नवम्बर तक घट जाती है और इस ऋतु में वार्षिक वर्षा का लगभग 5 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो पाता है।

शीत ऋतु का प्रारम्भ तापमान तथा सापेक्ष-आर्द्रता दोनों के पतन के साथ नवम्बर से होता है। सम्पूर्ण प्रदेश में वायुमण्डलीय दबाव दिसम्बर के अन्त अथवा जनवरी के प्रारम्भ से अधिक गहन होने लगता है। स्वच्छ आकाश, निम्न तापक्रम एवं आर्द्रता, मन्द गामिनी उत्तरी एवं उत्तरी-पश्चिमी पवनें तथा सुहावना मौसम शीत-ऋतु की मुख्य विशेषतायें हैं। जनवरी इस ऋतु का सर्वाधिक शीतल मास होता है।

हवाओं के स्थलीय एवं शुष्क होने के कारण इनसे वर्षा नहीं हो पाती है किन्तु जनवरी में मैदानी भागों में यदा-कदा पाला पड़ता है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी होता है तथा पर्वतीय शिखर सदैव हिमाच्छादित रहते हैं । भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उद्भूत शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों के आगमन से मौसम क्र में आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनसे 10 सें0मी0 तक वर्षा हो जाती है जो रबी की फसल के लिये लाभप्रद होती है किन्तु कभी-कभी इन चक्रवातों के साथ होने वाली उपल वृष्टि अत्यधिक हानिप्रद होती है । मैदानी भागों में शीतलहरों के प्रचलन से मौसम अत्यन्त शीतल तथा कष्टदायक हो जाता है ।

मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है । मार्च से तापक्रम में निरन्तर वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है जो मई तक अत्यधिक असहनीय हो जाती है और मैदानी भागों में कतिपय स्थलों का तापमान 46^{0} सें0ग्रे0 से भी ऊपर पहुँच जाता है । मई में अत्यधिक उष्ण पश्चिमी पवनें तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं जिन्हें 'लू' कहा जाता है । ये पवनें अत्यन्त उष्ण एवं शुष्क तथा शरीर को झुलसा देने वाली होती हैं । ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आँधियां तथा तूफान आते हैं जिनके साथ यदा-कदा उपलवृष्टि भी हो जाती है और धन जन की भारी क्षति होती है । इस ऋतु में वर्षा की मात्रा अत्यल्प होती है जो प्राय: 10 से 25 से0मी0 के मध्य पायी जाती है । पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त होती है ।

राज्य की सम्पूर्ण वर्षा की 80 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि वर्षा ऋतु में होती है और मात्र जुलाई एवं अगस्त माह में ही लगभग 60 प्रतिशत मात्रा प्राप्त हो जाती है । सितम्बर से मानसून के परावर्तन के साथ ही वर्षा की मात्रा में ह्रास होता जाता है । मानसूनी वर्षा अनियमित तथा अनिश्चित होती है जिससे प्रदेश के विभिन्न भागों में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी दशायें उत्पन्न होती रहती हैं जिससे प्रतिवर्ष काफी आर्थिक क्षति होती है । वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता के कारण प्रदेश के विशाल मैदानी एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में दुर्भिक्ष की सम्भावना बनी रहती है [चित्र 1.4] ।

1.5 प्राकृतिक वनस्पति

प्राकृतिक वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व मिट्टी तथा जलवायु-दशायें होती हैं। कुछ शताब्दियों पूर्व गंगा मैदान के वृहत् भाग वनाच्छादित थे। वर्तमान शताब्दी के चौथे दशक तक भी सरयूपार मैदान के विस्तृत क्षेत्र में सघन वनों का विस्तार था किन्तु पिछले 40-50 वर्षों में वन एवं वन क्षेत्रों की सैकड़ों हैक्टेयर भूमि कृषि के अन्तर्गत प्रयुक्त होने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश अपने वनों के अतीत गौरव एवं महत्ता से वंचित हो गया है। चित्र 1.5 से स्पष्ट है कि वनों के अवशेष केवल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तराई एवं भाबर क्षेत्रों तथा दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं और मैदानी भाग सामान्यतः वन विहीन हो चुके हैं।

राज्य का मात्र 10 प्रतिशत भाग ही वनाच्छादित है जबकि यह प्रतिशत सम्पूर्ण देश के लिये लगभग 20 प्रतिशत है। राज्यों में वनों के क्षेत्रीय वितरण में अधिक असमानता पायी जाती है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का 45 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 5 से भी कम है। राज्यों के कुल जनपदों में से 34 जनपदों में वन क्षेत्र नगण्य है और 20 जनपदों में वनाच्छादित क्षेत्र 10 प्रतिशत से भी अल्प है। उत्तरी पर्वतीय जनपदों के कुल क्षेत्रफल के 40-60 प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। बुन्देलखण्ड के पठारी जनपदों में वन क्षेत्र का प्रतिशत 5 से 10 तक है जबकि मिर्जापुर जनपद के पठारी एवं पहाड़ी भागों में 30 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित है। वन विभाग के संरक्षण के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त वनों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है - 1. सुरक्षित वन, 2. संरक्षित वन और 3. अवर्गीकृत वन। भौगोलिक आधार पर उत्तर प्रदेश के वनों को 5 प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है - 1. उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन, 2. उष्ण कटिबन्धीय कटीले वन, 3. उपोष्ण कटिबन्धीय आर्द्र सदापर्णी वन, 4. समशीतोष्ण कटिबन्धीय वन, और 5. अल्पाइन वन।

वर्षा की मात्रा के आधार पर उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वनों को दो उपवर्गों-

आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन में विभक्त किया जा सकता है । शिवालिक के निम्नवर्ती ढालों, तराई तथा भाबर क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेमी0 से अधिक है आर्द्र पर्णपाती वन विकसित होते हैं जिनके प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, गूलर, खैर, तुन, हल्दू और सेमल आदि हैं । वृक्षों के साथ-साथ बांस, सवाई, रामसई, थामर, मूज तथा कास आदि लम्बी घासें उत्पन्न होती हैं । मैदान तथा दक्षिणी पठार के 50 से 100 से0मी0 वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनों के वृक्ष उगते हैं जिनकी ऊँचाई वर्षा की अल्पता के कारण कम होती है । शीशम, चन्दन, हल्दू तथा महुआ इसके प्रमुख वृक्ष हैं । राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी जनपदों के 50 सेमी0 से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटी-छोटी काटेदार पत्तीयुक्त वृक्ष मिलते हैं जिनमें बबूल सर्वप्रमुख हैं । उत्तरी पर्वतीय जनपदों के 1000 से 2000 मीटर की ऊँचाई तक सदापर्णी वन मिलते हैं जिनमें चीड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है । उत्तरी पर्वतीय जनपदों के 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊँचाई पर समशीतोष्ण कटिबन्धीय आर्द्र वन पाये जाते हैं । इन वनों में देवदार, सिलवर, फर, स्प्रूस तथा नीली चीड़ आदि के कोण-धारी सदापर्णी वृक्ष उत्पन्न होते हैं । हिमालय के 3000 मीटर से अधिक ऊँचे भागों में अल्पाइन वनस्पतियाँ विकसित होती हैं । वर्च, पाइन, देवदार तथा भोजपत्र आदि इस क्षेत्र के मुख वृक्ष हैं जिनके साथ-साथ छोटे छोटे कोणधारी वृक्षों तथा झाड़ियों का भी बाहुल्य मिलता है ।

प्रदेश के वनों का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है । वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग घरेलू ईंधन से लेकर भवन-निर्माण सामग्री तथा विविध उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है । इन वनों से ही रसदार फल, जड़ी बूटियाँ तथा औषधियों आदि की प्राप्ति सम्भव हो पाती है । कागज एवं गत्ता के लिए लुग्दी और कत्था तथा अन्य उद्योगों के लिए सामग्री भी वनों से ही उपलब्ध होती है । पशुओं हेतु चारागाह प्रदान करने के अतिरिक्त वन भूमि संरक्षण तथा वातावरण प्रदूषण को नियमित करने में सहायक होते हैं ।

1. 6 मिट्टी एवं खनिज संसाधन

1. <u>मिट्टी</u>

मिट्टी भूपृष्ठ की मूल चट्टानों में उन परिवर्तनों का परिणाम होती है जो जलवायु तथा उच्चावचन की विभिन्न दशाओं के अन्तर्गत जैविक कारकों द्वारा सम्पादित होते हैं। संसार के प्राय: अधिकांश जीवधारियों एवं वनस्पतियों का भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मिट्टी द्वारा ही प्राप्त होता है। कृषि, पशुपालन तथा वन एवं वनोद्योग का आधार मिट्टियाँ ही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान क्षेत्र के लिए मिट्टियों का महत्व और भी अधिक होना स्वाभाविक है।

उत्तर में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पहाड़ी मिट्टी प्राप्त होती है। दक्षिण में दक्षिणी पठार पर प्राचीन युग की पर्तदार विन्ध्य शैलों के विखण्डन से निर्मित अवशिष्ट मिट्टी का विस्तार मिलता है। प्रदेश में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर मिट्टी के भारी होने की सामान्य प्रवृत्ति मिलती है। पश्चिमी सीमान्त जनपदों में जहाँ अर्द्धशुष्क दशायें पायी जाती हैं यत्र-तत्र रेह, मिट्टी और वायु जनित बालू के ढेर भी पाये जाते हैं। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत निम्न एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ नवीन जलोढ़ के निक्षेप से मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। उच्चवर्ती भागों में पुरातन जलोढ़ पाये जाते हैं जिसमें कंकड़ भी सम्मिलित होते हैं।

भूगर्भिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोणों से उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को तीन प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है - 1. हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ, 2. समतल मैदानी मिट्टियाँ, और 3. दक्षिणी पठारी मिट्टियाँ।

हिमालय प्रदेश की मिट्टियाँ नवीन तथा अपरिपक्व हैं जिनके कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उर्वरता अत्यल्प होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जो भूगर्भिक संरचना तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बालुका एवं छिद्रयुक्त तृतीयक मिट्टी मिलती है। दून घाटी में चिकनी तथा चिकनी दोमट मिट्टी उपलब्ध है जो लौहांश तथा जीवांश की अधिकता के कारण चाय की कृषि के लिए

उपयोगी है। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की कंकड़ीली-पथरीली मिट्टियाँ भी यत्र तत्र देखी जा सकती है।

गंगा के समतल मैदानी भागों में जलोढ़ या काँप मिट्टी का बाहुल्य है जिसका उद्भव गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसादों के सतत् निक्षेपण से हुआ है। निर्माणावधि एवं संरचना के आधार पर जलोढ़ को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है - 1. पुरातन जलोढ़ (बांगर मिट्टी) और 2. नूतन जलोढ़ (खादर मिट्टी) मैदान के अपेक्षाकृत उच्चवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, पुरातन जलोढ़ मिलते हैं जिन्हें 'बागर' के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भिन्नता के परिणामस्वरूप 'बांगर' क्षेत्र के पृथक-पृथक भागों में कटियार (चिकनी), बलुई, मटियार-दोमट, बलुई-दोमट तथा भूड़ आदि विविध प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं। आवरण-क्षय के कारण कतिपय क्षेत्रों में कंकड़ तथा कठोर मिट्टी के टीले भी मिलते हैं जो अनुपजाऊ होते हैं। कहीं-कहीं पर रेत युक्त मिट्टी का भी विस्तार है जो ऊसर या बंजर के रूप में कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है।

नदियों के बाढ़-क्षेत्रों में जहाँ तक बाढ़ का जल प्राय: प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है नवीन निक्षेप संचित होते रहते हैं जिन्हें नूतन जलोढ़ या 'खादर' मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी महीन कणों वाली, छिद्र युक्त तथा अपेक्षाकृत अधिक जल धारण-क्षमता युक्त होने के कारण अधिक उपजाऊ होती है। इसमें चूना, पोटाश, जीवांश तथा मैगनेशियम की मात्रा अधिक मिलती है। खादर की मिट्टियाँ बलुई, बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि कई प्रकार की होती है। अधिक उर्वरता के कारण इनमें कृत्रिम उर्वरकों की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जलधारण की क्षमता अधिक होने के कारण इनमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है।

दक्षिणी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय: विन्ध्य शैलों के विखण्डन से निर्मित अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिनमें स्थानीय विभिन्नतायें भी मिलती हैं। इन क्षेत्रों की प्रमुख मिट्टियाँ भोण्टा, माड़, काबड़, राकड़ तथा परवा आदि हैं। माड़ एवं काबड़ मिट्टियाँ दक्षिणी भारत की काली या रेगड़ मिट्टी के लगभग समान

होती हैं जो कृषि के लिए उपयोगी हैं । हमीरपुर तथा जालौन जनपदों में यमुना नदी के बीहड़ों में अल्प जीवांश वाली हल्के लाल रंग की महीन कणों वाली बलुई-दोमट मिट्टी मिलती है जिसे 'परवा' कहा जाता है । पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर आवरण-क्षय के परिणामतः अनुर्वर 'राकड़' मिट्टियाँ मिलती हैं । पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तर एवं शैल-चूर्ण के रूप में 'भोण्टा' नामक मिट्टी भी पायी जाती है ।

2. खनिज संसाधन

खनिज पदार्थों की उपलब्धि के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का एक अभाव ग्रस्त राज्य है । सैकड़ों मीटर की गहराई तक जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित विशाल गंगा मैदान में यत्र-तत्र मात्र कंकड़ों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का नितान्त अभाव है । हिमालय प्रदेश और दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में ही कतिपय खनिज निक्षेप उपलब्ध हैं । चूना पत्थर, सिलिका (रेत) फास्फेटिक शैल तथा मैग्नेसाइट प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज हैं । इनके अतिरिक्त पाइरोफिलाइट, कोयला, संगमरमर, कैल्साइट, अग्नि मृदा, ऐस्वेस्टस तथा कतिपय आधारभूत धातुयें जैसे जिप्सम, ग्रेफाइट तथा सल्फर भी यहाँ उपलब्ध हैं ।

पोर्टलैण्ड सीमेंट तथा रासायनिक उद्योगों में चूनापत्थर एक अत्यन्त उपयोगी तथा आधारभूत पदार्थ है । इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य औद्योगिक कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है । राज्य में चूने पत्थर के दो प्रमुख क्षेत्रों में से सर्वप्रमुख क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के देहरादून तथा गढ़वाल जनपद हैं तथा द्वितीय दक्षिणी पठार का मिर्जापुर तथा बाँदा जनपदी क्षेत्र हैं । भारत के सम्पूर्ण चूना पत्थर भण्डार (20842 करोड़ टन) का एक तिहाई से अधिक (777.2 करोड़ टन) उत्तर प्रदेश में संचित है ।[3] मिर्जापुर जनपद के चूना पत्थर की दो प्रमुख पेटियाँ हैं - कजरहट और रोहतास । ओबरा से कोटा के मध्य कजरहट पेटी में लगभग 11 करोड़ टन का भण्डार निहित है ।[4]

उत्तर प्रदेश देश का वृहत्तम सिलिका बालू उत्पादक राज्य है जहाँ से भारत के कुल उत्पादन का 70-75 प्रतिशत की उपलब्धि होती है । यह काँच उद्योग का आधारभूत एवं प्रधान कच्चा माल है । इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़ तथा बारगढ़ क्षेत्र

सिलका बालू के सर्वाधिक उत्पादक हैं। बाँदा, झाँसी, वाराणसी तथा देहरादून जनपदों में भी सिलिका बालू के निक्षेप हैं। प्रदेश में लगभग 15 करोड़ मैट्रिकटन मैग्नेसाइट के निक्षेप का अनुमान है।[5] इसका उपयोग इस्पात उद्योग में सहायक कच्चे माल के रूप में होता है। मैग्नेसाइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र देवलधर तथा बागेश्वर (अल्मोड़ा) हैं।

रासायनिक उर्वरकों, पोर्टलैण्ड सीमेंट, गंधक, तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली खड़िया (क्ले) का मुख्य रूप से निक्षेप उत्तरी पर्वतीय जनपदों में स्थित है। बर्तन तथा ईंट निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली अग्नि मिट्टी (फायर क्ले) तथा चीनी मिट्टी मिर्जापुर तथा बाँदा जनपदों के दक्षिणी क्षेत्रों से प्राप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में कुमायूं तथा गढ़वाल जनपद प्रमुख ताँबा और जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं। कालीनदी से लेकर गढ़वाल-देहरादून जनपदीय सीमा तक ताँबा-जस्ता पेटी मिलती है। अन्य पर्वतीय जनपदों - चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल तथा अल्मोड़ा में भी ताँबा के लघु निक्षेपों का अन्वेषण किया गया है।

प्रदेश में उच्च एवं मध्य श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का सर्वथा अभाव है और मात्र निम्न श्रेणी के लघु निक्षेप ही उत्तर में कुमायूँ क्षेत्र तथा दक्षिण में मिर्जापुर एवं झाँसी जनपदों में कतिपय विकीर्ण स्थलों पर पाये जाते हैं। घटिया श्रेणी तथा लौहांश की अल्पता के कारण इनका औद्योगिक महत्व अत्यल्प है।

कोयला प्राप्ति का एकमात्र क्षेत्र मिर्जापुर जनपद का कोटा कोयला क्षेत्र है जहाँ से द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। यह सिंगरौली कोयला क्षेत्र का ही आगे बढ़ा हुआ भाग है जहाँ लगभग 20 लाख टन कोयले के संचय का अनुमान है।

1.7 कृषि

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम अंग है। कृषि एवं इससे संबद्ध

कार्यों में प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या संलग्न है । प्रदेश के कुल उत्पादनों का 65 प्रतिशत से अधिक इसी व्यवसाय से उपलब्ध होता है । कृषि के विकास हेतु प्रदेश को कतिपय विशिष्ट जलवायु तथा भौतिक दशायें उपलब्ध हैं जो अन्य समीपवर्ती राज्यों को नहीं प्राप्त हैं । गंगा के समतल मैदान में गहरी एवं उर्वर जलोढ़ मिट्टी की बहुलता, पर्याप्त वर्षा एवं नहर तथा सिंचाई के अन्य साधनों की उपलब्धता आदि ने सम्मिलित रूप से इस प्रदेश को देश के सर्वाधिक उर्वर प्रदेश का स्वरूप प्रदान किया है ।

1. <u>भूमि उपयोग</u>

उत्तर प्रदेश के कुल आलेखित क्षेत्रफल (297.56 लाख हेक्टेयर) का 17.29 प्रतिशत वन के अन्तर्गत आता है तथा 24.71 प्रतिशत भूमि बंजर, ऊसर, परती, चारागाह, झाड़ियों आदि के रूप में पायी जाती है । इस प्रकार कुल क्षेत्रफल का 58.00 प्रतिशत भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत आता है (तालिका 1.1)

<u>तालिका 1.1</u>

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग (1983-84)

	क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	कुल आलेखित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1. आलेखित क्षेत्रफल	29,756	100.00
2. वन	5,121	17.29
3. ऊसर तथा कृषि के अयोग्य भूमि	1,105	3.70
4. गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि	2,352	7.90
5. कृषि योग्य बंजर	1,130	3.80
6. स्थायी चारागाह एवं पशुचारण	298	1.00
7. वृक्षों एवं झाड़ियों के अन्तर्गत भूमि	548	1.84
8. चालू परती	1,160	3.79
9. अन्य परती	780	2.61
10. शुद्ध बोयागया क्षेत्र	17,262	58.00
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	7,806	-

स्रोत : कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।

2. <u>शस्य प्रतिरूप</u>

उत्तर प्रदेश का शस्य प्रतिरूप विकासशील कृषि अर्थतंत्र का एक विशिष्ट उदाहरण है जहाँ अधिकांश कृषि भूमि का उपयोग निर्वाह-मूलक खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु होता है। कुल बोये गये क्षेत्रफल का लगभग 80 प्रतिशत भूमि बिभिन्न खाद्यानों के अन्तर्गत प्रयुक्त होती है। नकदी फसलें जैसे गन्ना और आलू के अन्तर्गत कृषिभूमि का अल्पांश ही लगा हुआ है।

खाद्य फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूँग आदि मुख्य हैं जबकि तेलहन (सरसो, अलसी, मूगफली, तिल), रेशेदार फसलें (कपास, सनई, पटसन) तथा चरी आदि प्रमुख अखाद्य फसलें हैं। खाद्यानों में गेहूँ का प्रथम स्थान है जो प्रदेश के कुल बोये गये क्षेत्रफल के 33.59 प्रतिशत क्षेत्रफल पर उत्पन्न किया जाता है (1982-83)। इसका वितरण समस्त मैदानी क्षेत्र पर है। गेहूँ के पश्चात् चावल दूसरे स्थान पर आता है जो कुल बोयी गयी भूमि के 20.48 प्रतिशत भाग पर पैदा किया जाता है। गेहूँ और चावल के पश्चात् चना (6.09 प्रतिशत) मक्का (4.39 प्रतिशत), बाजरा (3.86 प्रतिशत), जौ (2.53 प्रतिशत), ज्वार (2.28 प्रतिशत), मटर (2.20 प्रतिशत) का स्थान आता है। गन्ना प्रदेश की वृहत्तम औद्योगिक फसल है जिसका उत्पादन कुल कृषि भूमि के लगभग 7.22 प्रतिशत भाग पर किया जाता है।[6]

प्रदेश के सम्पूर्ण उपजें तीन फसलों-खरीफ, रबी और जायद के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती हैं। कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक (आधे से अधिक क्षेत्रफल) खरीफ फसल के अन्तर्गत प्रयुक्त होता है जिसकी प्रधान उपज चावल है। लगभग 43 प्रतिशत भूमि पर रबी की फसल उत्पन्न की जाती है जिसकी प्रमुख उपजें गेहूँ, चना मटर आदि हैं। जायद फसल के अन्तर्गत कुल कृषि भूमि का 1.00 प्रतिशत से भी कम भूमि प्रयुक्त हो पाती है।

3. <u>सिंचाई</u>

उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए सिंचाई का बड़ा महत्व है, विशेष

रूप से मानसूनी वर्षा के अनियमित, अनिश्चित तथा असमान वितरण के कारण इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है । बाढ़ और सूखा के पुनरावृत्ति से प्रदेश की विविध फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं । अतः केवल ग्रीष्मकालीन उपजों के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न उपजों के उचित विकास तथा अधिक उत्पादन हेतु सिंचाई अपरिहार्य है । वर्तमान काल में रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग तथा परिष्कृत बीजों के लिए उपयुक्त समय पर पर्याप्त जल की परमावश्यकता पड़ती है । कतिपय फसलें जैसे चावल और गन्ना के संतुलित विकास के लिए अन्य उपजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती है ।

प्रदेश के कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 188.55 लाख हेक्टेयर[7] है जो कुल कृषि भूमि का 48.46 प्रतिशत (1984-85) है । शक्ति चालित नलकूप, नहरें, तालाब एवं झीलें तथा साधारण कुएँ सिंचाई के प्रमुख साधन हैं । नलकूप और कुएँ से लगभग 47 प्रतिशत सिंचित भूमि को जल उपलब्ध होता है । प्रदेश में अनेक नहर सिंचाई योजनायें एवं परियोजनायें संचालित हैं जो कुल सिंचित भूमि के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्रफल को समाहित करती हैं । प्रदेश की विद्यमान नहर योजनाओं में ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, आगरा नहर, बेतवा नहर तथा केन नहर प्रमुख हैं ।

उत्तर प्रदेश में कच्चे एवं पक्के लगभग 15 लाख कुएँ हैं जिनका उपयोग सिंचाई तथा पेयजल प्राप्ति के लिए किया जाता है । कुओं से सिंचाई-हेतु पुर या चरस, रहट, ढेकली आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है । कुल सिंचित भूमि के लगभग आधे की सिंचाई नलकूप तथा कुओं द्वारा की जाती है । शक्ति चालित नलकूपों द्वारा 800 से 1000 एकड़ भूमि सिंचन क्षमता होती है अतः मैदानी भागों में जहाँ नहरें नहीं हैं नलकूपों के प्रचलन में प्रसार हो रहा है । नलकूपों द्वारा सिंचाई मुख्यतया पश्चिमी तथा पूर्वी जनपदों के उर्वर मैदानी भागों में की जाती है । पश्चिमी जनपदों के नलकूपों को गंगा जल विद्युत क्रम से तथा पूर्वी जनपदों को गंगा जल विद्युतक्रम तथा शारदा क्रम (सुहावल शक्ति गृह) से विद्युत उपलब्ध होती है ।

4. उर्वरक

हरित-क्रान्ति के पश्चात् पौधों के समुचित विकास तथा उपजों के उच्च उत्पादन हेतु विविध प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग नितान्त आवश्यक हो गया है। 1983-84 में नाइट्रोजन फास्फेट तथा पोटास आदि से सम्पन्न विभिन्न प्रकार के 5 लाख टन से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की खादें भी उल्लेखनीय मात्रा में प्रयुक्त होती हैं। इनमें गोबर की खाद, हरी खाद तथा कम्पोस्ट खाद विशेष उल्लेखनीय हैं।

5. पशु-धन

पशुओं से हमें अनेक उपयोगी पदार्थ दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ, चमड़े, हड्डियाँ, ऊन तथा मांस आदि प्राप्त होते हैं। इनमें से अनेक पदार्थ कतिपय उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे चमड़ा- शोधन, अस्थि पेरना, दरी तथा कम्बल निर्माण उद्योग आदि। बैलों तथा भैंसों को विविध कृषि कार्य में चालक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेतों की जुताई, कुओं से जल निष्कासन, फसलों की मड़ाई, तथा उत्पादनों को बाजारों तक पहुंचाने आदि कार्यों में इनका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। गाय-भैंसे प्रधान दुग्ध स्रोत हैं और इनसे प्राप्त गोबर मिट्टी के लिए उत्तम खाद बनती है। भारत में पशुओं की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पायी जाती है। पशु जनगणना 1978 के अनुसार प्रदेश में लगभग 136.3 लाख बैल और 66.5 लाख गायें, 140 लाख भैंसे, 20.6 लाख भेंड़ तथा 84.6 लाख बकरियाँ पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख घोड़े एवं खच्चर तथा 2 लाख गधे और 0.38 लाख ऊँट भी मिलते हैं जो भार वाहन के लिए उपयोगी होते हैं।[8] पर्वतीय जनपदों में भेंड़ तथा बकरियाँ मुख्य पालतू पशु हैं जिनसे दुग्ध, मांस, तथा ऊन और चमड़े प्राप्त होते हैं। प्रदेश सरकार आर्थिक पिछड़ेपन में सुधार हेतु कुक्कुट तथा सुअर पालन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में डेरी उद्योग के विकास-हेतु 'श्वेत क्रांति' चलायी जा रही है।

1.8 उद्योग धंधे

औद्योगिक कच्चे माल एवं शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता, परिवहन एवं संचार की अपर्याप्त सुविधाओं, कुशल श्रमिकों की अल्पता, पूँजी तथा स्थानीय उद्यमियों के अभाव के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक अविकसित एवं पिछड़ा राज्य है किन्तु अपनी विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ औद्योगिक उत्पादनों का वृहद् बाजार विद्यमान है। यहाँ औद्योगिक पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण औद्योगिक खनिजों तथा शक्ति के साधनों के अभाव को ही माना जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में कतिपय वृहत् उद्योगों का विकास मुख्यतया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। सूती वस्त्र, चीनी, कांच, कागज तथा ऊनी वस्त्र उद्योग प्रदेश के वृहत् पैमाने के उद्योग हैं जिनके विकास का कारण अधिक जनसंख्या द्वारा अधिक माँग और सस्ते श्रम की उपलब्धि तथा कतिपय कच्चे माल जैसे गन्ना, कपास, तिलहन आदि की पर्याप्त उपलब्धता है।

वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग है जिसका केन्द्रीकरण मुख्यतया स्थानीय माँग पर आधारित है। यहाँ सूती कारखानों की कुल संख्या 32 है जिनमें से 7 मिलें कानपुर नगर में केन्द्रित हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अन्य केन्द्र हैं - हाथरस, मोदीनगर, अलीगढ़, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मऊनाथ भंजन, टाण्डा, फैजाबाद आदि। उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र के छोटे-बड़े कुल 4 कारखाने हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग का सर्वप्रमुख केन्द्र कानपुर है जहाँ एशिया की प्रसिद्ध ऊनी मिल 'लाल इमली मिल्स' स्थित है। इसके अतिरिक्त मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद जनपदों में भी ऊनी वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ कार्यशील हैं। रेशमी वस्त्र के कारखानें वाराणसी मिर्जापुर, तथा शाहजहाँपुर में हैं। रेशमी वस्त्र निर्माण में वाराणसी अपनी उत्तम दक्षता एवं कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है जहाँ की बनारसी साड़ियाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। कानपुर में आयातित लुग्दी पर आधारित रेशम उद्योग की भी स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश में जूट उद्योग के कुल 7 कारखाने हैं। इसके प्रमुख केन्द्र कानपुर, वाराणसी तथा सहजनवा (गोरखपुर) में हैं जहाँ के प्रमुख उत्पादन बोरे,

टाट तथा वस्त्र आदि हैं ।

चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण उद्योग है । देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग एक तिहाई इसी प्रदेश से प्राप्त होता है । स्थानीय गन्ने पर आधारित चीनी उद्योग का स्थानीयकरण प्रदेश की विख्यात गन्ना पेटी में हुआ है जिसका विस्तार पश्चिम में सहारनपुर व मेरठ से लेकर पूर्व में देवरिया व बलिया जनपदों तक फैली हुई है । प्रदेश में कुल 90 चीनी कारखाने हैं जिनमें 21 सहकारी क्षेत्र में हैं । प्रमुख चीनी उत्पादक केन्द्र देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, सीतापुर, हरदोई, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नैनीताल आदि हैं/कुछ चीनी मिलें गंगा-घाघरा दो-आब के विभिन्न स्थानों पर भी स्थापित हुई हैं ।

उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग में प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का बाहुल्य है । यहाँ बड़े पैमाने पर कागज के 4 कारखानें (लखनऊ, सहारनपुर, रायबरेली और किच्छा, नैनीताल) हैं जहाँ बांसी कागज और स्ट्राबोर्ड अधिक मात्रा में तैयार किये जाते हैं । मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, पियराइच, इलाहाबाद आदि में छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं जहाँ मुख्यत: पेपर बोर्ड तैयार किया जाता है ।

खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग मुख्यतया मिर्जापुर जनपद में ही केन्द्रित हैं जहाँ स्थानीय चूना पत्थर पर आधारित सीमेण्ट के तीन कारखानें चुर्क, डाला तथा कजरहट स्थानों पर स्थापित किये गये हैं । सीमेंट का चौथा कारखाना मंदरासू (देहरादून) में स्थित है । सिलिका बालू पर आधारित शीशा उद्योग के कारखानें नैनी (इलाहाबाद) और रामनगर (वाराणसी), बहजोई (मुरादाबाद) ~~फिरोजाबाद~~, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, ससनी, हाथरस, इटावा, गाजियाबाद, बिजनौर आदि स्थानों पर केन्द्रित हैं । रेणुकूट (मिर्जापुर) के अल्मुनियम कारखाने के लिए बाक्साइट समीपस्थ बिहार राज्य की खानों से उपलब्ध होता है ।

अभियन्त्रण उद्योगों में कतिपय भारी औद्योगिक इकाइयाँ नैनी (इलाहाबाद)

में हैं, जैसे त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, भारत पम्प एवं कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० । ये सभी इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हैं । यहाँ निजी क्षेत्र में भी अनेक औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें जी०ई०सी० आफ इण्डिया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, जीप फ्लैश लाइट आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । गोरखपुर का रेलवे वर्कशाप और मरुआडीह (वाराणसी) का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ हैं । प्रतापगढ़ और रामनगर में टैक्टर फैक्ट्री भी स्थापित हुई हैं ।

प्रदेश के रासायनिक उद्योग की इकाइयाँ कानपुर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, झाँसी, इलाहाबाद तथा वाराणसी एवं गोरखपुर में स्थित हैं । अलकोहल, स्प्रिट तथा शराब उत्पादक अधिकांश रासायनिक इकाइयाँ शीरे के पर्याप्त उपलब्धता के कारण चीनी कारखानों के निकट स्थित हैं । शीरे का उपयोग कृत्रिम रबड़ तथा पालीथिन के लिए भी किया जाता है । देश का अधिकांश अलकोहल उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है । इसका प्रयोग मोटरों में ईंधन के रूप में किया जाता है और इसको शराब की भाँति भी उपयोग करते हैं ।

रासायनिक उर्वरक, दवायें, साबुन, प्लास्टिक पदार्थ तथा रबड़ एवं रबड़ उत्पादन तथा माचिस आदि प्रमुख रासायनिक उद्योग हैं । उत्तर प्रदेश में 6 उर्वरक कारखानें कार्यशील हैं जो गोरखपुर, बबराला, आँवला, जगदीशपुर, फूलपुर और रायबरेली में स्थित हैं । कानपुर, झाँसी, लखनऊ, सहारनपुर और इलाहाबाद में रासायनिक दवाओं से सम्बद्ध कारखाने हैं । प्रदेश में अनेक तेल कारखानों के होने पर भी वृहत् पैमाने पर साबुन उद्योग विकसित नहीं हो सका है । प्रदेश में रासायनिक उद्योगों के विकास की अभी पर्याप्त सम्भावनायें हैं ।

उत्तर प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं । हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है । इसके द्वारा चादर, परदे, धोतियाँ, साड़ियाँ, तौलिये, गमछे, बनियान आदि विविध वस्त्रों का निर्माण होता है जिसके मुख्य केन्द्र मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, मुबारकपुर, ~~एवं~~ धामपुर (बिजनौर), वाराणसी,

मऊनाथ भंजन, टाण्डा, अकबरपुर (फैजाबाद), खलीलाबाद (बस्ती), बाराबंकी, लखनऊ, आगरा, इटावा, कानपुर, गोरखपुर आदि हैं। दरी उद्योग आगरा, भदोही एवं खमरिया (वाराणसी), सम्भलपुर, इटावा, मेरठ आदि में विकसित हुए हैं। हस्त-करघा उद्योग में रेशमी वस्त्रों का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग मुख्यत: वाराणसी और उसके आस पास के क्षेत्रों में केंद्रित है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्र पर पाये जाते हैं। चमड़ा उद्योग प्रदेश का पुराना पारम्परिक उद्योग है जिसके मुख्य केन्द्र कानपुर, आगरा, अलीगढ़ और उन्नाव हैं किन्तु यह प्रदेश में घरेलू उद्योग के रूप में अनेक भागों में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत चर्मशोधन से लेकर विभिन्न चर्म सामग्री जैसे जूता-चप्पल, अटैची आदि उत्पादन तक सम्मिलित होते हैं। कुटीर उद्योग के अन्तर्गत हस्त-निर्मित कागज, दियासलाई, अगरबत्ती आदि के अति-रिक्त अनेक इंजीनियरिंग और रासायनिक उत्पादनों से सम्बद्ध उद्योग भी विकसित हुए हैं।

1.9 यातायात

उत्तर प्रदेश में रेल, सड़क, जलमार्ग एवं वायुमार्ग यातायात के प्रमुख साधन हैं। यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग बाहरी राज्यों से प्रदेश के विभिन्न भागों में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के पहुँचाने, खाद्यान्नों एवं तिलहनों को स्थानान्तरित करने, गन्ना आदि औद्योगिक पदार्थों को कारखानों तक भेजने तथा अन्य अनेक व्याव-सायिक कार्यों हेतु पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है। व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त प्रदेश में रेल, सड़क तथा वायु मार्गों द्वारा यात्रियों का आवागमन होता है।

उत्तर प्रदेश में सड़कें यातायात के प्रमुख साधन हैं किन्तु अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ सड़कों की कमी है। स्वतंत्रता के पूर्व यहाँ सड़कों की कुल लम्बाई 15000

किमी० थी । नियोजन काल में सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे वर्तमान समय में सड़कों की कुल लम्बाई बढ़कर 49,391 किमी० हो गयी है ‡1987-88‡ प्रदेश के कुल सड़कों में राष्ट्रीय, राजकीय, जनपदीय तथा ग्रामीण सड़कें सम्मिलित की गयी हैं । समस्त राष्ट्रीय मार्गों की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है जबकि अन्य सड़कें प्रदेश सरकार के अधीन होती हैं । सड़कों पर यातायात की समुचित व्यवस्था 'राजकीय सड़क परिवहन निगम' द्वारा की जाती है । पक्की सड़कों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो गाँवों को मुख्य मार्गों से सम्बद्ध करती हैं । सड़क पर चलने वाले वाहनों में ट्रकें, बसें, टैक्सियाँ, कारें, जीपें, मोटरें, टैम्पों, मोटर साइकिलें, स्कूटर, मोपेड, साइकिलें आदि प्रमुख हैं । ट्रकों का प्रयोग सामान ढोने के लिए तथा अन्य साधनों का प्रयोग यात्रियों के आवागमन हेतु किया जाता है ‡चित्र 1.6‡ ।

सघन जनसंख्या वाले समतल मैदानी भाग में जहाँ अनेक नगरों का विकास हुआ है, रेलों का जाल बिछा हुआ है । उत्तर प्रदेश में उत्तरी, उत्तरी-पूर्वी तथा मध्य रेलवे मुख्य हैं । प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र उत्तरी रेलवे के अन्तर्गत है जिसका विस्तार पूर्व में मुगलसराय से लेकर पश्चिम में गाजियाबाद तक है । उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तरी-पूर्वी रेल मार्ग का विस्तार है जिसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर है । उत्तरी-पूर्वी रेलवे लाइन उत्तरी रेलवे से मथुरा, हाथरस, कासगंज, बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, शाहगंज ‡जौनपुर‡ स्टेशनों पर मिलती है । मध्य रेलवे लाइन प्रदेश के आगरा, कानपुर तथा नैनी ‡इलाहाबाद‡ द्वारा उत्तरी रेलमार्ग से सम्बद्ध है जबकि आगरा तथा मथुरा पश्चिमी रेलमार्ग से भी जुड़े हुए हैं । उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों की कुल लम्बाई 8880.3 किमी० ‡1981 में‡ है जिसमें 5589 किमी० ब्राडगेज, 3289 किमी० मीटरगेज और 2.3 किमी० नैरोगेज है ।[9]

उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती आदि नदियाँ मैदानी भागों में नाव्य हैं । प्रदेश में लगभग 1500 किमी० तक जलमार्ग उपलब्ध है किन्तु रेलवे के विकास से जल यातयात का महत्व पहले से काफी घट गया है । गंगा नदी हरिद्वार

से कानपुर तक नौकारोहण तथा कानपुर से वाराणसी तक तथा उससे भी आगे तक स्टीमर चलाने योग्य है । कुछ बड़ी नहरें जैसे गंगानहर, शारदानहर आदि सिंचन के अतिरिक्त जल यातायात के लिए भी उपयोगी हैं ।

उत्तर प्रदेश में वायु यातायात का समुचित विकास नहीं हुआ है । राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे बमरौली (इलाहाबाद) आगरा, वाराणसी, अमौसी (लखनऊ) तथा गोरखपुर हैं जो मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे हैं । चकेरी (कानपुर) बरेली, झाँसी, हल्द्वानी, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर और ललितपुर तृतीय श्रेणी के हवाई अड्डे हैं । प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभाव है ।

1.10 शक्ति के साधन

शक्ति आधुनिक विकास की धुरी है जो विभिन्न प्रकार के ईंधनों से प्राप्त होती है जिनमें कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोलियम और जल मुख्य हैं । भविष्य में उद्योगों, परिवहन तथा अन्य कार्यों में आणविक, भूतलीय एवं सौर्य ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है ।

कोयला मिर्जापुर जिले में सिंगरौली बेसिन के कोयला क्षेत्र में सीमित मात्रा में पाया जाता है जिसका उत्खनन थोड़े संचय तथा घटिया प्रकार का होने के कारण व्यापारिक पैमाने पर नहीं होता है । इस कोयले का प्रयोग सामान्यतया ईंट भट्ठों तथा विद्युत आपूर्ति एजेंसियों द्वारा किया जाता है । उत्तर प्रदेश में खनिज तेल के संचय नहीं हैं अतः पेट्रोलियम की आवश्यकता की पूर्ति बाह्य भागों से होती है । अलकोहल को जो चीनी उद्योग के अवशिष्ट शीरे से बनाया जाता है पेट्रोलियम के साथ मिलाकर शक्ति अलकोहल प्राप्त की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में शक्ति के अन्य साधनों के अभाव में काफी समय से तापीय शक्ति का उपयोग किया जाता रहा है । प्रदेश का प्रथम विद्युतगृह 1903 में मंसूरी में स्थापित किया गया था । इसके पश्चात् कानपुर (1906), देहरादून (1915), लखनऊ (1916) और इलाहाबाद (1916) में शक्तिगृह स्थापित किये गये । 1928

में गंगानहर जल विद्युत गृह परियोजना का आरम्भ किया गया जिससे प्रदेश के पश्चिमी जनपदों को विद्युत उपलब्ध होने लगी । 1937 में फैजाबाद के निकट सोहावल शक्ति गृह तैयार हो गया था । स्वतन्त्रता प्राप्ति तक कतिपय अन्य स्थानों पर भी शक्ति गृहों का निर्माण हो गया था किन्तु अभी तक उनकी संस्थापित क्षमता बहुत कम थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 0178.54 मेगावाट थी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त (1961) तक 370.17 मेगावाट हो गयी । पिछले 20-25 वर्षों में जहाँ एक ओर अनेक नवीन तापविद्युत एवं जलविद्युत संयंत्रों की स्थापना की गयी है, वहीं पूर्ववर्ती विद्युतगृहों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गयी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त शक्ति गृहों को परस्पर सम्बद्ध करके गंगा विद्युत ग्रिड का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने में उल्लेखनीय सफलता मिली है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति मुख्यतया रिहन्द जल विद्युत योजना द्वारा होती है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में यमुना, माताटीला जलविद्युत योजना तथा रामगंगा योजना भी प्रमुख जलविद्युत योजनायें हैं ।[10] तापशक्तिगृहों में कानपुर हरदुआगंज, टाण्डा एवं ओबरा तापशक्तिगृह मुख्य हैं जिनसे प्रदेश के आन्तरिक भागों में बिजली प्राप्त होती है । इनके अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लक्सर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, टुण्डला आदि स्थानों पर डीजल विद्युत गृह भी हैं जहाँ डीजल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् की वाणिज्यिक प्रयोग हेतु उत्पादन क्षमता 4294 मेगावाट है जिनमें 2872 मेगावाट तापीय विद्युत और 1422 मेगावाट जल विद्युत है । 1985-86 में ताप विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर 34.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 1986-87 में 41.2 प्रतिशत हो गया । 1987-88 के लिए तापीय उत्पादन इकाइयों द्वारा 50 प्रतिशत का औसत प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।[11]

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति कई प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा की जाती है ।

1960 में उत्पादन गृहों से भारी शक्ति के पारेषण हेतु 220 के0वी0 पारेषण ट्रांसमिशन लाइनों का आरम्भ किया गया है। 400 के वी लाइनों का देश में सर्वप्रथम (1977) आरम्भ उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 1987 में 400 के0वी0 पारेषण लाइनों की कुल लम्बाई 1867 सर्किट किमी0 और 220 के0वी0 लाइनों की लम्बाई 5106 सर्किट कि0मी0 थी। प्रदेश में अत्यधिक भारी विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे 132 के0वी0 वोल्टेज तथा 220 के0वी0 वोल्टेज द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती है जबकि अधिसंख्यक उपभोक्ताओं को 66 के0वी0, 33 के0वी0 और 11 के0वी0 तथा एल0टी0 पारेषण लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया गया है। मार्च 1987 तक प्रदेश के 64 प्रतिशत गावों (लगभग 72 हजार) को विद्युत लाइनों से संयुक्त किया जा चुका है।[12]

1.11 जनसंख्या

1. आकार, वितरण एवं घनत्व प्रतिरूप

उत्तर प्रदेश भारत के अत्यधिक घने बसे हुए राज्यों में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का वृहतम राज्य है। जनगणना 1981 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 1108.62 लाख है जिसमें 588.19 लाख पुरुष तथा 520.43 लाख स्त्रियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 377 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है जो सम्पूर्ण भारत के जनसंख्या घनत्व (216) से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देशों तथा सम्पूर्ण आष्ट्रेलिया से कहीं अधिक है।

1901 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 486.25 लाख थी। वर्तमान शताब्दी के प्रथम एवं द्वितीय दशकों में राज्य में अकाल, महामारी, प्लेग, हैजा, इन्फ्लूएंजा आदि बीमारियों के कारण जनसंख्या की अपार हानि हुई। सन् 1901-11 और 1911-21 में जनसंख्या में क्रमशः 0.97 और 3.08 प्रतिशत का ह्रास हुआ। 1921 के पश्चात् जनसंख्या में वृद्धि होती गयी और तृतीय, चतुर्थ और पंचम दशकों में जनसंख्या

वृद्धि का प्रतिशत क्रमश: 6.66, 13.57 और 11.82 रहा । इस प्रकार स्वतन्त्र भारत की प्रथम जनगणना के समय प्रदेश की कुल जनसंख्या 632.16 लाख पहुँच गयी । नियोजन काल में मुख्यत: बीमारियों पर अंकुश लगने तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार से जनसंख्यावृद्धि दर बढ़ती गयी और तीस वर्ष में प्रदेश की जनसंख्या में 476.46 लाख की वृद्धि हो गयी (तालिका 1.2) ।

प्रदेश के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता मिलती है । यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या मध्यवर्ती समतल एवं उपजाऊ मैदानी पेटी में पायी जाती है जबकि उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय जनपदों में बहुत कम लोग निवास करते हैं । दक्षिण के पठारी भागों में मुख्य मैदानी भागों की तुलना में कम जनसंख्या पायी जाती है । जनपदों में इलाहाबाद(3797,033) सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है और सबसे कम जनसंख्या पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी (190,948) में अंकित की गयी है (चित्र 1.7)।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है । जन-संख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भारत के समस्त 22 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान केरल (654), प०बंगाल (614) और बिहार (402) के पश्चात् चौथा है । ग्रामीण क्षेत्र में यह घनत्व 313 व्यक्ति है जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए जनसंख्या का घनत्व 455 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है । जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय वितरण में अत्यधिक असमानता पायी जाती है । सामान्यतया समतल मैदानी भाग में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और दक्षिण के पठारी भाग में अल्प है जबकि उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ी जनपदों में अत्यल्प घनत्व ही मिलता है । लखनऊ (798) प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद है जिसके पश्चात् वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, और देवरिया आते हैं । जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व पर्वतीय जनपद उत्तर काशी (24) में अंकित किया गया है । अत्यल्प जनसंख्या वाले अन्य जनपद चमोली, पिथौरागढ़, टेहरीगढ़वाल और गढ़वाल हैं (चित्र 1.8) ।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं संरचना (1981)

क्र0 सं0	जनपद	कुल जनसंख्या लाख में (1981)	प्रतिशत वृद्धि (1971-81)	जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात	साक्षरता प्रतिशत	अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	जनसंख्या ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तरकाशी	1.91	29.19	24	881	28.92	22.88	93.05
2.	चमोली	3.64	24.53	40	1043	37.46	19.78	91.99
3.	टेहरी गढ़वाल	4.98	25.25	113	1088	27.89	12.78	95.87
4.	देहरादून	7.62	31.93	247	811	52.58	21.92	51.14
5.	गढ़वाल	6.38	15.34	117	1091	41.06	11.91	90.18
6.	पिथौरागढ़	4.89	55.94	55	1014	39.08	22.99	94.48
7.	अलमोड़ा	7.57	0.98	141	1081	37.76	20.84	93.72
8.	सहारनपुर	26.73	30.11	478	832	29.56	22.04	72.92
9.	नैनीताल	11.36	43.85	167	841	37.81	22.98	72.51
10.	मुजफ्फरनगर	22.74	26.20	545	843	30.10	14.81	78.28
11.	बिजनौर	19.39	30.14	400	863	26.71	20.50	75.21
12.	मेरठ	27.67	36.93	708	838	34.68	16.78	68.78
13.	गाजियाबाद	18.43	36.93	712	829	36.28	19.69	65.87
14.	बुलन्दशहर	23.58	13.74	542	864	28.97	21.44	80.66
15.	मुरादाबाद	31.49	29.66	528	843	19.82	17.10	73.05
16.	रामपुर	11.79	30.78	498	843	16.34	13.06	73.26
17.	बदायूँ	19.72	19.80	389	809	16.10	~~83.86~~ 16.85	83.86
18.	बरेली	22.73	27.71	552	830	22.04	12.49	71.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	पीलीभीत	10.08	34.06	288	846	20.44	17.13	83.78
20.	शाहजहाँपुर	16.48	28.11	360	813	21.44	17.87	80.62
21.	अलीगढ़	25.75	21.93	513	841	31.35	22.50	77.00
22.	मथुरा	15.60	20.94	409	812	30.63	19.65	78.93
23.	आगरा	28.53	23.58	594	828	33.45	22.15	61.90
24.	एटा	18.59	18.32	418	827	27.10	17.08	84.51
25.	मैनपुरी	17.26	19.42	397	828	33.30	18.39	88.92
26.	फर्रुखाबाद	19.49	25.19	456	825	32.02	17.41	83.85
27.	इटावा	17.43	20.37	403	831	37.29	25.41	85.21
28.	कानपुर	37.42	24.90	606	830	43.67	19.79	53.67
29.	फतेहपुर	15.72	23.01	379	830	25.97	23.73	91.01
30.	इलाहाबाद	37.97	29.27	523	896	27.99	24.53	79.63
31.	जालौन	9.86	21.24	216	837	35.95	27.12	80.08
32.	झाँसी	11.37	31.19	226	869	37.06	28.66	62.06
33.	ललितपुर	5.78	31.19	115	858	21.34	24.39	86.67
34.	हमीरपुर	11.94	20.84	167	856	26.31	24.56	83.39
35.	बाँदा	15.34	29.76	201	864	23.30	23.63	88.20
36.	खीरी	19.53	31.35	254	846	17.70	26.93	90.40
37.	सीतापुर	23.37	24.03	407	846	19.44	30.99	89.71
38.	हरदोई	22.75	23.00	380	827	22.19	29.93	88.94
39.	उन्नाव	18.23	22.78	400	889	25.28	30.19	88.13
40.	लखनऊ	20.15	24.52	797	847	40.33	23.86	47.40
41.	रायबरेली	18.87	24.90	409	941	23.08	29.56	92.63
42.	बहराइच	22.16	28.33	322	855	15.57	16.82	92.95

2. <u>जनसंख्या संरचना</u>

क. <u>लिंगानुपात</u>

उत्तर प्रदेश में 1981 जनगणनानुसार 588.19 लाख पुरूष और 520.43 लाख स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार लिंगानुपात 866 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरूष आता है । वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में प्रदेश में लिंगानुपात 937 था जो आगामी वर्षों में क्रमशः गिरता गया और 1971 में 879 रह गया । पिछले दशक में लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है । पाँच पर्वतीय जनपदों - गढ़वाल (1133), टेहरीगढ़वाल (1103), अल्मोड़ा (1099), पिथौरागढ़ (1055) और चमोली (1041) तथा तीन पूर्वी जनपदों, आजमगढ़ (1022), प्रतापगढ़ (1010) और जौनपुर (1010) में स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में (895) लिंगानुपात नगरीय क्षेत्रों (846) की अपेक्षा अधिक है । अधिकतम एवं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात क्रमशः गढ़वाल (1204) और बदायूं (798) जनपदों में पाया गया है । नगरीय क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक लिंगानुपात पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया (912) जनपद में और न्यूनतम लिंगानुपात पर्वतीय जनपद टेहरीगढ़वाल (555) में अंकित किया गया (तालिका 1.2)।

ख. <u>साक्षरता</u>

प्रदेश की कुल जनसंख्या में मात्र 27.16 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है । ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अनुपात और भी कम (23.06) है/नगरीय क्षेत्रों में 45.88 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है । उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता अनुपात सम्पूर्ण भारत के औसत से भी कम है क्योंकि भारत के कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में साक्षरता अनुपात क्रमशः 36.23, 29.65 और 57.40 प्रतिशत है जो उत्तर प्रदेश से अधिक है । प्रदेश में स्त्री साक्षरता तो बहुत ही कम है । यहाँ कुल स्त्री जनसंख्या का मात्र 14.00 प्रतिशत ही साक्षर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत 9.49 ही है । नगरीय क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधाओं तथा जागरूकता के कारण स्त्री साक्षरता 35.43 प्रतिशत तक पायी जाती है । इसके विपरीत पुरूष जनसंख्या

में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है । ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए पुरूष साक्षरता क्रमशः 35.18 और 54.73 प्रतिशत अंकित की गयी है ।

पिछले दशक (1971-81) में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1971 में पुरूष तथा स्त्री साक्षरता क्रमशः 31.50 और 10.55 प्रतिशत थी जो 1981 में बढ़कर क्रमशः 38.76 और 14.04 प्रतिशत हो गयी । देहरादून, कानपुर, गढ़वाल, लखनऊ,अल्मोड़ा आदि अधिक साक्षरता वाले जनपद हैं । इसके विपरीत राम-पुर, बहराइच, बदायूँ, गोण्डा, बरेली आदि जनपदों में साक्षरता दर अत्यल्प है (तालिका 1.2) ।

ग. व्यावसायिक संरचना

उत्तर प्रदेश में मुख्य कर्मियों की संख्या 323.97 लाख है जिनमें 295.90 लाख पुरूष हैं और मात्र 28.07 लाख स्त्रियाँ । इस प्रकार कुल जनसंख्या का 29.22 प्रतिशत ही मुख्य कर्मी वर्ग के अन्तर्गत आता है जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में पूर्णकालिक रूप से संलग्न है । पुरूष जनसंख्या में 50.31 प्रतिशत मुख्य कर्मी हैं जबकि स्त्रियों में यह अनुपात मात्र 5.39 प्रतिशत ही पाया जाता है । 1981 जनगणना में समस्त मुख्य कर्मियों को 4 वृहत् कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया गया है- 1. कृषक, 2. कृषि श्रमिक, 3. गृह उद्योगों में कार्यरत और 4. अन्य कर्मी । समस्त मुख्य कर्मियों में 58.52 प्रतिशत कृषक और 15.98 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं । इस प्रकार कृषि कार्यों में 74.50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है । मुख्य कर्मियों का 3.70 प्रतिशत गृह उद्योगों में और शेष 21.80 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न है । उपरोक्त चार वृहत् कार्यात्मक श्रेणियों में कुल पुरूष कर्मियों का क्रमशः 59.53, 14.16, 3.56 और 22.75 प्रतिशत लगा हुआ है और स्त्री कर्मियों में यह प्रतिशत क्रमशः 47.83, 35.23, 5.21 और 11.73 प्रतिशत है । उल्लेखनीय है कि एक-तिहाई से अधिक कार्यशील स्त्रियाँ कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड प्रदेश में महिला कृषि श्रमिकों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है जबकि पर्वतीय जनपदों में इसका प्रतिशत अत्यन्त अल्प है ।

घ. ग्रामीण-नगरीय संघटन

सन् 1971 में प्रदेश की 14.02 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय केन्द्रों में निवास करती थी। यह प्रतिशत बढ़कर 1981 में 17.95 हो गया है। इस प्रकार प्रदेश की 82.05 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उत्तर प्रदेश के कृषि-प्रधान राज्य होने के कारण तीन-चौथाई से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है और गाँवों में निवास करती है। गाँवों के आकार सामान्यतया मध्यम और वृहद् हैं जबकि बड़ी संख्या में छोटे आकार के गाँव भी पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों और दक्षिणी उच्च भूमि पर छोटे और बिखरे हुए अधिवास अधिक पाये जाते हैं। प्रदेश में नगरीकरण का स्तर सम्पूर्ण भारत (23.73 प्रतिशत) की तुलना में कम है किन्तु राज्य के वृहदाकार होने के कारण वहाँ नगरीय इकाइयों की संख्या (659) किसी भी अन्य राज्य से अधिक हैं। यहाँ एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 30 नगर पाये जाते हैं। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लखनऊ, देहरादून, कानपुर, आगरा और झाँसी जनपदों में 37 प्रतिशत से अधिक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद लखनऊ (52.60 प्रतिशत) है जिसके पश्चात् देहरादून और कानपुर जनपद आते हैं।

1.12 नगरीकरण एवं नगरीय केन्द्र

1. नगरीकरण की प्रकृति एवं प्रवृत्ति

मानव सभ्यता के प्रत्येक युग में नगरीय इकाइयाँ मानव सभ्यता एवं संस्कृति की केन्द्र रही हैं। अतः नगरीकरण को किसी प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक-सांस्कृतिक संरचना का प्रमुख सूचक समझा जाता है। 'नगरीकरण' शब्द समाज शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, नगर नियोजकों, भूगोलविदों तथा अन्य समाज-विज्ञानियों द्वारा तत्तद् विषयानुकूल विविध अर्थों एवं सन्दर्भों में प्रयुक्त होता रहा है।[13] नगरीकरण की प्रकृति एवं स्वरूप के अध्ययन में जनांकिकीय दृष्टिकोण सर्वाधिक व्यापक एवं लोकप्रिय रहा है। कुल जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या के अनुपात (नगरीय जनसंख्या/कुल जनसंख्या) का परिगणन नगरीकरण के विश्लेषण की सामान्य अवधारणा है।[14] किंग्स्ले डेविस के अनुसार, सम्पूर्ण जनसंख्या की तुलना में नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या

में आनुपातिक वृद्धि अथवा राष्ट्र की औसत जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा तीव्रगति से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को नगरीकरण का सूचक माना जाता है।[15] वास्तव में समंकों की सुलभता एवं सुगमता के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को ही नगरीकरण के सूचक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अस्तु, यहाँ उत्तर प्रदेश के नगरीय एवं नगर-तन्त्र के जनांकिकीय प्रारूप का स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जो नगरीय जनसंख्या की विविध प्रकार्यात्मक विशेषताओं के मूल्यांकन में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा।

कृषि प्रधान एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रक्रिया वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही अति मन्द रही है। तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि 1901 में प्रदेश की 11.08 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में

तालिका 1.3

उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि (1901 से 1981 तक)

वर्ष	कुल नगरीय जनसंख्या	प्रति दशक भिन्नता	प्रति दशक प्रतिशत भिन्नता	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1901	5,390,611	-	-	11.08
1911	4,906,673	- 483,938	- 8.98	11.19
1921	4,936,416	+ 29,743	+ 0.61	10.57
1931	5,568,789	+ 632, 373	+ 12.81	11.19
1941	7,016,490	+1,447,701	+ 26.00	12.41
1951	8,625,699	+1,609,209	+ 22.93	13.64
1961	9,479,895	+ 854,196	+ 9.90	12.85
1971	12,388,596	+2,908,701	+ 30.68	14.02
1981	19,899,115	+7,510,519	+ 60.62	17.95

निवास करती थी। प्रथम एवं द्वितीय दशक में प्लेग, हैजा, चेचक आदि संक्रामक बीमारियों के कारण नगरीय जनसंख्या में मृत्यु दर ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा अधिक होने के कारण नगरीकरण का स्तर 1921 में 10.57 प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात्

नगरीय जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः वृद्धि होती गयी और 1951 में यह अनुपात 13.64 प्रतिशत हो गया । नियोजन काल में नगरीय केन्द्रों की संख्या एवं पूर्ववर्ती नगरों के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप नगरीकरण को तीव्र गति प्राप्त हुई । इस प्रकार 1961 और 1971 जनगणनाओं में नगरीकरण का स्तर क्रमशः 12.85 और 14.02 प्रतिशत हो ग गया । पिछले दशक में सर्वाधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में नगरीय जन-संख्या का अनुपात 17.95 प्रतिशत तक पहुँच गया है किन्तु यह अभी देश के औसत नगरी-करण स्तर (23.73 प्रतिशत) से नीचे ही है ।

उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या 1901 में मात्र 53.91 लाख थी जो 1951 तक बढ़कर 86.25 लाख हो गयी । पिछले तीस वर्षों में प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में 112.73 लाख की वृद्धि के फलस्वरूप 1981 के कुल नगरीय जनसंख्या 198.99 लाख तक पहुँच गयी । इस प्रकार पिछले आठ दशकों में उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में 269.14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि सम्पूर्ण भारत की नगरीय जनसंख्या ने 507.80 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है । पिछले दशक (1971-81) में उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में 60.62 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । जनपदानुसार सर्वाधिक वृद्धि उन्नाव (466.37 प्रतिशत) में हुई है । अधिक वृद्धिवाले अन्य जनपद प्रतापगढ़, देवरिया, रायबरेली, बलिया, चमोली और बस्ती हैं जहाँ वृद्धि दर 125 प्रतिशत से अधिक रही है । इसके विपरीत अल्मोड़ा (21.69 प्रतिशत) न्यूनतम वृद्धि का जनपद है जिसके पश्चात् क्रमशः लखनऊ, कानपुर, आगरा, जौनपुर आदि जनपद आते हैं । उल्लेखनीय है कि प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण बड़ी संख्या में बड़े गावों का नगरों के रूप में रूपान्तरण रहा है ।

2. नगरीय अधिवासों का वर्गानुसार विश्लेषण

भारतीय जनगणना (1981) में नगरीय केन्द्रों को जनसंख्या के आधार पर छः श्रेणियों में विभक्त किया गया है -

प्रथम श्रेणी = 1,00,000 या अधिक

द्वितीय श्रेणी = 50,000 से 99,999

तृतीय श्रेणी = 20,000 से 49,999

चतुर्थ श्रेणी = 10,000 से 19,999

पंचम् श्रेणी = 5,000 से 9,999

षष्टम् श्रेणी = 5,000 से कम

तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ (1901) में उत्तर प्रदेश में कुल 458 नगरीय केन्द्र थे जिनकी संख्या आगामी जनगणनाओं में घटती-बढ़ती

<u>तालिका 1.4</u>

उत्तर प्रदेश में प्रति श्रेणी नगरों की संख्या (1901-81)

श्रेणी	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
प्रथम	7	7	7	8	12	16	17	22	30
द्वितीय	11	10	12	11	11	12	16	20	36
तृतीय	20	17	18	29	40	42	52	67	86
चतुर्थ	71	65	56	65	71	71	75	91	195
पंचम्	164	140	141	137	156	169	74	80	231
षष्ठम्	185	181	210	182	144	153	10	13	81
योग	458	420	444	432	434	463	244	293	659

प्रति नगरीय समूह (UA) को एक इकाई माना गया है।

रही। 1951 में प्रदेश में कुल 463 नगरीय इकाइयाँ थीं किन्तु जनगणना 1961 में नगर की परिभाषा कठोर कर देने के फलस्वरूप नगरों की कुल संख्या घटकर 244 ही रह गयी। जनगणना 1971 और 1981 में नगर की परिभाषा लगभग 1961 के समान ही रही और नगरों की संख्या बढ़कर 1971 में 293 और 1981 में 659 हो गयी। उल्लेखनीय है कि इस संख्या में एक नगरीय समूह (Urban Agglomeration) कोएकल

इकाई माना गया है । 1901 में प्रथम श्रेणी के केवल 7 नगर थे - कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी इलाहाबाद, मेरठ और बेरली । 1931 में मुरादाबाद के प्रथम श्रेणी में सम्मिलित हो जाने से इन नगरों की संख्या 8 हो गयी । प्रथम श्रेणी के नगर की संख्या बढ़कर 1951 में 16, 1961 में 17, 1971 में 22, और 1981 में 30 हो गयी । 1951 में द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या क्रमशः 12, 42 और 71 थी जो 1961 में क्रमशः 16, 52 और 75 हो गयी । 1961 में 'नगर' की परिभाषा कठोर कर दिये जाने से पंचम् और षष्टम् श्रेणी के नगरों की संख्या क्रमशः 169 और 153 (1951) से घटकर मात्र 74 और 10 रह गयी । 1971 जनगणना में 50 नगरीय इकाइयाँ और संयुक्त हो गयीं जिनमें 22 ऐसी थी जो 1951 जनगणना में नगरीय वर्ग में थी किन्तु 1961 में अवर्गीकृत हो गयी थीं और 28 प्रथम बार नगरीय श्रृंखला में समाहित हुई । इस प्रकार 1971 में पंचम् और षष्टम् श्रेणी के नगरों की संख्या बढ़कर क्रमशः 80 और 13 हो गयी (तालिका 1.4 एवं चित्र 1.9) ।

1981 जनगणना में पूर्ववर्ती दो नगरों - मारकुण्डी (मिर्जापुर) और रसूलपुर धुलरी (मेरठ) अवर्गीकृत कर दिया गया है जबकि एक नगरीय इकाई - कैला को गाजियाबाद (नगर पालिका परिषद्) के साथ संयुक्त कर दिया गया है । साथ ही नौ अन्य केन्द्र जो 1971 में स्वतंत्र नगर के रूप में थे नगरीय समूह के अंश बन गये हैं । पिछले दशक में प्रथम से षष्टम तक सभी नगरीय श्रेणियों में नगरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । प्रथम श्रेणी में 8, द्वितीय श्रेणी में 16, तृतीय श्रेणी में 19 चतुर्थ श्रेणी में 104, पंचम् श्रेणी में 151 और षष्टम् श्रेणी में 68 नगरीय केन्द्रों की वृद्धि हुई है । इस प्रकार 1981 में प्रथम से षष्टम श्रेणियों में नगरीय इकाइयों की संख्या क्रमशः 30, 36, 86, 195, 231 और 81 हो गयी है (चित्र 1.9 एवं 1.10) ।

नगरीय जनसंख्या के वर्गानुसार वितरण का अध्ययन प्रदेश में नगरीकरण के स्तर को इंगित करता है (तालिका 1.5) । 1901 में कुल नगरीय जनसंख्या का 23.86 प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरों में केन्द्रित था । बड़े नगरों के आकार में तीव्र वृद्धि एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के पदोन्नति से 1971 में प्रथम श्रेणी के नगरों का प्रभाग कुल नगरीय जनसंख्या के 57.06 प्रतिशत तक पहुँच गया था । पिछले दशक में इसमें 5.66

तालिका 1.5

प्रति श्रेणी में कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वितरण (1901-81)

श्रेणी	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981
प्रथम	23.86	25.16	25.36	27.49	37.36	45.21	54.43	57.06	51.40
द्वितीय	13.97	13.49	15.34	13.96	10.61	9.03	11.76	10.83	12.44
तृतीय	11.42	11.00	10,68	15.34	16.51	14.40	16.65	16.70	12.64
चतुर्थ	18.48	18.63	15.87	15.83	13.47	11.43	11.01	10.44	13.52
पंचम	20.95	19.50	19.51	16.81	15.42	11.88	5.92	4.74	8.56
षष्ठम्	11.32	12.12	13.24	10.57	6.63	6.05	0.23	0.23	1.44
योग	100	100	100	100	100	100	100	100	100

प्रतिशत का ह्रास होने से उक्त प्रभाग 51.40 प्रतिशत हो गया । तृतीय श्रेणी का प्र 16.70 प्रतिशत (1971) से घटकर 1981 में 12.64 प्रतिशत हो गया जबकि अन्य नगर वर्गों- द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम् श्रेणियों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि है जो क्रमशः 10.53, 10.44, 4.74 और 0.23 प्रतिशत (1971) से बढ़कर क्रमशः 12.44, 13.52, 8.56 और 1.44 प्रतिशत हो गयी है ।

तालिका 1.6 यह भी प्रदर्शित करती है कि पिछले आठ दशकों (1901-81) में प्रथम पाँच नगरीय श्रेणियों की जनसंख्या में क्रमशः 695.28, 228.53, 308.80, 169.93 और 49.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उसी अवधि में षष्टम् श्रेणी की जनसंख्या में 52.22 प्रतिशत का ह्रास अंकित किया गया है । इस प्रकार प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रथम से षष्टम् श्रेणियों में वितरण इस प्रकार है।प्रथम श्रेणी 102.3 लाख, द्वितीय श्रेणी 247.4 लाख, तृतीय श्रेणी 151.6 लाख, चतुर्थ श्रेणी 268.7 लाख, पंचम श्रेणी 170.4 लाख और षष्टम् श्रेणी 2.9 लाख (चित्र 1.9) ।

3. नगरीकरण का स्तर

प्रदेश में नगरीकरण का स्तर अर्थात् कुल जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या का

तालिका 1.6

उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में श्रेणी के अनुसार प्रति दशक प्रतिशत भिन्नता
(1901 से 1981 तक)

दशक	नगरीय श्रेणी					
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्टम
1901-11	- 3.63	- 12.11	- 12.29	- 7.86	- 15.41	- 2.78
1911-21	+ 1.01	+ 14.43	- 2.35	- 14.22	+ 0.39	+ 10.46
1921-31	+ 22.30	+ 4.76	+ 67.07	+ 9.73	- 3.91	- 11.66
1931-41	+ 71.21	- 4.40	+ 35.34	+ 6.18	+ 15.91	- 21.04
1941-51	+ 49.08	+ 2.74	+ 4.21	+ 8.87	+ 9.44	+ 15.21
1951-61	+ 32.03	+ 43.00	+ 27.06	+ 4.51	- 52.31	- 95.80
1961-71	+ 37.00	+ 20.37	+ 31.07	+ 23.85	+ 4.64	+ 32.14
1971-81	+ 44.68	+ 84.45	+ 21.62	+108.02	+190.00	+898.64
1901-81	+695.28	+228.53	+308.80	+169.93	+ 49.79	- 52.22

अनुपात 17.95 प्रतिशत है जो सम्पूर्ण देश के नगरीकरण स्तर (23.73 प्रतिशत) से 5.78 प्रतिशत कम है। पिछले दो दशकों में प्रदेश में नगरीकरण के स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। 1961 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 12.85 से बढ़कर 1971 में 14.02 और 1981 में 17.95 तक पहुँच गया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में नगरीकरण के स्तर में पर्याप्त विषमता पायी जाती है। जहाँ पश्चिमी एवं मध्यवर्ती जनपदों में नगरीकरण अधिक हुआ है वहीं पर्वतीय एवं पूर्वी जनपदों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत काफी कम है। लखनऊ प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत (52.60 प्रतिशत) जनपद है जबकि सुल्तानपुर जनपद में नगरीय जनसंख्या का स्तर (3.30 प्रतिशत) न्यूनतम है। अतः 1981 जनगणना के अनुसार समस्त 56 जनपदों को नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्नांकित पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है (चित्र 1.11)

1. अत्यल्प नगरीकृत क्षेत्र (10 प्रतिशत से कम),
2. अल्प नगरीकृत क्षेत्र (10 से 20 प्रतिशत),
3. सामान्य नगरीकृत क्षेत्र (20 - 30 प्रतिशत),

4. अधिक नगरीकृत क्षेत्र (30-40 प्रतिशत), और

5. अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्र (40 प्रतिशत तथा इससे ऊपर)

प्रदेश के कुल 38 जनपदों में नगरीकरण का स्तर अल्प (19 जनपद) और अत्यल्प (19 जनपद) है जहाँ नगरीय जनसंख्या का अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम है। सुल्तानपुर की स्थिति निम्नतम सोपान (3.30 प्रतिशत) पर है जिसके ऊपर टेहरी-गढ़वाल, बस्ती, प्रतापगढ़, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देवरिया, जौनपुर, उत्तरकाशी आदि हैं। 11 जनपद सामान्य नगरीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं : इलाहाबाद, मथुरा, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, रामपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, नैनीताल और बेरेली। 4 जनपदों - मेरठ, गाजियाबाद, झाँसी और आगरा में नगरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत उच्च है (30 प्रतिशत से अधिक)। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत (40 प्रतिशत से अधिक) जनपद लखनऊ (52.60 प्रतिशत), देहरादून (48.85 प्रतिशत) और कानपुर (46.32 प्रतिशत) हैं।

4. नगरीय घनत्व

नगरीय घनत्व प्रति वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में नगरीय जनसंख्या का सूचक है। प्रदेश के विभिन्न भागों में नगरीय घनत्व में अत्यधिक विषमता भी मिलती है। जहाँ एक ओर लखनऊ जनपद में नगरीय घनत्व 419 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 (उच्चतम) है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय जनपद उत्तरकाशी में यह मात्र 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 ही है। नगरीय घनत्व के आधार पर प्रदेश के समस्त 56 जनपदों (वर्ष 1981) को निम्नांकित पाँच वर्गों में रखा जा सकता है (चित्र 1.12) -

1. अत्यल्प नगरीय घनत्व वाले क्षेत्र (25 व्यक्ति/किमी0^2 से कम)
2. अल्प नगरीय घनत्व वाले क्षेत्र (25-49 व्यक्ति/किमी0^2)
3. मध्यम नगरीय घनत्व वाले क्षेत्र (50-99 व्यक्ति/किमी0^2)
4. उच्च नगरीय घनत्व वाले क्षेत्र (100-199 व्यक्ति/किमी0^2)
5. अत्युच्च नगरीय घनत्व वाले क्षेत्र (200 और अधिक व्यक्ति/किमी0^2)

उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में नगरीय घनत्व अत्यल्प अर्थात् <25 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 से भी कम हैं। इसमें से छः-उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टेहरी-गढ़वाल, अलमोड़ा और गढ़वाल उत्तरी-पश्चिमी पर्वतीय भाग में, पाँच-सुल्तानपुर, बहराइच, बस्ती, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर पूर्वी भाग में, दो - ललितपुर और बाँदा बुन्देलखण्ड में और खीरी मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं। कुल 16 जनपद अल्प घनत्व वाले

<u>तालिका 1.7</u>

नगरों की संख्या, नगरीय जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व का प्रति श्रेणी वितरण (1981)

नगरीय श्रेणी	नगरों के कुल संख्या का प्रतिशत	कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	कुल नगरीय क्षेत्रफल का प्रतिशत	जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी	प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि (1971-81)
प्रथम	4.55	51.40	34.11	6575	44.68
द्वितीय	4.46	12.44	10.32	5257	84.45
तृतीय	13.05	12.64	11.51	4796	21.62
चतुर्थ	29.59	13.52	20.99	2810	108.02
पंचम्	35.06	8.56	16.58	2254	190.00
षष्टम्	12.29	1.44	6.49	971	898.65
योग	100	100	100	4364	60.62

वर्ग में समाहित हैं। इस प्रकार प्रदेश के 30 जनपदों में नगरीय घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 से कम है। अन्य 11 जनपद मध्यम नगरीय घनत्व वाले वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं जहाँ नगरीय घनत्व 50 और 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 के मध्य पाया जाता है। वाराणसी (195), मुरादाबाद (142), सहारनपुर (129), रामपुर (133), देहरादून (127), अलीगढ़ (118), मुजफ्फरनगर (118), इलाहाबाद (107), और बुलन्दशहर (105) उच्च नगरीय घनत्व वाले जनपद हैं। अत्युच्च नगरीय घनत्व उन जनपदों में अंकित किया गया है जिनमें बड़े नगरीय केन्द्र स्थित हैं जैसे लखनऊ(419), कानपुर (281), गाजियाबाद (244), आगरा (226) और मेरठ (221)।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रक्रिया

संतोषजनक है। प्रकाश राव ने भारतीय नगरीकरण की तीन भिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है[16]: 1. महा नगरीकरण, 2. वाणिज्यीकरण या मध्यवर्त्ती नगरीकरण, और 3. ग्राम्य नगरीकरण या निर्वाहमूलक नगरीकरण। ये प्रक्रियायें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी पूर्णतया लागू होती हैं। महानगरीकरण के अन्तर्गत ग्रामीण और मध्यम तथा लघु नगरों से बड़ी संख्या में जनसंख्या का प्रवास बड़े नगरीय केन्द्रों की ओर हो रहा है जिससे बड़े नगर महानगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं जैसे कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद आदि। मध्यवर्ती नगरीकरण द्वारा लघु आकारीय नगरीय इकाइयाँ मध्यम और वृहद् नगरों में बदल रही है। तृतीय प्रक्रिया अर्थात् ग्राम्य नगरीकरण द्वारा नये नगरों का उद्भव हो रहा है, चाहे वह गाँवों की भौतिक वृद्धि का परिणाम हो अथवा प्रशासनिक या राजनीतिक निर्णय का। उल्लेखनीय है कि पिछले दशक (1971-81) में नगरीकरण की तृतीय प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है।

संदर्भ

1. Census of India 1981, Series - 22, Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.
2. Planning Atlas of Uttar Pradesh, Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad, 1987.
3. Wealth of India, C.S.I.R., Vol. 2.
4. वही.
5. संदर्भ 2.
6. उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़े, लखनऊ, 1984.
7. उत्तर प्रदेश में विकास का नया दौर, बहुमुखी प्रगति, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1987.
8. सन्दर्भ 2.
9. वही

10. मौर्य, साहबदीन, "उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका," ग्रामीण विकास - संकल्पना, उपागम एवं मूल्यांकन (सम्पादक - प्रमोद सिंह एवं अमिताभ तिवारी), पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ 213.

11. अमृत प्रभात दैनिक, इलाहाबाद, 24 अगस्त 1987.

12. देखें सन्दर्भ 10, पृष्ठ 214.

13. सिंह, रामनगीना एवं साहबदीन : "पूर्वी उत्तर प्रदेश में नगरीकरण", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 14, संख्या 2, 1978, पृष्ठ 83.

14. Bose, A. : Urbanization in India - An Enventory of Source Materials, Academic Books, Bombay, 1970.

15. Davis, Kingsley : "Urbanization in India - Past and Future", in Roy, Turner (ed.), India's Urban Future, Oxford University Press, Bombay, 1962, p. 1.

16. Prakasha Rao, V.L.S. : "The Process of Urbanization", Fulbright Newsletter, March 1973, New Delhi, pp. 10-14.

——————::o::——————

अध्याय दो

व्यवसाय : संकल्पना एवं निर्धारक तत्व

2.1 अर्थ एवं परिभाषा

व्यवसाय की संकल्पना एक गत्यात्मक विचार है जो कालान्तर में परिवर्तित होता रहता है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में व्यवसाय की अवधारणा में उल्लेखनीय अन्तर मिलता है। आधुनिक समाज में इसके अभिलक्षण, श्रम-विभाजन, कार्यों के विशिष्टीकरण, परिवर्तन की नवीन विधियों तथा प्रचलित विचारधारा के प्रभाव से युक्त अधिकांश जनों का अपनी जीविका की प्राप्ति तथा एक निश्चित सामाजिक स्तर को कायम रखने हेतु एक विशिष्ट और अपेक्षाकृत सतत् (अविराम) क्रिया में संलग्न होना है। सामाजिक विज्ञानों के साहित्य में यह क्रिया 'व्यवसाय' के रूप में अभिहीत की गयी है। व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा बहुत निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित है। सभी आधुनिक भाषाओं में इसके अनेक पर्यायवाची हैं और उनके अर्थ की भिन्नता यह प्रदर्शित करती है कि इस शब्दावली की विशिष्ट विषय वस्तु ऐतिहासिक युगों से किस प्रकार परिवर्तित होती रही है।[1]

'व्यवसाय' शब्दावली का प्रयोग सामान्यतया तीन विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में किया जाता है - 1. प्रौद्योगिकीय तथ्य जिसके अन्तर्गत व्यवसाय के क्रियान्वयन में सम्मिलित विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक कार्य सम्मिलित हैं। 2. आर्थिक तथ्य जिसके अन्तर्गत एक व्यवसाय से प्राप्त आय को समाहित किया जाता है जो जीविका प्रदान करती है। 3. सामाजिक तथ्य जो व्यवसाय के आधार पर एक व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है। शब्दावली के इन त्रपक्षीय सम्मिश्र के परिणामस्वरूप विभिन्न ऐतिहासिक दशाओं में व्यवसाय के अर्थ एवं परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है।।

आधुनिक समाज में व्यवसाय के सामाजिक और आर्थिक पक्ष अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार "बाजार मूल्य युक्त यह विशिष्ट क्रिया जिसे एक व्यक्ति आय के स्थायी प्रवाह की प्राप्ति के उद्देश्य से सतत् रूप से धारण करता है और जो बदले में व्यक्ति

के सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, व्यवसाय कहलाती है ।[2] इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठ रूप से व्यवसाय का तात्पर्य है एक विशिष्ट क्रिया जिससे व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करता है जबकि वस्तुनिष्ठ रूप से इसका अर्थ है क्रिया के विविध क्षेत्र जिसमें आधुनिक समाज विभाजित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीविका के साधनों और उसके सामाजिक स्तर में घनिष्ट सम्बन्ध है ।

व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है जिसमें एक समाज से दूसरे समाज और एक ही समाज में विभिन्न कालों में उल्लेखनीय विभिन्नता पायी जाती है । स्तर सामाजिक स्थिति है जो उसके व्यक्तिगत गुणों से पृथक सम्मान, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है ।[3]

आधुनिक समाज में भी कतिपय व्यवसायों को उच्च स्तर, प्रतिष्ठा और सामाजिक मूल्य प्राप्त हैं जिसके लिए सम्भवतः भूतकालीन परम्परागत शक्तियाँ ही उत्तरदायी हैं । यद्यपि व्यक्ति की आय सामाजिक स्तर के निर्धारण का एक प्रमुख कारक है किन्तु अनेक अन्य सामाजिक कारकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है । वे कार्य जो समाज को विशिष्टीकृत एवं व्यक्तिगत सेवायें प्रदान करते हैं, सामान्यतया श्रेष्ठ व्यवसाय समझे जाते हैं । "सम्भवतः पुरातन तथा प्राचीनतम विशिष्ट व्यवसाय सर्वत्र आध्यात्मिक वृत्ति को समझा जाता रहा है जिसके पश्चात् जादूगरों, भविष्य वक्ताओं, पैगम्बरों, वैद्यों, गायकों का स्थान है ।"[4]

ये वृत्तिक सेवायें विशुद्धरूप से व्यक्तिगत प्रकृति की हैं जो मानव आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करती हैं जिसके प्रतिफलस्वरूप कुछ धन या वस्तु प्राप्त हो जाती है । ये क्रियायें आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवसाय से भिन्न समझी जाती हैं । वर्तमान काल में 'व्यवसाय' का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है । अतः व्यवसाय का सामान्य अर्थ व्यक्ति या समूह द्वारा अपनायी गयी उस क्रिया से है जिसके द्वारा आर्थिक आय प्राप्त होती है । अनार्थिक क्रियाओं को व्यवसाय नहीं माना जाता है क्योंकि उनसे जीविका नहीं प्राप्त होती है ।

2.2 व्यवसाय का ऐतिहासिक विकास

व्यवसाय मानव समाज का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है, अत: इसके ऐतिहासिक विकास को विस्तृत सन्दर्भ में सामाजिक इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। मानव सभ्यता के आरम्भ से लेकर मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन विविध रूपों में करता रहा है क्योंकि मानव जीवन की निश्चित आवश्यकतायें इतनी सार्वभौमिक एवं समतापूर्ण हैं कि उनकी पूर्ण पूर्ति अवश्य होनी चाहिए और वे अधूरे अथवा अर्द्ध संतुष्टि को स्वीकार नहीं करती हैं।[5]

मानव सभ्यता के पूर्ववर्ती दिनों में आदिम मनुष्य की आवश्यकतायें अत्यन्त सीमित थीं और वह उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करता था जिसको वह स्वयं उत्पन्न करता था। उसके उत्पादन की वस्तुएँ उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुकूल होती थी। उस काल में राज्य या किसी प्रशासनिक संस्था के अभाव में व्यावसायिक जटिलता नहीं थी। पुरापाषाण काल में मानव के मुख्य व्यवसाय थे पशुओं का आखेट, मत्स्य पकड़ना और प्रकृतिप्रदत्त फलों तथा कन्दमूलों को एकत्रित करना। इसके पश्चात् मनुष्य ने पशुपालन आरम्भ किया। सम्भवत: नवपाषाणकाल के अन्त तक कृषि प्रमुख व्यवसायों में से एक थी और कुम्हार, बढ़ई, बुनकर तथा शिल्पकार आदि की कलाओं का भी ज्ञान हो चुका था।

प्राचीन काल में आर्य समाज चार वर्णों अथवा समूहों में विभक्त था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का व्यवसाय पुरोहित वृत्ति होता था और क्षत्रिय प्रशासनिक तथा प्रतिरक्षा कर्तव्यों का पालन करता था जबकि बाद में दोनों वर्गों के व्यवसाय इतने सुस्पष्ट नहीं रह गये क्योंकि उनकी क्रियायें कुछ सीमा तक एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। कृषि और व्यापार वैश्यों का मुख्य व्यवसाय था जबकि शूद्र प्रथम तीन वर्गों की आवश्यक सेवाओं के लिए होते थे।

आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि उत्तर वैदिक काल की आर्य सभ्यता भौतिक रूप से ऋग्वेद काल की तुलना में अधिक विकसित थी। आदि आर्य लघु साम्राज्यों में संगठित थे जो सम्भवत: आदिम प्रकृति के थे। आर्यों ने पशुचारण और कृषि

की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें पशुओं को मुद्रा के रूप में माना जाता था और बाजार मूल्यों का मापन उन्हीं द्वारा किया जाता था । इस संदर्भ में अपने विविध तथा बहुमूल्य उपयोगों के कारण गाय को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था ।

"आर्यों का आर्थिक-तंत्र अधिक विकसित नहीं था क्योंकि वे अपने इकाई मूल्य और विनिमय साधन के लिए दुर्वह गाय पर निर्भर थे । मुद्रा के रूप में निष्क नामक स्वर्ण सिक्के के प्रयोग का उल्लेख मिलता है जो सम्भवत: कतिपय प्रकार के स्वर्णाभूषणों के रूप में प्रयुक्त होते थे ।"[6] उत्तर वैदिक काल में लोग विशिष्टीकृत व्यापार और कलाओं से भी परिचित थे ।

भारतीय जातिक्रम की ही भाँति यूरोपीय समाज में भी सामाजिक वर्ग पाये जाते थे । यूरोपीय इतिहास के तथाकथित चार "स्टेट" जिन्हें अठारहवीं शताब्दी में मान्यता प्राप्त थी, भारत के चार प्रधान जातियों के ही तुल्य थे । ऐतिहासिक अभिलेखों से विदित है कि आधुनिक समाज के विकास के पूर्व इसकी संरचना व्यावसायिक की अपेक्षा मुख्यतया निगमित थी । निगमित समाज बन्द, स्थैतिक तथा संरक्षणात्मक प्रकार के समुदाय पर आधारित था जिसका अन्तिम स्वरूप जाति व्यवस्था थी जबकि व्यावसायिक समाज एक स्वतन्त्र तथा प्रगतिशील प्रकार का समाज है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अपने निजी पसन्द के व्यवसाय को अपनाता है । यहाँ तक कि आधुनिक समाज में चिकित्सक, वकील, अध्येता, सैनिक तथा अन्य दयालु तथा बौद्धिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों द्वारा वर्ग जागरूकता का विकास हुआ है जिससे उनका निगमित स्वरूप सम्मुख आया है ।

उद्योग और वाणिज्य दो पुर्जे हैं जो आर्थिक विकास हेतु साथ-साथ कार्य करते हैं और व्यवसायों की जटिलता में वृद्धि करते हैं । इस प्रकार उद्योग में व्यावसायों की जटिलता में वृद्धि समाज के आर्थिक विकास से बहुत अधिक सह-सम्बन्धित है । आधुनिक औद्योगीकरण की जटिलता के कारण अनेक व्यवसाय और सेवायें समाज में उद्भूत होती हैं जो उद्योग और वाणिज्य से सम्बद्ध असंख्य क्रियाओं को समाहित करती हैं ।

प्राचीन और मध्यकाल में सभ्यता की उन्नति के साथ-साथ गावों, नगरों तथा महानगरों का विकास सम्भव हुआ । नगरीय जीवन के विकास के साथ-साथ जन आवश्यकताओं में विस्तार हुआ जिसके फलस्वरूप अनेक समिश्र आर्थिक क्रियायें उत्पन्न हुईं जिससे व्यक्तियों द्वारा इन विविध क्रियाओं का संचालन किया जाने लगा । मनुष्य ने किसी एक कार्य में जिसके लिए वह सर्वाधिक सक्षम होता था विशिष्टीकरण प्राप्त करना आरम्भ किया । इस प्रकार 'श्रम-विभाजन' का उदय हुआ । विशिष्टीकृत श्रम के कारण अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ । वैदिक काल में आर्य समाज में प्रचलित वस्तु विनिमय की प्रथा हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसी न किसी रूप में पायी जाती है । विकसित वस्तु विनिमय अर्थतंत्र के कारण शिल्प कला का भी विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय वंशानुगत होता गया ।

वर्तमान काल में प्रदेश एवं देश के विभिन्न भागों में क्रियाओं के तीन प्रमुख समूह पाये जाते हैं - प्रथम हस्तकला हैं जो शिल्पकारी से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और जो 15वीं शताब्दी तक सार्वभौमिक रूप से प्रचलित थी । द्वितीय पारिवारिक या घरेलू प्रकार की है जिसने औद्योगिक पूँजीवाद को जन्म दिया और 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में प्रचलित थी । तृतीय कारखाना प्रकार की थी जो प्रथमतः 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैण्ड में उल्लेखनीय पैमाने पर उत्पन्न हुई और 19वीं शताब्दी के द्वितीय-चतुर्थ में फ्रांस में और उसके उपरान्त सम्पूर्ण संसार में प्रभावशाली रही ।[7]

2.3 श्रम-विभाजन

यद्यपि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आरम्भ तभी हो चुका था जब आर्य समाज की आदिम संरचना कतिपय कार्य-वर्ग में विभक्त थी किन्तु इसे एक ठोस स्वरूप पाने में सफलता तथाकथित 'मजदूरी कार्य' के उद्भव के साथ ही प्राप्त हो सकी । मजदूरी कार्य अवस्था में मजदूर के पास औजार होते थे और उपभोक्ता कच्चे माल उपलब्ध कराते थे । मजदूर पारिश्रमिक हेतु अपने कौशल से किसी की भी सेवा करने के लिए तत्पर होता था । निश्चित सार्वजनिक क्रियाओं के संपादन से उसे सार्वजनिक प्रतिष्ठा उपलब्ध थी । इस काल के हस्त कलाकार को भी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी । गावों में

स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं ।

वस्तुविनिमय प्रणाली के उपरान्त मौद्रिक प्रणाली का विकास हुआ जिसके द्वारा ~~प्रस्तुत सामग्री~~ नगरों ने उल्लेखनीय प्रगति की । उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर कार्य का स्थान शिल्पी संगठन ने ले लिया जिसमें एक शिल्पकार या श्रमिक केवल औजार ही नहीं बल्कि कच्ची सामग्री और कुछ मामलों में कार्यशाला की भी व्यवस्था करने लगा।

उसके उपरान्त शिल्पकार पृथक और सार्वजनिक निगमों के रूप में संगठित होकर अपने सदस्यों के आर्थिक रुचियों को आगे बढ़ाया और ~~जिन्होंने~~ उसने मध्यम कीमत पर इच्छित गुणों वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली । इस प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता थी श्रमिकों द्वारा संगठन का निर्माण । इस प्रकार शिल्पी वर्ग समान व्यवसाय वाले दस्तकारों का संगठन होता था जैसे बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार, बुनकर, कुम्हार आदि के संगठन । इस वर्ग पद्धति से उच्चतर तकनीकी कुशलता का विकास सम्भव हुआ जिससे श्रमिक के जीवन-स्तर और शिल्पनीति के नियत मापदण्ड में सुधार हुआ । औद्योगिक उत्पादनों में विविधता के साथ ही परिमाणात्मक विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप विनिमय प्रक्रिया कतिपय चरणों में विभक्त हो गयी । एक ही भवन में स्वतंत्र औद्योगिक शाखायें कार्यशील होने लगीं । औद्योगिक प्रक्रिया के इस विभाजन से विशिष्टीकृत अर्थ-व्यवस्थाओं में पारस्परिक विनिमय का होना अत्यन्त आवश्यक हो गया । इसके साथ ही उच्च लाभ की तुलना में उत्पादक वस्तुओं के परम्परागत स्तर को कायम रखना भी परमावश्यक था ।

पूँजीवाद के विकास के साथ ही उद्योगों के पंजीकरण और वाणिज्यीकरण का उद्-भव हुआ जिसके परिणामत: व्यवसायों का पुन: श्रेणीकरण हुआ और नवीन व्यावसायिक पदानुक्रमों का अभ्युदय हुआ । हस्तकला पद्धति में श्रम-विभाजन की प्राप्ति से स्वतन्त्र आर्थिक इकाइयों का सृजन होने लगा । संविदा पद्धति से एक नवीन औद्योगिक संगठन की उत्पत्ति हुई जिसके परिणामस्वरूप 'मजदूरी कार्य' के स्थायी वर्ग का उद्भव हुआ । औद्यो-गिक समाज दो विरोधी वर्गों- पूँजीपति उद्यमी और सर्वहारा वर्ग में विभक्त हो गया ।

इस प्रकार प्राचीन व्यावसायिक निगम का सामाजिक कार्य राज्य के अधीन हो गया। इस प्रकार उत्पादक और उसके बाजार के मध्य थोक व्यापारी आ गया जिसके कारण उत्पादक की आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी और वितरण प्रक्रिया में इस परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य साधारण सम्पर्क या संविदा हेतु पृथक व्यावसायिक संगठनों के साथ कार्यात्मक रूप से सम्बन्धित सेवाओं की श्रृंखलायें बन गयीं। इस पद्धति में व्यापारी शिल्पकार न होते हुए भी एक नवीन प्रकार का नियोक्ता बन गया।

वाणिज्यीकरण के परिणामस्वरूप औद्योगिक पंजीकरण की अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अन्तर्गत उत्पादन कार्य नियंत्रक स्वामी द्वारा संचालित होने लगा जो श्रमिकों को किराये पर नियोजित करता था। इसके परिणामस्वरूप शिल्पकारों के न केवल अपनी स्वतंत्रता और स्वामित्व का ही समापन हुआ बल्कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयुक्त कच्चे माल तथा यंत्रों के ऊपर से भी उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। इस प्रकार वे मात्र भाड़े के मजदूर ही रह गये जो व्यक्तिगत रूप से या उद्यमियों द्वारा उपलब्ध कराये गये यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग करते थे। उस औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से आधुनिक पूँजीवाद का उदय हुआ।

औद्योगिक क्रान्ति से मिल मजदूर दो वर्गों में विभक्त हो गया - कुशल और अकुशल मजदूर। इस प्रकार कारखाना पद्धति ने कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रम के स्वामी वर्ग का सृजन किया। इसके समान ही हस्तकला पद्धति में भी श्रमिकों का पदानुक्रम था - स्वामी, कारीगर और शिशु। उल्लेखनीय है कि कारखाना मजदूरों का कभी भी उत्पादन के सम्पूर्ण चरणों (प्रक्रमों) यहाँ तक कि उद्योग के अतिविशिष्टीकृत शाखा में भी स्वामित्व नहीं रह गया। वे उच्च औद्योगिक अधिकारियों जो तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में विशिष्टीकृत होते हैं की सहायता से तथा उनके निर्देशन में कार्य करने लगे।

2.4 व्यवसाय के निर्धारक तत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म और विकास जिस समाज में हुआ

है उसकी उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति तथा आकार के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का भी योगदान होता है । जीविका प्राप्ति हेतु किये गये मानवीय प्रयत्नों पर पर्यावरणी अवसरों तथा सभ्यता की अवस्था का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं के चयन पर सीमायें आरोपित करते हैं । सभ्यता के आरम्भिक अवस्था में मानवीय आवश्यकतायें बहुत साधारण और सीमित थीं जिसके फलस्वरूप व्यवसायों का क्षेत्र भी सीमित था । आर्थिक विकास में उन्नयन के साथ-साथ मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने विविध पर्यावरणी कारकों के सम्मिश्र संयोगों द्वारा व्यवसायों को बहुगुणित कर दिया ।

प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के व्यवसाय-चयन में प्राथमिक कारक हो सकता है जो जीविका चयन हेतु सीमायें निर्धारित करता है । किन्तु आधुनिक समाज में मनुष्य केवल प्राकृतिक वातावरण के निश्चित तत्वों पर ही आधारित नहीं है बल्कि वह वातावरण का अति सक्षम एवं सक्रिय कारक है जो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर लेता है । इस प्रकार मनुष्य के जीविका निर्धारण में प्राकृतिक वातावरण के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैयक्तिक पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है । इस प्रकार मनुष्य के व्यवसाय या जीविका को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारकों को चार प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है[8] :-

1. भौतिक-जैविक पर्यावरण 2. सामाजिक पर्यावरण, 3. सांस्कृतिक पर्यावरण और 4. वैयक्तिक पर्यावरण ।

1. <u>भौतिक-जैविक पर्यावरण</u>

मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएँ भौतिक-जैविक पर्यावरण के तत्वों द्वारा नियंत्रित अथवा प्रभावित होती है ।[9] मनुष्य के व्यवसाय की प्रकृति एवं स्वरूप के निर्धारण में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । भौतिक - जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत विविध प्रकार के जैविक तथा अजैविक प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे स्थानिक सम्बन्ध, भूविन्यास, अपवाह, जलवायु, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति और पशु-जीवन आदि ।

क. स्थानिक सम्बन्ध

किसी प्रदेश में मानव वर्ग के आवास, अर्थव्यवस्था तथा समाज की संरचना में स्थानिक कारकों का प्रभावी भूमिका होती है । विभिन्न प्रकार की अवस्थितियाँ - खगोलीय, सापेक्ष, प्रादेशिक तथा प्राकृतिक (आकार एवं आकृति सहित स्थलीय तथा सागर के संदर्भ में) वहाँ निवास करने वाले लोगों की क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रकार को निर्धारित करती हैं । किसी प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और तज्जनित मानव क्रियायें, ज्यामितीय स्थिति तथा प्राकृतिक स्थिति से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित होती हैं । एक सुगम्य प्रदेश में अल्प गम्य प्रदेश की तुलना में मानवीय क्रियाओं की विविधता अधिक पायी जाती है । इसी प्रकार एक वृहदाकार प्रदेश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित विविध आर्थिक क्रियाओं द्वारा सुगमतापूर्वक आत्म-निर्भर बन सकता है जबकि अत्यन्त लघु आकार का प्रदेश कठिनाई से जीवन-क्षम हो सकता है और इसी कारण वह जनता के आर्थिक विकास में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में असमर्थ होता है ।

स्थानिक कारकों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की स्थिति आदर्श है । यह देश के वृहद् उत्तरी मैदान के मध्य में स्थित है जो नदियों, रेल तथा सड़कों द्वारा पूर्णतः अभिगम्य है । प्रदेश के बड़े नगर अधिकांशतः नदी तटों और रेल एवं सड़क मार्गों पर स्थित हैं और परिवहन मार्गों द्वारा देश के प्रत्येक भाग से सम्बद्ध हैं ।

ख. स्थलाकृति

किसी क्षेत्र की स्थलाकृति उसके उच्चावचन और संविन्यास पर आधारित होती है । धरातलीय संविन्यास के दो मुख्य तत्त्व ढाल और निरपेक्ष उच्चावचन होते हैं । स्थल रूप केवल मानव बसाव को ही नहीं बल्कि उसकी जीविका तथा आर्थिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है । समतल मैदानी भागों में मानव जीवन की समस्त आवश्यक सुविधायें - उर्वर भूमि, सिंचाई, परिवहन और औद्योगिक संसाधन प्रायः सुगमता से उपलब्ध होती हैं । अतः मैदान मानव-निवास तथा अधिवासों के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त

क्षेत्र होते हैं । नहरों, सड़कों, रेलमार्गों का निर्माण मैदानी भागों में सुगमता पूर्वक तथा अपेक्षाकृत कम लागत से हो जाता है । परिवहन और संचार सुविधाओं के अभाव में किसी प्रदेश में वृहत् उद्योगों की स्थापना तथा उनका विकास सम्भव नहीं है । अंततः प्रदेश की जनसंख्या के आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण वहाँ के स्थल रूपों पर आधारित होता है । यहाँ तक कि शक्ति तथा वस्तुगत सुविधायें भी मैदानी भागों में पर्वतीय एवं ऊँचे-नीचे भागों की तुलना में अल्प व्यय और प्रयत्न से ही उपलब्ध करायी जा सकती हैं ।

उत्तर प्रदेश के आठ उत्तरी-पश्चिमी जनपद हिमालय के पर्वतीय अंश हैं तथा दक्षिण-पूर्व में मिर्जापुर जनपद के दक्षिणी खण्ड में भी विन्ध्य श्रेणी की पहाड़ियाँ मिलती हैं । प्रदेश की अधिकांश भूमि समतल एवं मैदानी है जो कृषि, परिवहन, व्यापार तथा अन्य सामान्य आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है । पर्वतीय भागों में कृषि योग्य भूमि की अल्पता तथा परिवहन साधनों की अपर्याप्तता के कारण उपरोक्त मैदानी आर्थिक क्रियायें विकसित नहीं हो पातीं । खनिज पदार्थों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप मिर्जापुर की उच्च भूमि पर उत्खनन तथा विनिर्माण की नवीन क्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ है ।

ग. अपवाह, धरातली एवं अन्तर्भौम जल

मानव जीवन के अस्तित्व के लिए वायु और जल अति महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं । नदियों, झीलों, तालाबों, तथा जलाशयों के रूप में धरातली जल मानव जीवन और उसकी जीविका को अत्यधिक प्रभावित करता है । प्राचीन काल में अधिकांश मानवीय बस्तियाँ नदी घाटियों और झील तटों पर बसी थीं जहाँ जलपूर्ति की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध होती थीं । मानव-सभ्यता के विकास एवं विस्तार के साथ साथ बस्तियाँ जल स्रोतों से दूर भी बसने लगीं । ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार अधिकांश वृहत् विश्व सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास नदी घाटियों से सम्भव हुआ था जैसे वीहो घाटी (चीन), दजला एवं फरात घाटी (मेसोपोटामिया), नील घाटी (मिश्र) और सिन्धु घाटी (भारत) आदि । आधुनिक काल में भी अधिकांश वृहद् नगर नदियों के तटों अथवा नदी संगम पर बसे हुए हैं ।

कृषि में सिंचाई तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल की महती आवश्यकता होती है। जल का अधिक उपयोग करने वाले उद्योग जैसे लौह-इस्पात, कागज, वस्त्र रंगाई और तैयारी संयंत्र आदि अधिकांशत: जल स्रोतों के निकट ही स्थित होते हैं। नदियाँ और जलाशय जलविद्युत उत्पादन मे सहायक होते हैं जिससे समीपवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं विशेषरूप से उद्योगों के विकास तथा विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नदियाँ और झीलों से निकाली गयीं नहरें मैदानी भागों मे सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई मुख्यतया नहरों और नलकूपों एवं साधारण कूपों द्वारा की जाती है जबकि तालाबों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेतु जल परिवहन सर्वाधिक मितव्ययी है जिसका उपयोग प्रदेश की बड़ी नदियों में ही हो पाता है।

अन्य कारकों के समान ही अन्तर्भौम जल भी मानव बसाव और व्यवसायों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक है। भूतल के नीचे अप्रवेश्य शैलों पर संचित भूगर्भवर्त्ती जलकूप की खुदाई करके या नलकूप लगाकर धरातल पर लाया जाता है जिसका उपयोग घरेलू, सिंचाई तथा विभिन्न औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। जहाँ अन्तर्भौम जल सुगमता से या अल्प कठिनाई से प्राप्त हो जाता है, धरातली जल के अभाव में भी उर्वर भूमि होने पर कृषि का विकास सम्भव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में घरेलू, कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में कूप तथा नलकूप दोनों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

घ. ऋतु और जलवायु

ऋतु अल्पकालीन वायुमण्डलीय दशा है जबकि ऋतु दशाओं, स्थिर अन्तरों और मौसमों के परिवर्तन के सम्मिलित योग को जलवायु कहा जाता है। जलवायु भौतिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है जो मानवीय क्रियाओं के साथ ही मनुष्य के भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, आश्रम (मकान एवं बस्तियाँ), कृषि के स्वरूप और उत्पादन तकनीक आदि को प्रभावित तथा नियंत्रित करता है। यह कृषि फसलों, खाद्य एवं पेय तथा औद्योगिक कच्चे माल को ही नहीं बल्कि उनके व्यापारिक गति एव दशाओं को भी प्रभावित करती है। प्रत्येक प्रदेश सामान्यतया उन्हीं वस्तुओं का

उत्पादन करते हैं जिसके लिए जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त होती है । अतः एक प्रदेश का अतिरिक्त उत्पादन निर्यात किया जाता है जिसके विनिमय स्वरूप उन आवश्यक वस्तुओं का आयात या क्रय किया जाता है जो स्थानीय रूप से उत्पादित या उपलब्ध नहीं होती हैं ।

देश के आन्तरिक भाग में स्थित उत्तर प्रदेश, सागर और भूमध्य रेखा से दूर है जहाँ मानसून प्रकार की जलवायु का आधिपत्य है जो कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों के लिए अति उत्तम है । मानवीय क्रियाओं एवं कार्यक्षमता पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में पड़ता है ।

ङ. मिट्टी एवं खनिज

मनुष्य, पशुओं तथा पौधों के भोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी ही है । शाकाहारी भोजन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मिट्टी से उत्पन्न वस्तुओं से होती है । जहाँ तक मांसाहारी भोजन का प्रश्न है, मांस प्रदान करने वाले पशु भी अपने भोजन के लिए कृषि उपजों और चरागाहों पर निर्भर करते हैं जो मिट्टी की ही देन है । जलवायु के उपयुक्त होने पर गहरी तथा उर्वर मिट्टी वाले क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है । इसके विपरीत मिट्टी हल्की तथा अनुपजाऊ होने पर जलवायु के उपयुक्त होने पर भी मनुष्य गैर कृषि व्यवसायों को अपनाने के लिए बाध्य होता है । केवल पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त मैदानी भागों में उपयुक्त मानसूनी जलवायु तथा उर्वर जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान तथा सघन जनसंख्या वाला प्रान्त है ।

मानव सभ्यता की प्रगति एवं विकास में खनिज पदार्थों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है । शक्ति तथा मशीनें खनिज पदार्थों के कारण ही सम्भव हो सकी हैं । आधुनिक उद्योग, परिवहन और संचार के समस्त संयोग खनिज पदार्थों की ही देन है क्योंकि सम्पूर्ण औजार, उपकरण तथा मशीनें धातुओं से ही निर्मित होती हैं जो खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं । अनेक खनिज पदार्थ जैसे, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आदि

ईंधन तथा शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं जबकि अनेक अन्य (धातु तथा अधातु) खनिज विविध औद्योगिक क्रियाओं हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे लौह अयस्क, बाॅक्साइट, मैंगनीज आदि । खनिज पदार्थों को आर्थिक संवृद्धि तथा उन्नति के मापदण्ड के रूप में माना जाता है क्योंकि वे अंतत: आर्थिक क्रियाओं के विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हैं ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक खनिज संसाधनों का प्राय: अभाव है जिसके कारण प्रदेश में खनिज-आधारित उद्योगों विशेष रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास नहीं हो सका है । मिर्जापुर जनपद की उच्च भूमि ही एक मात्र क्षेत्र है जहाँ प्रस्तर खनन, उत्खनन तथा औद्योगिक क्रियाओं का विकास नियोजन काल में हुआ है ।

च. <u>प्राकृतिक वनस्पति एवं पशुजगत्</u>

मानवीय क्रियाओं में प्राकृतिक वनस्पति का अपना अलग महत्व है । वन-आधारित उद्योगों के माध्यम से किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक वनस्पतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । कागज, लुग्दी, दियासलाई, फर्नीचर आदि उद्योगों को कच्चा माल वृक्षों से प्राप्त होता है । उत्तर प्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी जनपदों तथा मिर्जापुर के दक्षिणी भागों में वन का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है जबकि प्रदेश के मैदानी भाग लगभग वन विहीन हैं और नदियों की घाटियों तथा तराई एवं भावर पेटी में ही कतिपय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पायी जाती हैं ।

मानव जीवन के पश्चात् पशु जीवन द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन है । मनुष्य और पशु मानव सभ्यता के विकास के आरम्भ से लेकर साथ-साथ रहे हैं और एक दूसरे के सहायक रहे हैं । यद्यपि आरम्भिक काल में मनुष्य केवल पशुओं का शिकार करता था और उन्हें पालना नहीं जानता था किन्तु कालान्तर में क्रमश: उसने पशुओं को पालने की कला सीख ली और उनसे मांस के अतिरिक्त ऊन, हड्डियाँ और चमड़े भी प्राप्त करने लगा और पशुओं का प्रयोग सवारी तथा परिवहन प्रयोजनों हेतु भी करने लगा । आधुनिक काल में मनुष्य पशुओं और उनके उत्पादों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से करने लगा है ।

उत्तर प्रदेश में गाय और भैंस दूध के प्रमुख स्रोत हैं जबकि बैलों और भैंसों का उपयोग कृषि के विविध कार्यों में पशुशक्ति के रूप में किया जाता है । इसके साथ ही प्रदेश में भेंड़, बकरियाँ, गधे, सुअर, मुर्गियाँ, घोड़े, खच्चर और अनेक अन्य उपयोगी पशु भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं ।

2. सामाजिक पर्यावरण

सामाजिक पर्यावरण एक विस्तृत शब्दावली है जो मानव समाज से सम्बन्धित प्रत्येक तथ्य को समाहित करती है । मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में एक संगठन का सृजन करके पर्यावरण से समायोजन करता है । यही संगठन समाज कहलाता है जो मनुष्य के व्यवहार और जीवन के तरीके को नियंत्रित करता है तथा अनेक प्रकार से उसकी प्रगति का निर्देशन करता है ~~तथा अनेक प्रकार से उसकी प्रगति का निर्देशन करता है~~ । वह मनुष्यों के सम्मुख कतिपय सीमायें निर्धारित करता है जिसके अन्तर्गत ही वे आर्थिक क्रियाओं का चयन करते हैं । मनुष्य समाज में इसके आदर्श तथा प्रतिमानों (मानकों) के अनुसार आचरण करता है । अध्ययन के इस अनुभाग में सभी सामाजिक संरचनात्मक तत्वों की विवेचना न तो सम्भव है और न उपयोगी ही, अतः यहाँ केवल उन्हीं सामाजिक घटकों का विश्लेषण किया जा रहा है जो व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक व्यवसायों के चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं । सामाजिक पर्यावरण के मुख्य तत्व जाति, प्रजाति, जन जाति, धर्म आदि हैं ।

क. जाति-प्रथा

जाति-प्रथा समाज का सर्वाधिक मौलिक तथा विशिष्ट तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लोगों के जन्म, मृत्यु तथा स्थानान्तरण को भी प्रभावित करता है । आर्थिक और राजनैतिक तथ्य जातिगत विशेषताओं से प्रभावित होते हैं । किसी व्यक्ति की जाति वंशानुगत होती है । प्राचीन हिन्दू समाज चार वर्णों - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था जिसके विकृत रूप वर्तमान समाज में भी विद्यमान हैं । उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं के समान ही मुसलमानों, इसाइयों, सिखों, जैनों, बौद्धों तथा यहूदियों आदि में भी जातियाँ पायी जाती हैं ।

व्यक्ति के आर्थिक क्रिया (व्यवसाय) के निर्धारण में जाति एक प्रभावशाली कारक माना जाता है । "भारतीय उपमहाद्वीप में अब भी अनेक व्यवसाय हैं जो व्यक्ति की जाति तथा सामाजिक स्तर से नियंत्रित होते हैं ।"[10] अति आरम्भिक काल से ही व्यवसायों की व्यवस्था वर्ग अथवा जाति के अनुसार की गयी है । प्राचीन साहित्य 'मनुस्मृति' में मनु द्वारा इस वर्ग व्यवस्था की पुष्टि होती है । मनुस्मृति' में उल्लेख है कि "विश्व की समृद्धि के लिए उसने (ईश्वर ने) अपने मुख, अपनी भुजाओं, अपनी जाँघों तथा अपने पावों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को उत्पन्न किया है । किन्तु इस विश्व की सुरक्षा हेतु उसने उनके लिए जो उसके मुख, भुजाओं, जाँघों और पाँवों से उत्पन्न हुए हैं पृथक-पृथक कर्तव्यों और व्यवसायों का निर्धारण किया है ।"[11]

उत्पादन-संगठन पद्धति की भाषा में भारतीय समाज चार सामाजिक-आर्थिक वर्गों-कृषक, शिल्पकार, सेवी जातियाँ और भूमिहीन खेतिहर मजदूर में विभक्त है । यद्यपि शिक्षा के प्रसार तथा अन्य विकासात्मक कारकों ने व्यवसायों पर जातीय नियंत्रण में कमी तथा उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं, किन्तु विभिन्न जातियों द्वारा अभी भी परम्परागत व्यवसाय अपनाये जाते हैं । व्यावसायिक प्रतिरूपों तथा उनकी विविधता में परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक हुए हैं । सामाजिक-आर्थिक आधार पर उत्तर प्रदेश की समस्त जातियों को चार प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है - 1. सवर्ण जातियाँ, 2. पिछड़ी जातियाँ, 3. अनुसूचित जातियाँ और 4. अनुसूचित जनजातियाँ ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ उत्तर प्रदेश की प्रमुख सवर्ण जातियाँ हैं । ब्राह्मणों का समाज में विशिष्ट स्थान है । इनमें से कुछ पुरोहित हैं, कुछ भू-स्वामी और कृषक हैं जबकि ये बड़ी संख्या में व्यावसायिक सेवाओं में भी संलग्न हैं ।

प्रदेश में क्षत्रियों या राजपूतों (ठाकुरों) और भूमिहारों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है । वे ब्रिटिशकाल में मुख्य भूस्वामी और जमींदार थे । वर्तमान काल में भी वे मुख्यतया कृषक हैं और अपने क्षेत्र की अन्य जातियों की तुलना में अधिक भूमि रखते हैं ।

सेना और पुलिस सेवाओं में भी इनकी संख्या अधिक है । शिक्षा के प्रसार से कुछ अन्य प्रशासनिक, शैक्षिक एवं अन्य व्यावसायिक सेवाओं में भी प्रवृष्ट हो गये हैं ।

वैश्य मुख्यतया व्यापारी और व्यवसायी हैं किन्तु उनमें से कुछ अन्य व्यवसायों और सेवाओं में भी कार्यरत हैं । प्रदेश के कायस्थ सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यवसायों में लगे हुए हैं और उनमें से अनेक सरकारी एवं सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त हैं । इसी प्रकार अधिकांश खत्री नगरों में ही केन्द्रित हैं जो मुख्यतया व्यवसायी हैं किन्तु उनमें से कुछ भूस्वामी और धनपति (संपत्तिधारक) भी हैं ।

उपरोक्त सवर्ण जातियों के अतिरिक्त प्रदेश में अनेक ऐसी जातियाँ हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी समझी जाती हैं । इन पिछड़ी जातियों में अहीर, कुर्मी, काछी, मुराव, कोइरी प्रमुख हैं । ये अधिकांशतः कृषक हैं और इनका अल्पांश ही अन्य सेवाओं में प्रविष्ट हो पाया है । अहीर उत्तम कृषक होने के साथ ही पशुपालन और पशुचारण के अपने परम्परागत व्यवसाय को भी अपनाये हुए हैं । कुर्मी, काछी, कोइरी प्रधानतः कृषक हैं और अपने खेतों पर ही कार्य करते हैं । प्रदेश के नगरों और गाँवों में असंख्य दस्तकार और सेवी जातियाँ पायी जाती हैं जो अपने परम्परागत तथा वंशानुगत व्यवसायों को ही संचालित करते हैं । इनमें लोहार, सोनार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, गड़ेरिया, धोबी, नाई, दर्जी आदि प्रमुख हैं ।

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित हैं किन्तु नगरों में भी उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है । (चित्र 2.1) । उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जातियों में चमार, पासी, धोबी, खटिक, कोरी, नट, खरवार, मुसहर, दुसाध, बेलदार, मांझर, हेला, डोम, बधिक, भाटू, बाँसफोर, सिल्पहर आदि प्रमुख हैं जो प्रदेश के विभिन्न भागों में पायी जाती हैं । इनमें चमार संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक तथा क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे अधिक विस्तृत अनुसूचित जाति है ।

चमार 'चर्मकार' शब्द का अपभ्रंश रूप है जिसका अर्थ है चमड़ा, हड्डी और खाल कर्मी । किन्तु इन परम्परागत कार्यों में अब इनका अल्पांश ही संलग्न मिलता है और

अधिकांश कृषि और नगरीय मजदूरों के रूप में जीविका प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे पारम्परिक कर्मचारी, दैनिक मजदूर, किरायेदार (काश्तकार असामी) और कंचित ही भूस्वामी कृषक हैं।-12 मृतक पशुओं को बस्तियों से दूर हटाने के अतिरिक्त वे खालों और हड्डियों को प्राप्त करके उन्हें चमड़े में परिवर्तित करते हैं और बहुतेरे मोची (काबलर) के रूप में भी कार्य करते हैं। इस जाति की महिलायें समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग के लोगों के घरों तथा अब अस्पतालों में भी दाइयों के रूप में सेवायें करती हैं। इस जाति के लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि से प्राप्त मजदूरी और गौण स्रोत निजी कृषि तथा अन्य सेवायें हैं।

चमार की भाँति धोबी ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में पाये जाते हैं जो वस्त्र प्रक्षालन के परम्परागत व्यवसाय में संलग्न हैं। अन्य अनुसूचित जातियाँ प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में केन्द्रित हैं और सुवितरित नहीं हैं। इनमें बांसफोर, डोम, खटिक, भुइयार प्रमुख शिल्पी जातियाँ हैं। अनुसूचित जातियों में शिक्षा तथा तकनीकी प्रशिक्षण का प्राय: अभाव हैं अत: वे गावों में अकुशल श्रमिक के रूप में कृषि में तथा नगरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में कार्यरत हैं। ये जातियाँ अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं किन्तु वहाँ उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के अभाव में इनके निवास की जड़ें कमजोर तथा उथली हैं। अत: जीविका के साधनों की खोज में कतिपय लोग नगरीय क्षेत्रों को पलायन कर लेते हैं जहाँ अल्प भोगी निम्नस्तरीय सेवा कार्यों में संलग्न होकर जीविका प्राप्त करते हैं।

जनजातियाँ अन्य जातीय वर्गों से भिन्न हैं। आरम्भिक काल में यह बहादुर लोगों का समूह था जिसका नेतृत्व कतिपय मान्य प्रमुखों द्वारा होता था। अत: जन-जाति का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से हैं जिसमें व्यक्तियों के व्यवसाय, आदतें तथा विचारों आदि की समता हो जिसे वे परम्परागत रूप से प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों मे जनजाति उन व्यक्तियों का समुदाय है जो स्थायी निवास नहीं बनाते और जीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए समूह में आजीवन स्थानान्तरित होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर में पर्वतीय तथा तराई क्षेत्रों और दक्षिण में मिर्जापुर के दक्षिणी

पठारी क्षेत्रों में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं जबकि मैदानी भागों में जनजातियों का लगभग अभाव है। मैदानी नगरीय केन्द्रों में इनकी संख्या नगण्य हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के मुख्य निवासी 'भोटिया' हैं जो ग्रीष्मकाल में भेड़ बकरियों को लेकर अल्पाइन चरागाहों में 6000 मीटर की ऊँचाई तक चले जाते हैं और शीतकाल के प्रारम्भ होने के पूर्व ही निचली घाटियों में लौट आते हैं। पशुचारण के साथ-साथ ऊनी धागे तथा ऊनी वस्त्र तैयार करना इनका मुख्य व्यवसाय है।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 'थारू' आदिवासी निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, लकड़ी काटना तथा शिकार करना है। मिर्जापुर के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों मे 'भुइया' और 'कोल' आदिवासी निवास करते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा मजदूरी करना है।

ख. धर्मादि

मानव व्यवसाय के निर्धारण में धर्म भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक नियोजन के 38 वर्ष बीत जाने और शिक्षा के उल्लेखनीय प्रसार के बावजूद मानव जीवन के विविध पक्षों में अब भी धर्म को अत्यधिक गम्भीरता से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान दो प्रधान धार्मिक समुदाय हैं जो ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में पाये जाते हैं। हिन्दू जातियों के व्यवसायों का विभाजन मुख्यतया जातीय आधार पर हुआ है।

उत्तर प्रदेश में संख्या की दृष्टि से मुसलमानों का स्थान हिन्दुओं के बाद आता है किन्तु कतिपय नगरों मे इनकी संख्या हिन्दुओं से भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमान मुख्यत: कृषक हैं किन्तु बहुत से लोग व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं में भी संलग्न हैं। इस संदर्भ में जुलाहों और धुनियों का वस्त्र बुनने तथा दर्जियों के वस्त्र सिलाई के उद्योग उल्लेखनीय हैं। इसके विपरीत धातु, लकड़ी और हड्डियों से सम्बन्धित उद्योगों में मुसलमानों की संख्या अत्यल्प है।

सिख, इसाई और जैन अन्य धार्मिक समुदाय हैं जिनकी संख्या अल्प है और जो मुख्यतया नगरीय केन्द्रों में निवास करते हैं । सिख मुख्यतया व्यापार और वाणिज्य क्रियाओं में संलग्न हैं जबकि इसाई अधिकांशतः सरकारी और निजी क्षेत्र की विविध सेवाओं से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार जैन अधिकांशतः व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित हैं । यद्यपि व्यावसायिक संरचना पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव है किन्तु शिक्षा के प्रसार तथा धार्मिक मान्यताओं में ह्रास और पश्चिमी सभ्यता के प्रभावों से समान धर्म के व्यक्ति भी अपनी जीविका प्राप्ति हेतु उनविभिन्न व्यवसायों का चयन करने लगे हैं जो अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत पर्यावरणी अवसरों द्वारा निर्धारित होते हैं ।

3. <u>सांस्कृतिक पर्यावरण</u>

संस्कृति मानवीय शिष्ट व्यवहार और क्रिया-कलाप के तरीकों का योग है । यह सम्पूर्ण मानवीय व्यवहार का संग्रह है । "सांस्कृतिक पर्यावरण भू दृश्य के उन तत्वों का समिश्र है जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं । इसके अन्तर्गत कृषित क्षेत्र, कृत्रिम प्रवाह मार्ग, परिवहन-क्रम तथा स्वयं मनुष्य जैसे तत्व सम्मिलित हैं ।[13]

ब्रायन[14] का अनुकरण करते हुए स्पेन्सर[15] ने उन प्रक्रियाओं को भी सांस्कृतिक पर्यावरण का अंश माना है जिनके द्वारा पूर्वोक्त परिवर्तन किये जाते हैं, जैसे औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया । उन्होंने मानवीय कार्यात्मक व्यवहार की व्याख्या निम्नांकित रूप मे किया है :-

इस प्रकार सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों को निम्नांकित वर्गों में रखा जा सकता है - 1. कृषि, 2. औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय विकास, 3, नगरीकरण का स्तर, 4. शक्ति संसाधनों का विकास, 5. परिवहन और संचार साधनों की प्रगति, 6. जन- स्वास्थ्य तथा शिक्षा की व्यवस्था और 7. लोक प्रशासन ।
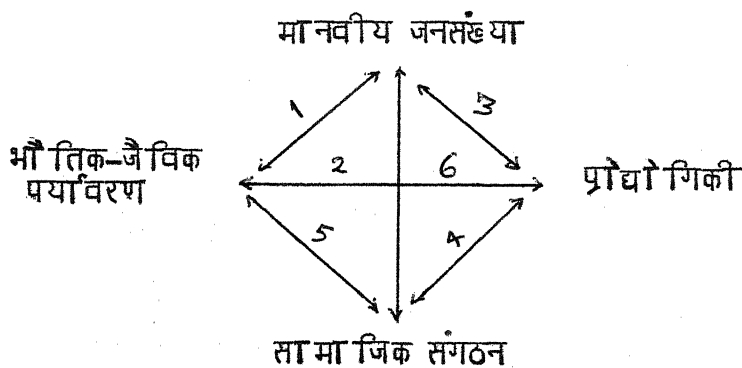
ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि आर्थिक तथा तकनीकी रूप से विकसित देश सांस्कृतिक-सम्पर्क प्रक्रिया के माध्यम से अल्प विकसित प्रदेशों में नवीन प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को विकसित करते हैं तथा उनके विकास का संचार करते हैं । परसंस्कृति ग्रहण के सभी चारों प्रक्रियाओं - अन्वेषण, आविष्कार, विकास और विसरण के माध्यम से एक प्रदेश की संस्कृति दूसरे प्रदेश की संस्कृति को प्रभावित करती है । फोर्ड के मतानुसार "ज्ञान और संस्कृति का विसरण पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्रों अथवा अतिग्रहणशील (ग्राही) व्यक्तियों तक स्वयं नहीं पहुँच जाता बल्कि इसमें दूरी और संयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।[16]

किसी क्षेत्र में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के निर्धारण में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया के रूप में नगरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । नगरीय व्यवसाय ग्रामीण व्यवसायों से काफी भिन्न होते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं (मुख्यत: कृषि) की प्रधानता होती है जबकि नगरीय केन्द्रों में द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियायें विकसित होती हैं । नगरीकरण में विकास के साथ-साथ प्राथमिक क्रियाओं के प्रभाव में ह्रास की प्रवृत्ति पायी जाती है । नगर प्राय: बहुधंधी होते हैं जिनमें विनिर्माण उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार, शिक्षा, प्रशासन तथा अन्य अनेक व्यावसायिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ संचालित होती हैं ।

औद्योगीकरण और नगरीकरण में घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध होता है । नगरीय केन्द्रों में विकास तथा कार्यात्मक विविधता के कारण अपेक्षाकृत अधिक रोजगार के अवसरों से आकर्षित होकर ग्रामीण-जनजीविका की खोज में नगरीय केन्द्रों की ओर प्रवास करते हैं ।

4. वैयक्तिक पर्यावरण

सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के पश्चात् वैयक्तिक पर्यावरण अति महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना को प्रभावित तथा नियंत्रित करता है ।[17] समान परिवेश में रहते हुए भी लोग वैयक्तिक कारकों के प्रभाव से भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं । वैयक्तिक कारक सामान्यतया वंशानुगत होते हैं । वैयक्तिक पर्यावरण के अन्तर्गत लिंग, आयु, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि को समाहित किया जाता है जो किसी कार्य में संलग्न व्यक्ति के भौतिक तथा मानसिक क्षमता, योग्यता, रुचि और गुण का निर्धारण करते हैं । इस प्रकार, वैयक्तिक पर्यावरण का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत विशेषताओं से है ।[18]

क. लिंग

एक व्यापार अपनाने के लिए व्यक्ति की क्षमता तथा योग्यता को निर्धारित करने में लिंग वैयक्तिक पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण पक्ष है । आधुनिक समाज में भी जहाँ एक ओर रोजगार प्रदान करने में पुरुष और स्त्रियों में उल्लेखनीय भेद-भाव किया जाता है वहीं दूसरी ओर अपनी सीमाओं तथा प्रतिबन्धों के कारण महिलायें सभी व्यवसायों के साथ समायोजन करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं । हमारे देश में अधिकांश महिलायें गृह-कार्यों में ही व्यस्त रहती हैं और वे आर्थिक क्रियाओं में संलग्न न होने के कारण जीविका हेतु अपने परिवार के पुरुष सदस्यों की आय पर निर्भर होती हैं । यहाँ महिलायें सामाजिक रीतिरिवाजों तथा प्रतिबन्धों के कारण भौतिक उत्पादनों में सहयोग नहीं दे पाती हैं । आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का योगदान पाश्चात्य विकसित देशों में भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में अधिक हैं । यह महिलाओं में स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के प्रति बढ़ती इच्छा, परिवार के आकार में कमी, घरेलू क्रियाओं में स्वचालित मशीनों के प्रयोग आदि का परिणाम है[19]। मध्यकाल में महिलायें जीवन की वास्तविकता से दूर रखी जाती थीं और उनका स्थान गृह के भीतर ही आरक्षित था लेकिन आधुनिक समाज में वे परिस्थितियाँ काफी सीमा तक परिवर्तित हो चुकी हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में महिलायें अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में द्वितीयक एवं

तृतीयक क्रियाओं में संलग्न हैं जिसके प्रमुख कारण नगरों में शिक्षा का प्रसार, परिवहन एवं संचार साधनों की उपलब्धता, उपयुक्त कार्यों के अपेक्षाकृत अधिक अवसर, बेहतर जीवन व्यतीत करने की बढ़ती इच्छा, परम्परागत सामाजिक रीति-रिवाजों तथा मान्यताओं की शिथिलता आदि हैं। अधिकांश महिलायें कृषि कार्यों तथा गृह उद्योगों में संलग्न हैं जबकि कतिपय शिक्षित एवं प्रशिक्षित महिलायें शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं में योगदान कर रही हैं।[20]

ख. आयु

आयु भी वैयक्तिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी व्यवसाय में संलग्नता हेतु व्यक्ति के भौतिक तथा मानसिक क्षमता एवं योग्यता का निर्धारण करती है। किसी प्रदेश में श्रमशक्ति की मात्रा और शक्ति उसकी जनसंख्या की आयु-संरचना द्वारा निर्धारित होती है। यह सामाजिक वर्ग के जनांकिकीय चरों में से एक है जो आर्थिक और सामाजिक अन्तर्क्रियाओं, सामाजिक अभिवृत्तियों और सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता को प्रभावित करता है।

भारतीय संविधान में शोषण तथा नैतिक एवं वस्तुगत परित्याग के विरुद्ध बच्चों और किशोरों के संरक्षण की व्यवस्था है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इतने कोमल समझे जाते हैं कि वे भौतिक तथा मानसिक भार का वहन नहीं कर सकते। अपरिपक्व होने के कारण वे किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में नहीं लगाये जा सकते। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे अपने वृद्धावस्था तथा दयनीय स्वास्थ्य के कारण भौतिक तनाव को सहने में असमर्थ होते हैं और जीवन के शेषकाल में कार्यों से अवकाश, विश्राम और शान्ति चाहते हैं। किन्तु अनेक बच्चे और वृद्ध पुरुष एवं महिलायें भी अपनी दरिद्र आर्थिक दशाओं के कारण अपनी जीविका हेतु किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न होने के लिए बाध्य होते हैं।

इस प्रकार 15-60 आयु वर्ग के अन्तर्गत जनसंख्या ही विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होने के लिए भौतिक तथा मानसिक रूप से उपयुक्त मानी जाती है। अतः

जनसंख्या के इस वर्ग को 'प्रभावी जनसंख्या' की संज्ञा दी जाती है। उल्लेखनीय है कि उक्त आयु-वर्ग के समस्त लोग आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते जिसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, आर्थिक दशाएँ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा लिंग आदि। कार्यशील जनसंख्या ~~प्रभावशील जनसंख्या~~ का वृहत् भाग जनसंख्या के प्रभावी आयु-वर्ग से ही प्राप्त होता है किन्तु इसमें कतिपय बच्चे और वृद्ध भी सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर प्रभावी आयु-वर्ग का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं वैयक्तिक कारणों से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं होता और गैर श्रमिक श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

ग. शिक्षा

व्यक्ति के व्यवसाय के चयन में शिक्षा एवं प्रशिक्षण का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तमान औद्योगिक युग में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार पर सम्पूर्ण आर्थिक कार्यों को तीन प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है[21] : 1. कुशल कार्य, 2. अर्द्ध कुशल कार्य और 3. अकुशल कार्य।

कुशल कार्य के अन्तर्गत व्यावसायिक, वैयक्तिक, प्राविधिक आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए अच्छी सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। प्राविधिक कार्यों के लिए गहन शिक्षा और प्राविधिक प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक होते हैं। इसके विपरीत अकुशल कार्य हेतु शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण आवश्यक नहीं होता है और यह मुख्यतया दैहिक होता है जिसमें भौतिक (शारीरिक) क्षमता की आवश्यकता होती है।

शिक्षा और कार्यात्मक विशिष्टीकरण परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे को प्रोन्नत करते हैं। शिक्षा या साक्षरता मात्र कार्यात्मक ही नहीं है बल्कि इसके घनिष्ट सम्बन्ध सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों से भी होते हैं। शिक्षा और साक्षरता में कुछ मौलिक अन्तर होता है। जो व्यक्ति किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है और अपना हस्ताक्षर बना लेता है उसे साक्षर माना जाता है जबकि

शिक्षा के लिए पाठशाला उत्तीर्ण करना भी आवश्यक है । सामान्यतया 'साक्षरता' शब्द का प्रयोग साक्षर और शिक्षित व्यक्तियों के लिए एक साथ किया जाता है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के अन्य भागों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । 1971 में प्रदेश की 21.70 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । यह प्रतिशत बढ़कर 1981 में 27.16 हो गया । साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक पायी जाती है । तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि

तालिका 2.1

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर (प्रतिशत में), 1981

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल जनसंख्या
ग्रामीण	35.18	9.49	23.06
नगरीय	54.73	35.43	45.88
कुल	38.76	14.04	27.16

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता मात्र 23.06 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता 45.88 प्रतिशत है । इसी प्रकार पुरुष साक्षरता (38.76 प्रतिशत) की अपेक्षा स्त्री साक्षरता (14.04 प्रतिशत) लगभग एक तिहाई है । स्त्री साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम (9.49 प्रतिशत) है जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग चार गुना (35.43 प्रतिशत) है (चित्र 2.2) ।

शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा कार्यात्मक गतिशीलता उत्पन्न होती है और श्रम का प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक, तृतीयक आदि कार्यों में स्थानान्तरण होता है । प्रदेश में मुख्यत: सामान्य शिक्षा के प्रसार से बड़ी संख्या में मैट्रिक, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक युवक तैयार हुए हैं जो केवल सफेदपोश कार्यों के लिए ही उपयुक्त हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव में प्राविधिक कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते । शिक्षित व्यक्तियों की संख्या की तुलना में सफेदपोश कार्यों में वृद्धि न हो पाने के कारण शैक्षिक

बेरोजगारों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । अतः शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है । नयी शिक्षानीति (1986)[22] में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और इसका क्रियान्वयन भी हो रहा है जिससे निकट भविष्य में कार्य से शिक्षा और प्रशिक्षण का सम्बन्ध और घनिष्ट हो सकेगा ।

घ. मनोविज्ञान एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण

वर्तमान गम्भीर बेरोजगारी के समय में यह आवश्यक नहीं रह गया है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुकूल रोजगार प्राप्त करे । उसे ऐसे कष्टप्रद एवं अनिच्छित कार्यों को भी स्वीकार करना पड़ सकता है जिससे प्राप्त पारिश्रमिक से उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी न हो पाती हो ।[23] वर्तमान मशीन युग में श्रमिकों का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं और उनको चलाने वाला मनुष्य भी मशीनवत् होता जा रहा है । कम्प्यूटर और सुपर कम्प्यूटर के प्रसार से मशीनें ही श्रमिक के हाथ और मस्तिष्क का कार्य करने लगी हैं । उद्योगपति कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन चाहता है जिसके लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों एवं कार्यालयों में श्रमिकों की छटनी भी होती है और भविष्य में रोजगार के अवसर कम होते जाते हैं । इससे बेरोजगारों की संख्या का और बढ़ना निश्चित है जो प्रदेश एवं देश के हित में नहीं होगा ।

व्यवसाय के चयन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । इच्छा एवं योग्यता के अनुकूल कार्य प्राप्त होने पर श्रमिक में कार्य करने की क्षमता एवं कुशलता का पूर्ण उपयोग होता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है । इसके विपरीत किसी विवशता में किये जाने वाले कार्य में व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करता और उस कार्य को किसी तरह काम चलाऊ ढंग से करता है जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः यथोचित उत्पादन हेतु कार्यों का इच्छा एवं योग्यतानुकूल होना परमावश्यक माना जाता है । भीषण बेरोजगारी के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी आदि) तक बनने के लिए प्रयास करता है । इसी प्रकार शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त

असंख्य युवक-युवतियाँ विभिन्न कार्यालयों में लिपिक के रूप में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के उदाहरण अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं। इससे कार्यशीलता पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ

1. Encyclopaedia of Social Sciences, 1965, Vol. XI-XII, pp.424.
2. Turmwald, R., Economics in Primitive Communities, London, 1932.
3. Maciver, R.M. and Page, C.H., "Social Status and Occupation, Society, 1959, p.350.
4. Ibid., fn. 1.
5. Brunhes, J., Human Geography, New York, 1952, p.30.
6. Basham, A.L., The Wonder that was India, 1967, p.35.
7. Shukla, M.C., Business Organization and Management, 1972, p. 19.
8. Maurya, S.D., Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, 1988, p.66.
9. Ibid.
10. Davis, Kingsley, Population of India and Pakistan, London, 1951.
11. Manusmriti, 1,31,87.
12. Eyles, J., Social Theory and Social Geography, Progress in Geography, OUP, London, 1977, p.207.
13. Davis, D.H., The Earth and Man, The Macmillan Company, New York, 1957, p.63.

Brayan, P.W., Man's Adaptation of Nature, London, 1933.

Spencer, J., Introducing Human Geography, John Wiley and Sons, New York, 1976, p.21.

Forde, C.D., Habitat, Economy and Society, Methuen, London, 1967, p.6.

Singh, H.D., "Determinants of Occupation - A Case Study of Eastern Uttar Pradesh, in Maurya, S.D. (ed.), Population and Housing Problems in India, Vol. 2, Chugh Publications, Allahabad, 1989, p. 151.

Maurya, S.D. and Gayatri Devi, "Socio-Cultural Determinants of Urban Occupation in Eastern Uttar Pradesh", in Singh, P. (ed.), Ecology of Urban India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1987, p. 138.

Gayatri Devi, "Emancipation of Women in India", in Maurya, S.D. (ed.), Women in India, Chugh Publications, Allahabad, 1988, pp. 41-42.

Ibid.

Maurya, S.D. and Gayatri Devi, "Determinants of Urban Occupations", in Maurya S.D. (ed.), Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad, 1989, p.64.

Government of India, Draft New Education Policy, 1986.

Op.cit., fn. 8, p.93.

——::o::——

अध्याय तीन

कार्यशील जनसंख्या

3.1 भूमिका

मनुष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक के रूप में भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और अपनी रुचि एवं आवश्यकतानुसार उनका उपभोग करता है । इस प्रकार प्राज्ञ मानव किसी प्रदेश के वास्तविक परिसम्पत्ति होते हैं जो इसके आर्थिक विकास एवं समृद्धि का निर्धारण करते हैं ।[1] विकासशील मानव संसाधनों में आधुनिकीकरण के सक्रिय अभिकर्ता मानव वर्ग हैं क्योंकि वे अकेले ही पूंजी निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सकते हैं और राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों का निर्माण कर सकते हैं ।[2]

किसी प्रदेश के विकास के स्तर के निर्धारण में वहाँ की कुल जनसंख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कार्यशील जनसंख्या जो विभिन्न व्यवसायों में आर्थिक रूप से संलग्न होती है । कुल जनसंख्या के उस अंश को जो विविध प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में कार्य करती है, सक्रिय जनसंख्या भी कहा जा सकता है । कुल जनसंख्या ही श्रम का एकमात्र स्रोत होती है अतः सक्रिय जनसंख्या कुल जनसंख्या से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होती है और सामान्यतया एक निश्चित अनुपात में पायी जाती है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता मिल सकती है । श्रम किसी भी आर्थिक क्रिया की मौलिक आवश्यकता है जिसके बिना कोई उत्पादन नहीं हो सकता । इसका तात्पर्य यह है कि पर्याप्त श्रम आपूर्ति वाले प्रदेश में अधिक मात्रा में सस्ती वस्तुओं का उत्पादन होगा क्योंकि श्रमशक्ति से भरपूर प्रदेश का अन्य तथ्यों के समान होने पर आर्थिक विकास में प्रबल आधार होता है । किन्तु भारत जैसे विकासशील देश में यह तथैव सत्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि यहाँ उत्पादन के अन्य कारक अधिक कमजोर हैं । आर्थिक रूप से पिछड़े इस प्रदेश में पूँजी निर्माण तथा निवेश विश्व के विकसित देशों की तुलना में अत्यल्प है ।[3]

जनसंख्या के आकार, संघटन तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अभिलक्षण आर्थिक विकास

की गति एवं स्तर के मौलिक निर्धारक हैं। जनांकिकीय शक्तियाँ जनसंख्या के समस्त कारकों की प्रकृति एवं मात्रा को ही प्रभावित नहीं करती हैं बल्कि वे आर्थिक पर्यावरण के प्रकार जिसमें एक क्रिया सम्पादित होती है को भी निर्धारित करती हैं। मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया प्राकृतिक संसाधन आधार के आकार एवं गुण को प्रभावित करती है। किसी स्थान या प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या को दो प्रधान वर्गों में विभक्त किया जा सकता है - अर्जक जनसंख्या तथा अनर्जक या निर्भर जनसंख्या। समस्त आर्थिक उत्पादन अर्जक जनसंख्या द्वारा प्राप्त होते हैं जिसका उपभोग अर्जक तथा अनर्जक दोनों वर्गों द्वारा किया जाता है। अतः अर्जक जनसंख्या की अधिकता समृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है।

3.2 जनगणना एव व्यावसायिक वर्ग

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के व्यावसायिक संरचना के अध्ययन हेतु भारतीय जनगणना के समंकों का प्राश्रय लिया गया है क्योंकि व्यावसायिक सूचना के लिए यही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। विभिन्न जनगणनाओं में एक 'श्रमिक' या 'कर्मी' की परिभाषा स्थायी न होकर कुछ सीमा तक परिवर्तित होती रही है। इसी प्रकार विभिन्न जनगणनाओं में जनसंख्या की व्यावसायिक तुलना में भी अधिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न जनगणनाओं में व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या के वर्गीकरण की पद्धति समान नहीं रही है। केवल कार्यात्मक वर्गों की संख्या ही नहीं बल्कि समान कार्यात्मक-वर्ग की परिभाषा में भी पर्याप्त असमानता पायी जाती है। अतः यहाँ भिन्न-भिन्न जनगणनाओं में जनसंख्या के कार्यात्मक वर्गीकरण की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जिससे व्यावसायिक तथ्य अधिक सुस्पष्ट हो सकें।

1. स्वतन्त्रता-पूर्व कालीन जनगणनायें

अर्जक जनसंख्या के विषय में सूचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम 1881 में किया गया जिसमें केवल प्रमुख अर्जक के व्यवसाय का ही अभिलेख किया गया था। 1891 जनगणना में इस पद्धति का परित्याग कर दिया गया और वास्तविक श्रमिक तथा आश्रित जनसंख्या में भेद न करके सम्पूर्ण जनसंख्या के जीविका साधनों को अभिलेखित किया गया। 1901

जनगणना में समस्त जनसंख्या को दो प्रधान श्रेणियों - वास्तविक कर्मी और आश्रित में वर्गीकृत किया गया था । वास्तविक कर्मी के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जो वास्तव में काम करते थे अथवा जो स्वयं या सेवकों के माध्यम से व्यापार को संचालित करते थे अथवा जो मकान किराया, पेंसन आदि से जीविका प्राप्त करते थे । जो व्यक्ति वास्तविक कर्मी नहीं थे उन्हें 'आश्रित' माना गया । इस जनगणना में समस्त व्यवसायों को दो प्रधान वर्गों - प्रमुख व्यवसाय तथा गौण व्यवसाय में विभक्त किया गया था । वह व्यवसाय जो आय का वृहद् स्रोत प्रदान करता था प्रमुख व्यवसाय और आय के अन्य स्रोतों को गौण व्यवसाय की संज्ञा दी गयी । इस प्रकार 1901 जनगणना में व्यवसाय 11 वृहद् कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किये गये थे - 1. भूतल का शोषण, 2. खनिज उत्खनन, 3. उद्योग, 4. परिवहन, 5. व्यापार, 6. सरकारी सेना, 7. लोक प्रशासन, 8. व्यावसायिक एवं स्वतंत्र कलायें, 9. घरेलू सेवायें, 10. जीविका के अनुत्पादक स्रोत -भिक्षुक, वेश्यायें आदि और 11. शेष ।

1911, 1921, तथा 1931 की जनगणनाओं में व्यवसाय को 4 प्रधान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था - 1. कच्ची सामग्रियों का उत्पादन, 2. मूल सामग्रियों की तैयारी तथा आपूर्ति, 3. लोक प्रशासन तथा स्वतंत्र कला और 4. विविध जिसको 12 उपविभागों में विभक्त किया गया था । 1931 जमगणना में परिणामों को अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से कतिपय परिवर्तन भी किये गये थे । इस जनगणना में सम्पूर्ण जनसंख्या को 3 प्रधान वर्गों में रखा गया था - 1. अर्जक, 2. कार्यरत आश्रित और 3. कार्यरहित आश्रित । उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्वयुद्ध काल में भारत सरकार युद्ध में संलग्न व्यक्तियों के विषय में सूचनाओं का प्रसार नहीं करना चाहती थी, अतः 1941 जनगणना में व्यावसायिक विवरणों का परित्याग कर दिया गया और 1931 में अपनाये गये व्यावसायिक वर्गों का मात्र अल्प संशोधनों के साथ 1941 जनगणना में भी तथैव अनुकरण किया गया ।

2. <u>जनगणना 1951</u>

स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में सम्पन्न हुई जिसमें महत्वपूर्ण तथा

दूरगामी परिवर्तन किये गये । उसमें व्यक्ति के व्यवसाय तथा उसकी जीविका के साधनों को समाहित किया गया । 1951 जनगणना में समस्त व्यवसायों को दो प्रधान वर्गों - 1. कृषि वर्ग, और 2. गैर कृषि वर्ग में रखा गया और प्रत्येक वर्ग को चार-चार उप-वर्गों में विभक्त किया गया ।[4]

क. <u>कृषि वर्ग</u>

1. अपने या अपने आश्रितों द्वारा पूर्णतः या मुख्यतया भूस्वामी कृषक ;
2. अपने या अपने आश्रितों द्वारा पूर्णतः या मुख्यतया भूमि रहित कृषक ;
3. कृषि मजदूर और उनके आश्रित ;
4. गैर कृषक भूस्वामी, कृषि लगान प्राप्तकर्ता और उसके आश्रित ।

ख. <u>गैर कृषि वर्ग</u>

1. कृषि के अतिरिक्त उत्पादन ;
2. वाणिज्य ;
3. परिवहन ; और
4. सेवायें एवं विविध क्रियायें ।

1951 जनगणना में आर्थिक स्तर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या तो 1. आत्म निर्भर या 2. अर्जन रहित आश्रित या 3. अर्जक आश्रित था ।

3. <u>जनगणना 1961</u>

पूर्ववर्ती जनगणना योजनाओं की त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से जनगणना 1961 में व्यावसायिक वर्गीकरण में पुनः परिवर्तन किया गया । इस जनगणना में 'व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण' की योजना को अपनाया गया और समस्त जनसंख्या को दो प्रधान श्रेणियों में विभाजित किया गया : 1. कार्यशील जनसंख्या, और 2. गैर कार्यशील जनसंख्या । कार्यशील जनसंख्या को पुनः नौ कार्यात्मक या जीविका वर्गों में विभक्त किया गया जो निम्नवत है[5] :

1. कृषक के रूप में कार्यरत कास्तकार ;

2. कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत खेतिहर मजदूर ;
3. उत्खनन, प्रस्तर खनन, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, आखेट, बागवानी, पक्षी पालन एवं सम्बन्धित क्रियाओं में कार्यरत ;
4. पारिवारिक उद्योग में कार्यरत ;
5. गैर पारिवारिक उद्योग में कार्यरत ;
6. निर्माण में कार्यरत ;
7. व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत ;
8. परिवहन, संग्रह एव संचार में कार्यरत ;
9. अन्य सेवाओं में कार्यरत ।

आर्थिक स्तर के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में संलग्न समस्त व्यक्तियों को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया था - 1. नियोजक, 2. कर्मचारी, 3. एकल कर्मी, और 4. परिवार कर्मी ।

4. <u>जनगणना 1971</u>

जनगणना 1971 में पिछली जनगणना 1961 के व्यावसायिक वर्गीकरण को ही अल्पान्तर से अनुकरण किया गया । ~~जनसंख्या~~ जनगणना 1971 में सम्पूर्ण जनसंख्या को दो वृहत् श्रेणियों - 1. कर्मी, और अकर्मी के अन्तर्गत रखा गया । कर्मियों को उनके कार्य के आधार पर पुनः नौ प्रधान वर्गों में रखा गया जो निम्न प्रकार है :

1. कृषक ;
2. कृषि श्रमिक ;
3. पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, आखेट, बागवानी, पक्षी पालन एवं सम्बन्धित क्रियाओं में कार्यरत ;
4. उत्खनन तथा प्रस्तर खनन में कार्यरत ;
5. विनिर्माण, प्रक्रमण, सेवा तथा मरम्मत में कार्यरत -
   अ. गृह उद्योग, और ब. गृह उद्योग के अतिरिक्त ;
6. निर्माण कार्य में कार्यरत ;

7. व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत ;

8. परिवहन, संग्रह एवं संचार में कार्यरत ; और

9. अन्य सेवाओं में कार्यरत ।

आर्थिक स्तर के अनुसार 1961 जनगणना की भाँति ही कार्यरत व्यक्तियों को चार श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया । 1971 जनगणना में ऐसे व्यक्ति को जो जनगणना के सन्दर्भ-काल में किसी उत्पादक कार्य में संलग्न नहीं था, गैर श्रमिक या अकर्मी के रूप में वर्गीकृत किया गया भले ही वह पेंसन, मकान किराया आदि से आय प्राप्त करता हो ।

5. जनगणना 1981

पूर्ववर्ती जनगणनाओं की तुलना में जनगणना 1981 में कुछ मौलिक परिवर्तन किये गये हैं । इसमें सम्पूर्ण जनसंख्या को तीन प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है[6] - 1. मुख्य कर्मी या श्रमिक 2. सीमान्त कर्मी या श्रमिक, और 3. अकर्मी या गैर श्रमिक ।

1961 और 1971 की जनगणनाओं में कर्मियों और अकर्मियों के विभाजन को 1981 जनगणना में समाप्त कर दिया गया है और एक वर्ष के सन्दर्भ में समय-उपयोग मापदण्ड को अपनाया गया है । वह व्यक्ति जो वर्ष के अधिकांश समय में आर्थिक कार्य कलापों में संलग्न रहा हो (कम से कम 183 दिन) उसे मुख्य श्रमिक या कर्मी माना गया है जबकि वे व्यक्ति जिन्होंने विगत वर्ष में कुछ ही समय काम किया हो, परन्तु वर्ष के अधिकांश समय में काम न किया हो उन्हें सीमान्त कर्मी या श्रमिक माना गया है । इसके विपरीत वे व्यक्ति जिन्होंने पिछले संदर्भ वर्ष की अवधि में कुछ भी काम न किया हो उन्हें अकर्मी या गैर श्रमिक माना गया है ।[7]

किसी आर्थिक उत्पादन के कार्यकलापों में भाग लेने को 'कार्य' परिभाषित किया गया है । यह भाग लेना शारीरिक या मानसिक या दोनों प्रकार का हो सकता है । कार्य के अन्तर्गत केवल शारीरिक कार्य करना ही नहीं बल्कि कार्य के प्रभावी देख-रेख और निर्देशन को भी सम्मिलित किया गया है ।[8]

मुख्य कर्मियों को पुन: 4 वृहत् कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया गया है[9]: 1. कृषक, 2. कृषि श्रमिक, 3. गृह उद्योग में कार्यरत, और 4. अन्य कर्मी । उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती 1951, 1961 एवं 1971 जनगणनाओं में कार्यशील जनसंख्या को 9 वृहत् कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया गया था । उन कार्यात्मक श्रेणियों की संख्या घटाकर 1981 में मात्र 4 तक सीमित कर दी गयी है । इस परिवर्तन के कारण 1981 जनगणना के कार्यात्मक श्रेणियों की तुलना पूर्ववर्ती जनगणनाओं की कार्यात्मक श्रेणियों से करना अत्यन्त कठिन हो गया है ।

3.3 कार्यशील जनसंख्या : प्रकृति एवं आकार

1981 जनगणना में सम्पूर्ण जनसंख्या को तीन प्रधान वर्गों - मुख्य कर्मी, सीमान्त कर्मी तथा अकर्मी में विभक्त किया गया है । इसमें मुख्य कर्मी ही कार्यशील जनसंख्या के प्रधान घटक हैं और सीमान्त कर्मियों का योगदान अत्यल्प है । उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों की कुल जनसंख्या 127.02 लाख है जिसमें 69.08 लाख पुरुष और 57.94 लाख स्त्रियाँ हैं । इन नगरों मे 34.22 लाख मुख्य कर्मी हैं जिसमें पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या क्रमश: 32.53 लाख और 1.69 लाख है । इस प्रकार कुल जनसंख्या में 26.94 प्रतिशत भाग मुख्य कर्मियों का है । मुख्य कर्मियों का प्रभाग प्रथम श्रेणी के नगरों में 27.04 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 26.53 प्रतिशत है । ज्ञातव्य है कि 1971 में इन्हीं नगरों में 25.91 लाख व्यक्ति कार्यशील थे । इस प्रकार आठवें दशक में मुख्य कर्मियों की संख्या में 32.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो उसी अवधि में कुल जनसंख्या में हुई वृद्धि (35.29 प्रतिशत) से 3.23 प्रतिशत कम है । प्रथम श्रेणी के नगरों में कर्मियों की संख्या में 30.66 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी जबकि द्वितीय श्रेणी के नगरों में यह वृद्धि 38.30 प्रतिशत पायी गयी है ।

तालिका 3.1 में कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है । इस तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों में औसतन 26.94 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कर्मियों के रूप में आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं किन्तु एक नगर से दूसरे नगर में इस अनुपात में भिन्नता देखने को मिलती है । कुल जनसंख्या में

तालिका 3.1

कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा मुख्य कर्मियों में लिंगानुपात (1981)

क्र0 सं0	नगर	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	महिलायें प्रति हजार पुरुष
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर	27.49	47.62	2.44	41
2.	लखनऊ	27.72	47.62	3.73	65
3.	वाराणसी	26.38	46.02	3.05	56
4.	आगरा	26.58	47.77	1.87	34
5.	इलाहाबाद	25.64	43.78	3.27	60
6.	मेरठ	28.26	49.76	2.91	50
7.	बरेली	26.69	47.44	2.38	43
8.	मुरादाबाद	27.57	49.91	1.53	26
9.	अलीगढ़	25.02	44.95	2.04	39
10.	गोरखपुर	24.09	41.77	2.84	56
11.	सहारनपुर	27.09	48.58	2.11	37
12.	देहरादून	30.28	50.66	4.86	77
13.	गाजियाबाद	30.03	51.50	3.30	51
14.	झाँसी	25.04	42.34	5.68	120
15.	शाहजहाँपुर	26.40	47.62	1.80	33
16.	रामपुर	27.66	51.20	2.38	41
17.	फिरोजाबाद	27.22	48.48	2.10	37
18.	मुजफ्फरनगर	25.57	46.20	1.97	37
19.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	29.38	51.53	2.41	38
20.	मथुरा	27.76	49.06	2.56	44
21.	हरद्वार	27.15	47.25	2.57	44
22.	फैजाबाद	28.84	47.76	4.22	68
23.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	27.42	48.26	3.06	54
24.	अमरोहा	26.24	46.40	3.62	69
25.	इटावा	25.65	44.66	3.95	77
26.	सम्भल	26.29	48.15	1.22	22
27.	जौनपुर	24.93	43.27	3.96	80
28.	बुलन्दशहर	24.93	44.58	2.40	46
29.	हापुड़	25.85	46.10	2.51	47

1	2	3	4	5	6
30.	सीतापुर	28.78	49.75	3.24	53
प्रथम श्रेणी के नगरों का योग :		27.04	47.30	2.89	50
31.	बहराइच	25.46	46.21	1.99	38
32.	बदायूँ	26.03	46.60	2.23	41
33.	हाथरस	25.99	46.28	1.98	36
34.	रायबरेली	28.57	48.91	3.64	61
35.	पीलीभीत	27.11	47.61	2.45	44
36.	मोदीनगर	28.44	49.59	2.33	38
37.	मऊनाथभंजन	31.52	45.18	16.40	328
38.	फतेहपुर	25.76	45.21	3.38	65
39.	रुड़की	34.60	55.57	3.01	36
40.	हलद्वानी-काठगोदाम	28.30	49.19	2.84	47
41.	उन्नाव	26.40	46.84	2.84	45
42.	बाँदा	25.46	44.14	2.82	53
43.	गोण्डा	26.20	45.98	2.26	41
44.	बस्ती	26.29	44.77	3.93	73
45.	मुगल सराय	24.93	43.93	1.86	35
46.	हरदोई	26.48	46.20	2.70	48
47.	खुर्जा	26.01	46.89	2.29	43
48.	चन्दौसी	25.71	46.40	1.81	34
49.	आजमगढ़	23.97	41.22	3.59	74
50.	उरई	23.92	41.91	1.89	37
51.	बाराबंकी	27.89	48.69	2.52	42
52.	बलिया	22.90	39.99	2.73	58
53.	कासगंज	25.10	45.14	2.10	41
54.	लखीमपुर	25.71	45.94	2.20	44
55.	गाजीपुर	23.50	41.00	3.45	73
56.	मैनपुरी	24.79	44.49	1.93	38
57.	बिजनौर	25.67	45.51	2.95	57
58.	ललितपुर	26.88	45.83	5.35	103
59.	देवरिया	24.37	42.29	2.86	56
60.	नजीबाबाद	26.12	47.45	2.27	43

1	2	3	4	5	6
61.	टाण्डा	29.08	47.70	8.26	155
62.	एटा	24.24	43.68	2.04	41
63.	शामली	27.15	48.31	1.80	31
64.	काशीपुर	26.57	47.36	2.33	42
65.	देवबन्द	26.47	46.94	1.41	25
66.	नगीना	26.83	48.57	2.09	38
द्वितीय श्रेणी के नगरों का योग		26.53	46.23	3.21	59
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		26.94	47.10	2.91	52

मुख्य कर्मियों का सर्वाधिक प्रतिशत (34.60) रुड़की में पाया गया है जिसके पश्चात् क्रमशः मऊनाथ भंजन (31.52), देहरादून (30.28), गाजियाबाद (30.03), फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ (29.38), टाण्डा (29.08) का स्थान है। इसके विपरीत मुख्य कर्मियों का न्यूनतम प्रतिशत (22.90) बलिया में अंकित किया गया है। मुख्य कर्मियों के निम्न प्रभाग वाले अन्य नगर गाजीपुर (23.50 प्रतिशत), उरई (23.92 प्रतिशत), आजमगढ़ (23.97 प्रतिशत), एटा (24.24 प्रतिशत), देवरिया (24.37 प्रतिशत), मैनपुरी (24.79 प्रतिशत), मुगल सराय (24.93 प्रतिशत), बुलन्दशहर (24.93 प्रतिशत) और जौनपुर (24.97 प्रतिशत) हैं (चित्र 3.1)।

व्यक्तियों के श्रमशक्ति में संलग्नता पर अधिवासों के आकार तथा जनसंख्या के आयु, लिंग तथा व्यवसायों की प्रकृति के साथ ही सामाजिक-आर्थिक दशाओं का उल्लेखनीय प्रभाव होता है। सामान्यतया वृहदाकार नगरों में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात लघु नगरों की तुलना में कम पाया जाता है क्योंकि वृहत् नगरों में शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में संलग्न व्यक्तियों की संख्या अधिक होने से आश्रितों की संख्या स्वभावतः अधिक पायी जाती है। इसी प्रकार जिन नगरों में गृह उद्योग और भारी विनिर्माण उद्योग विकसित होते हैं कर्मियों या श्रमिकों का अनुपात अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत कृषि में अधिक श्रमशक्ति वाले नगरों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम मिलता है।

समस्त वृहत् नगरों की कुल पुरुष जनसंख्या का 47.10 प्रतिशत मुख्य कर्मियों के

अन्तर्गत कार्यशील है । कार्यशील जनसंख्या का यह प्रभाग प्रथम श्रेणी के नगरों में 47.30 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी के नगरों में 46.23 प्रतिशत है जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश के प्रथम श्रेणी के नगरों में द्वितीय श्रेणी के नगरों की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है । रुड़की में 55.57 प्रतिशत (सर्वाधिक) पुरुष मुख्य कर्मी हैं जिसके पश्चात् फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ (51.53 प्रतिशत), गाजियाबाद (51.50 प्रतिशत), रामपुर (51.20 प्रतिशत), देहरादून (50.66 प्रतिशत), मुरादाबाद (49.91 प्रतिशत), सीतापुर (49.75 प्रतिशत), मोदीनगर (49.59 प्रतिशत), हल्द्वानी-काठगोदाम (49.19 प्रतिशत) और मथुरा (49.06 प्रतिशत) का स्थान है । इसके विपरीत पुरुष जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का न्यूनतम प्रतिशत (39.99) बलिया में है । गाजीपुर (41.00 प्रतिशत), आजमगढ़ (41.22 प्रतिशत), गोरखपुर (41.77 प्रतिशत) एवं उरई (41.91 प्रतिशत) नगरों के पुरुषों में कर्मियों का प्रतिशत अत्यल्प है ।

अन्य भारतीय नगरों की भाँति उत्तर प्रदेश के नगरों मे भी महिलायें मुख्यतया घरेलू कार्यों मे संलग्न रहती हैं और वे आर्थिक क्रियाओं में बहुत कम योगदान दे पाती हैं। अधिकांश भारतीय परिवारों में भोजन पकाने, बच्चों के पालन-पोषण, परिवार के सदस्यों की देख-रेख तथा अन्यान्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व महिलाओं पर होता है । इस प्रकार महिलायें प्राय: घरेलू क्रियाओं में संलग्न होती हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष आय नहीं प्राप्त होती है जबकि पुरुष बाह्य क्रियाओं में कार्यरत होकर आर्थिक उपार्जन करते हैं । अत: श्रमशक्ति में पुरुषों का ही प्रभुत्व रहता है और महिलाओं का योगदान अत्यल्प तथा सीमान्त प्रकृति का होता है । उत्तर प्रदेश के समस्त वृहत् नगरों में औसत रूप से मात्र 2.91 प्रतिशत महिलायें ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न पायी गयी हैं । यह अनुपात प्रथम श्रेणी के नगरों में 2.84 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 3.21 प्रतिशत है । इससे स्पष्ट है कि नगरीय आकार के घटने पर महिलाओं में कार्यशीलता-अनुपात में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पायी जाती है । इसी प्रकार उन नगरों में जहाँ गृह उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, महिलायें अपेक्षाकृत अधिक कार्यशील हैं । गृह उद्योग में उच्च विशिष्टीकरण वाला नगर मऊनाथ भंजन महिलाओं की सर्वाधिक कार्यशीलता धारक केन्द्र

है जहाँ 16.40 प्रतिशत महिलायें मुख्य श्रमिक हैं। मुसलमान जनसंख्या-बहुल इस नगर में सूती हस्तकरघा एवं शक्ति करघा उद्योग ने विशेष प्रगति की है। इन उद्योगों के लिए सामग्रियों के तैयार करने में महिलाओं का योगदान विशेष सराहनीय है। मऊनाथभंजन के पश्चात् टाण्डा में महिलाओं की कार्यशीलता (8.26 प्रतिशत) अधिक है। टाण्डा भी मऊ की ही भाँति मुसलमान जनसंख्या-बहुल तथा गृह उद्योग (सूती वस्त्र) का प्रसिद्ध केन्द्र है। बुन्देलखण्ड स्थित झाँसी और ललितपुर में भी महिलाओं की संलग्नता अपेक्षाकृत अधिक है जहाँ क्रमशः 5.68 और 5.35 प्रतिशत महिलायें आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। प्रशासनिक एवं शैक्षिक केन्द्र देहरादून (4.86 प्रतिशत) और फैजाबाद (4.22 प्रतिशत) में भी महिलायें अपेक्षाकृत अधिक कार्यशील हैं।

उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरों में महिलाओं की न्यूनतम कार्यशीलता सम्भल में आलेखित है जहाँ कुल महिला जनसंख्या का मात्र 1.22 प्रतिशत ही आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो सका है। इसी प्रकार अन्य 12 नगरों में 2.00 प्रतिशत से भी कम महिलायें ही आर्थिक कार्यों में योगदान दे पाती हैं। ये नगर हैं - देवबन्द (1.41), मुरादाबाद (1.53), चन्दौसी (1.81), शाहजहाँपुर (1.80), शामली (1.80), मुगलसराय (1.86), आगरा (1.87), उरई (1.89), मैनपुरी (1.93), मुजफ्फरनगर (1.97), हाथरस (1.98), और बहराइच (1.99)।

यदि कार्यशील जनसंख्या में पुरुष एवं स्त्रियों के अनुपात पर विचार किया जाय तो कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य सम्मुख प्रकट होते हैं जिनका नगरों की व्यावसायिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों की श्रमशक्ति में 95.07 प्रतिशत पुरुष तथा 4.93 प्रतिशत महिलायें हैं। प्रथम श्रेणी के नगरों के लिए यह अनुपात क्रमशः 95.22 एवं 4.78 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए 94.96 एवं 5.54 प्रतिशत है। सामान्यतया वृहद् नगरों में महिलाओं का प्रभाग न्यूनतर है। मऊनाथभंजन में महिलाओं का प्रभाग सर्वाधिक है जहाँ कुल श्रमशक्ति में 24.68 प्रतिशत महिलायें हैं। अधिक महिला अनुपात वाला द्वितीय नगर टाण्डा है जहाँ कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रभाग 13.42 प्रतिशत है। झाँसी तृतीय स्थान पर

आता है जिसकी श्रमशक्ति में 10.69 प्रतिशत महिलायें हैं । ललितपुर (चतुर्थ) की श्रम-शक्ति में 9.32 प्रतिशत प्रभाग महिलाओं का है । इसके विपरीत कई नगरों की श्रम-शक्ति में महिलाओं का योगदान 3.00 प्रतिशत से भी कम है । सम्भल निम्नतम स्थान पर है जिसकी श्रमशक्ति में महिलाओं का हिस्सा मात्र 2.17 प्रतिशत ही है । देवबन्द (2.40) और मुरादाबाद (2.57) में महिलाओं का हिस्सा 3.00 प्रतिशत से भी कम है ।

प्रादेशिक स्तर पर वृहत् नगरों की श्रमशक्ति में प्रति हजार पुरूषों पर 52 महिलायें कार्यरत हैं किन्तु विभिन्न नगरों में यह अनुपात समान नहीं है बल्कि उनमें पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । प्रथम श्रेणी के नगरों में उक्त अनुपात 50 महिलायें तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 59 महिलायें प्रति हजार पुरूष पाया गया है । सर्वाधिक लिंगानुपात (328) मऊनाथभंजन की श्रमशक्ति में पाया जाता है जो अन्य नगरों की तुलना में बहुत अधिक है । उच्च लिंगानुपात वाले नगरों में टाण्डा (155), झाँसी (120) और ललितपुर (103) प्रमुख हैं । न्यूनतम लिंगानुपात सम्भल में अंकित किया गया है जिसकी श्रमशक्ति में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 22 है । श्रमशक्ति में प्रति हजार पुरूषों पर 35 महिलाओं से कम अनुपात वाले नगर हैं - आगरा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, चन्दौसी, शामली और देवबन्द ।

3.4 कार्यशील जनसंख्या का वृहत् क्रिया-वर्गों में वितरण

प्रदेश के समस्त कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न क्रियाओं का क्रियावर्गों में वितरण द्वारा उसकी व्यावसायिक संरचना का ज्ञान होता है । विभिन्न भारतीय जनगणनाओं में क्रियाओं के वर्गीकरण में समानता न होने के कारण विभिन्न वर्षों में व्यावसायिक संरचना की तुलना करना अत्यन्त कठिन हो गया है । 1971 जनगणना में सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्या को 9 वृहत् क्रिया-वर्गों में विभक्त किया गया था जिसका विवरण अध्याय दो में दिया जा चुका है । 1981 जनगणना में क्रिया-वर्गों को सीमित कर दिया गया है । सम्पूर्ण जनसंख्या को तीन प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है : 1. मुख्य कर्मी, 2. सीमान्त कर्मी, और 3. अकर्मी । मुख्य कर्मियों को पुनः 4 क्रिया-वर्गों के अन्तर्गत

विभाजित किया गया है - क. कृषक, ख. कृषि श्रमिक, ग. गृह उद्योग में कार्यरत कर्मी, और 4. अन्य कर्मी । व्यावसायिक समानता एवं कार्य पद्धति के आधार पर प्रस्तुत प्रथम दो वर्गों - कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को एक संयुक्त वर्ग में समाहित किया गया है और इस संयुक्त क्रिया-वर्ग को 'कृषि' शब्द से अभिहीत किया गया है । तृतीय क्रिया-वर्ग को यथावत रखा गया है और चतुर्थ क्रिया-वर्ग के नाम से परिवर्तन किया गया है । इस प्रकार इस अध्ययन में सम्पूर्ण क्रियाओं को तीन वृहत् क्रिया-वर्गों में विभक्त किया गया हैं : 1. कृषि, 2. गृह उद्योग, और 3. विविध क्रियायें (चित्र 3.2) ।

1. कृषि

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रान्त है जहाँ की तीन-चौथाई से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । अनगरीय क्रिया होते हुए भी प्रदेश के अनेक नगरों विशेषरूप से छोटे नगरीय केन्द्रों की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है । कतिपय वृहत् नगरों में भी श्रमशक्ति का उल्लेखनीय प्रभाग कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध कार्यों में संलग्न है । उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की कुल श्रमशक्ति 3421.82 हजार व्यक्तियों में 103.23 हजार कृषक तथा 79.97 हजार कृषि श्रमिक हैं । इस प्रकार कुल श्रमशक्ति में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का प्रभाग क्रमशः 3.02 और 2.34 प्रतिशत है । कुल पुरुष कर्मियों का 3.06 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 2.14 प्रतिशत कृषक हैं जबकि पुरुष एवं महिला श्रमशक्ति में कृषि श्रमिकों का हिस्सा क्रमशः 2.28 और 3.48 प्रतिशत है ।

कुल श्रमशक्ति में कृषकों के सर्वाधिक अनुपात वाले नगर सम्भल और फतेहपुर हैं जिनकी श्रमशक्ति में 18.05 प्रतिशत कृषक हैं । उन्नाव (12.17), ललितपुर (12.09), बहराइच (11.41), और देवबन्द (10.97) में कृषकों का प्रतिशत 10 से अधिक है । इसके विपरीत फिरोजाबाद और मथुरा में कृषकों का प्रतिशत 1.00 से भी कम है । कुल श्रमशक्ति में कृषि श्रमिकों के प्रतिशत पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि सम्भल की कुल कार्यशील जनसंख्या में 17.08 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं जो अन्य किसी भी नगर से अधिक है । कृषि श्रमिकों के उच्च प्रतिशत वाले अन्य नगर उन्नाव (10.15), फतेहपुर (8.12),

नगीना §7.79§, बस्ती §7.77§, रायबरेली §7.04§ और बहराइच §7.01§ हैं। फिरोजाबाद, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा, मोदीनगर, रुड़की और हलद्वानी-काठगोदाम के श्रमशक्ति में कृषिश्रमिकों का प्रतिशत 1.00 से कम है।

2. गृह उद्योग

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल 252.19 हजार व्यक्ति गृह उद्योग में कार्यरत हैं जिनमें 226.66 हजार पुरुष तथा 25.53 हजार महिलायें हैं। इस प्रकार कुल कार्यशील जनसंख्या का 7.37 प्रतिशत गृह उद्योगों में लगा हुआ है। पुरुष कर्मियों का 6.96 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 15.16 प्रतिशत गृह उद्योगों में संलग्न है। मऊनाथ भंजन में 62.78 प्रतिशत कर्मी गृह उद्योग में कार्यरत हैं। गृह उद्योग में अधिक श्रमशक्ति धारक नगर टाण्डा §39.30 प्रतिशत§, वाराणसी §22.30 प्रतिशत§, मिर्जापुर - विन्ध्याचल §18.34 प्रतिशत§, अमरोहा §16.51 प्रतिशत§, इटावा §14.28 प्रतिशत§ और ललितपुर §12.34 प्रतिशत§ हैं। देहरादून, रुड़की और एटा ऐसे नगर हैं जिनकी 2.00 प्रतिशत से भी कम श्रमशक्ति गृह उद्योग से सम्बद्ध है।

यदि हम पुरुषों और महिलाओं के गृह उद्योग में संलग्नता का पृथक-पृथक अध्ययन करें तो पायेंगे कि गृह उद्योग ने पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक आकर्षित किया है। मऊनाथभंजन में 53.80 प्रतिशत पुरुष कर्मी गृह उद्योग में कार्यरत हैं जबकि इसकी 90.20 प्रतिशत महिला कर्मी गृह उद्योग में संलग्न हैं। इसी प्रकार टाण्डा के पुरुष एवं महिला कर्मियों का क्रमशः 36.14 तथा 59.67 प्रतिशत गृह उद्योग में लगा हुआ है। इटावा तथा अमरोहा में 11.03 और 14.24 प्रतिशत पुरुष कर्मी गृह उद्योग में संलग्न हैं जबकि इन्हीं नगरों की क्रमशः 56.22 तथा 49.19 प्रतिशत महिला कर्मी गृह उद्योगों में कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार के उदाहरण अन्य नगरों - वाराणसी §22.01एवं 27.66 प्रतिशत§, झाँसी §5.81 एवं 23.67 प्रतिशत§, रामपुर §7.08 एवं 23.79 प्रतिशत§, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ §6.60 एवं 22.08प्रतिशत§ आदि में भी पाये जाते हैं।

तालिका 3.2

मुख्य कर्मियों का वृहत् श्रमिक वर्गों में प्रतिशत वितरण तथा लिंगानुपात (महिलायें प्रति हजार पुरुष)

नगरीय श्रेणी	श्रमिक वर्ग			
	कृषक	कृषि श्रमिक	गृह उद्योग कर्मी	अन्य कर्मी
अ. प्रथम श्रेणी				
व्यक्ति	2.26	1.98	7.25	88.51
पुरुष	2.29	1.92	7.04	88.77
महिलायें	1.61	3.05	11.70	83.64
लिंगानुपात	35	80	84	47
ब. द्वितीय श्रेणी				
व्यक्ति	6.22	3.86	7.88	82.04
पुरुष	6.34	3.79	6.73	83.14
महिलायें	4.06	5.04	27.64	63.26
लिंगानुपात	38	78	241	45
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (अ + ब)				
व्यक्ति	3.02	2.34	7.37	87.27
पुरुष	3.06	2.28	6.96	87.70
महिलायें	2.14	3.48	15.16	79.22
लिंगानुपात	36	79	113	46

3. विविध क्रियायें

यह अनेक क्रियाओं का समूह है जिसके अन्तर्गत कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों के अतिरिक्त श्रमशक्ति को समाहित किया गया है। 1981 जनगणनानुसार, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल 2986.41 हजार श्रमिक विविध क्रियाओं में संलग्न हैं जिनमें 2852.95 हजार पुरुष तथा 133.46 हजार महिलायें हैं। इस प्रकार वृहत्नगरों में समस्त कर्मियों का 87.27 प्रतिशत भाग विविध क्रियाओं में कार्यरत पाया गया है। श्रमशक्ति में विविध क्रियाओं का हिस्सा प्रथम श्रेणी के नगरों

में 88.51 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 82.04 प्रतिशत है जिससे वृहत् नगरों में विविध क्रियाओं के संकेन्द्रण का संकेत मिलता है । विविध क्रियाओं में पुरूष कर्मियों का 87.70 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 79.22 प्रतिशत भाग संलग्न है ।

विविध क्रियाओं में श्रमशक्ति का अधिकांश भाग लगा हुआ है किन्तु विभिन्न नगरों में इसके संलग्नता अनुपात में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । रूढ़की के कुल श्रमशक्ति का 97.07 प्रतिशत विविध क्रियाओं मे संलग्न है जबकि मऊनाथ भंजन में यह अनुपात मात्र 33.17 प्रतिशत ही है । श्रमशक्ति में विविध क्रियाओं का हिस्सा सम्भल में 53.70 प्रतिशत, टाण्डा मे 55.01 प्रतिशत और फतेहपुर में 68.80 प्रतिशत है । अन्य नगरों में उक्त अनुपात 70 और 97 प्रतिशत के मध्य पाया जाता है ।

3.5 सीमान्त श्रमिक या कर्मी

उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के नगरों में 11,667 तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 8,748 सीमान्त श्रमिक हैं । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों में कुल 20,415 सीमान्त श्रमिक हैं जिसमें 7,342 पुरूष और 13,073 महिलाये हैं । वृहत् नगरों के कुल जनसंख्या का 0.16 प्रतिशत सीमान्त श्रमिक हैं जबकि यह अनुपात प्रथम श्रेणी के नगरों में 0.11 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी के नगरों मे 0.35 प्रतिशत है । समस्त वृहत् नगरों में 0.11 प्रतिशत पुरूष तथा 0.57 प्रतिशत महिलायें सीमान्त श्रमिक हैं किन्तु प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में यह अनुपात पृथक-पृथक है । प्रथम श्रेणी के नगरों में औसतन 0.12 प्रतिशत पुरूष तथा 0.11 प्रतिशत महिलायें सीमान्त श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के नगरों की पुरूष जनसंख्या और महिला जनसंख्या में सीमान्त श्रमिकों का अनुपात क्रमशः 0.17 तथा 0.57 प्रतिशत है ।

प्रदेश के कतिपय नगरों में सीमान्त श्रमिकों की संख्या अधिक है जबकि अनेक नगरों में इनका महत्त्व नगण्य सा है । संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सीमान्त श्रमिक (2,252) मऊनाथभंजन में हैं जिसके पश्चात् झांसी (1930), लखनऊ (1652), टाण्डा (990), देहरा-दून (896) और नगीना (859) का स्थान है । कुल जनसंख्या में सीमान्त श्रमिकों के प्रतिशत के अनुसार मऊनाथभंजन सर्वोच्च स्थान है जिसकी कुल जनसंख्या में 2.61 प्रतिशत

तालिका 3.3

कुल जनसंख्या में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत तथा सीमान्त श्रमिकों में लिंगानुपात (1981)

क्र0 सं0	नगर	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	महिलायें प्रति हजार पुरुष
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर	0.05	0.07	0.02	220
2.	लखनऊ	0.16	0.27	0.04	122
3.	वाराणसी	0.11	0.09	0.14	1269
4.	आगरा	0.06	0.07	0.05	631
5.	इलाहाबाद	0.07	0.09	0.05	486
6.	मेरठ	0.07	0.10	0.04	366
7.	बरेली	0.12	0.14	0.10	603
8.	मुरादाबाद	0.04	0.04	0.04	683
9.	अलीगढ़	0.09	0.03	0.16	4833
10.	गोरखपुर	0.11	0.12	0.11	777
11.	सहारनपुर	0.05	0.05	0.04	595
12.	देहरादून	0.31	0.39	0.21	427
13.	गाजियाबाद	0.02	0.02	0.02	963
14.	झाँसी	0.68	0.44	0.95	1920
15.	शाहजहाँपुर	0.17	0.19	0.15	697
16.	रामपुर	0.14	0.16	0.12	655
17.	फिरोजाबाद	0.02	0.03	0.02	452
18.	मुजफ्फरनगर	0.04	0.06	0.03	328
19.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	0.04	0.02	0.07	3000
20.	मथुरा	0.09	0.06	0.12	1604
21.	हरद्वार	0.04	0.03	0.04	1038
22.	फैजाबाद	0.36	0.18	0.59	2476
23.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	0.24	0.36	0.11	267
24.	अमरोहा	0.27	0.06	0.50	91
25.	इटावा	0.05	0.04	0.05	1167
26.	सम्भल	0.04	0.04	0.05	1087
27.	जौनपुर	0.29	0.16	0.45	2523
28.	बुलन्दशहर	0.12	0.07	0.17	2306
29.	हापुड़	0.01	0.00	0.03	13000

1	2	3	4	5	6
30.	सीतापुर	0.02	0.02	0.02	900
प्रथम श्रेणी के नगरों का योग		0.11	0.12	0.11	762
31.	बहराइच	0.02	0.02	0.03	1333
32.	बदायूँ	0.08	0.05	0.12	2000
33.	हाथरस	0.02	0.02	0.01	583
34.	रायबरेली	0.53	0.10	1.05	8833
35.	पीलीभीत	0.05	0.09	0.01	24
36.	मोदीनगर	0.01	0.01	0.01	1000
37.	मऊनाथभंजन	2.61	0.41	5.04	11108
38.	फतेहपुर	0.43	0.24	0.65	2376
39.	रुड़की	0.06	0.05	0.07	875
40.	हल्द्वानी-काठगोदाम	0.48	0.65	0.27	340
41.	उन्नाव	0.32	0.25	0.41	1365
42.	बाँदा	0.74	0.59	0.92	1288
43.	गोण्डा	0.03	0.05	-	-
44.	बस्ती	0.29	0.23	0.37	1333
45.	मुगलसराय	0.02	0.02	-	750
46.	हरदोई	0.06	0.02	0.10	4571
47.	खुर्जा	0.07	0.01	0.14	14333
48.	चन्दौसी	0.05	0.07	0.04	458
49.	आजमगढ़	0.54	0.34	0.77	1919
50.	उरई	0.14	0.11	0.17	1244
51.	बाराबंकी	0.01	-	0.01	-
52.	बलिया	0.42	0.53	0.29	466
53.	कासगंज	0.15	0.04	0.28	6750
54.	लखीमपुर	0.02	0.03	0.02	556
55.	गाजीपुर	0.36	0.34	0.39	1009
56.	मैनपुरी	0.06	0.06	0.07	1111
57.	बिजनौर	0.18	0.25	0.11	387
58.	ललितपुर	0.37	0.14	0.62	3976
59.	देवरिया	0.22	0.40	0.26	1161
60.	नजीबाबाद	0.58	0.53	0.63	1065

1	2	3	4	5	6
61.	टाण्डा	1.82	0.46	3.33	6500
62.	एटा	0.11	-	0.22	56000
63.	शामली	0.01	-	0.02	-
64.	काशीपुर	0.21	0.20	0.22	912
65.	देवबन्द	0.18	0.03	0.37	10750
66.	नगीना	1.70	0.24	3.37	12422
द्वितीय श्रेणी के नगरों का योग		0.35	0.17	0.57	2810
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		0.16	0.11	0.23	1781

सीमान्त श्रमिक हैं। दूसरे स्थान पर टाण्डा है जिसकी जनसंख्या में 1.82 प्रतिशत सीमान्त श्रमिक हैं। नगीना में 1.70 प्रतिशत सीमान्त श्रमिक हैं। इन तीन नगरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी नगर में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत 1.00 से अधिक नहीं है। हापुड़, मोदीनगर, बाराबंकी और शामली में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत 0.01 ही है।

ज्ञातव्य है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सीमान्त श्रमिक अधिक हैं क्योंकि बहुत सी महिलायें पूर्णकालिक कर्मी नहीं हैं जिन्हें सीमान्त श्रमिकों के वर्ग में रखा गया है। पुरुष जनसंख्या में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत किसी भी नगर में 1.00 तक नहीं पहुँच सका है। हलद्वानी-काठगोदाम में सर्वाधिक 0.65 प्रतिशत पुरुष सीमान्त श्रमिक हैं। पुरुष जनसंख्या में 0.50 प्रतिशत से अधिक सीमान्त श्रमिक बलिया (0.53), नजीबाबाद (0.53) और बाँदा (0.59) में पाये गये हैं। महिलाओं में सर्वाधिक सीमान्त श्रमिक मऊनाथभंजन में हैं जहाँ 5.04 प्रतिशत महिलायें सीमान्त श्रमिक हैं। टाण्डा में 3.33 प्रतिशत, नगीना में 3.37 प्रतिशत तथा रायबरेली में 1.05 प्रतिशत महिलायें सीमान्त श्रमिक हैं। इन चार नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी नगरों की महिलाओं में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत 1.00 से कम पाया जाता है।

सीमान्त श्रमिकों में महिलाओं की संख्या अधिक है। सीमान्त श्रमिकों में लिंगानुपात के विश्लेषण से कतिपय उल्लेखनीय परिणाम उभर कर सामने आते हैं। एटा के

सीमान्त श्रमिकों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 56000 आती है जो प्रदेश में सर्वोपरि है । इस प्रकार महिलायें पुरुषों की तुलना में 56 गुना अधिक हैं । उक्त लिंगानुपात खुर्जा में 14333, हापुड़ में 13000, नगीना में 12422, मऊनाथभंजन में 11108, देवबन्द में 10750, रायबरेली में 8823, कासगंज में 6750, टाण्डा में 6500, अलीगढ़ में 4833 और ललितपुर में 3976 है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गोण्डा में कोई भी महिला सीमान्त श्रमिक नहीं हैं जबकि बाराबंकी और शामली में कोई भी पुरुष सीमान्त श्रमिक नहीं हैं और एटा में मात्र एक पुरुष ही सीमान्त श्रमिक है ।

3.6 अकर्मी या गैर श्रमिक

प्रथम श्रेणी के नगरों में 7450.25 हजार तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 1809.22 हजार जनसंख्या अनर्जक है जो किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न नहीं है । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों में कुल 9259.47 हजार व्यक्ति अकर्मी हैं और आर्थिक रूप से दूसरे सदस्यों पर निर्भर हैं । इसमें 3646.92 हजार पुरुष तथा 5612.55 हजार महिलायें हैं । इस प्रकार कुल जनसंख्या में 72.90 प्रतिशत अकर्मी हैं । प्रथम श्रेणी के नगरों में यह प्रतिशत 72.85 तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में 73.12 प्रतिशत है । समस्त वृहत् नगरों में 52.79 प्रतिशत पुरुष तथा 96.86 प्रतिशत महिलायें अकर्मी या गैर श्रमिक हैं । अकर्मियों का सर्वाधिक अनुपात पूर्वी नगरों-बलिया और गाजीपुर में अंकित किया गया है जो क्रमशः 76.68 और 76.14 प्रतिशत है । इसके विपरीत न्यूनतम अनुपात रुड़की में पाया गया है जो कुल जनसंख्या का 65.34 प्रतिशत है । मऊनाथभंजन में अकर्मियों का प्रतिशत 65.87 है जो निचले स्तर से द्वितीय सोपान पर है । अन्य नगरों की जनसंख्या में अकर्मियों का अनुपात 69 और 76 प्रतिशत के मध्य पाया जाता है (चित्र 3.1) ।

पुरुष जनसंख्या में अकर्मियों का अधिकतम अनुपात बलिया (59.48 प्रतिशत) में पाया जाता है जिसके पश्चात् गाजीपुर (58.66 प्रतिशत), आजमगढ़ (58.44 प्रतिशत) और उरई (57.98 प्रतिशत) का स्थान है । अकर्मियों का न्यूनतम अनुपात (44.38 प्रतिशत) रुड़की में पाया गया है । महिलाओं में अधिकांश अकर्मी हैं । सम्भल में 98.71

तालिका 3.4

कुल जनसंख्या में अकर्मियों का प्रतिशत तथा अकर्मियों में लिंगानुपात (1981)

क्र० सं०	नगर	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	महिलायें प्रति हजार पुरुष
1	2	3	4	5	6
1.	कानपुर	72.46	52.31	97.54	1499
2.	लखनऊ	72.12	52.11	96.23	1537
3.	वाराणसी	73.51	53.89	96.81	1512
4.	आगरा	73.36	52.16	98.08	1612
5.	इलाहाबाद	74.29	56.13	96.68	1397
6.	मेरठ	71.67	50.15	97.05	1642
7.	बरेली	73.19	52.42	97.52	1589
8.	मुरादाबाद	72.39	50.05	98.43	1688
9.	अलीगढ़	74.89	55.02	97.80	1542
10.	गोरखपुर	72.80	58.11	97.05	1390
11.	सहारनपुर	72.86	51.37	97.85	1639
12.	देहरादून	69.41	48.95	94.93	1556
13.	गाजियाबाद	69.95	48.48	96.68	1565
14.	झाँसी	74.28	57.22	93.37	1458
15.	शाहजहाँपुर	73.43	52.19	98.05	1621
16.	रामपुर	72.20	52.19	97.50	1792
17.	फिरोजाबाद	72.76	51.49	97.88	1609
18.	मुजफ्फरनगर	74.39	53.74	98.00	1595
19.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	70.58	48.45	97.52	1653
20.	मथुरा	72.15	50.88	97.32	1616
21.	हरद्वार	72.81	52.72	97.39	1510
22.	फैजाबाद	70.80	52.06	95.19	1405
23.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	70.34	51.36	96.83	1612
24.	अमरोहा	73.49	53.54	95.88	1596
25.	इटावा	74.30	55.30	96.00	1521
26.	सम्भल	73.67	51.81	98.73	1662
27.	जौनपुर	74.78	56.57	95.59	1478
28.	बुलन्दशहर	74.95	55.35	97.43	1530

1	2	3	4	5	6
29.	हापुड़	74.14	55.90	97.46	1569
30.	सीतापुर	71.20	50.33	96.74	1581
प्रथम श्रेणी के नगरों का योग		72.85	52.57	97.05	1546
31.	बहराइच	74.52	53.77	97.98	1611
32.	बदायूँ	73.89	53.35	97.65	1582
33.	हाथरस	73.99	53.70	98.01	1541
34.	रायबरेली	70.90	50.99	96.31	1525
35.	पीलीभीत	72.84	52.30	97.54	1625
36.	मोदीनगर	71.55	50.40	97.66	1570
37.	मऊनाथभंजन	65.87	54.41	78.56	1303
38.	फतेहपुर	73.81	54.55	95.97	1528
39.	रुड़की	65.34	44.38	95.97	1449
40.	हलद्वानी-काठगोदाम	71.22	50.16	96.89	1584
41.	उन्नाव	73.28	52.91	96.75	1569
42.	बाँदा	73.80	55.27	96.26	1437
43.	गोण्डा	73.77	53.97	97.74	1496
44.	बस्ती	73.42	55.00	95.70	1438
45.	मुगलसराय	75.05	56.05	98.14	1441
46.	हरदोई	73.46	53.78	97.20	1499
47.	खुर्जा	73.92	53.10	97.57	1617
48.	चन्दौसी	74.24	53.53	98.15	1587
49.	आजमगढ़	75.49	58.44	95.64	1386
50.	उरई	75.94	57.98	97.94	1380
51.	बाराबंकी	72.11	51.30	97.47	1557
52.	बलिया	76.68	59.48	96.98	1382
53.	कासगंज	74.75	54.82	97.62	1551
54.	लखीमपुर	74.27	54.03	97.78	1565
55.	गाजीपुर	76.14	58.66	96.16	1431
56.	मैनपुरी	75.15	55.45	98.00	1525
57.	बिजनौर	74.15	54.24	96.94	1561
58.	ललितपुर	72.75	54.03	94.03	1532
59.	देवरिया	75.41	57.31	96.88	1402
60.	नजीबाबाद	73.30	52.02	97.10	1668

1	2	3	4	5	6
61.	टाण्डा	70.74	51.84	88.41	1527
62.	एटा	75.65	56.32	97.74	1519
63.	शामली	72.84	51.69	98.18	1586
64.	काशीपुर	73.22	52.44	97.45	1596
65.	देवबन्द	73.35	53.03	98.22	1513
66.	नगीना	71.47	51.19	94.54	1623
द्वितीय श्रेणी के नगरों का योग		73.12	53.60	96.22	1517
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		72.90	52.79	96.86	1539

प्रतिशत महिलायें अकर्मी हैं जो प्रदेश के अन्य नगरों से अधिक है । आगरा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, हाथरस, मुगलसराय, चन्दौसी, शामली और देवबन्द नगरों में 98.00 प्रतिशत से अधिक महिलायें अकर्मी हैं और आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं हैं । महिला जनसंख्या में अकर्मियों का न्यूनतम प्रतिशत (78.56) मऊनाथभंजन में पाया गया है । उक्त अनुपात टाण्डा में 88.41 प्रतिशत है और अन्य किसी भी नगर में यह 94.00 प्रतिशत से कम नहीं है ।

अकर्मियों या गैर श्रमिकों के लिंगानुपात पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात रामपुर में हैं जहाँ अकर्मियों में प्रति हजार पुरुषों पर 1792 महिलायें हैं । मुरादाबाद (1688), नजीबाबाद (1668), सम्भल (1662), फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ (1653), मेरठ (1642), सहारनपुर (1639), पीलीभीत (1625), नगीना (1623), शाहजहाँपुर (1621), खुर्जा (1617), मथुरा (1616), मिर्जापुर-बिन्ध्याचल (1612), बहराइच (1611) और फिरोजाबाद (1609) नगरों के गैर श्रमिकों में लिंगानुपात 1600 महिलायें प्रति हजार पुरुष से अधिक हैं । न्यूनतम लिंगानुपात (1303) मऊनाथभंजन में पाया गया है जिसके पश्चात् उरई (1380), बलिया (1382), आजमगढ़ (1386), गोरखपुर (1390) और इलाहाबाद (1397) का स्थान है ।

संदर्भ

1. Maurya, S.D. (1988) : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, p. 97.

2. The Gazzetteer of India, Vol. 3, Economic Structure and Activities Ministry of Education and Social Welfare, Govt. of India, New Delhi, 1975; p. 125.

3. Op.cit., fn.1, p.98.

4. Census of India, 1951, Vol.II, Uttar Pradesh, Part 1-A,Report, p.95.

5. Census of India, 1961, Uttar Pradesh, Part II-B (iii), General Economic Tables.

6. Census of India, 1981, Series 22, Uttar Pradesh, Part II-B,Primary Census Abstract.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

————::o::————

संदर्भ

1. Maurya, S.D. (1988) : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, p. 97.

2. The Gazzetteer of India, Vol. 3, Economic Structure and Activities, Ministry of Education and Social Welfare, Govt. of India, New Delhi, 1975; p. 125.

3. Op.cit., fn.1, p.98.

4. Census of India, 1951, Vol.II, Uttar Pradesh, Part 1-A, Report, p.95.

5. Census of India, 1961, Uttar Pradesh, Part II-B (iii), General Economic Tables.

6. Census of India, 1981, Series 22, Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

::o::

अध्याय चार

नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

4.1 भूमिका

नगरीय केन्द्रों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जिनमें स्थल एवं स्थिति, उद्भव एवं आयु, विकास-अवस्था, जनसंख्या आकार, कार्य आदि प्रमुख हैं। अवस्थिति (Location) के आधार पर नगर नदी तटीय, झील तटीय सागर तटीय, पहाड़ी, पठारी, मैदानी आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उद्भव-काल के अनुसार नगरों को प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर आदि श्रेणियों में रखा जाता है। इसी प्रकार विकास-अवस्था के आधार पर नगरों को मानव जीवन की अवस्थाओं की भाँति पूर्व शैशव, शैशव, बाल्य, किशोर, प्रौढ़, उत्तर प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों को आरोही क्रम में नगरीय ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर आदि वर्गों में रखा जाता है।

विविध आधारों पर नगरों के वर्गीकरण की सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उससे नगरीय विशेषता का स्पष्टीकरण किस सीमा तक हो पाता है। इस सन्दर्भ में नगरों का उनकी कार्यात्मक विशिष्टता के आधार पर किया गया वर्गीकरण सर्वाधिक उपयुक्त, तर्कसंगत एवं सार्थक माना जाता है क्योंकि कार्यात्मक विशिष्टीकरण के आधार पर नगरीय केन्द्रों को ग्रामों से पृथक किया जाता है।[1] वास्तव में नगर बहुधंधी (Multi-Functional) होते हैं और उनके आकार में वृद्धि के साथ कार्यात्मक जटिलता भी बढ़ती जाती है। नगर की अन्य विशेषतायें मुख्यतया उसके कार्यात्मक स्वरूप पर आधारित होती हैं। अतः अन्य आधारों की तुलना में कार्यात्मक विशिष्टीकरण नगरों के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मापदण्ड है।

नगरों में कार्यात्मक विविधता पायी जाती है। प्रत्येक बड़े नगर में प्रशासन,

व्यापार, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित क्रियायें विभिन्न अनुपात में पायी जाती हैं। कार्यात्मक वर्गीकरण का उद्देश्य नगर की सर्व प्रमुख क्रिया के आधार पर नगरों को प्रमुख कार्यात्मक-वर्गों में श्रेणीबद्ध करना होता है। इस प्रकार एक नगर को उस कार्यात्मक श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाता है जो उस नगर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। कार्यात्मक वर्गीकरण एकल कार्यात्मक (एक कार्य पर आधारित), द्वि-कार्यात्मक (दो कार्यों पर आधारित), तथा बहुल कार्यात्मक (दो से अधिक कार्यों पर आधारित) हो सकता है जो विशिष्टीकृत कार्यों की संख्या पर आधारित होता है।

4.2 पूर्ववर्ती कार्यात्मक वर्गीकरण

बीसवीं शताब्दी में विशेषरूप से पिछले चार-पाँच दशकों में संसार के विभिन्न देशों एवं प्रदेशों में नगरों के कार्यात्मक अध्ययन किये गये जिनमें भूगोलवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों के प्रयास विशेष उल्लेखनीय हैं। कार्यात्मक विशिष्टीकरण के आधार पर नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। प्रारम्भिक काल में नगरीय वर्गीकरण के प्रयास व्यक्तिगत अनुभवों तथा जानकारियों पर आधारित होते थे किन्तु पिछले चार दशकों में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण क्रमशः मात्रात्मक होता गया और अभिनव वर्षों में किये गये अधिकांश कार्यात्मक वर्गीकरण सांख्यिकीय एवं मात्रात्मक विधियों पर आधारित हैं। अतः नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाली समस्त विधियों को तीन प्रधान वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :

1. गुणात्मक विधियाँ,
2. गुणात्मक-परिमाणात्मक विधियाँ, और
3. परिमाणात्मक विधियाँ।

1. गुणात्मक विधियाँ

इसे परम्परागत या आनुभविक विधि के नाम से भी जाना जाता है जो

व्यक्तिगत अनुभव, ज्ञान, पर्यवेक्षण तथा आकलन पर आधारित है । नगरों के कार्यात्मक विश्लेषण में यह प्रारम्भिक अवस्था की द्योतक है । अनेक लेखकों ने अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षणों और अनुभवों के आधार पर नगरों को विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया है । यह मूलत: आनुभविक एवं असांख्यकीय विधि है ।

इस दिशा में सम्भवत: सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास आरूसो (1921)[2] का है । उन्होंने आनुभविक आधार पर नगरों को सक्रिय एवं निष्क्रिय दो वर्गों में रखा और पुन: सक्रिय नगरों को छ: प्रमुख वर्गों में विभक्त किया : 1. प्रशासनिक, 2. सुरक्षा, 3. सांस्कृतिक, 4. उत्पादक, 5. संचार, और 6. मनोरंजन नगर । उन्होंने प्रत्येक प्रमुख वर्ग को पुन: विभिन्न उपवर्गों में भी वर्गीकृत किया । प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकेंजी (1925)[3] ने आरूसो की भाँति ही अमेरिकी समुदायों को चार प्रधान श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया, जो इस प्रकार है : 1. प्राथमिक सेवा केन्द्र, 2. वाणिज्य केन्द्र, 3. औद्योगिक केन्द्र, और 4. अन्य केन्द्र (इसमें मनोरंजन तथा विश्राम केन्द्र भी सम्मिलित हैं जो उपर्युक्त तीनों कार्यों में से किसी भी कार्य में विशिष्टीकरण नहीं रखते) ।

जेम्स (1930)[4] ने भारतीय नगरों को छ: वर्गों में विभक्त किया : 1. राजधानी नगर, 2. धार्मिक नगर, 3. विनिर्माण नगर, 4. सैन्य केन्द्र, 5. आन्तरिक बाजार, और 6. समुद्र पत्तन । हाल (1934)[5] ने विभिन्न जापानी नगरों के विकास का अध्ययन किया और उन्हें चार वर्गों के अन्तर्गत रखा : 1. किला ~~(कौठिल)~~ नगर जो सुरक्षा एवं प्रशासन के केन्द्र थे, 2. मन्दिर एवं धार्मिक नगर, 3. वाणिज्य नगर, और 4. आधुनिक औद्योगिक-व्यापारिक नगर । वीमर और होयट (1939)[6] ने रोजगार स्रोतों पर विचार करते हुए नगरों को औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, मनोरंजन या स्वास्थ्य, विश्राम तथा शिक्षा केन्द्रों में विभक्त किया है । ट्रिवार्था (1952)[7] ने चीनी नगरों के विश्लेषण में उन्हें उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया । जिस्ट और हलबर्ट (1954)[8] ने आरूसो का अनुसरण करते हुए नगरों का वर्गीकरण प्रस्तुत

किया । किन्तु उन्होंने 'विविधीकृत नगर' के एक नवीन वर्ग को भी सम्मिलित किया जो किसी भी कार्य में विशिष्टीकृत नहीं थे । इस सन्दर्भ में रीस (1942-44)[9], मिन्द्स एवं खोरेव (1959)[10] तथा हान्स (1960)[11] द्वारा किये गये अध्ययन भी महत्वपूर्ण हैं ।

गुणात्मक विधियों के अन्तर्गत वर्णित नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरणों का सर्व-प्रथम दोष उनमें निहित व्यक्तिनिष्ठता की प्रधानता है । ये विधियाँ विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अनुभवों, विश्वास एवं दृष्टिकोणों तथा सामान्य पर्यवेक्षणों पर आधारित हैं जिसके परिणामस्वरूप एक नगर का कार्यात्मक वर्ग विभिन्न अध्ययनकर्त्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है । किन्तु कार्यात्मक वर्गीकरण की प्रारम्भिक विधि के रूप में यह विश्लेषणात्मक विधि कम महत्वपूर्ण नहीं है ।[12]

2. <u>गुणात्मक-परिमाणात्मक विधियाँ</u>

इस वर्ग में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों विधियाँ सम्मिलित होती हैं । नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु उनके रोजगार या कार्यात्मक जनसंख्या से सम्बन्धित आँकड़ों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, किन्तु कुछ ऐसे कार्यों जिनके विषय में उपयुक्त आँकड़े उपलब्ध नहीं होते व्यक्तिगत पर्यवेक्षणों का भी प्राश्रय लिया जाता है । इसी प्रकार किसी कार्यविशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा का निर्धारण भी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो सकता है । इस प्रकार यह विधि परिमाणात्मक होने के साथ ही गुणात्मक विशेषताओं से भी संयुक्त है ।

ऑगबर्न (1937)[13] ने व्यापार, विनिर्माण तथा परिवहन में संलग्न जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इस प्रकार नगरीय भूगोल के प्रारम्भिक अवस्था में सांख्यकीय वर्णनों पर आधारित अध्ययन पाये जा सकते हैं किन्तु इसका सर्वाधिक मान्य एवं महत्वपूर्ण उदाहरण हैरिस (1943)[14] द्वारा प्रस्तुत विधि है जिसका प्रयोग उन्होंने अमेरिका के नगरों के कार्यात्मक वर्गी-करण हेतु किया ।

हैरिस के अनुसार समस्त नगर ॥सिटी॥ कमोवेश मात्रा में बहु-कार्यात्मक होते हैं। उन्होंने अपने कार्यात्मक वर्गीकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित किया। हैरिस ने कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु जिन नगरों का चयन किया वे राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि कार्यात्मक इकाई थे। वर्गीकरण हेतु चयनित 988 नगर 605 कार्यात्मक इकाइयों के अन्तर्गत सम्मिलित थे। हैरिस ने वर्गीकरण के लिए नगरों के नौ प्रमुख प्रकारों को स्वीकार किया और प्रत्येक को उनके अंग्रेजी शब्द के प्रथम वर्ण ॥कुछ को अन्य वर्णों॥ से व्यक्त किया : 1. विनिर्माण नगर (Manufacturing cities-M' और M), 2. फुटकर व्यापार केन्द्र (Retail Centres-R), 3. विविधीकृत नगर (Diversified Cities-D) 4. थोक व्यापार केन्द्र (Wholesale Centres-W), 5. परिवहन केन्द्र (Transportation Centres-T) 6. उत्खनन नगर (Mining towns-S), 7. विश्वविद्यालय नगर (University towns-E), 8. विश्राम एवं अवकाश प्राप्त नगर (Resort and retirement towns-X और 9. अन्य प्रकार के नगर (Other types of cities including political - P).

प्रत्येक नगर में प्रधान कार्यों के निर्धारण हेतु हैरिस ने दो प्रकार के आकड़ों- व्यावसायिक आकड़ों तथा रोजगार आँकड़ों का प्रयोग किया। तुलनात्मक सुगमता हेतु उन्होंने सम्पूर्ण आँकड़ों को प्रतिशत में परिवर्तित किया और व्यवसाय को कुल कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में और रोजगार को विनिर्माण, थोक एवं फुटकर व्यापार में संलग्न कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में परिलक्षित किया। हैरिस ने व्यक्तिनिष्ठ आधार पर विभिन्न कार्यात्मक - वर्गों के लिए न्यूनतम दक्षता प्रतिशत का निर्धारण किया जो एक कार्यात्मक-वर्ग से दूसरे कार्यात्मक-वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न थे। उदाहरणार्थ, एक नगर को विनिर्माण M उप प्रकार के अन्तर्गत तभी रखा जा सकता है जबकि उसके विनिर्माण, थोक एवं फुटकर व्यापार में संयुक्त रूप से संलग्न कुल रोजगार का कम से कम 70 प्रतिशत विनिर्माण में लगा हो। इसके साथ ही कुल कार्यशील जनसंख्या का 30 से 45 प्रतिशत विनिर्माण तथा यांत्रिक उद्योगों में संलग्न होना चाहिए। फुटकर व्यापार केन्द्र के रूप में वर्गीकृत होने के लिए किसी

नगर के विनिर्माण, थोक एवं फुटकर व्यापार में कार्यरत कुल रोजगार का न्यूनतम 50 प्रतिशत फुटकर व्यापार में संलग्न होना आवश्यक माना गया है और इसके साथ ही यह अकेले थोकव्यापार में संलग्न रोजगार का कम से कम 2.2 गुना होना चाहिए । इसी प्रकार नगरों के अन्य कार्यात्मक श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रतिशत का निर्धारण हैरिस ने अपने व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार किया ।

नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की हैरिस की विधि का प्रयोग अनेक शोध-कर्त्ताओं ने कतिपय संशोधनों के साथ किया जिनमें नीडलर ओहल्सन §1945§[15], विक्टर जोन्स §1954§[16] और हार्ट §1955§[17] के कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं । हार्ट ने 1950 के व्यावसायिक आँकड़ों के आधार पर अमेरिका के दक्षिणी नगरों को 11 वर्गों में विभक्त किया । उन्होंने नगरों के दो अतिरिक्त वर्ग बनाये - व्यावसायिक केन्द्र और सैन्य केन्द्र । हैरिस की भाँति हार्ट ने भी विभिन्न कार्यों के लिये पृथक-पृथक न्यूनतम प्रतिशत का निर्धारण किया । इसी प्रकार डंकन एवं रीस §1956§[18] ने समुदायों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण का अध्ययन किया । उन्होंने विशिष्टीकरण के मापदण्ड के रूप में ऊपरी दशमक या शतमक वर्गों के न्यूनतम मूल्य का प्रयोग किया किन्तु यह विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न था । इस प्रकार डंकन एवं रीस की कार्यात्मक योजना मुख्यतया सांख्यकीय विश्लेषण पर आधारित है किन्तु विच्छेद विन्दु के रूप में दशमक का चुनाव नि:संदेह व्यक्तिनिष्ठ एवं काल्पनिक है ।

उपरोक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की इस वर्ग की विधियों के अन्तर्गत मुख्यत: व्यावसायिक अथवा रोजगार आँकड़ों का प्रयोग किया गया है किन्तु एक नगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण हेतु प्रयुक्त मापदण्ड या न्यूनतम सीमा का चुनाव व्यक्तिगत अनुभवों एवं कल्पनाओं पर आधारित है । अत: इन मापदण्डों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों के लिए उसी रूप में सुगमता से नहीं किया जा सकता ।

3. परिमाणात्मक विधियाँ

ये विधियाँ पूर्ण रूप से आँकड़ों पर आधारित हैं और इनमें मापदण्ड का चुनाव

सांख्यकीय अथवा गणितीय विधियों द्वारा किया जाता है । इसमें व्यक्तिनिष्ठता एवं व्यक्तिगत पक्षपात का सर्वथा अभाव रहता है और इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से किया जा सकता है । इस विधि में प्रयुक्त मापदण्ड सर्वाधिक विश्वसनीय, निश्चित और सुबोध होते हैं ।

1939 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 'राजनीतिक एवं आर्थिक नियोजन' (PEP)[19] ने एक नगर के प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग हेतु अवस्थिति लब्धि (Location Quotient) का परिकलन किया । एक नगर के एक कार्यात्मक वर्ग में संलग्न जनसंख्या के प्रतिशत को नगरों के औसत रोजगार से विभाजित करके उसमें 100 से गुणा करने पर अवस्थिति लब्धि प्राप्त हो जाती है । इस विधि के अनुसार, एक नगर जिसकी अवस्थिति लब्धि 100 थी 'औसत नगर' माना गया । इस प्रकार नगरों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया : 1. न्यूनतम विशिष्टीकृत (अवस्थिति लब्धि 110-129), 2. विशिष्टीकृत (130-149), 3. अधिक विशिष्टीकृत (150-169), और 4. अत्यधिक विशिष्टीकृत (170 और ऊपर) ।

इस सन्दर्भ में पावनाल (1953)[20] का कार्य विशेष उल्लेखनीय है जिन्होंने न्यूजीलैण्ड के नगरों के कार्यों के अध्ययन में गणितीय माध्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उन्होंने नगरों को 7 आकार-वर्गों में रखकर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक औसत रोजगार का परिकलन किया और अपने संदर्भित वर्ग के राष्ट्रीय माध्य से नगरों के धनात्मक विचलन को ज्ञात किया । पावनाल के अनुसार, इन राष्ट्रीय माध्यों (औसतों) से धनात्मक विचलनों को 6 विभिन्न कार्यों के तुलनात्मक महत्व के स्पष्टीकरण हेतु मापदण्ड के रूप में लिया गया है । उनके 6 कार्यात्मक वर्ग हैं : 1. विनिर्माण, 2. भवन एवं निर्माण, 3. प्राथमिक उद्योग, 4. परिवहन एवं संचार, 5. वितरण, वित्तीय, होटल एवं व्यक्तिगत सेवायें, और 6. प्रशासन एवं व्यावसायिक सेवायें । सातवाँ वर्ग (आवासीय कार्य) आर्थिक रूप से संलग्न व्यक्तियों और कुल जनसंख्या के अनुपात पर आधारित है । इस प्रकार एक नगर एक से अधिक कार्यों में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है ।

नेल्सन (1955)[21] ने 'अमेरिकी नगरों के सेवा वर्गीकरण' की अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं तार्किक योजना प्रस्तुत किया । उन्होंने किसी नगर के श्रमशक्ति के उस अनुपात को जो किसी क्रिया के सम्पादनार्थ संलग्न होता है उक्त क्रिया के वितरण के मापन का सर्वोत्तम साधन माना । नेल्सन ने मानक महानगरीय क्षेत्र, नगरीकृत क्षेत्र एवं 10,000 जनसंख्या या अधिक के नगरीय स्थलों के लिए '1950 सेंसस आफ पापुलेशन' में सूचीबद्ध वृहद् उद्योग समूहों को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया । इस प्रकार 897 नगरीय समूहों (प्रत्येक की जनसंख्या 10,000 या अधिक) को सेवा वर्गीकरण हेतु चुना गया । उन्होंने 9 वृहद् उद्योग समूहों का चुनाव किया और प्रत्येक नगर में उसकी कुल श्रमशक्ति में पृथक-पृथक क्रियाओं के प्रतिशत का परिकलन किया । इसी प्रकार 897 नगरों की कुल श्रमशक्ति में चयनित प्रत्येक क्रिया-वर्ग के प्रतिशत (गणितीय माध्य) की भी गणना किया । विभिन्न क्रिया-समूहों में औसत रोजगार (गणितीय माध्य) में पर्याप्त भिन्नता पायी गयी जो न्यूनतम 1.62 प्रतिशत (उत्खनन) से लेकर अधिकतम 27.07 प्रतिशत (विनिर्माण) थी ।

नेल्सन ने देखा कि एक क्रिया-समूह में संलग्न रोजगार के प्रतिशत में एक नगर से दूसरे नगर में अत्यधिक भिन्नता पायी जाती है । अतः इन विचलनों के मापन हेतु उन्होंने मानक विचलन (Standard Deviation) का चयन किया जो विचलन के सभी सांख्यकीय मापदण्डों में सम्भवतः सर्वाधिक सरल और अधिकतम बोधगम्य है । इस प्रकार 9 में से प्रत्येक क्रिया-समूह के लिए पृथक-पृथक मानक विचलन (गणितीय माध्य से) का परिकलन किया गया और विचलनों को गणितीय माध्य से 3 मानक विचलन तक मापा गया और प्रत्येक नगर को उपयुक्त कार्यात्मक-वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया । हैरिस की भाँति नेल्सन ने भी प्रत्येक क्रिया-समूह के लिए अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया । उदाहरणार्थ विनिर्माण में माध्य + 1 मानक विचलन से ऊपर कार्यात्मक प्रतिशत रखने वाले नगर को विनिर्माण 1 (Mf1) श्रेणी, 2 मानक विचलन से अधिक वाले नगर को विनिर्माण 2 (Mf_2) और 3 या अधिक मानक विचलन वाले नगर को विनिर्माण 3 (Mf_3) की श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया । इसी प्रकार अन्य

क्रिया समूहों के लिए भी समान विधि या प्रक्रिया अपनायी गयी और नगरों का क्र कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया ।

नेल्सन के सेवा वर्गीकरण में अनेक नगर ऐसे थे जो एक से अधिक कार्यों में विशिष्टीकरण रखते थे जबकि बहुत से नगर 9 क्रिया समूहों में से किसी में भी वर्गीकृत नहीं किये जा सके क्योंकि किसी भी कार्य में वे माध्य + 1 मानक विचलन से नीचे ही थे । इस प्रकार केअवर्गीकृत नगरों के लिए नेल्सन ने एक नये वर्ग-विविधीकृत (Diversified-D) का सृजन किया । नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की नेल्सन के ही समान विधि का प्रयोग स्टीगेंगा[22] ने उसी वर्ष ‡1955‡ नीदर लैण्ड के नगरों के वर्गीकरण हेतु किया । अतः नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की इस मानक विचलन विधि को नेल्सन-स्टीगेंगा विधि के नाम से भी जाना जाता है ।

क्वींसलैण्ड ‡आस्ट्रेलिया‡ के डार्लिंग डाउन्स के केन्द्रस्थलों की व्यावसायिक संरचना में भिन्नता पर कार्य करते हुए डिक ‡1961‡[23] ने नेल्सन के समान विधि का उपयोग किया किन्तु उन्होंने कार्यात्मक विशिष्टीकरण की श्रेणी निर्धारण में मानक -विचलन के साथ ही उक्त क्रिया के प्रतिशत रोजगार को भी अंकित करना उचित समझा। उदाहरणार्थ, उत्खनन में कुल श्रम शक्ति का 20 प्रतिशत एवं माध्य से 2 मानक विचलन वाले नगर को उत्खनन 20 + 2 (Mi^{20+2}) वर्ग के अन्तर्गत रखा गया ।

जॉन वेब ‡1959‡[24] ने मिनेसोटा ‡सं0रा0अ0‡ में नगरीय केन्द्रों के कार्यात्मक वर्गीकरण में दो सूचकांकों - कार्यात्मक सूचकांक और विशिष्टीकरण सूचकांक का प्रयोग किया । उनके कार्यात्मक सूचकांक का परिकलन निम्नांकित सूत्र द्वारा किया जा सकता है :

$$\text{कार्यात्मक सूचकांक} = \frac{P}{Mp} P$$

जबकि, P = एक कार्य में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ।

Mp = नगरीय समूह के समस्त नगरों में उक्त कार्य में रोजगार का औसत ।

विशिष्टीकरण सूचकांक के परिकलन में एक नगर के समस्त कार्यात्मक सूचकांकों के योग को 100 से विभाजित किया जाता है। विशिष्टीकरण सूचकांक के आधार पर जॉन वेब ने नगरीय केन्द्रों को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जिनमें प्रथम वर्ग न्यूनतम विशिष्टीकृत और सातवाँ वर्ग अत्यधिक विशिष्टीकृत नगरों का है। इनके मध्य, पाँच अन्य विशिष्टीकरण की श्रेणियाँ हैं। प्रथम से छठीं श्रेणी तक की ऊपरी सीमाओं के विशिष्टीकरण सूचकांक क्रमशः 1.10, 1.20, 1.40, 1.80, 2.60 और 4.20 हैं।

नगरों में श्रमशक्ति या रोजगार में मौलिक या अतिरेक अनुपात के मापन हेतु प्रयुक्त विधियों का प्रयोग अनेक लेखकों ने नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में भी किया है। किसी नगर में रोजगार की आवश्यक मात्रा से अधिक (या अतिरेक) रोजगार को विशिष्टीकरण का सूचक माना जाता है। इस सन्दर्भ में अलक्जैण्डर (1954)[25], मैटीला एवं थाम्पसन (1955)[26] और अलक्जैण्डरसन (1956)[27] द्वारा किये गये अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैटीला एवं थाम्पसन ने नगरीय केन्द्रों के कार्यों के महत्व के मूल्यांकन हेतु एक नवीन विधि का प्रयोग किया। उन्होंने राष्ट्रीय या प्रादेशिक औसत से ऊपर अतिरेक श्रमिकों के सूचकांक का परिकलन किया और एक नगर के कार्यात्मक अतिरेक और कुल अतिरेक रोजगार के अनुपात के आधार पर नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की एक नवीन विधि प्रस्तुत की। इसी प्रकार मैक्सवेल (1965)[28] ने न्यूनतम आवश्यकता उपागम के आधार पर कुल श्रमशक्ति से मौलिक श्रमशक्ति को अलग किया और कनाडा के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया।

बहुचर विश्लेषण में प्रोन्नति तथा आधुनिक कम्प्यूटर के प्रयोग द्वारा पिछले 20-25 वर्षों में नगरीय भूगोलवेत्ताओं ने नगरीय विशेषताओं के अध्ययन में अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर ली है। अब नगरों के सूक्ष्मदर्शी वर्गीकरणों हेतु नगर निवासियों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के साथ नगरीय स्थान की भौतिक विशेषताओं (लक्षणों) को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। इस दिशा में मोसर एवं स्कार्ट (1961)[29] का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है जिन्होंने तथ्य विश्लेषण (सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय विशेषताओं) के आधार पर ब्रिटेन के 157 नगरों का कार्यात्मक

वर्गीकरण प्रस्तुत किया । उन्होंने 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों पर कार्य किया और अपने विश्लेषण हेतु 57 चरों का चयन किया जिन्हें 8 वर्गों के अन्तर्गत रखा गया : 1. जनसंख्या आकार एवं संरचना, 2. जनसंख्या परिवर्तन, 3. परिवार एवं बसाव 4. आर्थिक विशेषता, 5. सामाजिक वर्ग, 6. मतदान विशेषतायें, 7. स्वास्थ्य, और 8. शिक्षा । इस प्रकार मोसर एवं स्काट ने नगरों को तीन वृहत् श्रेणियों में विभक्त किया : 1. मुख्यत: मनोरंजन, प्रशासनिक एवं वाणिज्य नगर, 2. मुख्यत: औद्योगिक नगर, और 3. उपनगर एवं उपनगरीय प्रकार के नगर ।

हैडन और बारगाटा (1965)[30] ने अमेरिकी नगरों के अध्ययन में नगरीय विशेषता के विश्लेषण हेतु 65 चरों का उपयोग किया । उन्होने विभिन्न नगरीय आकार के लिये पृथक-पृथक विश्लेषण किये । विस्तृत सांख्यकीय विश्लेषण के पश्चात् उन्होने नगरों के सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षणों के स्पष्टीकरण हेतु मैट्रिक्स से प्राप्त 16 कारकों का उपयोग किया । इसी प्रकार स्मिथ (1965)[31] ने बहुचरीय विश्लेषण के आधार पर 422 आस्ट्रेलियायी नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया । उन्होंने रोजगार आकड़े के सहसम्बन्ध का विश्लेषण करके 91 प्राथमिक वर्गों का निर्धारण किया। सह सम्बन्ध मैट्रिक्स के वर्ग-विश्लेषण के आधार पर उन्होने 17 कार्यात्मक श्रेणियाँ प्राप्त किया ।

बेरी (1972)[32] ने संयुक्त राज्य के 1762 नगरों का कार्यात्मक विश्लेषण किया जिसे उन्होने 'अमेरिकी नगरीय तन्त्र की गुप्त संरचना' की संज्ञा दी । बेरी ने 1762 अमेरिकी नगरों का 97 चरों के आँकड़ा मैट्रिक्स द्वारा कारक विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कारकों में सहसम्बन्ध न हो तो नगरीय केन्द्रों के आर्थिक आधार में नगरीय संरचनात्मक तथ्यों से स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति पायी जाती है ।

उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त अनेक भूगोलवेत्ताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने भी नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के विधितंत्रकी दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये हैं ।

4.3 प्रमुख भारतीय वर्गीकरण

भारत में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के प्रयास का आरम्भ वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्द्ध से होता है । अनेक शोधकर्त्ताओं एवं लेखकों ने भारत तथा इसके विभिन्न प्रदेशों के नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें अधिकांशने विदेशी लेखकों द्वारा अपनायी गयी विधियों का अनुशरण किया है । भारतीय जनगणना आयोग (1971) ने नगरों को 5 कार्यात्मक वर्गों में विभक्त किया है[23] : 1. प्राथमिक क्रियायें, 2. उद्योग, 3. व्यापार एवं वाणिज्य 4. परिवहन, और 5. सेवायें । इसके लिए प्रत्येक नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या में उपरोक्त कार्यों में संलग्न जनसंख्या के प्रतिशत का परिकलन किया गया है और किसी एक कार्यात्मक वर्ग के अन्तर्गत कुल कार्यशील जनसंख्या का 40 प्रतिशत या अधिक होने पर उसे एकल कार्यात्मक माना गया है । दूसरे विषय में दूसरे प्रमुख कार्यात्मक वर्ग को लिया गया है और इस प्रकार दोनों क्रियाओं का प्रतिशत 60 प्रतिशत या अधिक होने पर उसे द्वि-कार्यात्मक की श्रेणी में रखा गया है । यदि दो प्रमुख क्रियाओं का योग 60 प्रतिशत से कम रह जाता है तो तीसरी प्रमुख क्रिया को भी सम्मिलित कर लिया गया है और नगर को बहु-कार्यात्मक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । ~~कार्यों के बहु-कार्यात्मक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है~~ । कार्यों के तुलनात्मक महत्व को कुल कार्यशील जनसंख्या में उनके प्रतिशत द्वारा निश्चित किया गया है ।

वी0नाथ[34] ने 1954 में भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी वर्ष जानकी (1954)[35] ने केरल के नगरों को कार्यात्मक वर्गों में विभक्त किया और नगरों के कार्यों तथा विकास पर भौतिक और आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया । उन्होंने नगरों को 5 कार्यात्मक श्रेणियों के अन्तर्गत रखा- 1. प्रशासनिक केन्द्र, 2. वाणिज्य एवं औद्योगिक नगर, 3. कृषि, एकत्रण, वितरण का बाजार नगर, 4. मन्दिर नगर और 5. उद्यान नगर । अमृत लाल (1959)[36] ने नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण के स्तर के निर्धारण में माध्यिका (median) को मापदण्ड माना और ब्रिटिश राजनीतिक एवं आर्थिक नियोजन (PEP) द्वारा प्रयुक्त विधि का अनुकरण किया ।

नेल्सन की विधि का प्रयोग करते हुए काशीनाथ सिंह (1959)[37] ने उत्तर प्रदेश के नगरों का और गांगुली (1965)[38] ने 250 भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किये। प्रकाश राव (1962)[39] ने नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु अल्पतम वर्ग रैखिक समाश्रयण विधि के प्रयोग का सुझाव दिया। रफी उल्लाह (1965)[40] ने कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए एक नवीन उपागम प्रस्तुत किया जो वीबर[41] द्वारा मध्य पूर्व में शस्य-साहचर्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त विधि का संशोधित रूप है। इसे उन्होंने 'अधिकतम धनात्मक विचलन विधि' की संज्ञा प्रदान की है। काजी अहमद (1965)[42] ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 102 भारतीय नगरों की विशेषताओं का अध्ययन बहुचरीय विधि के आधार पर किया।

महामाया मुखर्जी[43] ने बिहार के नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में दो सूचकांकों का प्रयोग किया- 1. कार्यात्मक सूचकांक, और 2. विशिष्टीकरण सूचकांक। कार्यात्मक सूचकांक का परिकलन निम्नांकित सूत्र से किया गया है।

$$\text{कार्यात्मक सूचकांक} = \frac{ei - \frac{et.\,Ei}{Et}}{\frac{et.Ei}{Et}} \times \frac{ei}{et} \times 100$$

जबकि ei = स्थानीय कार्यात्मक रोजगार,

et = स्थानीय कुल रोजगार

Ei = राज्य का कार्यात्मक रोजगार,

$Et.$ = राज्य का कुल रोजगार।

एक नगर के समस्त कार्यात्मक सूचकांकों का योग उसका विशिष्टीकरण सूचकांक होगा। विशिष्टीकरण सूचकांक के आधार पर नगरों को 8 विशिष्टीकृत वर्गों में विभक्त किया गया है।

ओम प्रकाश सिंह (1968)[44] ने उत्तर प्रदेश के केन्द्रस्थलों के कार्यात्मक वर्गीकरण में दो प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग किया- 1. कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक

और 2. कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक (F.C.I.)। इनमें प्रथम का प्रयोग विशिष्टीकरण के निर्धारण हेतु और द्वितीय का प्रयोग पदानुक्रम के निर्धारण हेतु किया गया है। ये दोनों सूचकांक निम्नांकित सूत्र से ज्ञात किये जा सकते हैं :

(अ) आकार सूचकांक (S.I.) = $\frac{Cr. 100}{Rs}$

(ब) कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक (F.C.I) = $\frac{Cf. 100}{Rf}$

(स) कार्यात्मक विशिष्टीकरण लब्धि (F.S.Q) = $\frac{F.C.I.}{S.I.}$

(द) कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (F.S.I) = F.S.Q x Mf

जबकि,

Cf = केन्द्र की कार्यात्मक जनसंख्या

Rf = प्रदेश की कार्यात्मक जनसंख्या

Cr = केन्द्र की कुल जनसंख्या

Rs = प्रदेश की कुल जनसंख्या, और

Mf = प्रदेश में केन्द्र का औसत कार्यात्मक प्रतिशत।

मानक विचलन के आधार पर 5 विशिष्टीकरण वर्ग निर्धारित किये गये हैं : 1. 1 मानक विचलन के समीपी केन्द्र, 2. 1 मानक विचलन और अधिक, 3. 2 मानक विचलन और अधिक, 4. 3 मानक विचलन और अधिक, और 5. 4 मानक विचलन और अधिक। प्रत्येक कार्य में केन्द्रस्थलों के पदानुक्रमीय-वर्ग निर्धारण के लिए कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक (F.C.I) मूल्यों को अवरोही क्रम में रखा गया है और उन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित किया गया है। उनके विच्छेद बिन्दु या अन्तरण के आधार पर केन्द्रस्थलों का कार्यात्मक पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। इस वर्गीकरण की सर्वप्रमुख विशेषता है कार्यात्मक विशिष्टीकरण के साथ ही प्रदेश में केन्द्रस्थल के स्थान (पदानुक्रम) का निर्धारण जिस पर पूर्ववर्ती वर्गीकरणों में ध्यान नहीं दिया गया है।

आर०एन० सिंह और साहबदीन (1976)[45] ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण में कार्यात्मक विशिष्टीकरण और प्रादेशिक पदानुक्रम दोनों को साथ-साथ अपनाया । कार्यात्मक विशिष्टीकरण के निर्धारण हेतु कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक और पदानुक्रम निर्धारण हेतु कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक का परिकलन किया गया । उन्होने नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु नेल्सन की मानक विचलन विधि का प्रयोग किया किन्तु विशिष्टीकरण की न्यूनतम सीमा प्रादेशिक औसत को माना और नगरों को 4 विशिष्टीकरण वर्गों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया : 1. प्रादेशिक माध्य से ऊपर, 2. माध्य + 1 मानक विचलन, 3. माध्य + 2 मानक विचलन, 4. माध्य + 3 मानक विचलन और अधिक । कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक की गणना निम्नांकित सूत्र से की गयी है :

कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक $(Si) = 100\ e/w$

जहाँ, e = एक नगर में एक क्रिया में संलग्न जनसंख्या,

w = नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या

नगरों के प्रादेशिक पदानुक्रम निर्धारण हेतु केन्द्रीयता सूचकांक के परिकलन का सूत्र निम्नवत है :

कार्यात्मक केन्द्रीयता सूचकांक $(F.C.I) = r\ Si/\overline{Si}$

जबकि,

r = प्रादेशिक अनुपात सूचकांक = $100\ e/\Sigma e$

Si = कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक = $100\ e/w$

$\overline{Si}$ = प्रदेश के समस्त नगरों के Si का औसत = $100\ \Sigma e/\Sigma w$

e = अमुक कार्य में संलग्न नगर की कुल जनसंख्या ।

Σe = उक्त कार्य में संलग्न प्रदेश की कुल जनसंख्या,

w = नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या,

Σw = प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या ।

उपर्युक्त सूत्र द्वारा परिकलित केन्द्रीयता सूचकांकों का औसत और उससे मानक विचलनों की गणना की गयी है। इस प्रकार नगरों को 5 कार्यात्मक पदानुक्रम के अन्तर्गत रखा गया है: 1. प्रादेशिक राजधानी (3 मा0वि0 और अधिक), 2. प्रादेशिक केन्द्र (2 मा0वि0 और अधिक), 3. उप प्रादेशिक केन्द्र (1 मा0वि0 और अधिक), 4. परिस्थानीय केन्द्र (माध्य से ऊपर), और 5. स्थानीय केन्द्र (माध्य और उससे कम)।

भारतीय नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की दिशा में उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अनेक अन्य शोध अध्येताओं ने भी उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। उनमें एन0 अनन्तपद्मनाभन (1965)[46], एन0पी0 सक्सेना (1966)[47], ओंकार सिंह (1969)[48], एम0एन0 वासन्ता देवी (1969)[49], आर0आर0 त्रिपाठी (1970)[50], ए0 मित्रा (1972)[51], आर0पी0 सिंह एवं एम0पी0 दब्राल (1972)[52], आर0बी0 सिंह एवं सी0डी0 सिंह (1977)[53], पी0सी0 अग्रवाल एवं जेड0 टी0 खान (1979)[54], राम प्यारे (1980)[55] आदि द्वारा प्रस्तुत नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण उल्लेखनीय हैं।

4.4 वर्तमान वर्गीकरण

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। भारतीय जनगणना 1981 जो व्यावसायिक जनसंख्या सम्बन्धी समंकों का एकमात्र स्रोत है, में नगरीय क्रियात्मक वर्गों को निकाल दिया गया है और क्रियाशील जनसंख्या को केवल चार वृहत् वर्गों में विभक्त किया गया है जो नगरीय व्यावसायिक संरचना को प्रस्तुत नहीं करते। जनगणना 1971 में सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्या को नौ क्रिया-वर्गों में विभक्त किया गया है: 1. कृषक, 2. कृषि श्रमिक, 3. पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्य पालन, आखेट, उद्यान आदि में कार्यरत, 4. उत्खनन में कार्यरत, 5. गृह उद्योग, और गैर गृह उद्योग में कार्यरत 6. निर्माण कार्य में संलग्न 7. व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत, 8. परिवहन, संग्रह एवं संचार में संलग्न और 9. अन्य सेवाओं में कार्यरत। अतः नगरों के व्यावसायिक संरचना से सम्बद्ध उपलब्ध समंकों को ध्यान में रखते हुए 1981 जनगणना के प्रथम

एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 66 नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु 1971 जनगणना के समंकों को ही आधार बनाया गया है ।

1971 जनगणना के प्रथम चार क्रिया-वर्गों को उनकी प्रकृति के आधार पर एक ही वर्ग 'प्राथमिक क्रियायें' के अन्तर्गत रखा गया है और पंचम वर्ग के दो विभागों गृह उद्योग और गैर गृह उद्योग से सम्बन्धित कर्मियों का पृथक्-पृथक संख्या प्राप्त होने तथा उनकी प्रकृति में भिन्नता के कारण दोनों को दो स्वतंत्र क्रिया-वर्ग माना गया है । जनगणना के शेष क्रिया-वर्गों को उसी रूप में समाहित किया गया है यद्यपि उनके नाम में संशोधन किया गया है । इस प्रकार कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु चयनित (पुन: संगठित) 7 क्रिया-वर्ग इस प्रकार हैं :

1. प्राथमिक क्रियायें (Primary Activity)
2. गृह उद्योग (Household Industry)
3. विनिर्माण उद्योग (Manufacturing Industry)
4. निर्माण कार्य (Construction)
5. व्यापार एवं वाणिज्य (Trade & Commerce)
6. परिवहन एवं संचार (Transport & Communication)
7. सेवायें (Services)

1. वर्गीकरण की विधि एवं प्रक्रिया

नगरीय केन्द्र प्राय: बहुधंधी होते हैं जो विविध कार्यों को सम्पादित करते हैं जिनमें कोई एक या कुछ क्रियायें सर्वाधिक प्रभावी तथा महत्वपूर्ण होती हैं जिन्हें उनका मुख्य कार्य माना जा सकता है । कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु आर०एन० सिंह एवं साहबदीन (1976) द्वारा प्रयुक्त कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (Functional Specialization Index) का परिकलन किया गया है । यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रथम (30) एवं द्वितीय (36) श्रेणी के कुल 66 नगरों के सात क्रिया-वर्गों के लिए कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक को निम्नांकित सूत्र द्वारा परिकलित किया गया है :

तालिका 4.1

कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (का वि सू) के परिकलन की विधि

क्र० सं०	कार्यात्मक वर्ग	इलाहाबाद		मोदीनगर	
		कार्यशील जनसंख्या	का० वि० सूचकांक	कार्यशील जनसंख्या	का० वि० सूचकांक
*	कुल कार्यशील जनसंख्या	142,487	100.00	14,767	100.00
1.	प्राथमिक क्रियायें	8,139	5.72	140	0.95
2.	गृह उद्योग	8,292	5.82	225	1.52
3.	विनिर्माण	20,903	14.67	10,146	68.71
4.	निर्माण कार्य	2,381	1.67	241	1.63
5.	व्यापार एवं वाणिज्य	27,972	19.63	1,286	8.71
6.	परिवहन एवं संचार	13,189	9.26	836	5.66
7.	सेवायें	61,599	43.23	1,891	12.81

कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक $= 100\ e/w$

जहाँ,

e = एक नगर के एक क्रिया में संलग्न जनसंख्या,

w = उक्त नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या ।

एक नगर को किसी क्रिया में विशिष्टीकृत मानने के पूर्व उसी क्रिया में अन्य नगरों की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता अनुपात की तुलना करना आवश्यक है । यहाँ यह कल्पना की गयी है कि समान आकारीय वर्ग वाले नगरों में किसी क्रिया या क्रिया-वर्ग में संलग्न जनसंख्या का प्रादेशिक औसत प्रत्येक नगर के निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और इस प्रादेशिक औसत से ऊपर उक्त कार्य में जनसंख्या की संलग्नता अमुक नगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण की सूचक होती है । अतः समस्त 66 नगरीय केन्द्रों के लिए पृथक-पृथक सात क्रिया-वर्गों के लिए कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांकों तथा उनके माध्य की गणना की गयी है । तालिका 4.1 में इलाहा-

बाद और मोदीनगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक के गणना की प्रक्रिया प्रदर्शित की गयी है ।

प्रत्येक क्रिया-वर्ग के प्रादेशिक माध्य को विशिष्टीकरण के मापन का आधार माना गया है । किसी नगर में एक क्रिया-वर्ग के प्रादेशिक माध्य से ऊपर कार्यात्मक संलग्नता का प्रतिशत उक्त क्रिया-वर्ग के विशिष्टीकरण को प्रकट करती है । माध्य से विशिष्टीकरण की मात्रा में अधिक विचलन पाया जाता है, अतः नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण के सम्यक वर्गीकरण हेतु मानक विचलन (Standard Deviation) का प्रयोग किया गया है जिसका परिकलन समस्त 66 नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांकों के माध्य से किया गया है ।

तालिका 4.2

सात कार्यात्मक वर्गों के लिए कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांकों के माध्य और मानक विचलन

	सेवायें	व्यापार एवं वाणिज्य	विनिर्माण उद्योग	परिवहन एवं संचार	गृह उद्योग	प्राथमिक क्रियायें	निर्माण कार्य
माध्य	32.01	21.89	20.33	11.40	7.18	4.88	2.31
मानक विचलन	10.31	4.54	10.13	7.54	9.27	8.09	1.60
माध्य + 1 मा0वि0	42.32	26.43	30.46	18.94	16.45	12.97	3.91
माध्य + 2 मा0वि0	52.63	30.97	40.59	26.48	25.72	21.06	5.51
माध्य + 3 मा0वि0	62.94	35.51	52.72	34.02	34.99	29.15	7.11

तालिका 4.2 एवं चित्र 4.2 से यह भी परिलक्षित है कि क्रियात्मक विशिष्टीकरण सूचकांकों के माध्य में एक क्रिया से दूसरी क्रिया में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । सर्वाधिक माध्य मूल्य (32.01) सेवाओं के पक्ष में है जिसके पश्चात् व्यापार एवं वाणिज्य (21.89), भारी उद्योग (20.33), परिवहन एवं संचार

FREQUENCY DISTRIBUTION CURVES
DISTRIBUTION OF ECONOMIC ACTIVITIES AMONG TOWNS OF U.P.
HOUSEHOLD INDUSTRY
MEAN
1σ
2σ
3σ
4σ
5σ
6σ
10
20
30
40
50
60
TRADE & COMMERCE
40
30
20
10
0
MEAN
1σ
2σ
10
20
30
CONSTRUCTION
60
50
20
10
MEAN
1σ
2σ
3σ
4σ
10
MANUFACTURING
MEAN
1σ
2σ
3σ
4σ
10
20
30
40
50
60
70
PRIMARY ACTIVITY
MEAN
20
10
0
1σ
2σ
3σ
10
20
30
40
SERVICES
20
10
0
MEAN
1σ
2σ
3σ
10
20
30
40
50
60
70
PERCENTAGE OF FUNCTIONAL TO TOTAL WORKERS
TRANSPORT & COMMUNICATION
30
20
10
0
MEAN
1σ
2σ
3σ
4σ
5σ
10
20
30
40
50
% FUNCTIONAL TO TOTAL WORKERS
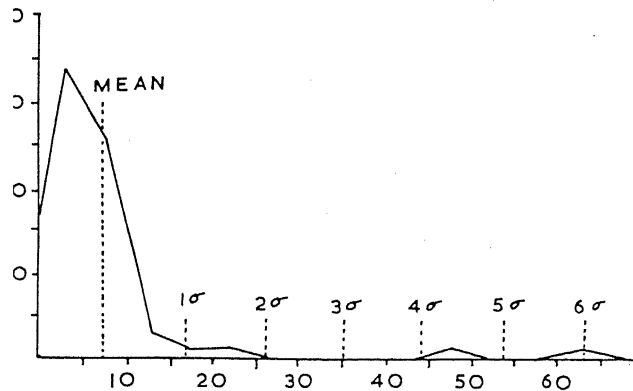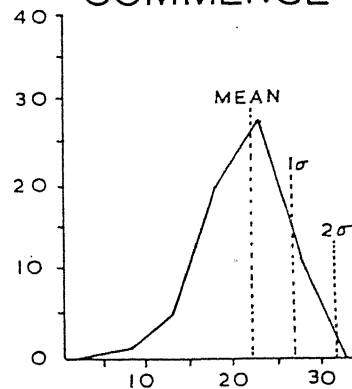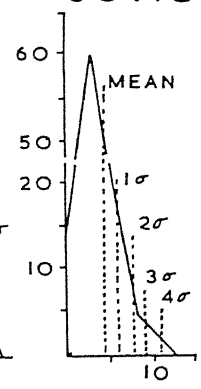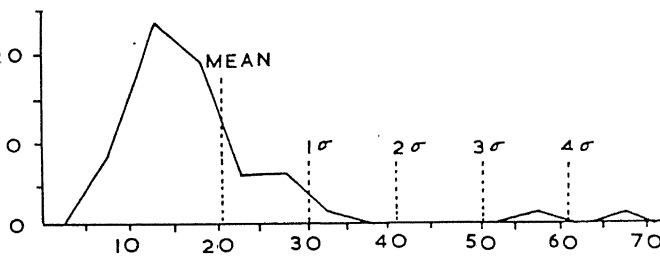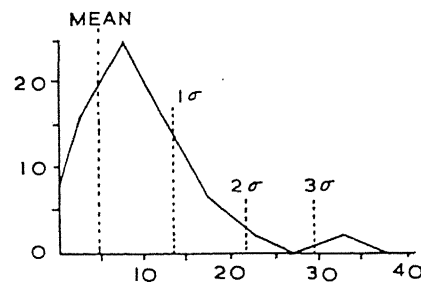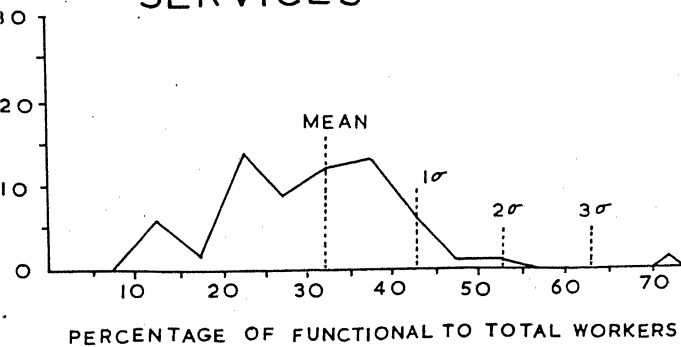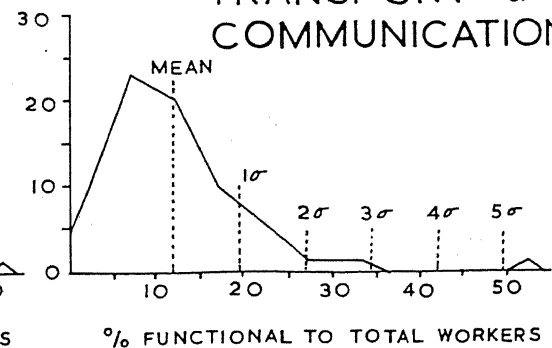
FIG. 4.1

§11.40§, गृह उद्योग §7.18§, प्राथमिक क्रियायें §4.88§, और निर्माण कार्य §2.31§ आते हैं। चित्र 4.1 में प्रदर्शित आवृत्ति चित्र द्वारा सात क्रियात्मक-वर्गों के सामान्य प्रकृति का आभास होता है। सेवाओं तथा प्राथमिक क्रियाओं के आवृत्ति वक्रों में अधिक समता परिलक्षित होती है जिनमें माध्य से विचलनों का प्रसार 3 मा0वि0 तक है। विनिर्माण उद्योग में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का प्रसार 4 मा0वि0 तक, निर्माण कार्य में 4 मा0वि0 तक, गृह उद्योग में 5 मा0वि0 तक, परिवहन एवं संचार में 5 मा0 वि0 तक है जबकि व्यापार एवं वाणिज्य में यह मात्र 1 मा0वि0 तक ही है।

तथ्यों के सामान्य वितरण में भिन्नता का प्रसार 3 मानक विचलन तक पाया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में मात्र व्यापार एवं वाणिज्य को छोड़कर अन्य क्रिया-वर्गों में भिन्नता का प्रसार 3 मा0वि0 या इससे अधिक है। अतः सामान्यीकरण द्वारा समस्त क्रियाओं में 3 मा0वि0 तक मापन किया गया है और नगरों को उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया गया है जो निम्नवत् है :

1. अल्प विशिष्टीकृत नगर §माध्य और माध्य + 1 मा0वि0 के मध्य§,
2. विशिष्टीकृत नगर §माध्य + 1 मा0वि0 तथा अधिक§,
3. अधिक विशिष्टीकृत नगर §माध्य + 2 मा0वि0 तथा अधिक§।
4. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर §माध्य * 3 मा0वि0 तथा अधिक§,

2. कार्यात्मक वर्ग

तालिका 4.3 में उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी §1981§ के समस्त 66 नगरों के कार्यात्मक वर्गों की सूची दी गयी है जिसमें नगरों को उनके जनसंख्या आकार के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया है। विभिन्न विशिष्टीकृत क्रियाओं को संकेताक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है यथा सेवाओं के लिए स, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए ब, विनिर्माण उद्योग के लिए भ, परिवहन एवं संचार के लिए प, गृह उद्योग के लिए ग, प्राथमिक क्रिया के लिए क और निर्माण कार्य के लिए न अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इन संकेताक्षरों के दाहिने अंकित अंक माध्य + मानक

विचलन मूल्य को प्रदर्शित करते हैं । जिन संकेताक्षरों के दाहिने कोई संख्या अंकित नहीं है, वह यह दर्शाता है कि उक्त क्रिया में कार्यात्मक विशिष्टीकरण प्रादेशिक माध्य से अधिक किन्तु माध्य + । मा0वि0 से कम है । प्रस्तुत बहुकार्यात्मक वर्गीकरण जिसमें प्रत्येक नगर को एक या एक से अधिक कार्यों में विशिष्टीकृत दिखाया गया है, में विभिन्न विशिष्टीकृत क्रियाओं को नगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक के अवरोही क्रम में रखा गया है । इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया को पहले और कम महत्वपूर्ण क्रिया को क्रमश: बाद में प्रदर्शित किया गया है (तालिका 4.3) । अग्रिम पंक्तियों में विभिन्न क्रिया वर्गों को उनके कार्यात्मक माध्य के अनुसार अवरोही क्रम में रखा गया है (चित्र 4.2) ।

तालिका 4.3

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

क्रम स0	नगर	कार्यात्मक वर्ग	विशिष्टीकृत कार्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	कानपुर	भ	1
2.	लखनऊ	स प	2
3.	वाराणसी	ग।	1
4.	आगरा	भ प ग न	4
5.	इलाहाबाद	स। क	2
6.	मेरठ	स	1
7.	बरेली	भ प न	3
8.	मुरादाबाद	भ प क	3
9.	अलीगढ़	भ क न	3
10.	गोरखपुर	प2	1
11.	सहारनपुर	भ ब प	3
12.	देहरादून	स2 न	2
13.	गाजियाबाद	भ। प न।	3
14.	झाँसी	प2	1

1	2	3	4
15.	शाहजहाँपुर	भ का। प	3
16.	रामपुर	भ प क ना।	4
17.	फिरोजाबाद	भ3	1
18.	मुजफ्फरनगर	बा। प क न	4
19.	फर्रुखाबाद	स भ ग क	4
20.	मथुरा	स भ क न	4
21.	हरद्वार	स ब प क ना।	5
22.	फैजाबाद	स का।	2
23.	मिर्जापुर	ब भ क	3
24.	अमरोहा	भ क ग ना।	4
25.	इटावा	स ब ग क	4
26.	सम्भल	क3 गा।	2
27.	जौनपुर	ब का। ग	3
28.	बुलन्दशहर	ब प क न	4
29.	हापुड़	ब प का। न	4
30.	सीतापुर	स ब क	3
31.	बहराइच	ब का। न	3
32.	बदायूँ	स का। प न	4
33.	हाथरस	बा। प क	3
34.	रायबरेली	स ब क ना।	4
35.	पीलीभीत	प क ना।	3
36.	मोदीनगर	भ3	1
37.	मऊनाथ भंजन	ग3 क	2
38.	फतेहपुर	क3	1
39.	रूड़की	स3	1
40.	हल्दूवानी-काठगोदाम	ब प ना।	3
41.	उन्नाव	सा। क	2
42.	बाँदा	स ब का। न	4
43.	गोण्डा	स प क	3
44.	बस्ती	स ब का।	3
45.	मुगलसराय	प3	1
46.	हरदोई	स ब क न	4
47.	खुर्जा	ब का। न	3

1	2	3	4
48.	चन्दौसी	ब प। क न	4
49.	आजमगढ़	स। ग क न	4
50.	उरई	स ब क। न।	4
51.	बाराबंकी	स क	2
52.	बलिया	स ब क।	3
53.	कासगंज	ब। प क	3
54.	लखीमपुर	स ब क	3
55.	गाजीपुर	स ब क न	4
56.	मैनपुरी	स ब। क	3
57.	बिजनौर	स क। प न2	4
58.	ललितपुर	ब क। ग	3
59.	देवरिया	स ब क। ग	4
60.	नजीबाबाद	ब भ प क न2	5
61.	टाण्डा	ग3 क	2
62.	एटा	स ब2 क	3
63.	शामली	भ ब क न।	4
64.	काशीपुर	क। प न3	3
65.	देवबन्द	क। न2	2
66.	नगीना	क2 न2	2

(क) सेवायें

इस क्रिया-वर्ग के अन्तर्गत विविध प्रकार की सेवायें सम्मिलित हैं जिनमें प्रशासनिक, शैक्षिक, चिकित्सा, राजनीतिक, सैन्य आदि सेवायें प्रमुख हैं । अध्ययन के लिए चयनित कुल 66 नगरों में से 28 नगरों को सेवाओं में विशिष्टता प्राप्त है (चित्र 4.3) । इस वर्ग का सर्वाधिक विशिष्टीकृत नगर रूड़की है जिसे स3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । यहाँ की 70.36 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न है । देहरादून (स2) अति विशिष्टीकृत सेवाकेन्द्र है जहाँ 53.85 प्रतिशत कार्मिक सेवाओं से सम्बद्ध हैं । तीन नगर - इलाहाबाद, उन्नाव और आजमगढ़ स। श्रेणी में वर्गीकृत हुए हैं । सेवाओं में विशिष्टीकृत शेष 23

नगर स प्रकार के (अल्प विशिष्टीकृत) हैं जिनके विशिष्टीकरण की गहनता प्रादेशिक माध्य से ऊपर किन्तु माध्य + । मानक विचलन से कम है ।

तालिका 4.4

विभिन्न क्रिया-वर्गानुसार विशिष्टीकृत नगरों की संख्या

क्रिया वर्ग	अल्प विशिष्टीकृत	विशिष्टीकृत	अधिक विशिष्टीकृत	अत्यधिक विशिष्टीकृत	योग
1. सेवायें	23	3	1	1	28
2. व्यापार एवं वाणिज्य	23	6	0	0	29
3. विनिर्माण उद्योग	13	1	0	2	16
4. परिवहन एवं संचार	22	1	2	1	26
5. गृह उद्योग	8	2	0	2	12
6. प्राथमिक क्रियाएं	31	16	1	2	50
7. निर्माण कार्य	16	9	4	1	30

(ख) व्यापार एवं वाणिज्य

व्यापार एवं वाणिज्य में कुल 29 नगर विशिष्टीकृत पाये गये हैं जिनमें 7 प्रथम श्रेणी के और शेष 22 द्वितीय श्रेणी के नगर हैं । यद्यपि व्यापारिक क्रियाएं प्राय: सभी नगरीय केन्द्रों में आवश्यक रूप से पायी जाती हैं किन्तु कतिपय नगरों की व्यावसायिक संरचना में इनका स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है । सामान्य वितरण की प्रकृति के कारण व्यापारिक क्रियाओं में अत्यधिक (ब3) और अधिक विशिष्टीकृत (ब2) नगरों का सर्वथा अभाव है और 6 नगर विशिष्टीकृत (ब1) श्रेणी के अन्तर्गत पाये गये हैं । मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी और एटा जो ब1 प्रकार के हैं, सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं । इस क्रिया-वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत शेष 23 नगर ब श्रेणी में आते हैं जहाँ विशिष्टीकरण की मात्रा प्रादेशिक माध्य से थोड़ा ही अधिक है (चित्र 4.4) ।

॥ग॥ विनिर्माण उद्योग

गृह उद्योगों के अतिरिक्त विनिर्माण उद्योगों को विनिर्माण उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । प्रदेश के कुल 16 नगर विनिर्माण उद्योग में विशिष्टीकृत पाये गये हैं जहाँ 32.00 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या इसी क्रिया-वर्ग में संलग्न है । इनमें से अधिकांश ॥13॥ प्रथम श्रेणी के नगर हैं और मात्र 3 नगर ही द्वितीय श्रेणी के हैं । दो नगर फिरोजाबाद और मोदीनगर विनिर्माण उद्योग में अत्यधिक विशिष्टीकृत ॥भ3॥ हैं जब भ2 प्रकार का कोई भी नगर विद्यमान नहीं है और भ1 का पद केवल एक नगर-गाजियाबाद को ही प्राप्त हो सका है । शेष 13 नगर अल्प विशिष्टीकृत ॥भ॥ प्रकार के हैं । उल्लेखनीय है कि मिर्जापुर-विन्ध्याचल ॥भ॥ और कानपुर ॥भ॥ को छोड़कर सभी औद्योगिक केन्द्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकेन्द्रित हैं ॥चित्र 4.5॥ ।

॥घ॥ परिवहन एवं संचार

परिवहन के अन्तर्गत स्थल ॥रेल एवं सड़क॥, वायु तथा जल परिवहन सम्मिलित है और संचार के अन्तर्गत डाक, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, दूरदर्शन आदि सम्मिलित हैं । इस क्रिया-वर्ग के अन्तर्गत कुल 26 नगरों को विशिष्टीकृत पाया गया है जहाँ 11.40 प्रतिशत ॥प्रादेशिक माध्य॥ से अधिक कर्मी परिवहन एवं संचार में संलग्न हैं । प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन मुगलसराय इस वर्ग का अत्यधिक विशिष्टीकृत ॥प3॥ नगर है जिसकी 53.44 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या परिवहन एवं संचार सेवाओं में लगी हुई है । उत्तर-पूर्व में गोरखपुर और दक्षिण-पश्चिम में झाँसी प2 प्रकार के नगर हैं और मात्र एक नगर चन्दौसी प1 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत हुआ है । शेष 22 नगरों को प पद प्राप्त हुआ है जो उनके अल्प विशिष्टीकृत होने का सूचक है । ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 15 विशिष्टीकृत नगर प्रथम श्रेणी के हैं और शेष 11 नगर द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत हैं ॥चित्र 4.6॥ ।

॥ङ.॥ गृह उद्योग

गृह उद्योग में मात्र 12 नगर ही विशिष्टीकृत पाये गये हैं जिनकी संख्या किसी

भी अन्य क्रिया-वर्ग के अन्तर्गत विशिष्टीकृत नगरों की संख्या से कम है। इनमें से 7 नगर - वाराणसी, आगरा, फर्रुखाबाद, अमरोहा, इटावा, सम्भल और जौनपुर प्रथम श्रेणी के और शेष 5 नगर द्वितीय श्रेणी के हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो नगर मऊनाथ भंजन और टाण्डा ग3 (अत्यधिक विशिष्टीकृत) प्रकार के हैं जिनकी क्रमशः 62.34 प्रतिशत तथा 46.38 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या गृह उद्योग में संलग्न पायी गयी है। ग2 पद किसी भी नगर को नहीं प्राप्त हो सका है जबकि वाराणसी और सम्भल ग1 (सामान्य विशिष्टीकृत) प्रकार के नगर हैं। शेष 8 नगर अल्पविशिष्टीकृत (ग) हैं जहाँ गृह उद्योग में 7.18 प्रतिशत (प्रादेशिक माध्य) से अधिक कार्यशील जनसंख्या संलग्न है (चित्र 4.7)।

(च) प्राथमिक क्रियायें

प्राथमिक क्रियाओं को प्रायः अनगरीय कार्य माना जाता है किन्तु उत्तर प्रदेश जैसे समतल एवं उर्वर मिट्टी युक्त कृषि प्रधान प्रदेश में कतिपय नगरों में कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्रियायें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रदेश के नगरों में प्राथमिक क्रियाओं की सामान्य उपस्थिति के परिणामस्वरूप इस क्रिया-वर्ग में सर्वाधिक (50) नगर विशिष्टीकृत रूप में वर्गीकृत हुए हैं। इनमें से दो-सम्भल और फतेहपुर क3 प्रकार के हैं, जहाँ क्रमशः 30.17 तथा 34.90 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं मुख्यतः कृषि कार्यों में संलग्न है। नगीना क2 प्रकार का एक मात्र नगर है जबकि क1 वर्ग के अन्तर्गत 16 नगर समाहित किये गये हैं। अधिकांश (31) नगर अल्पविशिष्टीकृत (क) हैं और प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं (चित्र 4.8)

(छ) निर्माण कार्य

निर्माण कार्य प्रायः सभी अधिवासों विशेषतः नगरीय इकाइयों के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक क्रिया है जो भवनों, सड़कों, रेलवे, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि के निर्माण, मरम्मत एवं सुधार को समाहित करती है। निर्माण कार्य हेतु कुल कार्यशील जनसंख्या के न्यून भाग की ही आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के समस्त 66 नगरों के कुल कार्यशील जनसंख्या में इस क्रिया-वर्ग का औसत अनुपात मात्र 2.31

प्रतिशत है जो अन्य सभी क्रिया-वर्गों से कम है । निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले कुल 30 नगरों में से एक [काशीपुर] न3 प्रकार का, चार [बिजनौर, नजीबाबाद, देवबन्द और नगीना] न2 प्रकार के, और नौ [गाजियाबाद, रामपुर, हरद्वार, अमरोहा, रायबरेली, पीलीभीत, हल्द्वानी-काठगोदाम, उरई और शामली] न1 प्रकार के नगर हैं । शेष 16 नगर अल्पविशिष्टीकृत [न] प्रकार के हैं [चित्र 4.9]

4.5 निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण द्वारा कतिपय सार्थक एवं उपयोगी परिणाम प्राप्त हुए हैं जिनसे भारतीय नगरों की वास्तविक कार्यात्मक दशाओं का बोध होता है । अधिकांश नगर कई क्रिया-वर्गों में विशिष्टीकृत पाये गये हैं जबकि 10 नगर [कुल का 15 प्रतिशत] एकल कार्यात्मक रूप में प्रकट हुए हैं । 11 नगरों को दो और 23 नगरों को तीन क्रिया-वर्गों में विशिष्टीकरण प्राप्त है । इसी प्रकार चार और पाँच क्रिया-वर्गों में विशिष्टीकृत नगरों की संख्या क्रमशः 20 और 2 हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु चयनित सात क्रिया-वर्गों में से विभिन्न नगरों में एक से लेकर पाँच क्रिया-वर्गों में प्रादेशिक माध्य से अधिक श्रमशक्ति संलग्न है । समस्त 66 नगरों में से प्रत्येक किसी न किसी क्रिया में अवश्य ही विशिष्टीकृत है और कोई भी ऐसा नगर नहीं है जो अवर्गीकृत हो । इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि प्रादेशिक माध्य को वर्गीकरण की निम्नतम सीमा मानने पर प्रत्येक नगर कम से कम एक क्रिया में अवश्य ही विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और इसके विपरीत कोई भी नगर सभी क्रियाओं में विशिष्टीकृत नहीं हो पायेगा । यदि किसी नगर के सम्पूर्ण श्रमशक्ति का विभाजन सभी क्रियाओं में प्रादेशिक माध्य के समान हो तो वह किसी भी क्रिया में विशिष्टीकृत नहीं होगा किन्तु यह एक आदर्श स्थिति है जो वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार प्रस्तुत नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण सार्थक एवं उपयोगी है जो वर्गीकरण के लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल रहा है ।

सन्दर्भ

1. Maurya, S.D. : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, 1988, pp.146.

2. Aurousseau, M. : "The Distribution of Population - A Consttructive Problem", Geographical Review, Vol. II, 1921, pp. 563-592.

3. McKenzie, R.D. : "The Ecological Approach to the Study of the Urban Community", in Park R.E., Burgess, E.M. and McKenzie R.D. : The city, The University of Chicago Press, Chicago, 1925.

4. James, H.E. : "Urban Geography of India", Bulletin of the Geographical Society of Philadelphia, Vol. 28, 1930, pp. 101-122.

5. Hall, R.B. : "The City of Japan - Nates on Distribution and Inherited Forms", A.A.A.G., Vol. 24, 1934, pp. 175-200.

6. Weimer, A.M. and Hoyt, Homer : Principle of Urban Real Estate New York, 1939.

7. Trewartha, G.T. : "Chinese Cities - Origin and Functions", A.A.A.G., Vol. 42, 1952, pp. 69-93.

8. Gist, N.P. and Halbert, L.A. : Urban Society, New York, 1954, p.8.

9. Rees, H. : "Functional Classification of Towns", Journal of the Manchester Geographical Society, Vol. 52, 1942-44, pp. 26-32.

10. Mints, A.A. and Khorev, B.S. : "An Attempt at Economic Geographic Typology of Soviet Cities," Voprosy Geografii, Vol. 45, 1959, pp. 72-88.

11. Hance, W.A. : "The Economic Location and Function of Tropical African Cities", Human Organization, Vol. 19, 1960, pp. 135-136.

12. Carter, H.C. : The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London, 1975, p.52.

13. Ogburn, F. : Social Characteristics of Cities, Chicago, 1937, pp. 41-46.

14. Haris, C.D. : "A Functional Classification of Cities in the United States", Geographical Review, Vol. 33, 1943, pp.86-99.

15. Ohlson, G.M. Kneedler : "Economic Classification of Cities", The Municipal Year Book, International City Managers' Association, Chicago, 1945, pp. 30-38.

16. Jones, Victor : "Economic Classification of Cities", The Municipal Year Book, op.cit., 1954, pp. 35-36 and 62-70; Idem and Forstall, R.L. : "Economic and Social Classification of Metropoliton Areas", Municipal Year Book, op. cit, 1963, pp. 31-44

17. Hart, J.F. : "Functions and Occupational Structure of Cities of the American South", A.A.A.G., Vol. 45, No. 3, 1955, pp. 269-286.

18. Duncan, O.D. and Reiss, A.J. : Social Characteristics of Urban and Rural Communities, 1950, John Wiley and Sons, New York, 1956, p. 12.

19. Political and Economic Planning (P.E.P.) : Report on the Location of Industry, London, 1939, pp. 32-42.

20. Pownall, L.L. : "The Function of New Zealand Towns", A.A.A.G., Vol. 43, No. 4, 1953, pp. 332-350.

21. Nelson, H.J. : "A Servis Classification of American Cities", Economic Geography, Vol. 3, 1955, pp. 189-210. Also reprinted in Mayer, H.M. and Kohn, C.F. (eds.) : Reading in Urban Geography, Central Book Depot, Allahabad, 1967, pp. 139-160.

22. Steigenga, W. : "A Comparative Analysis and Classification of Netherlands Towns", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 46, No. 6 & 7, 1955, pp. 105-119.

23. Dick, R.S. : Variations in the Occupational Structure of Central Places of the Darling Downs, Queensland, University of Queensland, Paper 1 & 2, 1961.

24. Webb, John W. : "Basic Concept in the Analysis of Urban Centres of Minnesota", A.A.A.G., Vol. 49, No. 1, 1959, pp. 55-72.

25. Alexander, John. W. : "The Basic-Nonbasic Concept of Urban Economic Functions", Economic Geography, Vol. 30, 1954, pp. 246-61.

26. Mattila, J.M. and Thompson, W.R. : " Measurement of the Economic Base of the Metropolitan Area", Land Economics, Vol. 31, 1955, pp. 215-228.

27. Alexandersson, G. : "City Forming and City Serving Production", The Industrial Structure of American Cities, University of Nebraska Press, Lincoln, 1956, pp. 14-20.

28. Maxwell, J.W. : "Functional Structure of Canadian Cities - A Classification of Cities", Geographical Bulletin, Vol. 7, 1965, pp. 79-104.

29. Moser, G.A. and Scott, W. : British Towns - A Statistical Study of Their Social and Economic Differences, London, 1961.

30. Hadden, J.K. and Borgatta, E.F. : American Cities - Their Social Characteristids, Chicago, 1965.

31. Smith, R.H.T. : "The Functions of Australian Towns", Tijd voor Eco. en Soc. Geog., Vol. 56, 1965.

32. Berry, B.J.L. : "Latent Structure of the American Urban System", in idem (ed.), City Classification Handbook-Methods and Applications, New York, 1972, pp. 11-40.

33. Census of India 1971, Uttar Pradesh, Part X-A, Towns and Village Directory, District Census Handbook of Azamgarh District, p. V.

34. Nath, V. : "Urbanization in India with Special Reference to the Growth of Cities", World Population Conference, Rome, 1954.

35. Janaki, V.A. : "Functional Classification of Urban Settlements in Kerala", Journal of Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Vol. 3, 1954, pp. 81-90.

36. Lal, Amrit : "Some Aspects of Functional Classification of Cities and a Proposed Scheme of Classifying Indian Cities", N.G.J.I., Vol. 5, No. 1, 1959, pp. 12-24.

37. Singh, K.N. : "Functional Classification of Towns in U.P.", N.G.J.I., Vol. 5, 1959, pp. 121-148.

38. Ganguli, B.N. : "Classification of Indian Cities, Town-Groups and Towns (With a Population of 50,000 and over)" in Chaudhuri, M.R. (ed.), Essays in Geography, The Geographical Society of India, Calcutta, 1965, pp. 82-92.

39. Prakasha Rao, V.L.S. : Presidential Address, Council of Geographers, Cuttak, 1962.

40. Rafiullah, S.M. : "A New Approach to Functional Classification of Towns", The Geographer, Vol. 12, 1965, pp. 40-53.

41. Weaver, J.C. : "Crop Combination Regions in the Middle West", Geographical Review, Vol. 44, No. 2, 1954, pp. 173-200.

42. Ahmad, Q. : "Indian Cities,- Characteristics and Correlates" Research Paper No. 102, Ph.D. Thesis, Deptt. of Geography, University of Chicago, 1965.

43. Mukherjee, M. : "Functions and Functional Classification of

Towns in Bihar", Ph.D. Thesis (unpublished), University of Patna, 1966.

44. Singh, O.P. : "Functions and Functional Classes of Central Places in Uttar Pradesh", N.G.J.I., Vol. 14, No. 2 & 3, 1968, pp. 83-127.

45. Singh, R.N. and Sahab Deen : "A Functional Typology of Urban Centres of Eastern Uttar Pradesh (India)", National Geographer, Vol. XI, No. 2, 1976, pp. 141-62.

46. Anantapadmanabhan, N. : "Functional Classification of Urban Centres in Madras State", Bombay Geographical Magazine, Vol. 13, 1965.

47. Saxena, N.P. : "Functional Analysis of Settlement", The Geographical Observer, Vol. 2, March 1966.

48. Singh, Onkar : "Functions and Functional Classification of Towns in Uttar Pradesh, N.G.J.I., Vol. 15, No. 3 & 4, 1969, pp. 179-195.

49. Vasanta Devi, M.N. : "Functional Classification of Towns in Tamil Nadu", Indian Geographical Journal, Vol. 44, No. 3 & 4, 1969, pp. 1-14.

50. Mitra, A. : "Functional Classification of India's Towns", in Bose, Ashish (ed.), Pattern of Population Change in India, Delhi, 1971, pp. 261-286.

51. Singh, R.P. and Dabral, M.P. : "An Analysis of Functional Characteristics of the Towns of Ganga-Yamuna Doab", Decan Geographer, Vol. 10, No. 2, 1972, pp. 15-22.

52. Singh, R.B. and Singh, G.D. : "Functional Classification of Service Centres in Saryupar Plain", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 13, No. 1 & 2, 1977, pp. 45-66

53. Tripathi, R.R. : "Functional Analysis of the Towns of Maharashtra State", Geographical Review of India, Vol. 32, No. 1, 1970, pp. 41-46.

54. Agrawal, P.C. and Khan, Z.T. : "Functional Analysis of Class I and II Towns of Madhya Pradesh", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 15, No. 2, 1979, pp. 91-106.

55. Ram Pyare : "Functional Classification of Towns of Bundelkhand (India)", National Geographer, Vol. 15, No. 1, 1980, pp. 53-66.

---------::o::---------

अध्याय पाँच

कृषि

5.1 भूमिका

उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या के आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टियों से निर्मित मैदान में उर्वर मिट्टी, जलवायविक परिस्थितियों की अनुकूलता, सिंचन सुविधाओं की पर्याप्तता आदि के फलस्वरूप कृषि इस प्रदेश के बहुसंख्यक जनता के आजीविका का प्रमुख साधन बन गयी है। यद्यपि कृषि को अनगरीय प्रकार्य माना जाता है किन्तु उत्तर प्रदेश जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है के अनेक नगरों के व्यावसायिक संरचना एवं अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनेक लघु नगरों में कृषि प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी पायी जाती है और कृषि कार्यों की प्रमुखता के कारण अन्य द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों का पर्याप्त विकास भी नहीं हो सका है।

प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कतिपय नगरों में भी कृषि का विशेष स्थान है। विभिन्न जनगणना वर्षों में व्यवसायों के कृषि-वर्ग के अन्तर्गत समाहित किये गये कार्यों में कुछ भिन्नता मिलती है। जनगणना 1951[1] में समस्त कर्मी जनसंख्या को दो प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया था - प्रथम कृषि वर्ग और द्वितीय गैर कृषि वर्ग। कृषि वर्ग के अन्तर्गत कृषकों, कृषि श्रमिकों और गैर कृषक भूस्वामियों एवं लगान प्राप्त कर्त्ताओं को सम्मिलित किया गया। 1961 जनगणना[2] में व्यावसायिक श्रेणियों में कुछ मौलिक परिवर्तन किये गये और समस्त कार्यशील जनसंख्या को नौ मुख्य कार्यात्मक श्रेणियों में विभक्त किया गया जिनमें प्रथम श्रेणी कृषकों की और द्वितीय श्रेणी कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित की गयी। तृतीय कार्यात्मक श्रेणी में उन श्रमिकों को समाहित किया गया जो उत्खनन, पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्योद्योग, आखेट, बागवानी आदि क्रियाओं में संलग्न थे। 1971 जनगणना में कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को 1961 जनगणना की भाँति ही तीन कार्यात्मक श्रेणियों कृषक, कृषि श्रमिक तथा पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्योद्योग, बागवानी आदि में संलग्न श्रमिक के अन्तर्गत ही रखा गया किन्तु तृतीय कार्यात्मक वर्ग से उत्खनन को पृथक करके चतुर्थ कार्यात्मक वर्ग में रखा गया जिससे तृतीय क्रिया वर्ग कृषि से पूर्णतः सम्बद्ध हो गया।

जैसा कि अध्याय तीन में उल्लिखित है, 1981 जनगणना[3] में समस्त मुख्य कर्मी जनसंख्या को 4 प्रधान क्रिया-वर्गों में विभक्त किया गया है जिनमें प्रथम एवं द्वितीय क्रिया-वर्ग क्रमशः कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को समाहित करते हैं । तृतीय क्रिया वर्ग गृह उद्योग के लिए है और चतुर्थ और अन्तिम क्रिया वर्ग में अन्य समस्त कर्मियों को सम्मिलित किया गया है जो उपरोक्त तीनों क्रिया वर्गों में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं । चतुर्थ क्रिया वर्ग में पशुचारण, मत्स्योद्योग, बागवानी आदि जैसी क्रियायें भी सम्मिलित हैं जिन्हें मूलतः कृषि वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए । किन्तु व्यवसायों की श्रेणियों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को पृथक वर्ग में रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है । अतः समंकों की उपलब्धता के अनुसार कृषि के अन्तर्गत केवल दो क्रिया-वर्गों कृषकों और कृषि श्रमिकों को ही अध्ययन के लिए चुना गया है और इनकी तुलना गत जनगणना (1971) के **उक्त** क्रिया-वर्गों के समंकों से की गयी है जिससे गत दशक में हुए परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके ।

प्रस्तुत अध्याय में उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यवसायिक संरचना में कृषि की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है । इस जनांकिकीय अध्ययन में उन नगरों के कृषि कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया है जिनकी व्यावसायिक संरचना तथा अर्थव्यवस्था में कृषि का विशिष्ट स्थान है । अध्याय के अन्त में परिमाणात्मक परीक्षण हेतु कृषि से सम्बन्धित कतिपय जनांकिकीय चरों के मध्य सह सम्बन्धों का परिगणन एवं विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है ।

5.2 कृषक एवं कृषि श्रमिकों की परिभाषा

जनगणना 1981 में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है[4] :

1. कृषक (Cultivator)

कृषक वह व्यक्ति माना गया है जो अकेला या कार्यकर्ता के रूप में सपरिवार अपनी स्वयं की भूमि, सरकारी पट्टे पर प्राप्त या किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से

बटाई या किराये पर ली गयी अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त भूमि पर खेती करता है। खेती करने में निर्देशन और देखरेख भी सम्मिलित है। खाद्यान्न जैसे गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि; अन्य फसलें जैसे गन्ना, मूँगफली, रेपियोका आदि तथा दालें, कच्चा जूट और अन्य इसी प्रकार रेशों वाली फसलें कपास इत्यादि के उत्पादन के लिए जुताई, बुवाई एवं कटाई को कृषकीय माना गया है। परन्तु फल और सब्जी उगाना, बागवानी या चाय, काफी, रबर इत्यादि के पेड़-पौधे लगाना इसमें सम्मिलित नहीं है।

2. कृषि श्रमिक

जो व्यक्ति नकद या अनाज के रूप में मजदूरी लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में काम करता है वह कृषि श्रमिक कहलाता है। खेत में लाभ-हानि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता है, वह केवल दूसरों के खेत में मजदूरी करता है।

5.3 कार्यशील जनसंख्या

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में कुल 183,206 व्यक्ति कृषि कार्यों में कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप में संलग्न हैं जिनमें 173,733 पुरूष तथा 9,473 महिलायें हैं। उक्त नगरों के कुल मुख्य कर्मी जनसंख्या का 5.36 प्रतिशत कृषि में संलग्न हैं जबकि यह प्रतिशत पुरूष कर्मियों के लिए 5.34 प्रतिशत और महिला कर्मियों के लिए 5.62 प्रतिशत है। कृषि प्रधानतया ग्रामीण व्यवसाय है किन्तु कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश के नगरीय केन्द्रों की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का महत्व कम नहीं है। सामान्यतया नगरीय आकार में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में कृषि-कार्यों का महत्व कम होता जाता है किन्तु लघु नगरों में कृषि विशेष महत्व रखती है।[5] उल्लेखनीय है कि यहाँ केवल बड़े नगरों का ही अध्ययन करना है किन्तु यदि हम प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों की पृथक-पृथक व्याख्या करें तो पायेंगे कि द्वितीय श्रेणी की व्यावसायिक संरचना में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रभाग 10.08 प्रतिशत है जबकि प्रथम श्रेणी के नगरों में इनका प्रभाग मात्र 4.24 प्रतिशत ही है। प्रथम श्रेणी के नगरों में पुरूष कर्मियों का 4.21 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 4.66

प्रतिशत कृषि में कार्यरत है । इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के नगरों में पुरुष कर्मियों का 10.13 प्रतिशत और महिला कर्मियों का 9.10 प्रतिशत कृषि कार्यों से सम्बद्ध है ।

कुल मुख्य श्रमिकों का कृषि में संलग्नता प्रतिशत विभिन्न नगरों में पृथक-पृथक देखने को मिलता है । कृषि में श्रमिकों की संलग्नता के दृष्टिकोण से सम्भल का प्रथम स्थान है जहाँ 35.13 प्रतिशत कर्मी जनसंख्या कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप में विविध कृषि कार्यों में संलग्न है । सम्भल के पश्चात् फतेहपुर (26.7 प्रतिशत) और उन्नाव (22.32 प्रतिशत) का स्थान है । इसके विपरीत पाँच नगरों - फिरोजाबाद(0.50), रूड़की (1.51), मथुरा (1.59), आगरा (1.66) और मोदीनगर (1.82) में दो प्रतिशत से भी कम कर्मी जनसंख्या कृषि से सम्बन्धित है ।

यदि कृषि में पुरुषों तथा महिलाओं की संलग्नता पर पृथक-पृथक अध्ययन किया जाय तो कतिपय उल्लेखनीय एवं अधिक उपयोगी तथ्य प्रकट होते हैं । प्रदेश में कृषि मुख्यतया श्रम-प्रधान है जिसमें कृषि प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्याय कार्य श्रमिकों द्वारा हाथ से ही सम्पादित होते हैं । यद्यपि भूकर्षण का कार्य मुख्यतया पुरुष ही करते हैं किन्तु बीज बपन से लेकर अन्नोपलब्धि तक के विविध कार्यों - निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई आदि कार्यों का सम्पादन स्त्रियाँ बड़ी कुशलता से करने में समर्थ होती हैं । अतएव भूमिहीन कुटुम्ब की स्त्रियों के जीविकोपार्जन के साधन कृषि के विविध क्रियाओं से ही प्राप्य है ।[6] अतः कृषि में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संलग्नता अधिक पायी जाती है । कुल पुरुष कर्मियों का सर्वाधिक 35.39 प्रतिशत (सम्भल) कृषि में लगा हुआ है । फतेहपुर (25.07), उन्नाव (22.93), बहराइच (18.45), देवबन्द(17.31) नगीना (17.55) आदि अन्य नगर हैं जहाँ पुरुष कर्मियों का 17.00 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि में संलग्न है । इसके विपरीत 6 नगर फिरोजाबाद, रूड़की, मथुरा, आगरा, मोदीनगर और लखनऊ में दो प्रतिशत से भी कम पुरुष कर्मी कृषि में संलग्न पाये गये हैं ।

फतेहपुर में कुल महिला कर्मियों का 42.95 प्रतिशत कृषि में संलग्न है जो प्रदेश के किसी भी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के नगर की कृषि में महिला संलग्नता से अधिक है । अधिक महिला संलग्नता वाले अन्य नगरों में मुगलसराय (25.52), बलिया (23.96),

<u>तालिका 5.1</u>

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के मुख्य कर्मी जनसंख्या में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत (1981)

क्र0 स0	नगर	कुल श्रमिक	पुरुष श्रमिक	स्त्री श्रमिक
1	2	3	4	5
1.	सम्भल	35.13	35.39	23.82
2.	फतेहपुर	26.17	25.07	42.95
3.	उन्नाव	22.32	22.93	8.73
4.	बहराइच	18.42	18.45	17.40
5.	देवबन्द	17.15	17.31	10.74
6.	नगीना	17.10	17.55	5.08
7.	रायबरेली	16.00	15.75	20.10
8.	ललितपुर	15.54	15.43	16.60
9.	जौनपुर	13.61	13.35	16.85
10.	बांदा	13.48	13.87	6.29
11.	बस्ती	13.22	12.74	20.00
12.	मुगलसराय	13.13	12.70	25.52 ~~10.79~~
13.	उरई	12.60	12.67	10.79
14.	फैजाबाद	11.76	11.35	17.63
15.	बिजनौर	11.39	11.75	5.13
16.	बलिया	10.87	10.11	23.96
17.	शाहजहाँपुर	10.66	10.82	5.57
18.	फर्रुखाबाद	10.48	10.69	5.20
19.	शामली	10.31	10.30	10.84
20.	मिर्जापुर विन्ध्याचल	10.07	5.26	20.84
21.	हापुड़	9.99	9.40	22.51
22.	खुर्जा	9.89	9.72	13.88
23.	कासगंज	9.73	9.93	4.66
24.	हरदोई	9.60	9.72	7.17
25.	मैनपुरी	9.32	16.56	1.52
26.	काशीपुर	9.28	9.52	3.58
27.	अमरोहा	9.27	9.60	4.48
28.	गाजीपुर	9.15	8.73	14.86
29.	देवरिया	8.98	8.69	13.97

1	2	3	4	5
30.	गोण्डा	8.76	8.71	9.95
31.	बाराबंकी	8.72	8.98	2.54
32.	चन्दौसी	8.18	8.19	8.20
33.	बदायूँ	7.83	12.11	5.30
34.	नजीबाबाद	7.79	8.03	2.04
35.	आजमगढ़	6.56	6.32	9.86
36.	पीलीभीत	6.28	6.41	3.09
37.	बुलन्दशहर	6.09	6.26	2.31
38.	हरद्वार	5.88	6.01	2.91
39.	रामपुर	5.74	5.78	0.93
40.	टाण्डा	5.69	5.96	3.95
41.	गोरखपुर	5.66	5.72	4.71
42.	लखीमपुर	4.89	4.94	3.93
43.	सीतापुर	4.80	4.98	1.56
44.	इटावा	4.27	4.54	0.72
45.	मुजफ्फरनगर	4.21	4.27	2.92
46.	मेरठ	4.18	4.08	6.32
47.	मऊनाथ भंजन	4.05	4.76	1.87
48.	गाजियाबाद	4.03	4.06	3.53
49.	इलाहाबाद	3.97	3.79	6.85
50.	झाँसी	3.87	3.63	5.95
51.	अलीगढ़	3.83	3.84	3.36
52.	वाराणसी	3.20	3.17	3.80
53.	एटा	3.39	3.53	0.20
54.	कानपुर	3.18	2.07	5.98
55.	मुरादाबाद	3.18	3.21	1.79
56.	बरेली	2.89	2.95	1.58
57.	हाथरस	2.44	2.51	0.48
58.	लखनऊ	2.32	1.37	1.51
59.	देहरादून	2.32	2.30	2.81
60.	हलद्वानी-काठगोदाम	2.28	2.14	5.37
61.	सहारनपुर	2.20	2.21	1.77
62.	मोदीनगर	1.82	1.84	1.21

1	2	3	4	5
63.	आगरा	1.66	1.68	1.02
64.	मथुरा	1.59	1.52	2.99
65.	रुड़की	1.51	1.55	0.74
66.	फिरोजाबाद	0.50	0.88	0.51
	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर	5.36	5.34	5.62

सम्भल (23.82), हापुड़ (22.51), मिर्जापुर-विन्ध्याचल (20.84), रायबरेली (20.10) और बस्ती (20.00) हैं जहाँ एक - पाँचवें से अधिक कार्यशील महिलायें कृषि से सम्बन्धित हैं । इसके विपरीत कुल 66 नगरों में से 15 नगरों में महिला कर्मियों का 2.00 प्रतिशत से भी कम कृषि में कार्यरत हैं । एटा (0.20), हाथरस (0.48), फिरोजाबाद (0.51), इटावा (0.72), रुड़की (0.74) और रामपुर (0.93) में कृषि कार्यों में महिला कर्मियों का 1.00 प्रतिशत से भी कम अंश लगा हुआ है ।

1. कृषक

1981 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल 103,233 कृषक हैं जो मुख्यतया अपनी निजी या पट्टे पर प्राप्त या बटाई पर ली गयी भूमि पर खेती करते हैं । इनमें 99,630 पुरुष तथा 3,603 स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार 3.02 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषक वर्ग के अन्तर्गत आती है । कुल पुरुष कर्मियों तथा महिला कर्मियों में कृषक वर्ग का प्रभाग क्रमशः 3.06 और 2.14 प्रतिशत है । प्रथम श्रेणी के नगरों में जहाँ द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं का प्रभुत्व है, कृषि का स्थान या तो अत्यन्त निम्न है या नगण्य है । प्रथम श्रेणी के नगरों में औसतन 2.26 प्रतिशत मुख्य कर्मी ही कृषि में संलग्न हैं । यह प्रतिशत पुरुष तथा महिला कर्मियों में क्रमशः 2.29 और 1.61 है । इसके विपरीत द्वितीय श्रेणी के नगरों जिनका आकार अपेक्षाकृत लघु है में कृषि कर्मियों के प्रभाग में वृद्धि हो जाती है । द्वितीय श्रेणी के नगरों में औसतन 6.22 प्रतिशत मुख्य कर्मी जनसंख्या कृषक हैं जबकि पुरुष और महिला कर्मियों में कृषकों का प्रभाग क्रमशः 6.34 प्रतिशत तथा 4.06 प्रतिशत आता है (चित्र 5.1) ।

तालिका 5.2

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के मुख्य कर्मी जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

क्र0 सं0	नगर	कृषक/कुल मुख्य कर्मी (प्रतिशत) कुल कर्मी	पुरुष कर्मी	महिला कर्मी	महिला कृषक प्रति 1000 पुरुष कृषक
1	2	3	4	5	6
1.	सम्भल	18.05	18.31	6.48	8
2.	फतेहपुर	18.05	18.08	17.39	63
3.	उन्नाव	12.17	12.60	2.64	10
4.	बहराइच	11.41	11.39	11.81	39
5.	देवबन्द	10.97	11.12	4.91	11
6.	नगीना	9.31	9.51	4.06	16
7.	रायबरेली	8.96	8.96	9.00	61
8.	ललितपुर	12.08	12.29	10.16	85
9.	जौनपुर	8.73	8.79	8.04	73
10.	बाँदा	8.77	9.08	3.04	18
11.	बस्ती	5.45	5.63	3.08	40
12.	मुगलसराय	6.22	6.29	4.14	23
13.	उरई	8.38	8.55	3.89	17
14.	फैजाबाद	5.98	5.96	6.13	70
15.	बिजनौर	6.68	6.94	2.18	18
16.	बलिया	6.21	6.10	8.03	76
17.	शाहजहाँपुर	5.26	5.35	2.52	15
18.	फर्रुखाबाद	5.38	5.48	2.57	18
19.	शामली	4.01	4.06	2.59	20
20.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	2.31	2.24	3.49	85
21.	हापुड़	3.80	3.95	0.58	7
22.	खुर्जा	5.77	5.83	4.44	33
23.	कासगंज	5.20	5.31	2.33	18
24.	हरदोई	5.93	6.00	4.62	37
25.	मैनपुरी	6.58	6.79	0.95	5
26.	काशीपुर	6.00	6.30	1.61	10
27.	अमरोहा	6.13	6.44	1.67	18
28.	गाजीपुर	6.58	6.16	12.30	147

1	2	3	4	5	6
29.	देवरिया	5.57	5.70	3.18	31
30.	गोण्डा	5.08	5.19	2.35	18
31.	वाराबंकी	5.53	5.71	1.13	8
32.	चन्दौसी	6.64	6.69	5.35	27
33.	बदायूँ	4.49	8,76	2.18	10
34.	नजीबाबाद	3.83	3.93	1.36	15
35.	आजमगढ़	4.77	4.55	7.85	127
36.	पीलीभीत	4.90	5.01	2.49	22
37.	बुलन्दशहर	3.77	3.90	0.89	10
38.	हरद्वार	1.16	1.20	0.24	9
39.	रामपुर	4.52	4.55	0.41	11
40.	टाण्डा	2.71	2.98	0.99	51
41.	गोरखपुर	3.02	3.08	2.09	38
42.	लखीमपुर	3.23	3.32	1.36	18
43.	सीतापुर	3.28	3.43	0.61	9
44.	इटावा	2.64	2.80	0.62	17
45.	मुजफ्फरनगर	2.56	2.62	1.08	15
46.	मेरठ	1.75	1.79	1.02	28
47.	मऊनाथ भंजन	2.52	3.04	0.95	103
48.	गाजियाबाद	2.15	2.18	1.62	38
49.	इलाहाबाद	1.72	1.72	1.65	58
50.	झाँसी	2.67	2.53	3.86	183
51.	अलीगढ़	2.25	2.28	1.35	23
52.	एटा	2.35	2.44	0.20	3
53.	वाराणसी	1.88	1.92	1.23	36
54.	कानपुर	1.83	1.83	1.96	44
55.	मुरादाबाद	2.32	2.34	1.19	13
56.	बरेली	1.93	1.96	1.32	29
57.	हाथरस	1.41	1.45	0.24	6
58.	लखनऊ	0.89	0.93	0.40	28
59.	देहरादून	1.01	1.00	1.15	88
60.	हलद्वानी-काठगोदाम	1.50	1.38	4.05	138
61.	सहारनपुर	1.33	1.33	1.18	33

1	2	3	4	5	6
62.	मोदीनगर	1.57	1.61	0.55	13
63.	आगरा	0.73	0.74	0.37	17
64.	मथुरा	0.97	0.98	0.64	29
65.	रुड़की	1.08	1.11	0.42	14
66.	फिरोज़ाबाद	0.49	0.50	0.36	26
	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर	3.02	3.06	2.14	36

सम्भल और फतेहपुर नगरों (प्रत्येक 18.05 प्रतिशत) में कृषकों का प्रतिशत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किसी भी नगर से अधिक है । अन्य नगर जहाँ कृषकों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, ये हैं - उन्नाव (12.71), ललितपुर (12.08), बहराइच (11.41), देवबन्द (10.97), नगीना (9.31), रायबरेली (8.96), बाँदा (8.77), जौनपुर (8.73), उरई (8.38) आदि । इसके विपरीत चार नगरों - फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और लखनऊ में कृषकों का प्रभाग 1.00 प्रतिशत से भी कम है । अन्य 12 नगरों - रुड़की, मोदीनगर, सहारनपुर, हलद्वानी-काठगोदाम, देहरादून, हाथरस, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी और हरिद्वार में कुल कार्यशील जनसंख्या का 2.00 प्रतिशत से अल्प भाग ही कृषक के रूप में कार्यरत हैं ।

प्रदेश में पुरुष कर्मियों का कृषकों के रूप में अधिकतम प्रतिशत 18.31 है जो सम्भल में अंकित किया गया है । पुरुष कृषकों के उच्च प्रभाग वाले अन्य नगर फतेहपुर, उन्नाव, ललितपुर, बहराइच और देवबन्द हैं जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक पुरुष कर्मी कृषक हैं । फतेहपुर में 17.39 प्रतिशत (सर्वोच्च) महिला कर्मी कृषक हैं । उल्लेखनीय है कि महिला कृषकों का प्रभाग केवल बहराइच और ललितपुर में ही 10 प्रतिशत से अधिक है ।

यदि कृषक के रूप में पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को देखा जाय तो महिलाओं का योगदान अत्यल्प मिलता है । प्रथम श्रेणी के नगरों में औसत रूप से प्रति हजार पुरुष कृषकों पर महिला कृषकों की संख्या मात्र 35 है जबकि द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए यह संख्या 38 आती है । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों के कृषक वर्ग

में लिंगानुपात 36 महिलायें प्रति हजार पुरुष हैं । कृषक वर्ग में अधिकतम लिंगानुपात 183 महिलायें प्रति हजार पुरुष झाँसी में पाया गया है जिसके पश्चात् क्रमशः बस्ती (173), गाजीपुर (147), हलद्वानी-काठगोदाम (133), आजमगढ़ (127) और नऊ-नाथ भंजन (103) नगरों का स्थान है । कृषक वर्ग का न्यूनतम लिंगानुपात (3 महिलायें प्रति हजार पुरुष) एटा नगर में अंकित किया गया है । मैनपुरी (5), हाथरस (6), बाराबंकी (8), सम्भल (8) और हरद्वार (9) नगरों में महिलाओं का अनुपात अत्यल्प (10 महिलायें प्रति हजार पुरुष से भी कम) है ।

2. कृषि श्रमिक

प्रदेश के 66 बृहत् नगरों में संयुक्त रूप से 79,973 कृषि श्रमिक हैं जिनमें 74,103 पुरुष और 5,870 महिलायें हैं । ये कृषि श्रमिक दूसरे व्यक्ति के खेतों में कार्य करते हैं जिसके बदले उन्हें पारिश्रमिक स्वरूप नकद या अनाज प्रदान किया जाता है । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कार्यरत सम्पूर्ण कर्मी जनसंख्या का 2.34 प्रतिशत कृषि श्रमिक या खेतिहर मजदूर हैं । पुरुष श्रमिकों में 2.28 प्रतिशत तथा महिला श्रमिकों में 3.48 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं । कृषि श्रमिकों का प्रतिशत नगरीय आकार में वृद्धि के साथ-साथ सामान्यतया घटता है । उदाहरणार्थ, प्रथम श्रेणी के नगरों के मुख्य कर्मियों में कृषि श्रमिकों का प्रभाग 1.98 प्रतिशत है जबकि द्वितीय श्रेणी के नगरों में उक्त प्रभाग 3.86 प्रतिशत आता है । इसी प्रकार की प्रवृत्ति पुरुष तथा महिला श्रमिकों में भी पायी जाती है । प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों में कृषि श्रमिक के रूप में पुरुष कर्मियों का क्रमशः 1.92 और 3.79 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का क्रमशः 3.05 प्रतिशत एवं 5.04 प्रतिशत संलग्न है ।

सम्भल में कुल श्रमशक्ति का 17.08 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में है जो प्रदेश के 66 वृहत् नगरों में सर्वाधिक है । कृषि श्रमिकों के प्रतिशत प्रभाग के अनुसार अवरोही क्रम में उन्नाव, नगीना, बस्ती, बहराइच, फतेहपुर, रायबरेली, मुगलसराय, शामली और देवबन्द आते हैं जहाँ कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 6.00 से अधिक है । इसके विपरीत 27 नगर ऐसे हैं जहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 2.00 प्रतिशत से भी कम प्रभाग कृषि

तालिका 5.3

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के मुख्य कर्मी जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

क्र० सं०	नगर	कृषि श्रमिक/कुल मुख्य कर्मी (प्रतिशत)			महिला कृषि श्रमिक प्रति 1000 पुरुष कृषि श्रमिक
		कुल श्रमिक	पुरुष श्रमिक	महिला श्रमिक	
1	2	3	4	5	6
1.	सम्भल	17.08	17.08	17.34	22
2.	फतेहपुर	8.12	6.99	25.56	238
3.	उन्नाव	10.15	10.33	6.09	27
4.	बहराइच	7.01	7.06	5.59	30
5.	देवबन्द	6.18	6.19	5.83	23
6.	नगीना	7.79	8.04	1.02	5
7.	रायबरेली	7.04	6.79	11.10	99
8.	ललितपुर	3.45	3.14	6.44	211
9.	जौनपुर	4.88	4.56	8.81	154
10.	बाँदा	4.71	4.79	3.25	36
11.	बस्ती	7.77	7.11	16.92	173
12.	मुगलसराय	6.91	6.41	21.38	116
13.	उरई	4.22	4.12	6.90	62
14.	फैजाबाद	5.78	5.39	11.50	145
15.	बिजनौर	4.71	4.81	2.95	35
16.	बलिया	4.66	4.01	15.93	229
17.	शाहजहाँपुर	5.40	5.47	3.05	18
18.	फर्रुखाबाद	5.11	5.21	2.63	19
19.	शामली	6.30	6.24	8.25	41
20.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	7.76	3.02	17.35	312
21.	हापुड़	6.19	5.45	21.93	190
22.	खुर्जा	4.12	3.89	9.44	104
23.	कासगंज	4.53	4.62	2.33	20
24.	हरदोई	3.67	3.72	2.55	33
25.	मैनपुरी	2.64	9.77	0.57	8
26.	काशीपुर	3.17	3.22	1.97	26

1	2	3	4	5	6
27.	अमरोहा	3.14	3.16	2.81	62
28.	गाजीपुर	2.57	2.57	2.56	73
29.	देवरिया	3.41	2.99	10.79	203
30.	गोण्डा	3.68	3.52	7.60	88
31.	बाराबंकी	3.19	3.27	1.41	18
32.	चन्दौसी	1.54	1.50	2.85	64
33.	बदायूँ	3.34	3.35	3.12	39
34.	नजीबाबाद	3.96	4.10	0.68	7
35.	आजमगढ़	1.79	1.77	2.01	84
36.	पीलीभीत	1.38	1.41	0.60	18
37.	बुलन्दशहर	2.32	2.36	1.42	27
38.	हरद्वार	4.72	4.81	2.67	25
39.	रामपुर	1.22	1.23	0.52	18
40.	टाण्डा	2.98	2.98	2.96	154
41.	गोरखपुर	2.64	2.64	2.62	56
42.	लखीमपुर	1.66	1.62	2.57	70
43.	सीतापुर	1.52	1.55	0.95	33
44.	इटावा	1.63	1.74	0.10	4
45.	मुजफ्फरनगर	1.65	1.65	1.84	42
46.	मेरठ	2.43	2.29	5.30	115
47.	मऊनाथ भंजन	1.53	1.72	0.92	176
48.	गाजियाबाद	1.88	1.88	1.91	52
49.	इलाहाबाद	2.25	2.07	5.20	152
50.	झाँसी	1.20	1.10	2.09	228
51.	अलीगढ़	1.58	1.56	2.01	50
52.	एटा	1.04	1.09	-	-
53.	वाराणसी	1.32	1.25	2.57	115
54.	कानपुर	1.35	1.24	4.02	134
55.	मुरादाबाद	0.86	0.87	0.60	19
56.	बरेली	0.96	0.99	0.26	11
57.	हाथरस	1.03	1.06	0.24	8
58.	लखनऊ	1.43	1.44	1.11	50
59.	देहरादून	1.32	1.30	1.66	98

1	2	3	4	5	6
60.	हलद्वानी-काठगोदाम	0.78	0.76	1.32	82
61.	सहारनपुर	0.87	0.88	0.59	25
62.	मोदीनगर	0.25	0.23	0.66	107
63.	आगरा	0.93	0.94	0.65	23
64.	मथुरा	0.62	0.54	2.35	190
65.	रूढ़की	0,43	0.44	0.32	36
66.	फिरोजाबाद	0.01	0.33	0.15	17
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		2.34	2.28	3.48	79

श्रमिक के रूप में कार्यरत है और 9 नगरों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 1.00 से भी कम है । ये नगर हैं : फिरोजाबाद, मोदीनगर, रूढ़की, मथुरा, हलद्वानी-काठगोदाम, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और बरेली ।

पुरुष कर्मियों का सर्वाधिक प्रभाग (17.08 प्रतिशत) भी सम्भल में ही प्राप्त हुआ है जिसके पश्चात् उन्नाव (10.33), मैनपुरी (9.77), नगीना (8.04), बस्ती (7.11), बहराइच (7.06) और फतेहपुर (6.99) नगरों का स्थान है । अन्य नगर जहाँ कुल पुरुष श्रमशक्ति का 5.00 प्रतिशत से अधिक कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, ये हैं - फर्रुखाबाद, फैजाबाद, हापुड़, शाहजहाँपुर, देवबन्द, शामली, मुगलसराय और रायबरेली । उल्लेखनीय है कि पुरुष कृषि श्रमिकों की तुलना में पुरुष कृषकों का प्रतिशत सामान्यतया अधिक है किन्तु कतिपय नगरों में कृषि श्रमिकों का प्रभाग कृषकों से अधिक भी है । उदाहरणार्थ बस्ती, मुगलसराय, शाहजहाँपुर, शामली, हापुड़, मैनपुरी, हरद्वार में पुरुष कृषि श्रमिकों की संख्या कृषकों से अधिक है ।

प्रदेश के नगरों में महिलायें कृषक की अपेक्षा कृषि श्रमिक अधिक हैं जो दूसरे कृषकों या भूस्वामियों के खेतों पर मजदूरी करके जीविकार्जन करती हैं । समस्त 66 वृहत् नगरों में औसत रूप से 3.48 प्रतिशत महिला कर्मी कृषि श्रमिक हैं जबकि प्रथम एवं

द्वितीय श्रेणी के नगरों में महिला कर्मियों का कृषि श्रमिक के रूप में पृथक-पृथक संलग्नता क्रमशः 3.05 प्रतिशत और 5.04 प्रतिशत है । कृषि कार्यों में महिलाओं का योगदान कृषक के रूप में कम और कृषि मजदूर के रूप में अधिक है । फतेहपुर में एक-चौथाई से अधिक महिला श्रमिक कृषि मजदूर (25.56 प्रतिशत) हैं जो समस्त वृहत् नगरों में सर्वाधिक है । हापुड़ (21.93 प्रतिशत), मुगलसराय (21.38 प्रतिशत), मिर्जापुर - विन्ध्याचल (17.35 प्रतिशत), सम्भल (17.34 प्रतिशत), बस्ती (16.92 प्रतिशत), बलिया (15.93 प्रतिशत), फैजाबाद (11.50 प्रतिशत), रायबरेली (11.10 प्रतिशत), और देवरिया (10.79 प्रतिशत) अन्य ऐसे नगर हैं जहाँ 10.00 प्रतिशत से अधिक महिला कर्मी कृषि मजदूर हैं । इसी प्रकार खुर्जा, जौनपुर, शामली और गोण्डा में भी महिला कृषि मजदूरों का उल्लेखनीय योगदान है । इसके विपरीत 15 नगरों में 1.00 प्रतिशत से भी कम महिला कर्मी कृषि मजदूर या श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं । इनमें सबसे निम्नतम प्रभाग इटावा (0.10 प्रतिशत) में अंकित किया गया है । इसी प्रकार नगण्य महिला कृषि मजदूर वाले कतिपय अन्य नगर हैं - फिरोजाबाद, बरेली, रूड़की, हाथरस, पीलीभीत, मैनपुरी, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मोदीनगर आदि ।

5.4 कृषि में विशिष्टीकरण

कृषि प्रधानतः ग्रामीण क्रिया है किन्तु प्रदेश के लघु नगरों में ही नहीं अपितु कतिपय वृहत् नगरों की व्यावसायिक संरचना में भी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है । तालिका 5.1 से स्पष्ट है कि प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में 5.36 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषक एवं कृषि श्रमिक के रूप में संलग्न है । इनमें से 41 ऐसे नगर हैं जहाँ इस प्रादेशिक माध्य (5.36 प्रतिशत) से अधिक श्रमशक्ति कृषि कार्यों में लगी हुई है । किसी नगर के कार्यात्मक विशिष्टीकरण की माप हेतु प्रादेशिक माध्य से मानक विचलन (Standard Deviation) का परिकलन किया गया है जिसे कार्यात्मक विशिष्टीकरण की गहनता के मापदण्ड के रूप में प्रयोग किया गया है । इस प्रकार कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (कुल श्रमशक्ति में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का प्रतिशत) के आधार पर नगरों को 4 विशिष्टीकृत वर्गों में विभक्त किया गया है । ये विशिष्टीकृत वर्ग अवरोहीक्रम में इस प्रकार हैं (चित्र 5.2) :

1. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 3 मा0वि0 से ऊपर),

2. अधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 2 मा0वि0 से ऊपर),

3. सामान्य विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 1 मा0वि0 से ऊपर),

4. अल्प विशिष्टीकृत नगर (माध्य से ऊपर) ।

कृषि में विशिष्टीकृत नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण के परास निम्नवत् हैं :

क्र0 सं0	नगरों के प्रकार	कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (प्रतिशत में)
1.	अत्यधिक विशिष्टीकृत	27.92 से ऊपर
2.	अधिक विशिष्टीकृत	20.40 - 27.92
3.	सामान्य विशिष्टीकृत	12.88 - 20.40
4.	अल्प विशिष्टीकृत	5.37 - 12.88

1. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर

सम्भल (जनसंख्या 108,232) प्रथम श्रेणी का नगर है जिसे कृषि में अत्यधिक विशिष्टता प्राप्त है । यहाँ 28,456 व्यक्ति मुख्य कर्मी के रूप में कार्यरत हैं । इस प्रकार कुल जनसंख्या में मुख्यकर्मी जनसंख्या का प्रतिशत 26.29 है जो प्रदेश के प्रथम श्रेणी (27.07 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (26.53 प्रतिशत) के नगरों के औसत से कम है । यहाँ कुल जनसंख्या का मात्र 0.04 प्रतिशत भाग ही सीमान्त श्रमिक के अन्तर्गत आता है । इस प्रकार सम्भल की कार्यशील जनसंख्या में सीमान्त श्रमिकों का महत्व लगभग नगण्य है। सम्भल नगर के 35.13 प्रतिशत कर्मी विभिन्न कृषि कार्यों में कृषक अथवा कृषि श्रमिक के रूप में संलग्न हैं । गत दशक (1971-81) में सम्भल की जनसंख्या में 25.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु इसकी कार्यशील जनसंख्या में 20.12 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है । यहाँ कृषकों तथा कृषिश्रमिकों की संख्या में क्रमशः 33.91 प्रतिशत और 59.80 प्रतिशत की

तालिका 5.4

कृषि में विशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं कृषि में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत में भिन्नता

क्र० सं०	नगर	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत	दशकीय भिन्नता (1971-81)			
			कुल जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	कृषि में संलग्न कर्मी	
					कृषक	कृषि श्रमिक
1.	2	3	4	5	6	7
1.	सम्भल	26.29	+25.38	+ 20.12	+ 33.91	+ 59.80
2.	फतेहपुर	25.76	+55.18	+ 46.76	+ 38.24	- 20.83
3.	उन्नाव	26.40	+98.43	+112.94	+ 481.19	+539.12
4.	बहराइच	25.46	+35.11	+ 21.62	+ 7.01	+ 82.40
5.	देवबन्द	26.47	+34.24	+ 34.18	+ 27.48	+ 77.36
6.	नगीना	26.83	+35.99	+ 44.54	+ 28.60	+ 2.73
7.	रायबरेली	28.57	+131.39	+150.60	+ 501.28	+461.68
8.	ललितपुर	26.88	+61.79	+ 63.74	+ 71.43	+ 83.99
9.	जौनपुर	24.93	+30.23	+ 27.00	- 7.81	+ 10.36
0.	बाँदा	25.46	+43.11	+ 36.66	+ 52.98	+ 12.14
1.	बस्ती	26.29	+39.95	+ 27.92	- 1.78	- 23.34
2.	मुगलसराय	24.93	+141.94	+115.16	+2234.80	+13155.55
3.	उरई	23.92	+56.18	+ 48.58	+ 38.50	+ 21.38
4.	फैजाबाद	28.84	+30.38	+ 33.55	+ 17.48	+ 12.76
5.	बिजनौर	25.67	+31.01	+ 30.04	- 0.21	+ 27.27
6.	बलिया	22.90	+31.00	+ 16.44	+ 33.89	- 34.75
7.	शाहजहाँपुर	26.40	+42.36	+ 41.36	+ 19.35	+ 19.02
8.	फर्रुखाबाद	29.38	+45.08	+ 47.89	+ 64.61	+237.43
.	शामली	27.15	+40.29	+ 41.58	+ 38.82	-128.55
.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	27.42	+20.62	+ 16.59	- 31.00	- 31.60
.	हापुड़	25.45	+44.30	+ 46.69	+ 15.28	+ 7.23
.	खुर्जा	26.01	+33.58	+ 28.56	+ 6.89	+ 5.26
.	कासगंज	25.10	+32.14	+ 25.40	+ 26.74	+ 71.50
.	हरदोई	26.48	+44.21	+ 44.10	+ 24.65	+153.37
.	मैनपुरी	24.79	+34.39	+ 32.56	- 8.65	+ 36.39
.	काशीपुर	26.57	+54.74	+ 54.51	+ 28.01	+ 44.37

1	2	3	4	5	6	7
27.	अमरोहा	26.24	+ 36.25	+ 42.38	+ 3.60	+ 49.84
28.	गाजीपुर	23.50	+ 33.07	+ 27.84	+ 27.41	+ 1.08
29.	देवरिया	24.67	+ 46.02	+ 34.11	+ 60.17	− 54.34
30.	गोण्डा	26.20	+ 34.53	+ 27.21	+ 24.24	− 7.58
31.	बाराबंकी	27.89	+ 43.40	+ 36.92	+ 52.46	+ 43.15
32.	चन्दौसी	25.71	+ 25.43	+ 22.23	+ 24.35	+216.67
33.	बदायूँ	26.03	+ 28.81	+ 31.27	+ 35.80	+ 18.27
34.	नजीबाबाद	26.17	+ 29.41	+ 28.01	+ 5.15	+ 87.50
35.	आजमगढ़	23.97	+ 62.40	+ 53.74	+ 50.40	+ 2.15
36.	पीलीभीत	27.11	+ 29.70	+ 29.08	+ 16.07	− 14.69
37.	बुलन्दशहर	24.93	+ 73.83	+ 73.38	+ 67.76	+171.04
38.	हरद्वार	27.15	+ 84.10	+ 71.22	− 31.34	+ 98.72
39.	रामपुर	27.66	+ 26.76	+ 26.15	+ 21.60	− 19.93
40.	टाण्डा	29.08	+ 30.91	+ 20.56	− 30.65	− 22.24
41.	गोरखपुर	24.09	+ 33.77	+ 21.56	+125.81	+ 23.58
	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर	26.94	+ 35.29	+ 32.06	+ 26.39	+ 25.97

प्रगति हुई है जो प्रादेशिक औसत से अधिक है (तालिका 5.4) । कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की यह प्रवृत्ति सम्भल में कृषि कार्यों की प्रबलता तथा विशिष्टता की सूचक है ।

सम्भल में कृषि में संलग्न 9999 व्यक्तियों में से 9852 पुरुष तथा 147 स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार कृषि में संलग्न पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 98.53 और 1.47 प्रतिशत है । यहाँ 5,138 कृषक हैं जिनमें 5,098 पुरुष और 40 महिलायें हैं । सम्भल में कृषि मजदूरों की संख्या 4,861 है जो कृषकों से कुछ कम है और इसमें पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 4,754 और 107 है । इस प्रकार कृषकों तथा कृषि श्रमिकों में लिंगानुपात क्रमशः 8 और 22 महिलायें प्रति हजार पुरुष हैं जो कृषि में महिलाओं की अनुपस्थिति और असंलग्नता को प्रकट करता है ।

प्रथम श्रेणी का नगर होते हुए भी सम्भल नगर की प्रशासनिक सीमा के बाहर और अन्दर भी पर्याप्त उर्वर भूमि की उपलब्धता तथा उद्योग, व्यापार, प्रशासन आदि जैसे द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों के समुचित विकास के अभाव में यहाँ एक-तिहाई से अधिक श्रमशक्ति कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप में खेतों में कार्य करती है । यहाँ कृषक तथा कृषि श्रमिक मुख्यतया शाक-सब्जी तथा गन्ना जैसी मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन में सक्रिय रहते हैं जिससे कृषि अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है ।

2. अधिक विशिष्टीकृत नगर

फतेहपुर और उन्नाव इस विशिष्टीकृत वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जहाँ क्रमशः 26.17 प्रतिशत और 22.32 प्रतिशत कर्मी जनसंख्या कृषक और कृषि श्रमिक हैं । ये दोनों ही द्वितीय श्रेणी के नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1981 में क्रमशः 84,851 तथा 75,983 थी । फतेहपुर की 25.76 प्रतिशत और उन्नाव की 26.40 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कर्मी है जबकि इन नगरों में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 0.43 तथा 0.32 है ।

फतेहपुर में 3,944 कृषक हैं जिनमें 3,712 पुरुष और 232 महिलायें हैं । इस प्रकार यहाँ की 18.05 प्रतिशत कर्मी जनसंख्या कृषक है जहाँ लिंगानुपात 63 महिलायें प्रति हजार पुरुष आता है । फतेहपुर में कृषि श्रमिकों की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण है जहाँ 8.12 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है । यहाँ 1,775 कृषि श्रमिक हैं जिनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 1,434 और 341 है । इस प्रकार प्रति हजार पुरुष कृषि श्रमिकों पर महिला कृषि श्रमिकों की संख्या 238 है जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के औसत (79) का तीन गुना है । तालिका 5.4 दर्शाती है कि गत दशक में यद्यपि फतेहपुर की जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्रमशः 55.18 प्रतिशत और 46.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु कृषकों की संख्या में 38.24 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । इसके विपरीत कृषि श्रमिकों में 20.83 प्रतिशत का ह्रास हुआ है जो मुख्यतः कृषि श्रमिकों का कृषकों तथा अन्य व्यवसायों में गतिशीलता एवं स्थानान्तरण के कारण सम्भव हो सका है । पिछले दशक में यहाँ गृह उद्योग तथा अन्य विविध क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप कृषि पर से जनसंख्या भार में कमी आयी है ।

3. <u>सामान्य विशिष्टीकृत नगर</u>

बहराइच, देवबन्द, नगीना, रायबरेली, ललितपुर, जौनपुर, बाँदा, बस्ती और मुगलसराय नगरों को कृषि में सामान्य विशिष्टीकृत माना गया है जहाँ कार्यात्मक विशिष्टीकरण की मात्रा माध्य + 1 मानक विचलन (12.38) से अधिक है। ये नगर प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। देवबन्द और नगीना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रायबरेली मध्यवर्ती प्रदेश में, ललितपुर और बाँदा बुन्देलखण्ड में तथा जौनपुर, मुगलसराय एवं बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें केवल जौनपुर (जनसंख्या 105,140) ही प्रथम श्रेणी का नगर है और शेष सभी द्वितीय श्रेणी के नगर हैं।

बहराइच में मुख्य श्रमिकों की संख्या 25,430 है जो कुल जनसंख्या का 25.46 प्रतिशत है। यहाँ कुल श्रमशक्ति का 18.42 प्रतिशत कृषि में संलग्न है जिसमें 11.41 प्रतिशत कृषक तथा 7.01 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं। बहराइच के पुरुष कर्मियों का 11.39 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 11.81 प्रतिशत कृषक है जबकि पुरुष एवं महिला कर्मियों में कृषि श्रमिकों का प्रभाग क्रमश: 7.06 प्रतिशत और 5.59 प्रतिशत है। इस प्रकार कृषक तथा कृषि श्रमिक क्रिया-वर्ग में लिंगानुपात क्रमश: 39 और 30 महिलायें प्रति हजार पुरुष आता है। इन समंकों से स्पष्ट है कि यहाँ कृषि में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। बहराइच की जनसंख्या गत दशक में 35.11 प्रतिशत बढ़ी है जबकि कार्यशील जनसंख्या में मात्र 21.62 प्रतिशत की वृद्धि हो पायी है। यहाँ कृषकों की संख्या में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या में 82.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 5.4)। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि कृषि श्रमिकों में हुई है जो कृषि पर अतिरिक्त जनसंख्या भार की ओर संकेत करता है।

देवबन्द और नगीना की व्यावसायिक संरचना में कृषि का स्थान लगभग समान है। इन नगरों की क्रमश: 26.47 और 26.83 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य श्रमशक्ति का निर्माण करती है। देवबन्द में 10.97 प्रतिशत कर्मी कृषक तथा 6.18 प्रतिशत कर्मी कृषि श्रमिक हैं जबकि नगीना की श्रमशक्ति में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों का प्रभाग क्रमश: 9.31 प्रतिशत तथा 7.79 प्रतिशत है। इन नगरों में कृषि में महिलाओं का योगदान अपेक्षाकृत

अल्प है । देवबन्द में जहाँ पुरुष कर्मियों का 11.12 प्रतिशत कृषक और 6.19 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं वहीं महिला कर्मियों में इन क्रियावर्गों का प्रभाग क्रमशः 4.91 और 5.83 प्रतिशत है । इसी प्रकार नगीना में भी पुरुष कर्मियों का 9.51 और 8.04 प्रतिशत क्रमशः कृषक और कृषि श्रमिक हैं जबकि महिला कर्मियों में उक्त क्रिया वर्गों का प्रतिशत क्रमशः 4.06 और 1.02 ही है । यदि लिंगानुपात पर दृष्टिपात किया जाय तो देवबन्द के कृषकों में यह 11 महिलायें और कृषि श्रमिकों में 23 महिलायें प्रति हजार पुरुष हैं । नगीना में उक्त लिंगानुपात क्रमशः 16 और 5 है । पिछले दशक में देवबन्द और नगीना के कृषकों की संख्या में क्रमशः 27.48 और 28.60 प्रतिशत वृद्धि अंकित की गयी जबकि इन्हीं नगरों के कृषि श्रमिकों में 77.38 और 2.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

अतितीव्रगति से वर्द्धमान रायबरेली नगर उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित है । गत दशक में यहाँ की जनसंख्या में 131.39 प्रतिशत और कार्यशील जनसंख्या में 150.60 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी है । सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि उक्त अवधि में इसके कृषकों की संख्या में 509.28 प्रतिशत तथा कृषि श्रमिकों की संख्या में 461.68 प्रतिशत कर्मी की वृद्धि हुई है जो अन्य नगरों की तुलना में अत्यधिक है । रायबरेली की 16.00 प्रतिशत कर्मी जनसंख्या कृषि से जीविकोपार्जन करती है जिसमें 8.96 प्रतिशत कृषक तथा 7.04 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं । पुरुष कर्मियों का 8.96 प्रतिशत और महिला कर्मियों का 9.00 प्रतिशत कृषक है जबकि पुरुष एवं महिला कर्मियों में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 6.79 तथा 11.10 है । कृषक वर्ग में लिंगानुपात 61 महिलायें प्रति हजार पुरुष है जबकि कृषि श्रमिक वर्ग में यह अनुपात 99 महिलायें प्रति हजार पुरुष है । इस प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ कृषि में विशेषरूप से कृषि मजदूर के रूप में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है ।

ललितपुर जो प्रदेश के धुर दक्षिण-पश्चिम में बुन्देलखण्ड के पठारी भाग में स्थित है, के कुल कार्यशील जनसंख्या का 15.54 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा हुआ है जिसमें 12.09 प्रतिशत कृषक तथा 3.45 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं । पुरुष कर्मियों में कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के प्रभाग क्रमशः 12.29 और 3.14 प्रतिशत है जबकि महिला कर्मियों में उक्त क्रिया

वर्गों का प्रभाग क्रमशः 10.16 और 6.44 प्रतिशत है । यहाँ महिलाओं की भागीदारी कृषकों की तुलना में कृषि श्रमिक के रूप में अधिक है । उदाहरणार्थ, प्रति हजार पुरुष कृषकों पर महिला कृषकों की संख्या 85 है जबकि कृषि श्रमिकों में लिंगानुपात 211 महिलायें प्रति हजार पुरुष आता है । गत दशक में ललितपुर की जनसंख्या (61.79 प्रतिशत) और कार्यशील जनसंख्या (63.74 प्रतिशत) में वृद्धि की तुलना में इसके कृषकों (71.43 प्रतिशत) और कृषि श्रमिकों (83.99 प्रतिशत) की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है (तालिका 5.4) ।

सामान्य विशिष्टीकृत वर्ग के अन्य चार नगरों-जौनपुर (13.61), बाँदा 13.48), बस्ती (13.32) और मुगलसराय (13.22) में कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत लगभग समान है । कुल कर्मी जनसंख्या में कृषकों और कृषि श्रमिकों का पृथक्-पृथक प्रतिशत जौनपुर में 8.73 और 4.88, बाँदा में 8.77 और 4.71, बस्ती में 545 और 7.77 तथा मुगल सराय में 6.22 और 6.91 है । इन नगरों में पुरुष कर्मियों का क्रमशः 8.79, 9.08, 5.63 और 6.29 प्रतिशत कृषक हैं जबकि महिला कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत क्रमशः 8.04, 3.04, 3.08 और 4.14 है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इन नगरों में कृषक के रूप में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्त्व नहीं रखती । इसी प्रकार जौनपुर के पुरुष कर्मियों का 4.56 प्रतिशत, बाँदा के पुरुष कर्मियों का 4.79 प्रतिशत, बस्ती के पुरुष कर्मियों का 7.11 प्रतिशत, और मुगलसराय के पुरुष कर्मियों का 6.41 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में कार्यशील हैं । इन नगरों में महिला कर्मियों का क्रमशः 8.81, 3.25, 16.92 और 21.38 प्रतिशत कृषि श्रमिकों के रूप में जीविकोपार्जन में संलग्न है । बुन्देलखण्ड की पठारी भूमि में स्थित बाँदा में महिला कृषि श्रमिकों की भूमिका अत्यल्प है किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के समतल एवं उपजाऊँ तथा कृषि प्रधान क्षेत्र में स्थित जौनपुर, बस्ती और मुगलसराय में अनेक प्रकार के कृषि कार्यों में महिला श्रमिकों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होती है, विशेषरूप से फसलों की रोपाई, निराई (खर-पतवार निकालने), कटाई आदि कार्यों में । जौनपुर, बाँदा, बस्ती और मुगल सराय के कृषक वर्ग में लिंगानुपात क्रमशः 73, 18, 40 और 23 महिलायें प्रति हजार पुरुष हैं जबकि इन्हीं नगरों के कृषि श्रमिकों में लिंगानुपात क्रमशः 154, 36, 173 और 116 महिलायें प्रति हजार पुरुष पाया गया है (तालिका 5.2 एवं 5.3) ।

यदि गत दशक में इन नगरों की जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा कृषि में संलग्न कृषकों एवं कृषिश्रमिकों की संख्या में हुए परिवर्तनों पर दृष्टिपात किया जाय तो इनमें पर्याप्त भिन्नता मिलती है। जौनपुर की कुल जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्रमश: 30.23 प्रतिशत और 27.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु उसी अवधि में कृषकों की संख्या में 7.81 प्रतिशत ह्रास अंकित किया गया है जबकि 10.36 प्रतिशत की वृद्धि कृषिश्रमिकों के आकार में हुआ है। बाँदा की जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और कृषकों तथा कृषि श्रमिकों सभी में वृद्धि हुई है जो क्रमश: 43.11, 36.66, 52.98 और 12.14 प्रतिशत है। बस्ती की जनसंख्या में 39.95 प्रतिशत और कार्यशील जनसंख्या में 27.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कृषकों और कृषि श्रमिकों की संख्या में क्रमश: 1.78 और 23.24 प्रतिशत का ह्रास हुआ है जो सम्भवत: कार्यशील जनसंख्या के अन्य व्यवसायों में स्थानान्तरण के कारण ही सम्भव हो पाया है। मुगलसराय जो प्रधानत: परिवहन नगर है में गत दशक में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी है। इसकी जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्रमश: 141.94 और 115.16 प्रतिशत का विकास हुआ जबकि कृषकों की संख्या में 22 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। कृषिश्रमिकों की संख्या जो 1971 में मात्र 9 थी बढ़कर 1981 में 1193 तक पहुँच गयी। इस प्रकार कृषिश्रमिकों की संख्या दस वर्षों में 132 गुना बढ़ गयी। यह तथ्य मुगलसराय में कृषि में रोजगार वृद्धि तथा कृषि विकास की ओर इंगित करता है।

4. अल्पविशिष्टीकृत नगर

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 29 नगरों में अनेक कुल कार्यशील जनसंख्या का 5.36 प्रतिशत से 12.88 प्रतिशत तक कृषक एवं कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है। ये नगर कृषि में कार्यात्मक गहनता के अनुसार अल्पविशिष्टीकृत नगरों की श्रेणी में रखे गये हैं। उरई (12.60), फैजाबाद (11.76), बिजनौर (11.39), बलिया (10.87), शाहजहाँपुर (10.66), फर्रुखाबाद (10.40), शामली (10.31) और मिर्जापुर-विन्ध्याचल (10.07) में 10 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति कृषि में संलग्न है। कृषि में 8 से 10 प्रतिशत तक संलग्नता वाले नगर हैं - हापुड़, खुर्जा, कासगंज, हरदोई, मैनपुरी, काशीपुर, अमरोहा,

गाजीपुर, देवरिया, गोण्डा, बाराबंकी और चन्दौसी । अन्य नगर जहाँ प्रादेशिक औसत (5.36 प्रतिशत) से अधिक श्रमशक्ति कृषक एवं कृषि श्रमिक के रूप में क्रियाशील है, वे हैं - बदायूँ, नजीबाबाद, आजमगढ़, पीलीभीत, बुलन्दशहर, हरद्वार, रामपुर, टाण्डा और गोरखपुर (तालिका 5.1) ।

कृषि में अल्पविशिष्टीकृत कतिपय नगरों में महिलाओं का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है । बलिया, हापुड़ तथा मिर्जापुर-विन्ध्याचल में कार्यशील महिलाओं का क्रमशः 23.96, 22.51 और 20.84 प्रतिशत भाग कृषि में संलग्न है । इसके विपरीत महिला श्रमशक्ति की कृषि में संलग्नता रामपुर, मैनपुरी, नजीबाबाद, बुलन्दशहर, बाराबंकी और हरद्वार में 3.00 प्रतिशत से भी कम है ।

यद्यपि गत दशक (1971-81) में इस वर्ग के सभी नगरों की जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में 20 से 50 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई है किन्तु इनमें से कतिपय नगरों के कृषि श्रमिकों की संख्या में ह्रास भी हुआ है जिसका प्रमुख कारण श्रमिकों का अन्य व्यवसायों में स्थानान्तरण है । बलिया में कृषकों की संख्या में 33.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके कृषि श्रमिकों की संख्या 34.75 प्रतिशत घट गयी । इसी प्रकार देवरिया में भी 10 वर्षों में कृषकों की संख्या 60.17 प्रतिशत बढ़ गयी किन्तु कृषि श्रमिकों में 54.34 प्रतिशत का ह्रास पाया गया है । गाजीपुर में कृषि श्रमिकों में नाममात्र (1.08 प्रतिशत) की कमी आयी है जबकि कृषकों की संख्या में 27.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हरद्वार (31.34 प्रतिशत), मैनपुरी (8.65 प्रतिशत) और बिजनौर (0.21 प्रतिशत) में कृषकों की संख्या में कमी आयी है जबकि इनके कृषि श्रमिकों की संख्या में 98.72, 36.39 और 27.27 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख है । मिर्जापुर-विन्ध्याचल के कृषकों और कृषि श्रमिकों दोनों की संख्या में ह्रास हुआ जो क्रमशः 31.00 और 31.60 प्रतिशत है (तालिका 5.4) ।

उरई, फैजाबाद, बिजनौर, बलिया, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, खुर्जा, कासगंज, हरदोई, मैनपुरी, काशीपुर, अमरोहा, गाजीपुर, देवरिया, गोण्डा, बाराबंकी, चन्दौसी, बदायूँ, आजमगढ़, पीलीभीत, बुलन्दशहर, रामपुर और गोरखपुर नगरों में कृषि श्रमिकों

की तुलना में कृषकों की संख्या अधिक है किन्तु कतिपय अन्य नगरों में कृषि श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक है । शामली, मिर्जापुर-विन्ध्याचल, हापुड़, नजीबाबाद, हरद्वार, और टाण्डा में कृषि श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक हैं । उरई में कुल कर्मियों का 8.38 प्रतिशत कृषक हैं जो इस वर्ग का अधिकतम है जबकि कृषकों का न्यूनतम 1.16 प्रतिशत हरद्वार में प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार कृषि श्रमिकों का अधिकतम प्रतिशत मिर्जापुर-विन्ध्याचल (7.76) में अंकित किया गया है और न्यूनतम (1.22 प्रतिशत) रामपुर में पाया गया है ।

कृषकों तथा कृषि श्रमिकों में पुरुषों और महिलाओं के सापेक्ष योगदान पर विचार करने से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सम्मुख आते हैं । कृषक वर्ग में गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर-विन्ध्याचल, बलिया और फैजाबाद में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है जहाँ क्रमशः 147, 127, 85, 76 और 70 महिलायें प्रति हजार पुरुष सक्रिय हैं और इसके विपरीत यह अनुपात मैनपुरी (5), हापुड़ (7), बाराबंकी (8), हरद्वार (9), काशीपुर (10), बदायूँ (10), बुलन्दशहर (10) और रामपुर (11) में अत्यल्प है । वास्तव में कृषि में संलग्न अधिकतर महिलायें श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं जिसके कारण कुछ ही नगरों को छोड़कर, शेष में लिंगानुपात 50 महिलायें प्रति हजार से अधिक हैं । अल्प-विशिष्टीकृत वर्ग के नगरों के कृषि श्रमिकों में सर्वाधिक लिंगानुपात (312 महिलायें प्रति हजार पुरुष) मिर्जापुर-विन्ध्याचल में पाया गया है जिसके पश्चात् बलिया (229), देवरिया (203), हापुड़ (190), टाण्डा (154), फैजाबाद (145), खुर्जा (104), गोण्डा (88) और आजमगढ़ (84) नगर आते हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्धन एवं भूमिहीन पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों की महिलायें अन्य उपयुक्त कार्यों के अभाव में दूसरे व्यक्तियों के खेतों पर काम करके मजदूरी के रूप में जीविका प्राप्त करती हैं ।[7] उदाहरणार्थ, मिर्जापुर-विन्ध्याचल में 17.35 प्रतिशत, बलिया में 15.93 प्रतिशत, फैजाबाद में 11.50 प्रतिशत और देवरिया में 10.79 प्रतिशत कार्यशील महिलायें कृषि श्रमिक हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुर्जा विशेष उल्लेखनीय है जहाँ कुल महिला कर्मियों का 21.93 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में क्रियाशील है ।

5.5 अविशिष्टीकृत नगर

प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 66 नगरों में से 25 नगर इस वर्ग में आते हैं जहाँ प्रादेशिक औसत (5.36 प्रतिशत) से कम श्रमशक्ति कृषि में संलग्न है । इनमें 18 प्रथम श्रेणी के और 7 द्वितीय श्रेणी के नगर हैं । सामान्यतया नगरीय आकार में वृद्धि के साथ उसकी कार्यात्मक संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होता है । जहाँ लघु नगरों में कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्रियायें मुख्य होती है वहीं वृहत् नगरों मे प्राथमिक क्रियाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है और द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियायें प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती हैं । उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में भी यह तथ्य लागू होता है । क्वाल (KAVAL) नगरों-कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 18 नगरो की व्यावसायिक संरचना में कृषि का प्रभाग अत्यल्प है । लखनऊ, आगरा, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, मोदीनगर और रुड़की मे 3.00 प्रतिशत से भी कम श्रमशक्ति कृषि मे संलग्न है । इनमें फिरोजाबाद में कृषि का स्थान सर्वाधिक नगण्य है जहाँ कुल श्रमशक्ति मे कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रभाग मात्र 0.50 प्रतिशत ही है (तालिका 5.2 एवं 5.3) ।

कतिपय अविशिष्टीकृत नगरों में महिलाओं का कृषि में भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है । उदाहरणार्थ - मेरठ में कुल महिला श्रमशक्ति का 6.32 प्रतिशत, कानपुर मे 5.98 प्रतिशत, झाँसी में 5.95 प्रतिशत और हलद्वानी-काठगोदाम मे 5.37 प्रतिशत कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है । इसी प्रकार यदि कृषि में पुरूषो तथा महिलाओं के अनुपात पर दृष्टिपात किया जाय तो हम पायेंगे कि झाँसी में प्रति हजार पुरूषों पर 183 महिलायें कृषक हैं । कृषक वर्ग में यह लिंगानुपात हलद्वानी-काठगोदाम (138), मऊ-नाथ भंजन (103) और देहरादून (88) में भी अपेक्षाकृत अधिक है । कृषि श्रमिकों के मामले मे झाँसी सर्वोपरि है जहाँ प्रति हजार पुरूष श्रमिकों पर 228 महिला श्रमिक हैं । इसके पश्चात् मथुरा (190), मऊनाथ भंजन (176), इलाहाबाद (152), कानपुर (134), वाराणसी (115), मोदीनगर (107) और देहरादून (98) आते हैं ।

5.6 कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता के कतिपय जनांकिकीय सहचर

कृषि को अनगरीय कार्य माना जाता है जो ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में अन्तर स्पष्ट करने का प्रमुख मापदण्ड है ।[8] नगरीकरण में वृद्धि का कृषि प्रकार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार किसी नगर की कुल कार्यशील जनसंख्या या कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात, साक्षरता एवं कृषि कार्यों में लिंगानुपात का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध उसकी श्रमशक्ति मे कृषकों और कृषि श्रमिकों के अनुपात से होता है । कृषि में विशिष्टीकरण एवं उपरोक्त जनांकिकीय सहचरों के मध्य पाये जाने वाले सहसम्बन्धों का सांख्यकीय विश्लेषण अगली पंक्तियों में किया गया है (चित्र 5.3)।

1. जनसंख्या आकार

कृषि प्रधानतया ग्रामीण व्यवसाय है और अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध कार्यों से जीविका प्राप्त करती है । अधिवासों के आकार में वृद्धि के साथ-साथ अन्य व्यवसाय भी पनपने लगते हैं और कृषि में संलग्न श्रमशक्ति का प्रभाग क्रमशः घटने लगता है । इसी क्रम में नगरों के जनसंख्या आकार में वृद्धि होने पर कृषि मे विशिष्टीकरण मे ह्रास होता है । लघु नगरों में प्रायः कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत वृहत् (नगरों की तुलना में अधिक पाया जाता है किन्तु स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक पर्यावरण के प्रभाव से उक्त तथ्य यथावत नहीं पाया जाता बल्कि अनेक अपवाद भी मिलते हैं । उत्तर प्रदेश के 66 वृहत् नगरों के संदर्भ में जनसंख्या आकार और कृषि मे विशिष्टीकरण गहनता के मध्य परिकलित सहसम्बन्ध गुणांक - 0.30 है जो दोनों चरों के मध्य ऋणात्मक एवं सामान्य सहसम्बन्ध का संकेतक है । इस सम्बन्ध का समाश्रयण समीकरण $Y = 6.93 - 0.082x$ है जो स्पष्ट करता है कि जनसंख्या में प्रति इकाई (दस हजार) वृद्धि होने पर कार्यात्मक गहनता में 0.082 इकाई का ह्रास होगा जबकि 6.93 स्थिरांक है । इसे सरल समाश्रयण रेखा द्वारा चित्र 5.3ए में भी प्रदर्शित किया गया है ।

2. कार्यशील जनसंख्या

जनसंख्या आकार की ही भाँति कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होने पर

श्रमशक्ति का स्थानान्तरण कृषि के अतिरिक्त कार्यों में होने लगता है । प्रस्तुत अध्ययन में यह प्राप्त हुआ है कि कृषि मे अधिक विशिष्टीकृत नगरो में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सामान्यतया कम है जबकि अविशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है । इस प्रकार कार्यशील जनसंख्या के अनुपात तथा कृषि में विशिष्टीकरण गहनता के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक -0.404 पाया गया है जो दोनों चरों में ऋणात्मक किन्तु प्रभावशाली सहसम्बन्ध को व्यक्त करता है । उक्त सहसम्बन्ध की अभिव्यक्ति हेतु परिकलित समाश्रयण समीकरण $Y = 52.27 - 1.85 x$ प्राप्त हुआ है जिससे विदित होता है कि क्रियाशील जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत) में प्रति इकाई वृद्धि होने पर कार्यात्मक विशिष्टीकरण मे 1.850 इकाई का ह्रास हो जाता है जबकि 52.270 स्थिरांक है । सरल समाश्रयण रेखा का प्रदर्शन चित्र 5.3बी. में किया गया है ।

3. साक्षरता

कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है जिसके लिए शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती । कृषक एवं कृषि श्रमिक सामान्यतया अशिक्षित एवं अकुशल होते हुए भी कृषि के विभिन्न कार्यों में संलग्न होकर अपना योगदान देते हैं । द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों मे शिक्षा तथा प्रशिक्षण आवश्यक होते हैं जबकि कृषि में निरक्षरता भी विशेष बाधक नहीं होती है । साक्षरता के विकास के साथ ही जनसंख्या अन्य कार्यों की ओर गतिशील होने लगती है । इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में साक्षरता एवं कृषि में विशिष्टीकरण गहनता के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक -0.495 प्राप्त हुआ है जो दोनों चरों मे ऋणात्मक और प्रभावशाली सहसम्बन्ध को स्पष्ट करता है । इसके लिए परिकलित समाश्रयण समीकरण $Y = 25.99 - 0.40x$ है जिससे स्पष्ट है कि साक्षरता में प्रति इकाई वृद्धि होने पर कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता मे -0.40 इकाई का ह्रास सम्भावित है जबकि 25.99 स्थिरांक है । इस सहसम्बन्ध का रैखिक प्रदर्शन चित्र 5.3सी. में किया गया है ।

4. लिंगानुपात

कृषि कार्यों मे महिलाओ को भी काम करने के अवसर प्राप्त होते है । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि श्रमिकों के रूप मे असंख्य महिलायें खेती मे संलग्न पायी जाती हैं किन्तु नगरो मे श्रमिक महिलायें अन्य कार्यों मे संलग्न होती हैं जहाँ उन्हे अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है जैसे निर्माणकार्य एवं गृह उद्योग । अनेक महिलाऐं कृषक के रूप मे भी खेती से सम्बद्ध होती है । इस प्रकार नगरों मे कृषि कार्यों मे महिलायें कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप मे संलग्न होती हैं किन्तु उनका योगदान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है । कृषि में विशिष्टीकरण गहनता तथा लिंगानुपात के मध्य परिकलित सहसम्बंध गुणांक + 0.03 प्राप्त हुआ है जो धनात्मक किन्तु अत्यल्प सहसम्बन्ध का सूचक है । इस सहसम्बन्ध की अभिव्यक्ति समाश्रयण समीकरण $Y = 51.92 + 0.20x$ से भी हो जाती है जो स्पष्ट करता है कि कार्यात्मक विशिष्टीकरण में प्रति इकाई वृद्धि होने पर लिंगानुपात में 0.20 इकाई की वृद्धि सम्भावित है जबकि 51.92 स्थिरांक है । चित्र 5.3डी. में प्रदर्शित सरल समाश्रयण रेखा इसी सहसम्बन्ध को व्यक्त करती है ।

सन्दर्भ

1. Census of India 1951, Vol.II, Uttar Pradesh, Part I-A, Report.
2. Census of India 1961, Uttar Pradesh, Part II-B (iii), General Economic Tables.
3. Census of India 1981, Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.
4. Ibid.
5. Maurya, S.D. : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, 1988, p.186.

6. मौर्य, साहबदीन एवं गायत्रीदेवी, "उत्तर प्रदेश की श्रमशक्ति में महिला योगदान", विकासशील भूगोल पत्रिका, वर्ष 4, संख्या 1 एवं 2, 1985, पृष्ठ 24.

7. Singh, H.D,: "Occupational Distribution of Population in Eastern Uttar Pradesh - A Study in Geographical Background, D.Phil. Thesis (unpublished) University of Allahabad, 1978.

8. सिंह, राम नगीना एवं साहबदीन : "पूर्वी उत्तर प्रदेश में नगरीकरण", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 14, सं0 2, 1978, पृष्ठ 83-96.

अध्याय छः

गृह उद्योग

6.1 भूमिका

उत्तर प्रदेश में जहाँ वृहत् उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में लघु एवं गृह उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पर्याप्त पूँजी की कमी, औद्योगिक कच्चे पदार्थों एवं शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता के कारण जहाँ एक ओर वृहत् औद्योगिक इकाइयों को संस्थापित करना कठिन कार्य है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में जनसंख्या की अधिकता तथा रोजगार के अवसर की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों में प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि हेतु गृह उद्योगों का विकास ही सर्वाधिक उपयोगी युक्ति प्रतीत होती है। शताब्दियों से प्रदेश की जनता लघु एवं गृह उद्योगों से धनोपार्जन करके जीविका यापन करती रही है। वास्तव में गृह उद्योग हमारी आर्थिक प्रणाली के अभिन्न अंग रहे हैं जिनमें न्यूनतम पूँजी से अधिकतम रोजगार प्रदान करने की क्षमता विद्यमान होती है।

सर्वप्रथम भारतीय जनगणना 1961[1] में गृह-उद्योग को कार्यों के एक पृथक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। जनगणना 1971[2] में विनिर्माण, सेवा तथा मरम्मत में संलग्न कर्मियों को दो उपवर्गों में विभक्त किया गया था - 1. गृह उद्योग और 2. गृह उद्योग के अतिरिक्त उद्योग। जनगणना 1981[3] में समस्त मुख्य कर्मियों को चार प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है जिनमें से तीसरा वर्ग 'गृह उद्योग' का है। प्रस्तुत अध्याय में उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना में गृह उद्योगों पर प्रकाश डाला गया है जिसके अन्तर्गत गृह उद्योगों की प्रकृति, भूमिका और महत्व को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस जनांकिकीय अध्ययन में उन नगरीय इकाइयों के गृह उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है जिनकी कार्यात्मक संरचना में गृह उद्योगों का विशिष्ट स्थान है। परिणामों के परिमाणात्मक परीक्षण के उद्देश्य से गृह उद्योगों और उससे सम्बद्ध कतिपय जनांकिकीय चरों के मध्य पाये जाने वाले सहसम्बन्धों का आंकलन सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया है।

6.2 गृह उद्योग की परिभाषा

जनगणना 1981 में गृह उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है[4]: "गृह उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं और मुख्यत: परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव की सीमा के अन्तर्गत और नगरीय क्षेत्रों में उस मकान के अन्दर या अहाते में जिसमें परिवार रहता है, चलाया जाता है। मुखिया को सम्मिलित करके गृह उद्योग में अधिकतर कार्यकर्त्ता परिवार के ही होने चाहिए। उद्योग इस पैमाने पर नहीं होना चाहिए कि भारतीय कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने योग्य हो या होने में आता हो।"

गृह उद्योग का मुख्य आधार परिवार के एक या अधिक सदस्यों का संलग्न होना है। यही मापदण्ड नगरीय क्षेत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। नगरीय क्षेत्रों में जहाँ संगठित उद्योग अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व रखते हैं, गृह उद्योग उस परिसर में होना चाहिए जहाँ इसके सहभागी/सहकर्मी रहते हों। नगरीय क्षेत्रों में यदि परिवार के सदस्यों द्वारा एक उद्योग संचालित किया जाता है जो उनके निवास के परिसर से दूरी पर हो, तो वह गृह उद्योग नहीं माना जायगा। इसे मकान के परिसर के भीतर स्थित होना चाहिए जहाँ परिवार के सदस्य रहते हों।

गृह उद्योग वस्तुओं के उत्पादन, प्रक्रमण, सेवा कार्य, मरम्मत या बनाने और विक्रय (किन्तु केवल विक्रय नहीं) से सम्बन्धित होना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता, चिकित्सक, नाई, संगीतज्ञ, नर्तक, धोबी, ज्योतिषी आदि द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय या केवल ऐसे व्यापार या व्यवसाय या सेवायें जो भले ही परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर चलाये जाते हों, गृह उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

6.3 कार्यशील जनसंख्या

1981 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में कुल 2,52,195 व्यक्ति गृह उद्योग में कार्यरत थे जिनमें 2,26,664 पुरुष

और 25,531 स्त्रियाँ थीं । कुल कार्यशील जनसंख्या का 7.37 प्रतिशत इसी उद्योग में संलग्न है जबकि यह प्रतिशत पुरूष कर्मियों के लिए 6.73 और स्त्री कर्मियों के लिए 15.16 आता है । यद्यपि पारिवारिक आधार पर सम्पादित होने वाले गृह उद्योग मुख्यता ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं किन्तु नगरीय केन्द्रों के अर्थ-तंत्र एवं व्यावसायिक संरचना में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है ।[5] गृह उद्योगों का महत्व सामान्यतया बड़े नगरों की अपेक्षा छोटे नगरीय इकाइयों के लिए अधिक है । प्रदेश के प्रथम श्रेणी के नगरों में औसतन 7.25 प्रतिशत मुख्य श्रमिक गृह उद्योग में लगे हुए हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के नगरों में यह अनुपात 7.88 प्रतिशत पाया गया है । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में पुरूष कर्मियों का 7.02 और 6.73 प्रतिशत तथा स्त्री कर्मियों का 11.70 और 27.64 प्रतिशत गृह उद्योग में संलग्न है ।

गृह उद्योग में श्रमिकों की संलग्नता का प्रतिशत विभिन्न नगरों में पृथक-पृथक मिलता है जिनमें काफी अन्तर पाया जाता है । जहाँ एक ओर मऊनाथ भंजन में 62.74 प्रतिशत और टाण्डा में 39.30 प्रतिशत श्रमिक गृह उद्योग में संलग्न हैं वहीं दूसरी ओर कई नगर ऐसे हैं जहाँ गृह उद्योग में श्रमिकों का प्रतिशत दो से भी कम है। ये नगर हैं : रूड़की, देहरादून और एटा । यदि पुरूष और स्त्री श्रमिकों की भागीदारी पर पृथक-पृथक विचार किया जाय तो अधिक उपयोगी तथ्य सम्मुख प्रकट होते हैं । सामान्यतया अधिकांश नगरों में उनके कुल पुरूष श्रमिकों का गृह उद्योग में संलग्नता अनुपात स्त्री श्रमिकों की तुलना में कम है । प्रदेश के समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल पुरूष श्रमिकों का 6.73 प्रतिशत गृह उद्योग में कार्यरत है जबकि इसमें कुल स्त्री श्रमिकों का 15.16 प्रतिशत संलग्न है । पुरूष श्रमिकों में गृह उद्योग का सर्वाधिक प्रभाग 53.80 प्रतिशत मऊनाथ भंजन में पाया गया है जिसके पश्चात् टाण्डा (36.14), वाराणसी (22.01), मिर्जापुर-विन्ध्याचल (18.36) और अमरोहा (14.24) का स्थान है । इन्हीं नगरों में स्त्री श्रमिकों की संलग्नता का प्रतिशत क्रमश: 90.20, 59.67, 27.66, 18.13 और 49.19 है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रूड़की, देहरादून, एटा, गोण्डा, उरई, हल्द्वानी-काठगोदाम, पीलीभीत, बदायूँ, माजियाबाद, हरद्वार और काशीपुर (कुल 11 नगर) में पुरूष

श्रमिकों का 3.00 प्रतिशत से कम प्रभाग गृह उद्योग में लगा हुआ है जबकि इसके विपरीत केवल 3 नगर - लखीमपुर, बस्ती और हरदोई ही ऐसे हैं जहाँ इस क्रिया-वर्ग में स्त्री श्रमिकों का 3.00 प्रतिशत से कम अंश संलग्न है ।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में गृह उद्योग में कार्यरत पुरूषों एवं स्त्रियों के अनुपात ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात का सहारा लिया जा सकता है । प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में कुल श्रमिकों में औसत लिंगानुपात 113 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरूष है । गृह उद्योग जो अधिकांशतः परिवार के सदस्यों द्वारा अपने घर में ही संचालित होता है, महिलाओं के लिए शुभावसर प्रदान करता है जिससे गृह उद्योग महिलाओं में अधिक लोकप्रिय है ।[6] गृह उद्योग में लिंगानुपात किसी भी अन्य क्रिया-वर्ग से अधिक पाया जाता है । प्रदेश स्तर पर 66 नगरों में औसत लिंगानुपात कृषक वर्ग में 36, कृषि श्रमिक वर्ग में 79 और विविध क्रिया-वर्ग में 46 आता है जबकि गृह उद्योग में यह अनुपात 113 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरूष है । गृह उद्योग में सर्वाधिक लिंगानुपात (549) मऊनाथ भंजन में अंकित किया गया है जिसके पश्चात् झाँसी (488), काशीपुर (425), इटावा (394), नगीना (262), टाण्डा (256), ललितपुर (247) और अमरोहा (240) आते हैं । इस क्रिया-वर्ग का न्यूनतम लिंगानुपात (22 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरूष) मुरादाबाद में पाया गया है । निम्न लिंगानुपात वाले अन्य नगरों में लखीमपुर, सम्भल, मोदीनगर, हरदोई, आगरा, कानपुर, सहारनपुर आदि प्रमुख हैं जहाँ लिंगानुपात 50 से कम पाया जाता है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम श्रेणी के नगरों में गृह उद्योग अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है और फलतः इसमें स्त्रियों की भागीदारी भी कम है । इस प्रकार प्रथम श्रेणी के 30 नगरों के गृह उद्योग में प्रति 1000 पुरूष औसतन 84 स्त्रियाँ कार्यरत हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के 36 नगरों के लिए यह अनुपात 241 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरूष है जो पहले का लगभग तीन गुना है ।

6.4 गृह उद्योग में विशिष्टीकरण

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में 7.37 प्रतिशत श्रमिक गृह उद्योगों में लगे हुए हैं। अनेक नगरों में यह प्रतिशत माध्य से कम है जबकि कतिपय नगरों में गृह उद्योगों में श्रमिकों की संलग्नता प्रदेश के औसत से अधिक भी है। गृह उद्योग में विशिष्टीकरण की दृष्टि से यहाँ यह कल्पित है कि किसी भी नगर में प्रदेश के उपर्युक्त औसत (7.37 प्रतिशत) से इस क्रिया-वर्ग में अधिक संलग्नता अमुक नगर में गृह उद्योग के विशिष्टीकरण का सूचक होगा। इस प्रकार 18 नगर गृह उद्योग में विशिष्टीकृत माने गये हैं जहाँ प्रादेशिक माध्य से अधिक श्रमशक्ति उक्त क्रिया-वर्ग में संलग्न है। पुन: इन विशिष्टीकृत नगरों को कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (कुल श्रमिकों में गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत) के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है जिसका निर्धारण प्रादेशिक माध्यम (7.37) से परिकलित मानक विचलन (9.20) द्वारा किया गया है। विशिष्टीकृत नगरों के 4 वर्ग अवरोहीक्रम में इस प्रकार हैं :

1. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 3 मा०वि० से ऊपर),
2. अधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 2 मा०वि० से ऊपर),
3. सामान्य विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 1 मा०वि० से ऊपर),
4. अल्प विशिष्टीकृत नगर (माध्य से ऊपर)।

विशिष्टीकृत नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण के परास (Range) निम्नवत हैं :

क्र० स०	नगरों के प्रकार	कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (प्रतिशत में)
1.	अत्यधिक विशिष्टीकृत	34.97 से ऊपर
2.	अधिक विशिष्टीकृत	25.78 - 34.97
3.	सामान्य विशिष्टीकृत	16.58 - 25.77
4.	अल्प विशिष्टीकृत	7.37 से ऊपर

1. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर

गृह उद्योग में विशिष्टीकरण प्राप्त कुल 18 नगरों में से दो - मऊनाथ भंजन और टाण्डा अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर हैं जहाँ कुल कर्मी जनसंख्या का क्रमश: 62.78 और 39.30 प्रतिशत गृह उद्योग में संलग्न है । गृह उद्योग में उत्पादित वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के उक्त दोनों केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जहाँ वृहत् पैमाने के उद्योगों का लगभग अभाव है ।

उत्तर प्रदेश में गृह उद्योग में सर्वाधिक विशिष्टीकृत मऊनाथ भंजन (जनसंख्या 86,326) द्वितीय श्रेणी का नगर है जहाँ 27,213 व्यक्ति मुख्य कर्मी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इस प्रकार यहाँ 31.52 प्रतिशत जनसंख्या सक्रिय रूप से आर्थिक कार्यों में संलग्न है जो प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के औसत (26.53 प्रतिशत) से 5 प्रतिशत अधिक है । मऊनाथ भंजन में सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत (2.61) भी प्रदेश के अन्य नगरों की तुलना में काफी अधिक है । मुख्य कर्मियों और सीमान्त कर्मियों को मिलाने पर कुल श्रमिकों का प्रतिशत 34.13 हो जाता है । गत दशक (1971-81) में मऊनाथ भंजन की जनसंख्या में 34.76 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है किन्तु मुख्य श्रमिकों की संख्या में मात्र 11.58 प्रतिशत वृद्धि हुई है । गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या में 12.37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जो प्रदेश के औसत (35.71 प्रतिशत) तथा अन्य नगरों की तुलना में काफी कम है ।

मऊनाथ भंजन में गृह उद्योग में संलग्न 17,085 कर्मियों में से 11,027 पुरुष और 6,058 स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार गृह उद्योग में पुरुषों और स्त्रियों का प्रभाग क्रमश: 64.40 और 35.60 प्रतिशत है । इस उद्योग में स्त्रियों का योगदान सबसे अधिक मऊनाथ भंजन को ही प्राप्त है जो प्रति 1000 पुरुषों पर 549 है । यह लिंगानुपात प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के औसत (113) का लगभग पाँच गुना है और उक्त श्रेणियों के किसी भी नगर से अधिक है । उल्लेखनीय है कि मऊनाथ भंजन की अधिकांश जनसंख्या मुसलमान है और मुख्य रूप से हस्तकरघा उद्योग में संलग्न हैं । हस्तकरघा उद्योग से सम्बद्ध अनेक कार्य स्त्रियाँ कर लेती हैं और कुछ कार्य तो

तालिका 6.1

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में गृह उद्योग में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

क्र0 सं0	नगर	कुल मुख्य श्रमिकों से गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत			गृह उद्योग में स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष
		कुल कर्मी	पुरुष कर्मी	स्त्री कर्मी	
1	2	3	4	5	6
1.	मऊनाथ भंजन	62.78	53.80	90.20	549
2.	टाण्डा	39.30	36.14	59.67	256
3.	वाराणसी	22.30	22.01	27.66	70
4.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	18.34	18.36	18.13	54
5.	अमरोहा	16.51	14.24	49.19	240
6.	इटावा	14.28	11.03	56.22	394
7.	ललितपुर	12.34	10.91	26.20	247
8.	सम्भल	11.16	11.09	14.59	29
9.	जौनपुर	9.99	9.55	15.40	129
10.	अलीगढ़	9.84	9.89	8.49	34
11.	मेरठ	9.32	9.20	11.68	63
12.	गाजीपुर	8.94	8.57	14.04	120
13.	बाराबंकी	8.82	8.15	24.61	128
14.	नजीबाबाद	8.20	7.42	26.60	153
15.	गोरखपुर	8.14	7.86	13.05	94
16.	रामपुर	7.88	7.08	23.79	139
17.	मुरादाबाद	7.75	7.78	6.47	22
18.	झाँसी	7.72	5.81	23.67	488
19.	आगरा	7.35	7.35	7.62	35
20.	आजमगढ़	7.27	7.14	8.94	92
21.	फर्रुखाबाद	7.17	6.60	22.08	129
22.	हाथरस	6.88	6.39	20.52	116
23.	बाँदा	6.67	6.24	14.86	125
24.	कासगंज	6.55	5.95	21.46	146
25.	शाहजहाँपुर	6.54	6.31	13.72	71
26.	फैजाबाद	5.46	5.43	5.94	74

1	2	3	4	5	6
27.	बरेली	5.36	5.19	9.20	76
28.	बलिया	5.34	5.26	6.74	74
29.	लखनऊ	5.26	5.33	4.18	51
30.	सहारनपुर	5.08	5.04	6.25	46
31.	लखीमपुर	5.08	5.18	2.27	24
32.	फतेहपुर	5.03	5.07	4.42	57
33.	बुलन्दशहर	4.97	4.69	11.61	113
34.	खुर्जा	4.97	4.89	6.81	60
35.	देवबन्द	4.85	4.68	11.66	61
36.	मैनपुरी	4.83	4.70	8.33	67
37.	नगीना	4.73	3.89	27.03	262
38.	इलाहाबाद	4.51	4.28	8.26	117
39.	सीतापुर	4.50	4.20	10.07	128
40.	रायबरेली	4.33	4.28	5.12	73
41.	चन्दौसी	4.27	4.11	9.09	75
42.	उन्नाव	4.22	4.15	5.63	61
43.	हापुड़	4.19	3.81	12.09	150
44.	मोदीनगर	4.12	4.15	3.28	30
45.	देवरिया	4.12	4.14	3.73	51
46.	बहराइच	4.10	3.96	7.95	76
47.	काशीपुर	4.05	2.96	29.75	425
48.	मुजफ्फर नगर	4.00	3.86	7.61	73
49.	मथुरा	3.88	3.78	6.25	73
50.	बस्ती	3.86	4.11	2.91	54
51.	फिरोजाबाद	3.80	3.50	12.04	127
52.	कानपुर	3.63	3.61	3.99	46
53.	बिजनौर	3.61	3.33	8.60	146
54.	हरदोई	3.60	3.65	2.55	34
55.	मुगल सराय	3.36	3.31	4.83	51
56.	शामली	3.14	3.08	5.19	52
57.	बदायूँ	2.93	2.71	8.20	125
58.	हरद्वार	2.82	2.76	4.15	67
59.	पीलीभीत	2.75	2.45	9.55	171
60.	गाजियाबाद	2.74	2.68	3.94	75

1	2	3	4	5	6
61.	उरई	2.41	2.32	4.60	73
62.	हल्द्वानी-काठगोदाम	2.29	2.22	3.74	80
63.	गोण्डा	2.14	2.04	4.56	90
64.	एटा	1.59	1.52	3.32	89
65.	देहरादून	1.49	1.35	3.38	19[illegible]
66.	रुड़की	1.41	1.33	3.79	103
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		7.37	6.73	15.16	113

अधिकांशतः स्त्रियों द्वारा ही किये जाते हैं। अतः यहाँ आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है।

हस्त करघा उद्योग मऊनाथ भंजन का वृहत्तम गृह उद्योग है। यहाँ हस्त करघे द्वारा सूती साड़ियाँ, चादरें, धोतियाँ, तौलिये, गमछे आदि वस्त्रों को निर्मित किया जाता है। मऊनाथ भंजन सूतों की रंगाई और वस्त्रों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। गत दो दशकों में शक्ति चालित करघों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे बुनकरों की कार्यक्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इन करघों को सूत की आपूर्ति हेतु यहाँ सूत कातने का कारखाना स्थापित किया गया है।

टाण्डा उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख नगर है जहाँ गृह उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। 1981 जनगणना के अनुसार टाण्डा की जनसंख्या 54,474 है जिसमें 15,839 मुख्य कर्मी हैं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रभाग 29.08 प्रतिशत है। यहाँ सीमान्त श्रमिक कम हैं जिसका प्रभाग 0.18 प्रतिशत ही है। गत दशक (1971-81) में टाण्डा की कुल जनसंख्या और कर्मी जनसंख्या में क्रमशः 30.91 और 20.56 प्रतिशत वृद्धि हुई है किन्तु गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों में मात्र 2.13 प्रतिशत की ही वृद्धि अंकित की गयी है जो यहाँ के गृह उद्योग के विकास की प्रौढ़ावस्था तथा स्थायित्व का सूचक है। यहाँ 1971 में कुल कार्यशील जनसंख्या का

तालिका 6.2

विशिष्टीकृत नगरों के कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं गृह उद्योग में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत भिन्नता

क्र0 सं0	नगर	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत	दशकीय भिन्नता (1971-81)		
			कुल जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	गृह उद्योग में संलग्न कर्मी
1	2	3	4	5	6
1.	मऊनाथ भंजन	31.52	+34.76	+11.58	+ 12.37
2.	टाण्डा	29.08	+30.91	+20.56	+ 2.13
3.	वाराणसी	26.38	+31.39	+25.41	+ 16.83
4.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	27.42	+20.62	+16.59	+276.79
5.	अमरोहा	26.24	+36.25	+42.38	+167.12
6.	इटावा	25.65	+30.60	+27.79	+ 36.48
7.	ललितपुर	26.88	+61.79	+63.74	+113.51
8.	सम्भल	26.29	+25.38	+20.12	- 22.49
9.	जौनपुर	24.93	+30.23	+27.00	+121.10
10.	अलीगढ़	25.02	+27.17	+22.88	+ 84.47
11.	मेरठ	28.26	+45.92	+44.23	+145.54
12.	गाजीपुर	23.50	+33.07	+27.84	+ 73.84
13.	बाराबंकी	27.89	+43.40	+36.92	+221.43
14.	नजीबाबाद	26.12	+29.41	+28.01	+ 58.52
15.	गोरखपुर	24.09	+33.17	+21.56	+ 50.17
16.	रामपुर	27.66	+26.76	+26.15	+143.32
17.	मुरादाबाद	27.57	+26.66	+31.22	+ 60.74
18.	झाँसी	25.04	+43.41	+45.02	+ 73.94
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर		26.94	+35.29	+32.06	+ 35.71

46.4 प्रतिशत गृह उद्योग में लगा हुआ था किन्तु यह 1981 में घटकर 39.30 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार गृह उद्योग के प्रभाग में 7.10 प्रतिशत का ह्रास हुआ है ।

टाण्डा के गृह उद्योग में कुल 6,224 व्यक्ति संलग्न हैं जिनमें 4,956 पुरुष

और 1,268 स्त्रियाँ हैं। इस प्रकार यहाँ गृह उद्योग में पुरुषों तथा स्त्रियों का प्रभाग क्रमशः 66.96 और 23.04 प्रतिशत आता है और लिंगानुपात 256 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है। मऊनाथ भंजन की ही भाँति टाण्डा भी मुसलमान-बहुल नगर है जहाँ सूतीवस्त्र उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ मुसलमान स्त्रियाँ परिवार के सदस्यों के साथ विविध प्रकार के कार्यों में सहयोग करती हैं। उल्लेखनीय है कि टाण्डा के गृह उद्योग में लिंगानुपात वर्ष 1971 (200 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष) की तुलना में 56 अधिक हैं जो स्त्रियों की सक्रियता की ओर इंगित करता है।

टाण्डा में हस्तकरघा तथा शक्ति चालित करघा दोनों कार्य कर रहे हैं जिनसे मुख्यतया सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ सूती साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, तौलिये, गमछे, चादरें आदि अधिक बनाये जाते हैं। गत एक दशक के भीतर शक्ति चालित करघों द्वारा टेरीकाट वस्त्र का उत्पादन किया जाने लगा है जो गृह उद्योग के अन्तर्गत ही आते हैं। गृह उद्योग में सेंथिटिक वस्त्रों का उत्पादन सूती वस्त्रों का स्थान लेता जा रहा है और साथ ही हस्तकरघे कम होते जा रहे हैं तथा शक्तिचालित करघे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार टाण्डा के सूती वस्त्र उद्योग में रोजगार में क्रमशः गिरावट आ रही है जो इस उद्योग के विकास में मुख्य बाधक हो गयी है।

2. <u>सामान्य विशिष्टीकृत नगर</u>

गृह उद्योगों के दो सामान्य विशिष्टीकृत नगर हैं - वाराणसी और मिर्जापुर विन्ध्याचल जो एक-दूसरे से अत्यन्त निकट गंगा नदी के क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर स्थित हैं। दोनों ही प्रथम श्रेणी के नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1981 में क्रमशः 797,162 और 127,787 थी। वाराणसी में मुख्य कर्मियों का 22.30 प्रतिशत और मिर्जापुर-विन्ध्याचल में 18.34 प्रतिशत गृह उद्योग से सम्बद्ध है।

गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों की दृष्टि से वाराणसी प्रदेश का वृहत्तम नगर है जहाँ 46,904 श्रमिक गृह उद्योग में कार्यरत हैं। गत दशक (1971-81) में वाराणसी की कुल जनसंख्या और कर्मी जनसंख्या में क्रमशः 31.39 और 25.41 प्रतिशत की

वृद्धि हुई है जो प्रादेशिक औसत (क्रमशः 35.29 एवं 32.06 प्रतिशत) से कम है । गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या में मात्र 16.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों में औसत वृद्धि 35.71 प्रतिशत अंकित की गयी है । प्रथम श्रेणी के नगरों में यह वृद्धि 38.44 प्रतिशत थी ।

वाराणसी में गृह उद्योग में संलग्न 46,904 श्रमिकों में से 43,833 पुरूष हैं और 3,073 स्त्रियाँ । इस प्रकार यहाँ गृह उद्योग में कार्यरत पुरूषों और स्त्रियों के प्रभाग क्रमशः 93.66 और 6.34 प्रतिशत हैं । वाराणसी के गृह उद्योग में स्त्रियों की संलग्नता अत्यन्त कम है जिसके लिए सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक उत्तरदायी हैं । यहाँ गृह उद्योग में प्रति हजार पुरूष स्त्रियों की संख्या मात्र 70 आती है जो प्रदेश के अनेक विशिष्टीकृत नगरों तथा प्रदेश के अन्य 66 वृहद् नगरों के औसत (113) से काफी कम है ।

रेशम हस्तकला, ताँबे और पीतल की जरी, आभूषण, सोने के धागे का कार्य, हस्तिदन्त कार्य आदि वाराणसी के परम्परागत गृह उद्योग हैं । वाराणसी के रेशमी वस्त्रों को पूर्वी कला और कौशल का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है । वाराणसी की हस्तकरघा द्वारा निर्मित रेशमी साड़ियाँ, ब्रोकेड्स, दुपट्टे और स्कार्फ केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हैं । स्वर्ण तारों द्वारा कढ़ाई आदि कलात्मक उत्तमता ने विश्व बाजार में वाराणसी साड़ियों का स्थायी स्थान बना दिया है
केन्द्रों पर वाराणसी रेशम के लिए आरक्षित
और पश्चिमी देशों में अति फैशन वाली दूकानों के कतिपय दूकानें पायी जाती हैं जो वाराणसी के रेशम उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को व्यक्त करती हैं ।[7] राज्य के हस्तकरघा उद्योग में रेशमी वस्त्रों का विशिष्ट स्थान है जो मुख्यतया वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में केन्द्रित है । वाराणसी की रेशमी कला बहुत प्राचीन है । ईशा-पूर्व पाँचवीं-छठीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के समय में शाही भवनों में परदों और चित्रपट के रूप में यहाँ के रेशमी वस्त्रों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता था । यदि हम वाराणसी में रेशमी हस्तकरघों का सर्वेक्षण करें तो वस्त्रों के डिजाइनों और रंगों में अधिक विविधता पायेंगे ।[8] माँग के अनुसार वाराणसी में वस्त्रों के दो तरह

के उत्पादन किये जाते हैं - 1. सामान्य जनता के लिए बड़ी मात्रा में सस्ती साड़ियों को तैयार करने वाले लघु कारखानें, और 2. उत्तम किस्म की साड़ियों को तैयार करने वाली परम्परागत इकाइयाँ जिनमें मानव, श्रम और कौशल प्रधान होता है ।[9] वाराणसी में हस्त करघे द्वारा कई प्रकार के खादी वस्त्र तैयार किये जाते हैं जिनमें गंजी, साड़ियाँ, चादरें, गमछे, दरियाँ आदि प्रमुख हैं ।

वाराणसी के परम्परागत हस्तकरघा उद्योग में अब कुछ परिवर्तन हो रहे हैं । उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु शक्ति चालित करघों का प्रयोग बढ़ रहा है । हस्तकरघा उद्योग के अतिरिक्त यहाँ प्रिंटिंग, काष्ठ उद्योग, पीतल तथा कलई के बर्तन बनाने, कागज बोर्ड एवं गत्ता, पेंट व वार्निश बनाने आदि के कार्य गृह उद्योग के रूप में किये जाते हैं ।

मिर्जापुर-विन्ध्याचल में 6,428 व्यक्ति गृह उद्योग में लगे हुए हैं जिनमें 6,101 पुरुष और मात्र 327 स्त्रियाँ हैं । इस प्रकार यहाँ गृह उद्योग में स्त्रियों का योगदान मात्र 5.07 प्रतिशत ही है जिसके कारण लिंगानुपात 54 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष आता है । मिर्जापुर-विन्ध्याचल के गृह उद्योगों में दरी व कम्बल बनाना, धातु के बर्तन बनाना, शक्ति चालित करघों द्वारा सूती वस्त्र बुनना, चर्म उद्योग आदि प्रमुख हैं । यहाँ पीतल और कलई के बर्तन अधिक बनाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे उत्पादन भी गृह उद्योग के अन्तर्गत किये जाते हैं जिसमें चीनी मिट्टी एवं पत्थर के बर्तन, दियासलाई, अगरबत्ती बनाना आदि प्रमुख हैं ।

3. अल्प विशिष्टीकृत नगर

उत्तर प्रदेश में गृह उद्योग में विशिष्टीकृत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 18 नगरों में से 14 नगर अल्प विशिष्टीकृत नगरों की श्रृंखला में आते हैं जहाँ विशिष्टीकरण की मात्रा प्रादेशिक माध्य (7.37 प्रतिशत) से अधिक किन्तु माध्य + 1 मानक विचलन (16.56) से कम है । विशिष्टीकरण की मात्रानुसार अवरोही क्रम में ये नगर हैं (तालिका 6.1) : अमरोहा, इटावा, ललितपुर, सम्भल, जौनपुर, अलीगढ़,

मेरठ, गाजीपुर, बाराबंकी, नजीबाबाद, गोरखपुर, रामपुर, मुरादाबाद और झाँसी ।

गत दशाब्दी (1971-81) में इस वर्ग के नगरों में सम्भल (22.49 प्रतिशत ह्रास) के अतिरिक्त न्यूनतम 36.48 प्रतिशत (इटावा) और अधिकतम 167.12 प्रतिशत (अमरोहा) की वृद्धि हुई । अल्प विशिष्टीकृत नगर सामान्यतया अन्य क्रिया-वर्गों में भी विशिष्टीकरण रखते हैं जिनके कारण उनकी कार्यात्मक संरचना में गृह उद्योग का स्थान प्राय: गौण हो जाता है ।

अमरोहा में काष्ठ की वस्तुओं, पीतल व कलई के वर्तन, मिट्टी के वर्तन बनाने तथा हथकरघा द्वारा खादी तैयार करने का कार्य गृह उद्योग के रूप में किया जाता है । इटावा हथकरघा उद्योग का प्रमुख केन्द्र है जहाँ विविध प्रकार के सूती वस्त्र बनाये जाते हैं । यहाँ खादी गंजी, गाढ़ा, चादरें, धोतियाँ आदि बनाये जाते हैं । इटावा दरी निर्माण के लिए प्रदेश का प्रमुख केन्द्र है । हस्त करघा उद्योग जो लघु उद्योग का एक प्रमुख घटक है ललितपुर, सम्भल, जौनपुर, बाराबंकी, नजीबाबाद, गोरखपुर, झाँसी आदि नगरों में भी उल्लेखनीय मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है । मेरठ और नजीबाबाद में दरी एवं कम्बल उद्योग विकसित हुआ है । अलीगढ़ विशेषरूप से ताला, कैंची, चाकू, छूरे, सरौते आदि निर्माण के लिए देशभर में विख्यात है । यहाँ का ताला उद्योग एक विकसित गृह उद्योग है । अलीगढ़ में चर्म उद्योग में भी काफी लोग लगे हुए हैं ।

मुरादाबाद पीतल व कलई के बर्तन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र है जहाँ बर्तनों पर कलई करने का कार्य विशेष स्थान रखता है । यहाँ ऊनी चादर, कम्बल, लोई आदि भी गृह उद्योग के रूप में निर्मित किये जाते हैं । मेरठ में खेल के विविध सामान, चाकू, कैंचियाँ, सरौते, प्लास्टिक के सामान, ब्रश निर्माण आदि धंधे में श्रमिकों का उल्लेखनीय प्रभाग लगा हुआ है । इसके अतिरिक्त यहाँ दियासलाई बनाने वार्निश एवं पेन्ट निर्माण, टार्च के पार्ट्स बनाने, साबुन बनाने, फलों से रस निकालने

एवं उनकी पैकिंग करने तथा रासायनिक पदार्थों के निर्माण सम्बन्धी उद्योग भी पाये जाते हैं ।

अल्प विशिष्टीकृत उपरोक्त विभिन्न नगरों के गृह उद्योगों में स्त्रियों के योगदान की मात्रा में काफी भिन्नता मिलती है । झाँसी में गृह उद्योग में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है जहाँ स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुष 488 है । इसके पश्चात् क्रमशः इटावा (394), ललितपुर (247), अमरोहा (240) और नजीबाबाद (153) है । इसके विपरीत मुरादाबाद (22), सम्भल (29) और अलीगढ़ (34) में लिंगानुपात अत्यल्प है और गृह उद्योग में स्त्रियों की संख्या नगण्य है ।

6.5 अविशिष्टीकृत नगर

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 66 नगरों में से 48 नगरों को विशिष्टीकरण नहीं प्राप्त है । इनमें कुछ नगर ऐसे हैं जहाँ गृह उद्योग में उल्लेखनीय श्रमिक संलग्न हैं किन्तु उन नगरों के आकार की तुलना में इन श्रमिकों की संख्या कम होने के कारण ये नगर गृह उद्योग में विशिष्टीकृत नहीं माने जा सकते यद्यपि यहाँ गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों की संख्या कतिपय विशिष्टीकृत किन्तु लघु नगरों के गृह उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या से अधिक हो सकती है । आगरा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, फैजाबाद आदि इसी प्रकार के नगर हैं । इसके विपरीत कई ऐसे नगर भी हैं जहाँ गृह उद्योग का महत्व नाम मात्र ही है जैसे रुड़की, देहरादून, एटा, हल्द्वानी काठगोदाम, हरद्वार, मुगल सराय आदि ।

आगरा, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, हाथरस, शाहजहाँपुर, बाँदा आदि नगरों में गृह उद्योग में पर्याप्त श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है किन्तु उक्त नगरों के वृहद् आकार एवं श्रमशक्ति की तुलना में इस क्रिया-वर्ग का प्रतिशत प्रादेशिक औसत से कम है । आगरा अनेक गृह उद्योगों के लिए विख्यात है । उत्तम किस्म की दरियों का निर्माण आगरा में होता है । यहाँ खादी उद्योग द्वारा विविध प्रकार के खादी वस्त्र तैयार किये जाते हैं । आगरा में चर्म उद्योग (जूता,

चप्पल, प्लास्टिक के सामान, बीड़ी व सिगरेट बनाने, ब्रश निर्माण, प्रिंटिंग आदि विविध प्रकार के गृह उद्योग विकसित हुए हैं । प्रदेश के वृहत्तम औद्योगिक नगर कानपुर में वृहद् उद्योगों के साथ ही गृह उद्योग भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । कानपुर में खादी उद्योग, दुग्ध पदार्थों के निर्माण, ऊनी वस्त्र एवं कम्बल निर्माण, चर्म उद्योग, तम्बाकू (बीड़ी, सिगरेट) उद्योग, ताला निर्माण, बिस्कुट, प्लास्टिक, लोहे की कड़ाहियों, दियासलाई, दवाइयों एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण का कार्य महत्वपूर्ण है ।

आजमगढ़ और फैजाबाद में गृह उद्योग के रूप में मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग ही पाया जाता है । कुटीर धंधे के रूप में काँच के सामान बनाने का प्रमुख केन्द्र फिरोजाबाद है जहाँ 100 से भी अधिक छोटे-छोटे कारखाने हैं जो काँच की रेशमी तथा साधारण चूड़ियाँ बनाते हैं । अकेले फिरोजाबाद की चूड़ियाँ देश के लगभग आधी माँग को पूरा करती हैं । हाथरस में गृह उद्योग के अन्तर्गत काँच पदार्थों का निर्माण किया जाता है । फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में पीतल व कलई के वर्तन, सुगन्धित तेल, तम्बाकू, बीड़ी व सिगरेट आदि वस्तुओं के निर्माण के साथ ही कपड़े पर छपाई के कार्य गृह उद्योग के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।

6.6 कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता के कतिपय जनांकिकीय सहचर

गृह उद्योग जिनमें संलग्न व्यक्तियों की संख्या प्रायः कम होती है और जिनका संचालन प्रधानतया परिवार के सदस्यों द्वारा होता है ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाये जाते हैं । यहाँ सांख्यकीय आधार पर यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में गृह उद्योग में संलग्न श्रम शक्ति के अनुपात या कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता का संबंध जनांकिकीय तथ्यों जैसे जनसंख्या आकार, कार्यशील जनसंख्या, साक्षरता तथा लिंगानुपात से किस सीमा एवं दिशा की ओर है? इस उद्देश्य से दो चरों के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का परिगणन किया गया है और समाश्रयण समीकरण तथा सरल समाश्रयण रेखा के द्वारा सहसम्बन्धों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है (चित्र 6.2

1. जनसंख्या आकार

गृह उद्योगों का विकास सामान्यतया पारम्परिक रूप में हुआ है और अधिवास के आकार में वृद्धि के साथ वहाँ संचालित गृह उद्योग भी विकसित होते जाते हैं और इस प्रकार इस उद्योग में संलग्न श्रमशक्ति के प्रभाग में कोई विशेष अन्तर परिलक्षित नहीं होता। इसी प्रकार जिन अधिवासों या नगरीय इकाइयों में गृह उद्योग विकसित नहीं होते उनके आकार के बढ़ने पर श्रमशक्ति का गृह उद्योगों में संलग्नता प्रतिशत बढ़ने नहीं पाता। गृह उद्योगों का विकास किसी भी आकार की नगरीय इकाइयों में हो सकता है। अतः जनसंख्या आकार और गृह उद्योग में विशिष्टीकरण गहनता (प्रतिशत) में कोई प्रभावशाली सम्बन्ध नहीं मिलता है। इन दोनों चरों के मध्य परिकलित सहसम्बन्ध गुणांक + 0.026 प्राप्त हुआ है जो स्पष्ट करता है कि जनसंख्या आकार और कार्यात्मक विशिष्टीकरण में धनात्मक किन्तु अत्यल्प सम्बन्ध पाया जाता है। इस हेतु परिकलित समाश्रयण समीकरण $Y = 7.19 + 0.009X$ से विदित होता है कि जनसंख्या में प्रति इकाई (दस हजार) में वृद्धि होने पर गृह उद्योग में कार्यात्मक विशिष्टीकरण (प्रतिशत) में 0.009 इकाई की वृद्धि सम्भावित है जबकि 7.19 स्थिरांक है। इसका रैखिक प्रदर्शन चित्र 6.2A में सरल समाश्रयण रेखा द्वारा किया गया है।

2. कार्यशील जनसंख्या

गृह उद्योगों में परिवार के अधिकांश सदस्य कार्यरत होते हैं। इनके द्वारा परिवार की महिलाओं तथा वृद्ध पुरुषों को भी रोजगार प्राप्त होता है। अतः जिन नगरों में गृह उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है वहाँ की जनसंख्या में श्रमशक्ति का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। इस प्रकार गृह उद्योग सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्यशील जनसंख्या के अनुपात तथा गृह उद्योग में विशिष्टीकरण के मध्य + 0.257 का सहसम्बन्ध पाया गया है जो दोनों चरों में धनात्मक एवं सामान्य सम्बन्ध का प्रतीक है। इन्हीं दोनों चरों के सम्बन्धों की अभिव्यक्ति हेतु परिकलित समाश्रयण समीकरण $Y = -34.49 + 1.55X$

से स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या या श्रमशक्ति के अनुपात में प्रति इकाई वृद्धि के साथ ही कार्यात्मक विशिष्टीकरण में 1.55 इकाई भी वृद्धि होगी जबकि -34.49 स्थिरांक है (चित्र 6.2B) ।

3. साक्षरता

पारम्परिक गृह उद्योगों में परिवार के अधिकांश या सभी सदस्य सहयोगी होते हैं और उत्पादन में सहायता करते हैं । यहाँ तक कि बच्चे, वृद्द एवं महिलायें भी गृह उद्योगों में सक्रिय योगदान देते हैं । गृह उद्योगों में विद्यालय जाने योग्य बालक एवं बालिकायें भी संलग्न हो जाते हैं और परिवार की आय वृद्धि में सहायक बनते हैं । इसके साथ ही असंख्य निर्धन परिवारों के बच्चे स्थानीय गृह उद्योगों में संलग्न होकर कुछ आमदनी प्राप्त करनेलगते हैं । इस प्रकार असंख्य बालक बालिकायें विद्यालय का दर्शन भी नहीं कर पाते और अशिक्षित रह जाते हैं जो अन्तत: साक्षरता अनुपात को बढ़ने में अवरोधक होते हैं । साक्षरता के बढ़ने पर श्रमिकों का स्थानान्तरण अन्य द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में होने लगता है और गृह उद्योग के प्रभाग में ह्रास होने लगता है । साक्षरता तथा कार्यात्मक विशिष्टीकरण के मध्य प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक -0.259 है जो ऋणात्मक तथा सामान्य सहसम्बन्ध का बोधक है । इस हेतु परिकलित समाश्रयण समीकरण $y = 21.60 - 0.28x$ से विदित होता है कि साक्षरता में प्रति इकाई वृद्धि होने पर गृह उद्योग में विशिष्टीकरण की मात्रा में 0.28 इकाई का ह्रास होगा जबकि 21.60 स्थिरांक है । इसे सरल समाश्रयण रेखा द्वारा चित्र 6.2C में प्रदर्शित किया गया है ।

लिंगानुपात

गृह उद्योग जो आवासीय गृहों या आवास के निकट स्थित कार्यशालाओं में प्रधानत: परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होते हैं, महिलाओं के लिए उपयुक्त रोजगार हेतु सुअवसर प्रदान करते हैं ।[10] अत: अधिकांश गृह उद्योगों में मालिक के परिवार की अथवा दूसरे निर्धन परिवार की महिलायें भी संलग्न होकर अपनी अथवा

अपने परिवार की आय वृद्धि करती हैं। अतः जिन नगरों में गृह उद्योगों विशेषतः वस्त्र उद्योग, बीड़ी, माचिस, अगरबत्ती, कढ़ाई, बुनाई आदि का विकास होता है श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है। गृह उद्योगों में अधिक विशिष्टीकृत नगरों - मऊनाथ भंजन, टाण्डा, इटावा, झाँसी, अमरोहा, ललितपुर आदि नगरों में गृह उद्योग में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है (तालिका 6.1)। कुल श्रमशक्ति में गृह उद्योग में संलग्न श्रमशक्ति के प्रभाग या कार्यात्मक विशिष्टीकरण और उक्त क्रिया-वर्ग में ही लिंगानुपात के मध्य परिकलित सहसम्बन्ध गुणांक + 0.519 आया है जो धनात्मक और उच्च सहसम्बन्ध का परिचायक है। समाश्रयण समीकरण $Y = 69.55 + 5.90\,x$ से स्पष्ट होता है कि कार्यात्मक विशिष्टीकरण में प्रति इकाई वृद्धि होने पर लिंगानुपात में 5.90 इकाई की बढ़ोत्तरी सम्भावित है। इस सम्बन्ध को सरल समाश्रयण रेखा द्वारा चित्र 6.2 D में प्रदर्शित किया गया है।

सन्दर्भ

1. Census of India 1961 - Uttar Pradesh, Part II-B (III), General Economic Tables.

2. Census of India 1971 - Uttar Pradesh, Part II-A, General Population Tables.

3. Census of India 1981 - Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.

4. Ibid.

5. Singh, R.N. and Sahab Deen : "Occupational Structure of Urba[n] Centres of Eastern Uttar Pradesh : Household Industry - A Case Study", National Geographer, Vol. 14, No. 2, 1979, pp. 159-174.

6. Maurya, S.D. : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, 1988, p. 232.

7. Das, L.K.V. : "The Exotic World of Varanasi Silk", Northern India Patrika, A Daily from Allahabad, Oct. 20, 1979.

8. Ibid.

9. Murakami, M. : "The Cottage Handloom Industry in the Middle and Lower Ganga Plain", in Singh R.L. (ed.), Rural Settlements in Monsoon Asia, National Geographical Society of India, Varanasi, 1972, p. 126.

10. Gayatri Devi : "Educational and Functional Status of Women in Eastern Uttar Pradesh", in Maruya, S.D. (ed.), Women in India, Chugh Publications, Allahabad, 1988, p. 212.

------::O::------

अध्याय सात

विविध क्रियायें

7.1 विविध क्रिया वर्ग - स्वरूप विवेचन

नगर प्रकृत्या बहुधन्धी होते हैं जहाँ अनेक प्रकार की क्रियायें सम्पादित होती हैं। इन्हीं विविध क्रियाओं तथा उत्पादनों एवं सेवाओं द्वारा नगर अपने चतुर्दिक व्याप्त ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों से क्रियात्मक रूप से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार नगर को एकाकी भौतिक या सामाजिक इकाई नहीं माना जा सकता। इसे प्राथमिक रूप से क्रियाओं का केन्द्रीय क्षेत्र माना जाना चाहिए।[1] नगर वास्तव में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं का केन्द्र होता है जहाँ प्राथमिक क्रियायें कम महत्वपूर्ण होती हैं किन्तु उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, प्रशासन आदि कियायें विशेष महत्त्व की होती हैं।

1981 जनगणना[2] के अनुसार कुल मुख्य कर्मियों को चार प्रधान श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिनमें चौथी और अन्तिम श्रेणी 'अन्य कर्मियों' (Other Workers) की है। प्रस्तुत अध्ययन में इस क्रिया-वर्ग को ही 'विविध क्रियायें' नाम से व्यवहृत किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम तीन कार्यात्मक वर्गों - कृषक, कृषि श्रमिकों तथा गृह उद्योग में संलग्न श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य समस्त कर्मियों को समाहित किया गया है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, कृषक, कृषि मजदूर या गृह उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर सभी काम करने वाले इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में कारखानें और बागवानी में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, अध्यापक, पुजारी, मनोरंजन करने वाले, व्यापारी, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, उत्खनन, निर्माण का काम करने करने वाले आदि व्यक्ति आते हैं।[3]

ज्ञातव्य है कि 1971 जनगणना[4] में समस्त कार्यशील जनसंख्या को 9 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों में विभक्त किया गया था जिनमें से प्रथम - कृषक, द्वितीय - कृषि श्रमिक और पंचम अ -गृह उद्योग में संलग्न श्रमिक को 1981 जनगणना में पृथक व्यावसायिक श्रेणी के रूप में रखा गया और शेष अन्य व्यावसायिक श्रेणियों - तृतीय, चतुर्थ, पंचम-ब, षष्टम, सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् को 'अन्य कर्मियों' की श्रेणी में समाहित किया गया है।

प्रकार 1981 जनगणना में 'अन्य कर्मियों' के अन्तर्गत 1971 जनगणना की निम्नांकित कार्यात्मक श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है :

3. वनोद्योग, मत्स्य पालन, आखेट, बागवानी, फलोद्यान तथा अन्य सम्बद्ध क्रियायें,
4. उत्खनन एवं प्रस्तर खनन,
5(ब) विनिर्माण, प्रक्रमण, सेवा कार्य तथा मरम्मत (गृह उद्योग को छोड़कर),
6. निर्माण कार्य,
7. व्यापार एवं वाणिज्य
8. परिवहन, भण्डारण एवं संचार,
9. अन्य सेवायें ।

प्रस्तुत अध्याय में उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना में विविध क्रियाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है । 1981 जनगणना में विविध क्रियाओं के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न क्रिया-वर्गों के पृथक-पृथक समंक उपलब्ध नहीं हैं जबकि उक्त समंक 1971 जनगणना में उपलब्ध थे । अतः अध्ययन को तथ्यपूर्ण एवं सार्थक बनाने के उद्देश्य से अनेक स्थलों पर 1971 जनगणना के समंकों पर आधारित होना पड़ा है । नगरों के कार्यात्मक विशिष्टीकरण स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही अध्याय चार में नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के तथ्यों का यथोचित उपयोग किया गया है । अध्याय के अन्त में परिमाणात्मक परीक्षण हेतु विविध कार्यों से सम्ब कतिपय जनांकिकीय चरों के मध्य सहसम्बन्धों का परिकलन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने क भी प्रयास किया गया है ।

7.2 कार्यशील जनसंख्या

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों में कुल 29,86,4 कर्मी विविध कार्यों में सेवारत हैं जिनमें 28,52,955 पुरुष और 1,33,459 महिलायें हैं । इस प्रकार विविध क्रियाओं में संलग्न सम्पूर्ण श्रमिकों में 95.53 प्रतिशत पुरुष औ 4.47 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं । उक्त नगरों की अधिकांश श्रमशक्ति (87.27 प्रतिशत) इ

क्रिया-वर्ग में संलग्न है । पुरुष श्रमिकों का 87.70 प्रतिशत तथा महिला श्रमिकों का 79.22 प्रतिशत विविध क्रियाओं में कार्यरत है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस क्रिया-वर्ग ने पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों को कम आकर्षित किया है । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना में विविध क्रियाओं का प्रभाग (88.51 प्रतिशत) द्वितीय श्रेणी के नगरों (82.04 प्रतिशत) की अपेक्षा अधिक है । इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या आकार में वृद्धि के साथ विविध क्रियाओं में श्रमिकों की संलग्नता बढ़ती जाती है ।

यद्यपि नगरों की व्यावसायिक संरचना में विविध क्रियाओं का प्रभाग सर्वाधिक है किन्तु विभिन्न नगरों के श्रमिकों की विविध क्रियाओं में संलग्नता प्रतिशत में पर्याप्त भिन्नता देखी जा सकती है । तालिका 7.1 से स्पष्ट है कि रुड़की के सम्पूर्ण श्रमशक्ति का 97.07 प्रतिशत विविध क्रियाओं में कार्यरत है जो प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में सर्वाधिक है । इसके पश्चात् देहरादून (96.18 प्रतिशत), हल्द्वानी-काठगोदाम (95.43 प्रतिशत), फिरोजाबाद (95.39 प्रतिशत) और एटा (95.01 प्रतिशत) का स्थान है । व्यावसायिक संरचना में विविध क्रियाओं का अल्पतम महत्त्व मऊनाथ भंजन में पाया गया है जहाँ मात्र 33.17 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या ही इस क्रिया-वर्ग में संलग्न है । वे नगर जहाँ विविध क्रियाओं में 75.00 प्रतिशत से कम श्रमशक्ति कार्यरत है, इस प्रकार हैं : सम्भल - 53.70 प्रतिशत, टाण्डा - 55.01 प्रतिशत, फतेहपुर - 68.80 प्रतिशत, ललितपुर - 72.12 प्रतिशत, उन्नाव- 73.46 प्रतिशत, अमरोहा - 74.22 प्रतिशत और वाराणसी - 74.49 प्रतिशत ।

विविध क्रियाओं में पुरुषों तथा स्त्रियों की पृथक-पृथक सहभागिता पर विचार करने से कुछ उपयोगी, रुचिकर तथा सार्थक परिणाम प्रकट होते हैं जो व्यावसायिक संरचन के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण हैं । अध्ययन हेतु चयनित समस्त नगरों में औसतन 87.70 प्रतिशत पुरुष कर्मी विविध क्रियाओं में संलग्न हैं किन्तु विभिन्न नगरों में इस अनुपात में भिन्नता पायी जाती है । यह भिन्नता अधिकतम 97.13 प्रतिशत (रुड़की) से लेकर न्यूनतम 41.44 प्रतिशत (मऊनाथ भंजन) तक पायी जाती है । इसी प्रकार यदि महिलाओं की विविध क्रियाओं में संलग्नता अनुपात पर दृष्टिपात करें तो यह भिन्नता

अधिकतम 95.47 प्रतिशत (रूड़की) और न्यूनतम 7.92 प्रतिशत (मऊनाथभंजन) के मध्य है। इस प्रकार पुरूषों तथा महिलाओं दोनों ही श्रमिकों के संलग्नता अनुपात रूड़की में सर्वाधिक और मऊनाथ भंजन में न्यूनतम अंकित किये गये हैं। प्रदेश में कुल 20 नगर ऐसे हैं जहाँ 90 प्रतिशत से अधिक पुरूष श्रमशक्ति विविध क्रियाओं के संचालन में संलग्न हैं और 4 नगरों -रूड़की, देहरादून, हल्द्वानी-काठगोदाम और फिरोजाबाद में 95.00 प्रतिशत से अधिक पुरूष कर्मी इसी क्रिया वर्ग में कार्यरत हैं। कुल 17 नगरों में महिला श्रमशक्ति का 90 प्रतिशत से अधिक भाग विविध क्रियाओं में कार्यरत है जबकि रूड़की ही एकमात्र नगर है जिसकी 95.00 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक इस क्रिया-वर्ग में संलग्न हैं। विविध क्रियाओं में 50 प्रतिशत से कम पुरूष श्रमशक्ति वाला एक मात्र नगर मऊनाथ भंजन है जबकि चार नगरों - मऊनाथ भंजन - 7.92 प्रतिशत, टाण्डा - 36.38 प्रतिशत, इटावा - 43.06 प्रतिशत और अमरोहा - 46.33 प्रतिशत में महिला श्रमिकों का 50 प्रतिशत से कम भाग विविध क्रियाओं में लगा हुआ है।

विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति में औसतन 46 महिलायें प्रति हजार पुरूष हैं किन्तु विभिन्न नगरों में इस अनुपात में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। यह अनुपात प्रथम श्रेणी के नगरों में 47 और द्वितीय श्रेणी के नगरों में 45 महिलायें प्रति हजार पुरुष हैं। टाण्डा में विविध कार्यों में संलग्न प्रति हजार पुरूषों पर 97 महिलायें हैं जो अन्य किसी भी नगर से अधिक है। इसके पश्चात् क्रमशः झाँसी - 93, ललितपुर - 80, देहरादून - 75, जौनपुर - 70, आजमगढ़ - 69, बस्ती - 67, लखनऊ - 66, मऊनाथ भंजन - 63, गाजीपुर - 63 और फैजाबाद - 62 नगर आते हैं जहाँ इस क्रिया-वर्ग में प्रति हजार पुरूषों पर 60 से अधिक महिलायें क्रियाशील हैं। महिलाओं का अल्पतम अनुपात(24) देवबन्द में अंकित किया गया है। अन्य तीन नगरों - सम्भल, मुरादाबाद और मुगलसरा में भी विविध कार्यों में प्रति हजार पुरूषों पर 30 महिलायें से कम अनुपात ही पाया गया है।

7.3 विविध क्रियाओं में विशिष्टीकरण

विविध क्रियाओं में सम्मिलित अधिकांश क्रियायें नगरीय हैं, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य, सांस्कृतिक आदि।

अतः नगरों विशेषरूप से वृहत् नगरों की आर्थिक-संरचना में इस क्रिया-वर्ग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है और अधिकांश श्रमशक्ति इसी क्रिया-वर्ग में कार्यरत है । उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त 66 नगरों के 87.27 प्रतिशत कर्मी विविध क्रियाओं में संलग्न हैं । कतिपय नगरों में इस प्रादेशिक माध्य (87.27 प्रतिशत) से कम श्रमिक विविध क्रियाओं में कार्यरत है किन्तु कुछ अन्य नगरों में इस क्रिया-वर्ग में संलग्न श्रमिकों का प्रभाग प्रादेशिक माध्य से अधिक भी है जो उन नगरों के विविध क्रियाओं में विशिष्टीकरण का सूचक है । इस प्रकार उन नगरों को जिनके कुल श्रमशक्ति का 87.27 प्रतिशत से अधिक अंश विविध क्रियाओं में नियुक्त है, इस क्रिया-वर्ग में विशिष्टीकृत माना गया है ।

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 26 नगरों को विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत पाया गया है । इन विशिष्टीकृत नगरों को कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक (कुल श्रमशक्ति से विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत) के आधार पर 4 उपवर्गों में विभक्त किया गया है जिसके निर्धारण हेतु प्रादेशिक माध्य (87.27) से परिकलित मानक विचलन (7.88) को मापदण्ड के रूप में प्रयोग किया गया है । उल्लेखनीय है कि विशिष्टीकृत नगरों की प्रथम दो श्रेणियों - 1. अत्यधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 3 मा0वि0 से ऊपर), और 2. अधिक विशिष्टीकृत नगर (माध्य + 2 मा0 वि0 से ऊपर) की श्रेणी में कोई भी नगर नहीं आता है क्योंकि माध्य (87.27) + 2 मा0वि0 (15.76) मिलकर 103.05 हो जाता है जबकि कार्यात्मक विशिष्टीकरण सूचकांक 100 से ऊपर नहीं हो सकता । इस प्रकार विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत नगरों की दो ही श्रेणियाँ हैं -

1. सामान्य विशिष्टीकृत नगर (माध्य * 1 मा0वि0 से ऊपर),
2. अल्प विशिष्टीकृत नगर (माध्य से ऊपर) ।

1. <u>सामान्य विशिष्टीकृत नगर</u>

विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत कुल 26 नगरों में से 4 नगर सामान्य विशिष्टीकृत नगरों (माध्य + 1 मानक विचलन) की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इनमें से तीन

तालिका 7.1

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में विविध कार्यों में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत एवं लिंगानुपात (1981)

क्र0 सं0	नगर	कुल मुख्य कर्मियों से विविध कार्यों में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत			विविध कार्यों में कार्यरत महिलायें प्रति हजार पुरुष
		कुल कर्मी	पुरुष कर्मी	महिला कर्मी	
1	2	3	4	5	6
1.	रुड़की	97.07	97.13	95.47	35
2.	देहरादून	96.18	96.35	94.29	75
3.	हल्द्वानी-काठगोदाम	95.43	95.64	90.89	45
4.	फिरोजाबाद	95.39	95.68	87.45	34
5.	एटा	95.01	94.95	96.48	42
6.	मोदीनगर	94.06	94.00	95.52	39
7.	मथुरा	94.53	94.70	90.75	42
8.	गाजियाबाद	93.22	93.26	92.52	51
9.	कानपुर	93.19	93.32	90.03	40
10.	सहारनपुर	92.73	92.76	91.98	37
11.	लखनऊ	92.42	92.30	94.32	66
12.	मुजफ्फरनगर	91.78	91.87	89.47	36
13.	बरेली	91.75	91.85	89.22	42
14.	इलाहाबाद	91.53	91.93	84.89	56
15.	हरद्वार	91.30	91.23	92.94	45
16.	आगरा	90.99	90.98	91.36	34
17.	पीलीभीत	90.97	91.13	87.36	42
18.	हाथरस	90.68	91.10	79.00	31
19.	सीतापुर	90.70	90.82	88.38	52
20.	लखीमपुर	90.03	89.88	93.20	46
21.	गोण्डा	89.10	89.24	85.49	39
22.	मुरादाबाद	89.07	89.00	91.74	27
23.	बुलन्दशहर	88.95	89.05	86.08	44
24.	झाँसी	88.40	90.56	70.38	93
25.	रामपुर	88.08	87.13	74.42	35
26.	चन्दौसी	87.54	87.71	82.71	32
27.	देवरिया	86.90	87.17	82.30	53

1	2	3	4	5	6
28.	हरदोई	86.80	86.63	90.28	50
29.	काशीपुर	86.67	87.52	66.67	32
30.	मेरठ	86.50	86.72	82.00	47
31.	शामली	86.54	86.62	93.96	30
32.	अलीगढ़	86.33	86.26	88.05	40
33.	गोरखपुर	86.19	86.42	82.24	54
34.	आजमगढ़	86.17	86.54	81.20	69
35.	हापुड़	85.82	86.78	65.39	36
36.	मैनपुरी	85.82	85.68	90.15	39
37.	खुर्जा	85.13	85.38	79.31	40
38.	उरई	84.99	85.01	84.60	37
39.	बिजनौर	84.99	84.92	86.26	57
40.	बदायूँ	84.24	85.18	86.50	42
41.	नजीबाबाद	84.01	84.55	71.36	36
42.	बलिया	83.78	84.52	69.30	47
43.	कासगंज	83.72	84.12	73.88	36
44.	मुगलसराय	83.51	83.99	69.66	29
45.	बस्ती	82.92	83.34	77.09	67
46.	शाहजहाँपुर	82.79	82.86	70.72	32
47.	फैजाबाद	82.78	83.21	76.42	62
48.	बाराबंकी	82.46	82.87	72.84	37
49.	फर्रुखाबाद	82.34	82.71	72.71	34
50.	गाजीपुर	81.90	82.70	71.11	63
51.	इटावा	81.46	84.43	43.06	39
52.	बाँदा	79.85	79.90	78.85	52
53.	रायबरेली	79.67	79.97	74.78	57
54.	नगीना	78.17	78.56	67.89	33
55.	देवबन्द	78.00	78.01	77.60	24
56.	बहराइच	77.48	77.59	74.65	37
57.	जौनपुर	76.40	77.10	67.75	70
58.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	75.60	76.39	61.03	43
59.	वाराणसी	74.49	74.82	68.54	51
60.	अमरोहा	74.22	76.16	46.33	42

1	2	3	4	5	6
61.	उन्नाव	73.46	72.91	85.63	53
62.	ललितपुर	72.12	73.66	57.20	80
63.	फतेहपुर	68.80	68.85	52.62	49
64.	टाण्डा	55.01	57.90	36.38	97
65.	सम्भल	53.70	53.52	61.59	36
66.	मऊनाथ भंजन	33.17	41.44	7.92	63
	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर	87.27	87.70	79.22	46

देहरादून, हल्द्वानी-काठगोदाम और रुड़की उत्तरी भाग में और अन्य एक - फिरोजाबाद पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इन नगरों में 95 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति विविध क्रियाओं में संलग्न होकर आर्थिक उपार्जन करती है।

उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरों में रुड़की विविध क्रियाओं में सर्वाधिक विशिष्टीकृत नगर है जिसकी 97.07 प्रतिशत श्रमशक्ति उक्त क्रिया-वर्ग में कार्यरत है। रुड़की द्वितीय श्रेणी (जनसंख्या 79,076) का नगर है जहाँ 27,359 मुख्य श्रमिक हैं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 34.60 आता है जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों के प्रादेशिक औसत (26.53 प्रतिशत) से 8.07 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक कार्यों में संलग्नता का सर्वाधिक प्रतिशत रुड़की में ही प्राप्त हुआ है।

यहाँ सीमान्त श्रमिकों का प्रतिशत नगण्य (0.06 प्रतिशत) है। गत दशक 1971-81 में रुड़की की कुल जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्रमशः 26.61 और 24.54 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है। विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की संख्या में भी लगभग समान ही (23.55 प्रतिशत) वृद्धि हुई है (तालिका 7.2)।

रुड़की में विविध क्रियाओं में कार्यरत कुल 26,558 श्रमिकों में 25,651 पुरुष और 907 महिलायें हैं। इस प्रकार इस क्रिया-वर्ग में संलग्न कर्मियों में 96.52 प्रतिशत पुरुष और 3.42 प्रतिशत महिलायें हैं। रुड़की की विविध सेवाओं में महिलाओं का योगदान

तालिका 7.2

विशिष्टीकृत नगरों की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत, तथा कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मियों एवं विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों की संख्या में दशकीय प्रतिशत भिन्नता

क्र0 सं0	नगर	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत	दशकीय भिन्नता (1971-81)		
			कुल जनसंख्या	कार्यशील जनसंख्या	विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मी
1.	रुड़की	34.60	+ 26.61	+ 24.54	+ 23.55
2.	देहरादून	30.28	+ 44.01	+ 48.35	+ 48.64
3.	हल्द्वानी-काठगोदाम	28.30	+ 48.07	+ 34.23	+ 35.17
4.	फिरोजाबाद	27.42	+ 51.15	+ 52.92	+ 50.28
5.	एटा	24.24	+ 60.39	+ 49.32	+ 56.19
6.	मथुरा	27.76	+ 13.81	+ 18.51	+ 20.94
7.	मोदीनगर	28.44	+101.64	+ 68.83	+ 61.86
8.	गाजियाबाद	30.03	+124.88	+136.34	+133.14
9.	कानपुर	27.49	+ 28.53	+ 19.43	+ 20.35
10.	सहारनपुर	27.09	+ 31.04	+ 30.89	+ 31.05
11.	लखनऊ	27.72	+ 23.79	+ 23.25	+ 22.98
12.	मुजफ्फरनगर	25.57	+ 49.69	+ 51.59	+ 49.19
13.	बरेली	26.69	+ 37.82	+ 38.11	+ 39.24
14.	इलाहाबाद	25.64	+ 26.71	+ 16.96	+ 19.63
15.	हरद्वार	27.15	+ 48.10	+ 71.22	+ 71.35
16.	आगरा	26.58	+ 17.76	+ 21.65	- 23.41
17.	पीलीभीत	27.11	+ 29.70	+ 29.08	+ 36.20
18.	हाथरस	25.99	+ 25.03	+ 21.54	+ 26.44
19.	सीतापुर	28.79	+ 51.71	+ 53.95	+ 54.95
20.	लखीमपुर	25.71	+ 39.43	+ 29.34	+ 27.76
21.	गोण्डा	26.20	+ 34.53	+ 27.21	+ 33.38
22.	मुरादाबाद	27.57	+ 26.66	+ 31.22	+ 30.76
23.	बुलन्दशहर	24.93	+ 73.83	+ 73.38	+ 67.59
24.	झांसी	25.04	+ 43.41	+ 45.02	+ 12.82
25.	रामपुर	27.66	+ 26.76	+ 26.15	+ 24.42
26.	चन्दौसी	25.71	+ 25.43	+ 22.23	+ 21.93
	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगर	26.94	+ 35.29	+ 32.06	+ 32.14

अत्यल्प है और लिंगानुपात मात्र 35 महिलायें प्रति हजार पुरुष है जो इस क्रिया-वर्ग के प्रादेशिक औसत 46 से 11 अंक नीचे है । महिलाओं की संलग्नता कम होते हुए भी यह तथ्य विशेष महत्वपूर्ण है कि यहाँ की 95.47 प्रतिशत कार्यशील महिलायें विविध क्रियाओं में ही संलग्न हैं । वास्तव में रुड़की प्रधानतः एक शैक्षिक एवं सेवा केन्द्र है । 1971 जनगणनानुसार यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का 8.57 प्रतिशत विनिर्माण उद्योग में, 1.37 प्रतिशत निर्माण कार्य में, 12.57 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 3.86 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में तथा 70.36 प्रतिशत अन्य सेवाओं में संलग्न था । कार्यात्मक वर्गीकरण (अध्याय 4) के अनुसार रुड़की उच्चतम श्रेणी (स3) का सेवा केन्द्र है । रुड़की मुख्यतया यहाँ स्थित अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के लिए विख्यात है और यहाँ की अधिकांश आर्थिक, सामाजिक क्रियायें इसी शैक्षिक पर्यावरण से सम्बद्ध हैं ।

विविध क्रियाओं में विशिष्टीकरण के पदसोपान में देहरादून (96.18 प्रतिशत) द्वितीय स्थान पर है । 1981 जनगणनानुसार देहरादून की कुल जनसंख्या (2,93,010) में 30.28 प्रतिशत मुख्य कर्मी (88,715) हैं । सीमान्त श्रमिकों का प्रभाग 0.31 प्रतिशत है जिससे समस्त कर्मियों का प्रतिशत 30.59 हो जाता है । पिछले दशक में देहरादून की कुल जनसंख्या में 44.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । विविध कार्यों में भी इनके समकक्ष ही 48.64 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है ।

देहरादून में विविध क्रियाओं में संलग्न कुल कर्मियों की संख्या 85,323 है जिस 79,346 पुरुष और 5,977 महिलायें हैं । इस प्रकार इस क्रिया-वर्ग में पुरुषों तथा महिलाओं का प्रभाग क्रमशः 93 और 7 प्रतिशत है और लिंगानुपात 75 महिलायें प्रति हजार पुरुष आता है । 1971 जनगणना के आधार पर किये गये कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार देहरादून विविध सेवाओं के लिए अधिक विशिष्टीकृत (स2) नगर है जहाँ आधी से अधिक (53.85 प्रतिशत) श्रमशक्ति विभिन्न सेवा कार्यों में कार्यरत थी । इसके अति रिक्त कुल श्रमशक्ति का भारी उद्योगों में 13.01 प्रतिशत, निर्माण कार्य में 2.59 प्रतिश व्यापार एवं वाणिज्य में 16.72 प्रतिशत तथा परिवहन एवं संचार में 8.45 प्रतिशत सं पाया गया ।

देहरादून हिमालय के दक्षिणी पादस्थल पर स्थित है जहाँ उत्तरी रेलमार्ग समाप्त हो जाता है । भारत का भूमापन विभाग, भारतीय सैन्य अकादमी तथा वन अनुसंधान शाला यहीं स्थित हैं । पर्वतीय एवं मैदानी भूमियों के मिलन स्थल पर स्थित देहरादून में एक विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जहाँ बड़ी संख्या में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं । यहाँ वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे कागज, दिया-सलाई, फर्नीचर, स्लीपर, पैकिंग के डिब्बे आदि के निर्माण के उद्योग धन्धे विकसित हुए हैं । यहाँ व्यापारिक क्रियाओं तथा परिवहन एवं संचार सेवाओं के विकास से उल्लेखनीय मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है ।

विविध क्रियाओं में कार्यात्मक विशिष्टीकरण की मात्रानुसार हल्द्वानी-काठगोदाम तृतीय स्थान पर आता है जहाँ 95.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इसी क्रिया-वर्ग में संलग्न है । यह द्वितीय श्रेणी (जनसंख्या 77,300) का नगर है जिसकी 28.30 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कर्मियों के रूप में क्रियाशील है । यहाँ 0.48 प्रतिशत जनसंख्या सीमान्त श्रमिक के अन्तर्गत कार्यरत है जिससे कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 28.78 हो जाता है । गत दशक (1971-81) में हल्द्वानी-काठगोदाम की कुल जनसंख्या और मुख्य कर्मी जनसंख्या में क्रमशः 48.07 और 34.23 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है जबकि इसकी विविध क्रियाओं में सम्मिलित कर्मियों की संख्या में 35.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

हल्द्वानी-काठगोदाम में विविध क्रियाओं में संलग्न कुल 20,879 कर्मियों में से 19,981 पुरुष तथा शेष 898 महिलायें हैं । इस प्रकार उक्त क्रिया वर्ग में पुरुषों और महिलाओं का योगदान क्रमशः 95.70 और 4.30 प्रतिशत है और लिंगानुपात 45 महिलायें प्रति हजार पुरुष आता है जो प्रादेशिक औसत के समान ही है । उल्लेखनीय है कि यहाँ पुरुष कर्मियों का 95.64 प्रतिशत और महिला कर्मियों का 90.89 प्रतिशत विविध क्रियाओं में ही संलग्न है ।

हल्द्वानी-काठगोदाम मुख्यतः व्यापारिक तथा परिवहन केन्द्र है । यहाँ 1971 में कुल कार्यशील जनसंख्या का 29.72 प्रतिशत विभिन्न सेवाओं में, 25.62 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 17.29 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में संलग्न था । इसके अतिरिक्

विनिर्माण उद्योगों में 17.12 प्रतिशत तथा निर्माण कार्यों में 4.17 प्रतिशत श्रमशक्ति कार्यशील थी ।

फिरोजाबाद विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत चतुर्थ नगर है जिसकी 95.39 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इसी क्रिया-वर्ग में संलग्न है । यह प्रथम श्रेणी (जनसंख्या 202,338) का नगर है जहाँ 55,072 मुख्य कर्मी हैं । इस प्रकार कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मियों का प्रतिशत 27.22 है । यहाँ पुरूष जनसंख्या का 48.48 प्रतिशत सक्रिय रूप से आर्थिक कार्यों में संलग्न है किन्तु महिला जनसंख्या में उक्त प्रभाग मात्र 2.10 प्रतिशत ही है । फिरोजाबाद में सीमान्त श्रमिकों का अंश (0.02 प्रतिशत) लगभग नगण्य है । गत दशक में इसकी जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों की संख्या में क्रमश: 51.15, 52.92 और 50.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो समस्त वृहत् नगरों के प्रादेशिक औसत का लगभग डेढ़ गुना है ।

फिरोजाबाद में विविध क्रियाओं में कार्यरत 52,532 कर्मियों में से 50,825 पुरूष और 1,707 महिलायें हैं । इस प्रकार उक्त क्रिया-वर्ग में पुरूषों और महिलाओं का योगदान क्रमश: 96.75 और 3.25 प्रतिशत है और लिंगानुपात 34 महिलायें प्रति हजार पुरूष आता है । फिरोजाबाद में पुरूष कर्मियों का 95.68 प्रतिशत तथा महिला कर्मियों का 87.45 प्रतिशत विविध क्रियाओं में ही संलग्न है । यह प्रधानत: एक औद्योगिक नगर है जहाँ 56.18 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या विनिर्माण उद्योगों में कार्यरत पायी गयी है (1971) । इसके अतिरिक्त व्यापार एवं वाणिज्य में 19.76 प्रतिशत, परिवहन एवं संचार में 5.80 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 13.15 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है । काँच के सामान-निर्माण में फिरोजाबाद का विशिष्ट स्थान है । काँच के आधुनिक कारखानों में काँच के बर्तन, बोतलें, शीशियाँ, काँच की चादरें, लैम्प, वैज्ञानिक उपकरण आदि का निर्माण किया जाता है । कुटीर उद्योग के रूप में फिरोजाबाद काँच के सामान बनाने का प्रमुख केन्द्र है जहाँ 125 से भी अधिक लघु कारखानें काँच की रेशमी तथा साधारण चूड़ियों का निर्माण करते हैं । फिरोजाबाद की चूड़ियाँ देश भर में विख्यात हैं जो देश की लगभग आधी माँग की पूर्ति करती हैं ।

2. अल्प विशिष्टीकृत नगर

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 22 नगरों को विविध क्रियाओं में अल्प विशिष्टीकृत पाया गया है जहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रादेशिक माध्य (87.27 प्रतिशत) से अधिक प्रभाग विविध क्रियाओं में संलग्न है किन्तु यह माध्य + 1 मानक विचलन (95.15 प्रतिशत) से नीचे हैं। इनमें से केवल चार नगरों - मोदीनगर, हरद्वार हाथरस, और चन्दौसी के अतिरिक्त सभी 18 नगर जनपद मुख्यालय हैं। इस वर्ग के 16 नगरों में 90.00 प्रतिशत से अधिक कर्मी विविध क्रियाओं में संलग्न होकर आर्थिक उपार्जन करते हैं। ये नगर अवरोही क्रम में इस प्रकार हैं : एटा (95.01 प्रतिशत), मथुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बरेली, इलाहाबाद, हरद्वार, आगरा, पीलीभीत, हाथरस, सीतापुर और लखीमपुर (90.03 प्रतिशत)। अन्य 6 नगर जहाँ प्रादेशिक औसत से अधिक श्रमशक्ति विविध क्रियाओं में कार्यरत हैं, ये हैं - गोण्डा, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, झाँसी, रामपुर और चन्दौसी।

एटा (जनसंख्या 54,784) द्वितीय श्रेणी का नगर है जिसकी 24.24 प्रतिशत जनसंख्या ही मुख्य कर्मी है। पुरुषों तथा महिलाओं का क्रमश: 43.68 और 2.04 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के अन्तर्गत है। यहाँ विविध क्रियाओं में लिंगानुपात 42 महिलायें प्रति हजार पुरुष है। एटा मुख्य रूप से प्रशासनिक (जनपद मुख्यालय) और व्यापारिक केन्द्र है जहाँ 1971 में 28.37 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या व्यापार एवं वाणिज्य में और 35.78 प्रतिशत विविध सेवाओं में संलग्न थी। विनिर्माण और परिवहन में उक्त प्रतिशत क्रमश: 16.54 तथा 8.14 था। गत दशक में एटा की कुल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और विविध कार्यों में संलग्न जनसंख्या में क्रमश: 60.39, 49.32 और 56.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा गृह उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में ह्रास हुआ है।

मथुरा (जनसंख्या 159,498) प्रथम श्रेणी का नगर है जिसकी 27.76 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कर्मी है। पुरुषों और महिलाओं में कर्मियों का प्रभाग क्रमश: 49.06 तथा 2.56 है। यहाँ विविध क्रियाओं में संलग्न कुल 41,861 कर्मियों में 95.94 प्रति

महिलायें हैं । गत दशक में मथुरा की कुल जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या में क्रमश: 13.81 तथा 18.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की संख्या में 20.94 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । मथुरा एक प्रशासनिक (सेवा), व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर है । 1971 जनगणनानुसार मथुरा की 38.17 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या विविध सेवाओं में, 21.53 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 16.40 प्रतिशत विनिर्माण में और 3 प्रतिशत निर्माण कार्य में संलग्न थी । यहाँ तेल शोधन, रसायनिक उर्वरक, सूतीवस्त्र निर्माण के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे उद्योग-धंधे भी विकसित हैं । मथुरा एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल के साथ ही जनपद मुख्यालय भी है जहाँ बड़ी संख्या में कर्मी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं में लगे हुए हैं ।

मोदीनगर, गाजियाबाद और कानपुर प्रधानत: औद्योगिक नगर हैं । 1971 जनगणनानुसार मोदीनगर में कार्यशील जनसंख्या का 68.71 प्रतिशत, गाजियाबाद में 32.57 प्रतिशत और कानपुर में 30.20 प्रतिशत भारी विनिर्माण उद्योग में संलग्न पाया गया । कानपुर में 20.93 प्रतिशत कर्मी व्यापार एवं वाणिज्य में तथा 31.01 प्रतिशत विविध सेवाओं में कार्यरत थे । गाजियाबाद में उक्त क्रिया-वर्गों में श्रमिकों का प्रभाग क्रमश: 17.40 तथा 24.54 प्रतिशत रहा । गाजियाबाद एक प्रमुख परिवहन केन्द्र भी है जहाँ 14.74 प्रतिशत कर्मी परिवहन एवं संचार में संलग्न पाये गये हैं ।

कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है जहाँ अनेक उद्योगों का केन्द्रीकरण हुआ है । यहाँ विकसित उद्योगों में सूती व ऊनी वस्त्रोद्योग चर्म एवं चर्म उत्पाद उद्योग, उर्वरक, वनस्पति तेल आदि उद्योगों का केन्द्रीकरण हुआ है । कानपुर में सूती वस्त्र के एक दर्जन से अधिक कारखाने हैं जिनमें एलगिन मिल्स लि0, म्योर मिल्स, विक्टोरिया मिल्स, अथर्टन मिल्स, स्वदेशी मिल्स, जे0के0 मिल्स, जैपुरिया मिल्स, कानपुर काटन मिल्स, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स प्रमुख हैं । देश का प्रथम ऊनी कारखाना 'लाल इमली' की स्थापना 1876 में कानपुर में ही हुई थी जो वर्तमान में भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ऊनी कारखाना है जहाँ उच्च कोटि के ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है । कानपुर उत्तरी भारत में चमड़ा उद्योग का भी प्रमुख केन्द्र है जहाँ उच्च कोटि के जूते, चप्पलें, सूट-केस तथा सेना में प्रयुक्त होने वाले विविध

सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं । 'कानपुर कूपर एलेन' चमड़े का प्रसिद्ध कारखाना है । यहाँ अनेक रासायनिक उद्योगों का भी विकास हुआ है जिनमें गंधक, तेजाब, साबुन, वार्निश आदि प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त विविध इंजीनियरिंग तथा उपजों पर आधारित दाल एवं चावल बनाने और आटा पीसने के कारखानें भी कानपुर में अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं । औद्योगिक विकास के साथ-साथ कानपुर एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी बन गया है । यह कपास, सूती-ऊनी वस्त्र, चमड़े के सामान, अनाज, तिलहन आदि का प्रमुख वितरक केन्द्र है ।

कानपुर प्रधानत: औद्योगिक-व्यापारिक नगर होते हुए एक प्रमुख शैक्षिक केन्द्र भी है । यहाँ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य नगर से अधिक है । यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालिटेक्नीक आदि के अतिरिक्त कई स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालय भी हैं जहाँ शिक्षण कार्य सम्पादित होते हैं ।

मोदीनगर और गाजियाबाद में मुख्यत: भारी उद्योग और रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है । इन नगरों में सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, अल्कोहल तथा विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के कारखाने हैं । यहाँ के इंजीनियरिंग कारखानों में मशीनों तथा उनके पुर्जे, साइकिलें, टिन के कनस्तर आदि सामान बनाये जाते हैं ।

सहारनपुर (जनसंख्या 295,355) की 27.09 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कर्मी है । पुरुष जनसंख्या का 48.58 प्रतिशत तथा महिला जनसंख्या का 3.21 प्रतिशत आर्थिक क्रियाओं में योगदान दे रहा है । गत दशक में इसकी जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और विविध क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या में क्रमश: 31.04, 30.89 और 31.05 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । यहाँ पुरुष कर्मियों का 92.76 प्रतिशत और महिला कर्मियों का 91.98 प्रतिशत विविध क्रियाओं में संलग्न है । सहारनपुर जनपद मुख्यालय होने के साथ ही प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक एवं परिवहन केन्द्र भी है । 1971 जनसंख्या के अनुसार इसकी कुल कार्यशील जनसंख्या का 26.84 प्रतिशत विनिर्माण उद्योग में,

22.65 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 22.84 प्रतिशत विविध सेवाओं में और 17.12 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में कार्यरत था । सहारनपुर में सूतीवस्त्र, चीनी, कागज, काष्ठ आदि के कारखानें स्थापित हुए हैं । यहाँ आटा पीसने और दाल बनाने के भी कारखाने हैं ।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा प्रदेश का द्वितीय वृहत्तम (1007,604) नगर है । यहाँ की 27.72 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है किन्तु यह अनुपात पुरूषों और स्त्रियों में क्रमश: 47.62 प्रतिशत और 3.73 प्रतिशत है । लखनऊ महानगर के 92.42 प्रतिशत कर्मी विविध क्रियाओं में संलग्न हैं । इस क्रिया-वर्ग में पुरूष कर्मियों का 92.30 प्रतिशत और महिला कर्मियों का 94.32 प्रतिशत कार्यरत है । इसकी कुल कार्यशील जनसंख्या में पुरूषों और स्त्रियों का योगदान क्रमश: 97.68 और 2.32 प्रतिशत है । आठवें दशक में लखनऊ की कुल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या और विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की संख्या में क्रमश: 23.79, 23.25 और 22.98 प्रतिशत का विकास हुआ है ।

1971 जनगणना के समंकों पर आधारित नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार लखनऊ सेवा कार्यों तथा परिवहन एवं संचार में विशिष्टीकृत है । इसकी 41.44 प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या विविध सेवाओं में और 13.88 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में संलग्न थी जो प्रादेशिक औसत से अधिक है । व्यापार तथा भारी उद्योग में उक्त प्रभाग क्रमश 18.77 और 16.29 प्रतिशत था । यहाँ सचिवालय, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के अनेक कार्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, कई स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, अस्पताल, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आदि स्थित हैं जिनसे 2.5 लाख से अधिक लोग आर्थिक रूप से सम्बद्ध हैं । लखनऊ उत्तरी तथा उत्तर-पूर्व रेलवे का बृहद् जंक्सन और सड़क परिवहन का प्रमुख केन्द्र है । प्रदेश का डाक एवं तार तथा 'दूर संचार' का प्रधान केन्द्र भी लखनऊ में ही है । यहाँ का अमौसी द्वितीय श्रेणी का हवाई अड्डा है जहाँ से राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं । लखनऊ उड्डयन क्लब का प्रधान केन्द्र है ।

विविध क्रियाओं में अल्पविशिष्टीकृत मुजफ्फरनगर और बरेली प्रथम श्रेणी के न

हैं जिनकी क्रमश: 91.78 और 91.75 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या विविध कार्यों में लगी हुई है। इन नगरों के उक्त क्रियावर्ग में संलग्न श्रमशक्ति में महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: 3.50 और 4.00 है जबकि अधिकांश महिला कर्मी विविध क्रियाओं में ही संलग्न हैं। गत दशक में मुजफ्फरनगर की कुल जनसंख्या और विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों की संख्या में क्रमश: 49.69 तथा 49.19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि बरेली में यह वृद्धि क्रमश: 37.82 तथा 39.24 प्रतिशत रही। मुजफ्फरनगर प्रधानत: व्यापारिक और परिवहन केन्द्र है जहाँ 1971 में कुल कार्यशील जनसंख्या का 28.41 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में और 13.50 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में संलग्न था। बरेली औद्योगिक नगर है जहाँ परिवहन तथा अन्य सेवाओं का भी विशिष्ट स्थान है। इन क्रियाओं में बरेली की श्रमशक्ति का क्रमश: 20.74 प्रतिशत तथा 17.40 प्रतिशत भाग लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरनगर और बरेली दोनों ही जनपद मुख्यालय हैं और विविध सेवाओं में इनके श्रमशक्ति का क्रमश: 29.24 और 31.20 प्रतिशत संलग्न था। बरेली में सूती वस्त्र, चीनी, दियासलाई एवं काष्ठ, वार्निश एवं ताड़पीन निर्माण के कारखाने हैं।

इलाहाबाद (जनसंख्या 6,50,070) एक प्रसिद्ध सेवा केन्द्र है जिसकी 91.53 प्रतिशत श्रमशक्ति विविध क्रियाओं में कार्यरत है। इस क्रियावर्ग में पुरुष श्रमिकों का 91.43 प्रतिशत और महिला श्रमिकों का 84.89 प्रतिशत भाग लगा हुआ है किन्तु इस व्यवसाय वर्ग में स्त्रियों का प्रतिशत मात्र 3.26 प्रतिशत ही है। गत दशक में इसकी कुल जनसंख्या, श्रमशक्ति एवं विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति में क्रमश: 26.71, 16.96 और 19.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इलाहाबाद प्रधानत: सेवा केन्द्र है और 1971 में इसकी श्रमशक्ति का 43.23 प्रतिशत विविध सेवाओं में संलग्न था। इसके अतिरिक्त 14.67 प्रतिशत श्रमशक्ति वृहद् उद्योगों में, 19.63 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में तथा 9.26 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में कार्यरत थी।

इलाहाबाद (प्रयाग) हिन्दुओं का प्रमुख धार्मिक एवं तीर्थस्थान है जहाँ त्रिवेणी के पावन संगम पर प्रति वर्ष माघ मास में सामान्य मेला, प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ और छठें वर्ष अर्द्धकुम्भ का मेला लगता है जहाँ देश भर के तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ धार्मिक कार्यों में संलग्न पण्डों एवं पुजारियों की बड़ी संख्या है जिनकी जीविका धार्मिक क्रियाओं पर ही

आधारित है । यह उत्तर रेलवे का जंक्सन है तथा उत्तर-पूर्व रेलवे का अन्तिम स्टेशन भी है । यह सड़क परिवहन का भी केन्द्र है । इसके निकट स्थित बमरौली द्वितीय श्रेणी का हवाई अड्डा है । औद्योगिक दृष्टि से नैनी (इलाहाबाद) का विशेष महत्त्व है जो एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया है । यहाँ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में तीन वृहद् उद्योग[5] 1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, 2. भारत पम्प एवं कम्प्रेशर लि0, और 3. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि0 स्थापित हुए हैं । इसके साथ ही निजी क्षेत्र में कई उद्योगों का विकास हुआ है जिनमें जीप फ्लैश लाइट, इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन आदि उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार इलाहाबाद में वृहद् उद्योगों की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

इलाहाबाद प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र है जहाँ विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, कृषि महाविद्यालय और पालीटेक्निक के अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक महाविद्यालय हैं जिनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि का शिक्षण कार्य होता है । केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के अनेक कार्यालय जैसे महालेखाकार कार्यालय, शिक्षा निदेशालय, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषद्,राजस्व कार्यालय आदि यहीं स्थित हैं । उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद में ही है । इस प्रकार सेवा केन्द्र के रूप में इलाहाबाद का विशिष्ट स्थान है ।

हरद्वार भी प्रथम श्रेणी का नगर है जिसकी 91.30 प्रतिशत श्रमशक्ति विविध क्रियाओं में लगी हुई है । इसकी कुल जनसंख्या (145,946) का 27.15 प्रतिशत आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत है । हरद्वार हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केन्द्र भी है । 1971 में इसकी कुल श्रमशक्ति का 37.57 प्रतिशत सेवाओं में, 23.45 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 12.62 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में संलग्न था । इसकी 12.60 प्रतिशत श्रमशक्ति विनिर्माण उद्योग में भी लगी हुई थी ।

उत्तर प्रदेश का चतुर्थ वृहत्तम नगर आगरा (जनसंख्या 7,47,318) की कुल श्रम

शक्ति का 90.99 प्रतिशत विविध क्रियाओं में संलग्न है । इसकी 26.58 प्रतिशत जन-संख्या ही आर्थिक कार्यों में सहयोग दे रही है । उक्त क्रियाशीलता अनुपात पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 47.77 और 1.87 प्रतिशत है । इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का योगदान अत्यल्प है । आठवें दशक में आगरा की कुल जनसंख्या और कार्य शील जनसंख्या में 17.76 और 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों की संख्या में 23.41 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गयी है । 1971 जनगणना के अनुसार विनिर्माण और परिवहन में आगरा को सामान्य विशिष्टीकरण प्राप्त है । इसकी श्रमशक्ति का 24.25 प्रतिशत विनिर्माण उद्योग में, 21.88 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 12.86 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में तथा 26.35 प्रतिशत विविध सेवाओं में लगा हुआ था ।

आगरा दक्षिण-पश्चिम में उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे केन्द्र है । यह सड़क यातायात का भी केन्द्र है । आवागमन का प्रमुख केन्द्र होने के कारण यह नगर व्या-पारिक और औद्योगिक केन्द्र भी बन गया है । यहाँ चमड़े के सामान - जूता, चप्पल, सूटकेस आदि बनाने के कई कारखाने हैं । दरियाँ और कालीन बनाने का कार्य कार-खानों तथा गृह उद्योग दोनों ही रूपों में किया जाता है । आगरा में सूती वस्त्र के कई कारखाने हैं । आगरा शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केन्द्र है जहाँ एक विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज तथा कई स्नातकोत्तर एवं स्नातक महाविद्यालय संचालित होते हैं । विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के कारण आगरा एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र भी है जहाँ देश-विदेश से पर्यटक आते रहते हैं ।

अल्प विशिष्टीकृत अन्य नगरों में प्रथम श्रेणी के नगर सीतापुर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, झाँसी और रामपुर तथा द्वितीय श्रेणी के नगर पीलीभीत, हाथरस, लखीमपुर, गोण्डा, और चन्दौसी हैं । मुख्य कर्मियों का अनुपात पीलीभीत में 27.11 प्रतिशत, हाथरस में 25.99 प्रतिशत, सीतापुर में 28.78 प्रतिशत, लखीमपुर में 25.71 प्रतिशत, गोण्डा में 26.20 प्रतिशत, मुरादाबाद में 27.57 प्रतिशत, बुलन्दशहर में 24.93 प्रतिशत झाँसी में 25.04 प्रतिशत, रामपुर में 27.66 प्रतिशत और चन्दौसी में 25.71 प्रतिशत है । इन नगरों में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मियों का विविध क्रियाओं में पृथक-पृथक

संलग्नता प्रतिशत लगभग समान ही है किन्तु पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अत्यल्प है । केवल झाँसी को छोड़कर जहाँ इस क्रियावर्ग में प्रति हजार पुरुषों पर 93 महिलायें पायी जाती हैं, इनमें से किसी भी अन्य नगर में लिंगानुपात 53 महिलायें प्रति हजार पुरुष से अधिक नहीं है । मुरादाबाद ‡27‡ और हाथरस ‡31‡ में यह लिंगानुपात न्यूनतम है ।

गत दशक में बुलन्दशहर में विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की संख्या में अधिकतम 67.59 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अंकित की गयी है जबकि यह वृद्धि सीतापुर में 54.95 प्रतिशत, पीलीभीत में 36.20 प्रतिशत, झाँसी में 42.82 प्रतिशत, गोण्डा में 33.38 प्रतिशत, मुरादाबाद में 30.76 प्रतिशत, हाथरस में 26.44 प्रतिशत, लखीमपुर में 28.76 प्रतिशत, रामपुर में 24.24 प्रतिशत और चन्दौसी में 21.93 प्रतिशत रही । उल्लेखनीय है कि इन नगरों में विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों की वृद्धि इनकी जनसंख्या वृद्धि के लगभग समानुपाती रही है जिससे इनकी व्यावसायिक संरचना में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है । केवल हाथरस और चन्दौसी को छोड़कर अन्य आठ नगर जनपद मुख्यालय हैं ।

कार्यात्मक वर्गीकरण ‡अध्याय चार‡ के अनुसार मुरादाबाद और रामपुर औद्योगिक नगर हैं जिनकी 25.45 और 28.66 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या वृहत् विनिर्माण उद्योगों में लगी हुई थी । इन नगरों में व्यापार, परिवहन तथा अन्य सेवाओं में भी कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख भाग संलग्न है । मुरादाबाद की कार्यशील जनसंख्या का 15.16 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 17.39 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में तथा 24.99 प्रतिशत विविध सेवाओं में कार्यरत था जबकि रामपुर के लिये उक्त प्रभाग क्रमशः 16.25, 14.48 तथा 23.75 प्रतिशत पाया गया है । मुरादाबाद में चीनी, अलकोहल, काँच, दाल बनाने तथा आटा पीसने, काष्ठ एवं फर्नीचर आदि के कारखानें हैं । यहाँ कई प्रकार के लघु उद्योग भी विकसित हैं जिनमें पीतल व कलई के बर्तन बनाना प्रमुख हैं । रामपुर में सूती वस्त्र का कारखाना है । यहाँ के अन्य लघु उद्योगों में अल्कोहल निर्माण दियासलाई आदि प्रमुख हैं ।

झाँसी जनपद मुख्यालय होने के साथ ही प्रमुख परिवहन केन्द्र है जिसकी 30.32

प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या परिवहन एवं संचार में संलग्न थी (1971) जबकि बृहत् नगरों का प्रादेशिक औसत 11.40 प्रतिशत ही था । यह दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंकशन है । पीलीभीत, हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर, बुलन्दशहर और चन्दौसी व्यापारिक केन्द्र हैं जिनकी कुल कार्यशील जनसंख्या का क्रमशः 20.72, 28.80, 24.74, 26.15, 27.37 और 22.47 प्रतिशत व्यापार और वाणिज्य में कार्यरत पाया गया है । चन्दौसी, गोण्डा, हाथरस, पीलीभीत, बुलन्दशहर, मुरादाबाद और रामपुर की व्यावसायिक संरचना में परिवहन एवं संचार का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन नगरों में कुल कार्यशील जनसंख्या का क्रमशः 19.10, 16.11, 15.33, 15.87, 11.53, 17.39 और 14.48 प्रतिशत भाग परिवहन एवं संचार में कार्यरत पाया गया है । यदि अन्य सेवाओं में संलग्न कर्मियों के प्रभाग को देखा जाय तो यह मुरादाबाद में 24.99, रामपुर में 23.75, झांसी में 31.56, सीतापुर में 39.97, हाथरस में 22.44, पीलीभीत में 27.15, गोण्डा में 33.67, चन्दौसी में 24.78, लखीमपुर में 39.18 और बुलन्दशहर में 31.95 प्रतिशत है (1971) ।

7.4 अविशिष्टीकृत नगर

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 66 नगरों में से 40 नगरों में कुल श्रमशक्ति का विविध क्रियाओं में संलग्न प्रभाग समस्त वृहत् नगरों के प्रादेशिक माध्य (87.27 प्रतिशत) से कम है अतः इन्हें उक्त क्रियावर्ग में विशिष्टीकृत नहीं माना गया है । मऊनाथ भंजन में न्यूनतम 33.17 प्रतिशत कर्मी ही विविध क्रियाओं में संलग्न हैं । इस क्रिया-वर्ग में 70 प्रतिशत से कम प्रभाग रखने वाले अन्य नगर सम्भल, टाण्डा और फतेहपुर हैं । इसके विपरीत 85 प्रतिशत और प्रादेशिक माध्य (87.27 प्रतिशत) के मध्य श्रमशक्ति वाले नगर क्रमशः खुर्जा, मैनपुरी, हापुड़, आजमगढ़, गोरखपुर, अलीगढ़, शामली, मेरठ, काशीपुर, हरदोई और देवरिया हैं । इनमें से कतिपय नगर विविध क्रियाओं के उप, वृहत्-उद्योग, निर्माण कार्य, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार तथा अन्य विविध सेवाओं में से एक या एक से अधिक में विशिष्टीकरण भी रखते हैं किन्तु इन सभी क्रियाओं के साथ संयुक्त हो जाने से उनका किसी विशेष क्रिया-वर्ग में विशिष्टीकरण परिलक्षित नहीं हो पाता । इसे स्पष्ट करने हेतु 1971 जनगणना के समंकों का प्राश्रय लिया गया है ।

गोरखपुर (प2) और मुगलसराय (प3) पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशिष्ट परिवहन केन्द्र हैं। यहाँ 1971 में क्रमश: 26.54 और 53.44 प्रतिशत श्रमशक्ति परिवहन एवं संचार में कार्यरत थी।[6] बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, मिर्जापुर-विन्ध्याचल, अमरोहा, नजीबाबाद और शामली प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हैं जो भ श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत हुए हैं। इन नगरों की क्रमश: 20.74, 26.39, 26.84, 22.03, 22.77, 21.70, 25.77, 22.10 एवं 27.23 प्रतिशत श्रमशक्ति वृहत् विनिर्माण उद्योगों में लगी हुई थी। बरेली में चीनी, सूती वस्त्र, अलकोहल काष्ठ आदि के कारखाने हैं। मिर्जापुर-विन्ध्याचल में सूती वस्त्र; अमरोहा में धातु के वर्तन; सहारनपुर में चीनी, कागज, सूती वस्त्र और अल्कोहल; नजीबाबाद में वनस्पति तेल, काँच; अलीगढ़ में ताले, और शामली में धातु के बर्तन बनाने के उद्योग अपना विशेष स्थान रखते हैं।

मुजफ्फरनगर, मैनपुरी और कासगंज में व्यापारिक क्रिया का विशेष महत्व है और इन नगरों में क्रमश: 28.41, 27.63 और 27.51 प्रतिशत श्रमशक्ति व्यापार और वाणिज्य में कार्यरत पायी गयी है। अन्य नगर जहाँ व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न कर्मियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, ये हैं : जौनपुर (25.80), हापुड़ - 24.12, रायबरेली - 23.90, बाँदा - 24.65, बस्ती - 24.10, हरदोई - 24.10, उरई- 24.64, बलिया - 26.19, गाजीपुर - 25.32, देवरिया - 24.18 और शामली - 25.78।

अनेक जनपद मुख्यालय विविध क्रियाओं में विशिष्टीकृत नहीं पाये गये हैं किन्तु वहाँ जनपदीय प्रशासनिक कार्यालय एवं क्रियायें निश्चित रूप से विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन केन्द्रों पर जनपद के मुख्य चिकित्सालय, न्यायालय, शिक्षण संस्थायें विभिन्न जनपद स्तरी कार्यालय आदि पाये जाते हैं जिनमें अधिकांशत: शिक्षित कर्मी संलग्न होते हैं। गोरखपुर फैजाबाद, बस्ती, मेरठ, अलीगढ़, आजमगढ़, मैनपुरी, उरई, बिजनौर, बदायूँ, बाराबंकी, गाजीपुर, इटावा, शाहजहाँपुर, बलिया, बाँदा, रायबरेली, जौनपुर, बहराइच, वाराणसी, ललितपुर, फतेहपुर आदि इसी प्रकार के नगर हैं जो प्रमुख प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र होते हुए भी विविध क्रियाओं के संयुक्त क्रियावर्ग में विशिष्टीकृत नहीं हो सके हैं

7.5 कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता के कतिपय जनांकिकीय सहचर

विविध क्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक वर्गों को सम्मिलित किया गया है जैसे विनिर्माण उद्योग (गृह उद्योग के अतिरिक्त), निर्माणकार्य, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार तथा विविध सेवायें आदि । विविध सेवाओं में शिक्षा, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, सैन्य आदि सेवायें समाहित हैं । ये सभी विविध क्रियायें मुख्यत: नगरीय केन्द्रों परसंकेन्द्रित होने की प्रवृत्ति रखती हैं । यद्यपि पृथक-पृथक क्रियावर्गों या सेवाओं की प्रकृति तथा उनके संकेन्द्रण की प्रवृत्ति में पर्याप्त भिन्नता मिलती है किन्तु सामूहिक रूप से नगरों में इन क्रियाओं की कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता कुछ जनांकिकीय तथ्यों से सम्बद्ध होती हैं और उनके मध्य सहसम्बन्ध पाये जाते हैं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं । यहाँ कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता और उसके चार सहचरों - जनसंख्या आकार, कार्यशील जनसंख्या, साक्षरता एवं लिंगानुपात के मध्य पाये जाने वाले सहसम्बन्ध गुणांक का परिकलन किया गया है और उनके समाश्रयण समीकरण का निर्धारण करते हुए सरल समाश्रयण रेखा का प्रदर्शन चित्र 7.2 में किया गया है ।

1. जनसंख्या आकार

विविध क्रियाओं के अन्तर्गत सम्मिलित कियायें नगरीय प्रकृति की हैं अत: नगरीय आकार में वृद्धि के साथ-साथ इन क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति में वृद्धि तो स्वाभाविक है किन्तु कार्यात्मक गहनता के दृष्टिकोण से इस क्रिया-वर्ग के भिन्न भिन्न घटकों में अन्तर पाया जाता है । सामान्यतया नगरीय आकार में वृद्धि के साथ-साथ सेवाओं में संलग्न श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि पायी जाती है किन्तु विनिर्माण, व्यापार या परिवहन आदि पर यह प्रवृत्ति तथैव लागू नहीं होती है । यहाँ नगरों के जनसंख्या आकार और उनकी विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति के प्रतिशत या कार्यात्मक विशिष्टीकरण गहनता के मध्य परिकलित सहसम्बन्ध गुणांक + 0.208 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त दोनों चरों के मध्य साधारण धनात्मक सहसम्बन्ध का स्पष्टीकरण होता है । इन दोनों चरों के लिए समाश्रयण समीकरण $Y = 85.58 + 0.09 X$ आया है जो यह स्पष्ट करता है

कि जनसंख्या ४x४ में प्रति इकाई ४दस हजार४ वृद्धि होने पर विविध क्रियाओं के कार्यात्मक गहनता में 0.090 इकाई की वृद्धि होगी जबकि 85.58 स्थिरांक है । सम्बन्धित सरल समाश्रयण रेखा का प्रदर्शन चित्र 7.2ए में किया गया है ।

2. कार्यशील जनसंख्या

नगरों की कार्यशील जनसंख्या और कुल जनसंख्या के अनुपात का प्रभाव विविध क्रियाओं के विशिष्टीकरण गहनता पर भी पड़ता है किन्तु यह तथ्य अधिक प्रभावशाली नहीं है । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के समस्त नगरों में कार्यशील जनसंख्या अनुपात और विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति के अनुपात ४प्रतिशत४ के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक + +0.012 पाया गया है जो धनात्मक किन्तु अत्यल्प सहसम्बन्ध का बोधक है । इन दोनों चरों के सहसम्बन्ध को समाश्रयण समीकरण $Y = 84.99 + 0.084 x$ भी स्पष्ट कर रहा है । इस समीकरण से यह विदित है कि कार्यशील जनसंख्या अनुपात में प्रति इकाई वृद्धि होने पर विविध क्रियाओं की गहनता में 0.084 इकाई की वृद्धि होना सम्भावित है जबकि 84.99 स्थिरांक है । इससे सम्बद्ध सरल समाश्रयण रेखा चित्र 7.2 बी में प्रदर्शित है ।

3. साक्षरता

विविध क्रियाओं के कतिपय घटकों जैसे, बागवानी एवं मत्स्यपालन आदि, निर्माण कार्य, व्यापार एवं परिवहन आदि में अशिक्षित तथा अकुशल श्रमिक बड़ी मात्रा में संलग्न हैं और इनका अनुपात प्राय: साक्षरता के अनुकूल नहीं पाया जाता जबकि अधिकांश सेवायें जैसे लोक प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, विधि आदि प्रत्यक्षत: शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार विनिर्माण कार्य में जहाँ एक ओर उच्च प्रशिक्षण प्राप्त अभियन्ता कार्यरत होते हैं वहीं असंख्य अशिक्षित श्रमिक भी विभिन्न अकुशल कार्यों में संलग्न होते हैं । अत: साक्षरता अनुपात और विविध क्रियाओं में संलग्न कर्मियों के प्रतिशत में अधिक गहरा सम्बन्ध नहीं परिलक्षित होता है । इन दोनों चरों के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक + 0.224 है जो धनात्मक है और यह प्रकट करता है कि किसी नग की जनसंख्या में साक्षरता अनुपात में वृद्धि होने पर उसके विविध क्रियाओं में संलग्न कि के अनुपात में भी वृद्धि होती है । इसका परिकलित समाश्रयण समीकरण है $Y = 72.$

+ 0.28 x जिससे स्पष्ट होता है कि साक्षरता अनुपात में प्रति इकाई वृद्धि पर विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमशक्ति के अनुपात में 0.28 इकाई की वृद्धि सम्भावित है जबकि 72.94 स्थिरांक है। इस सहसम्बन्ध को चित्र 7.2सी में सरल समाश्रयण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

4. लिंगानुपात

जैसा कि विदित है विविध क्रियाओं के विभिन्न घटकों की प्रकृति में पर्याप्त विभेद मिलता है, कुछ क्रियायें महिलाओं के लिए सुअवसर प्रदान करती हैं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि किन्तु अधिकांश क्रियाओं में महिलाओं की संलग्नता अत्यल्प है विशेषरूप से विनिर्माण उद्योग तथा परिवहन एवं संचार में। इस प्रकार सम्मिलित रूप में विविध क्रियाओं में श्रमशक्ति के अनुपात में वृद्धि होने पर इस क्रियावर्ग में महिलाओं का अनुपात घटता जाता है जो उक्त दोनों चरों के मध्य प्राप्त सहसम्बन्ध गुणांक - 0.237 से स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए परिकलित समाश्रयण समीकरण $y = 74.80 - 0.33\ x$ से विदित है कि कार्यात्मक गहनता में प्रति इकाई वृद्धि होने पर लिंगानुपात में 0.33 इकाई का ह्रास होगा जबकि 74.80 स्थिरांक है। उक्त सहसम्बन्ध को चित्र 7.2डी में देखा जा सकता है।

सन्दर्भ

1. Mayer, H.M. : "Geography and Urbanism" in idem and Kohn, C.F. : Readings in Urban Geography, Central Bank Depot, Allahabad, 1967, pp. 7-8.

2. Census of India 1981, Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.

3. Ibid.

4. Census of India 1971, Uttar Pradesh, Part II-A, General Population Tables.

5. Government of Uttar Pradesh : Industrial Revolution, Planning and Research Division, Directorate of Industries, Kanpur, 1971, p. 5.

6. Singh, R.N. and Sahab Deen : "Transportk and Communication in the Occupational Structure of Urban Centres in Eastern Uttar Pradesh", Geographical Review of India, Vol. 44, No.3, pp. 69-88.

------------::o:------------

अध्याय आठ

निष्कर्ष एवं सुझाव

देश के अन्य भागों की भाँति उत्तर प्रदेश ने भी नियोजन के 38 वर्ष पूरे कर लिया है । अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी । अनेक महान उद्देश्यों को लेकर विकास योजनायें बनायी गयीं और उनको क्रियान्वित किया गया जिनमें कार्यावसरों तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य भी सम्मिलित है । इन योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य जनता के लिए अधिक से अधिक रोजगार अव-सरों को प्रदान करना रहा है ।[1] "प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश अन्य प्रान्तों की तुलना में नितान्त अविकसित था । हर सम्भव चेष्टा के बाद भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश की विकास दर सम्पूर्ण भारत की विकास दर से कम रही । परन्तु इसके बाद प्रदेश के विकास में तीव्रता आयी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश ने देश की विकास दर 5.3 से आगे बढ़कर 5.7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर ली । छठीं योजना में भी देश की विकास दर 5.2 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की विकास दर 5.8 प्रतिशत रही ।"[2] उत्तर प्रदेश की सातवीं योजना का आकार छठीं योजना से 77.4 प्रतिशत अधिक है और इस योजना में विकास दर छः प्रतिशत निर्धारित की गयी है ।[3]

विगत अध्यायों में उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की जन-संख्या के आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता की प्रगति तथा वर्तमान व्यावसायिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । व्यावसायिक गतिशीलता के अध्ययन हेतु 1981 जनगणना के व्यावसायिक समंकों की तुलना 1971 जनगणना के समंकों से की गयी है । इस प्रकार के अध्ययन से प्रदेश की नगरीय अर्थव्यवस्था तथा नगरीय जनसंख्या की व्यावसायिक विशेषताओं से सम्बद्ध कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सम्मुख आते हैं जिनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रोन्नति तथा रोज-गार वृद्धि हेतु उपयुक्त उपायोंका सुझाव दे सकते हैं ।

प्रस्तुत अध्याय के दो प्रमुख लक्ष्य हैं : प्रथम, उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना की मुख्य विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करना,

तथा द्वितीय, नगरीय कार्यशील जनसंख्या के वर्तमान प्रतिरूप में रोजगार एवं व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त तथा सकारात्मक उपायों का सुझाव प्रदान करना ।

8.1 नगरीय व्यावसायिक संरचना के प्रमुख तथ्य

नगरीय व्यवसाय प्राय: ग्रामीण व्यवसायों से भिन्न हुआ करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्यपालन आदि की प्रमुखता पायी जाती है जबकि नगरीय केन्द्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक आदि क्रियाओं का संकेन्द्रण होता है । नगरों में विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्रियायें विकसित होती हैं । यद्यपि लघु नगरों में जिनकी प्रोन्नति गावों के विकास से होती है प्राय: ग्रामीण पर्यावरण एवं व्यवसायों का ही प्रभुत्व देखने को मिलता है किन्तु वृहत् नगरों में नगरीय पर्यावरण विकसित हो जाता है और अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर-प्राथमिक प्रकार्यों में संलग्न होती है । यहाँ अध्ययन हेतु उन नगरों का चयन किया गया है जिनकी जनसंख्या 1981 जनगणनानुसार 50 हजार या इससे अधिक है । अत: वृहदाकार के फलस्वरूप उक्त नगरों में नगरीय क्रियाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए किन्तु कृषि प्रधान मैदानी भागों में स्थित होने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है । उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना के प्रमुख तथ्य निम्नांकित हैं :

1. निम्न कार्यशीलता

1981 जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में संयुक्त रूप में मात्र 26.94 प्रतिशत जनसंख्या ही श्रमशक्ति में संलग्न है जो उत्तर प्रदेश तथा अनेक अन्य राज्यों के औसत से काफी कम है । उत्तर प्रदेश और भारत की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्रमश: 29.22 प्रतिशत तथा 33.45 प्रतिशत है । सम्पूर्ण भारत की नगरीय जनसंख्या का 29.23 प्रतिशत मुख्य श्रमिकों के रूप में श्रमशक्ति में संलग्न है । उत्तर प्रदेश में भी कुल नगरीय जनसंख्या में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 27.30 है । इस प्रकार स्पष्ट है कि चयनित नगरों में कार्यशीलता का प्रतिशत प्रदेश तथा देश की सम्पूर्ण जनसंख्या ही नहीं बल्कि नगरीय जनसंख्या के औसत से भी निम्न है ।

ज्ञातव्य है कि भारत के ही विभिन्न राज्यों में कार्यशीलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है । केन्द्रशासित राज्य अरुणाचल प्रदेश में 49.61 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है जो देश के लिए अधिकतम है । कुल जनसंख्या में उच्च कार्यशीलता वाले राज्यों में नागालैण्ड (47.53 प्रतिशत), सिक्किम (46.60 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (42.26 प्रतिशत), मेघालय (43.44 प्रतिशत), मिजोरम (41.73 प्रतिशत), दादरा एवं नगर हवेली (40.81 प्रतिशत), मनीपुर (40.35 प्रतिशत), तमिलनाडु (39.30 प्रतिशत), महाराष्ट्र (38.71 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (38.41 प्रतिशत) उल्लेखनीय हैं । किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में कार्यशीलता के स्तर का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है अतः कुल जनसंख्या में श्रमशक्ति का प्रभाव एक-तिहाई से कम होना चिन्ता का विषय है और विकास में अवरोधक । उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरों में यह अनुपात एक चौथाई से कुछ ही अधिक है । यहाँ अर्जक जनसंख्या की तुलना में अनर्जक अर्थात् आश्रित जनसंख्या लगभग तीन गुना है जो निर्वाह मूलक पिछड़ी अर्थव्यवस्था की द्योतक है ।

2. आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का अत्यल्प योगदान

भारतीय महिलाओं की स्वतंत्र अस्मिता में जहाँ एक ओर धार्मिक और सामाजिक अवरोध हैं वहीं दूसरी ओर आर्थिक बाधायें कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । हमारे देश में आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों का योगदान बहुत ही कम पाया जाता है और अधिकांश महिलायें घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती हैं । वे आर्थिक रूप से अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर करती हैं ।[4] भारतीय जनगणना 1981 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में मात्र 2.91 प्रतिशत महिलायें ही मुख्य श्रमिक हैं । ऐसे कुल 66 नगरों में से 13 नगर ऐसे हैं जिनकी 2.00 प्रतिशत से भी कम महिलायें श्रमशक्ति में सम्मिलित हैं ।

महिलाओं की आर्थिक कार्यों में कम संलग्नता के कई उल्लेखनीय कारण हैं जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है उनकी घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता । भारतीय समाज में अधिकांश और कहीं-कहीं सम्पूर्ण घरेलू कार्य केवल महिलाओं को करने पड़ते हैं । बच्चों के लालन-पालन, खाना पकाने एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा से लेकर पानी भरने, ईंधन इकट्ठा करने तथा पशुओं की देखरेख तक अनेक प्रकार के अनार्थिक कार्य करने पड़ते

हैं। चूँकि इन कार्यों में पुरुष रुचि नहीं लेते अत: इन घरेलू कार्यों में स्त्रियों की व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि वे घर से बाहर कार्य करने को सोच भी नहीं पातीं।[5]

पाश्चात्य औद्योगिक देशों में आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की संलग्नता भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। पाश्चात्य देशों में महिलाओं में स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता एवं तत्परता, लघु परिवार, घरेलू क्रियाओं में स्वचालित मशीनों के प्रयोग, शिशु पालन केन्द्रों का प्रचलन आदि के परिणामस्वरूप महिलायें आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होकर अपने परिवार की आय एवं भौतिक साधनों में वृद्धि करती हैं। उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरों की श्रमशक्ति में महिलाओं का अनुपात अत्यल्प है। इनकी कुल कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का योगदान मात्र 4.93 प्रतिशत ही है और 95.07 प्रतिशत पुरुषों द्वारा पूरा किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं में महिलाओं के अनुपात में भिन्नता भी मिलती है। कृषकों में 3.44 प्रतिशत तथा कृषि श्रमिकों में 7.34 प्रतिशत महिलायें हैं जबकि गृह उद्योगों में महिलाओं का योगदान 10.12 प्रतिशत हो गया है। अन्य विविध क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत 4.47 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिलाओं का झुकाव गृह उद्योग की ओर अधिक है तथा कृषि श्रमिक के रूप में भी अपेक्षाकृत अधिक महिलायें कार्यरत हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण महिलाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी है जिससे महिला श्रमिक मुख्यतया अशिक्षित एवं अकुशल हैं जो कृषि और गृह उद्योगों के लिए ही उपयुक्त हैं। विविध नगरीय सेवाओं में जिनमें शिक्षा तथा प्रशिक्षण आवश्यक होते हैं महिलाओं की संलग्नता अपेक्षाकृत न्यून है। किन्तु नगरीय केन्द्रों में शिक्षा के प्रसार, परिवहन एवं संचार साधनों में वृद्धि, उपयुक्त कार्यों की उपलब्धता, बेहतर जीवन व्यतीत करने की बढ़ती इच्छा, परम्परागत सामाजिक रीति-रिवाजों तथा मान्यताओं में शिथिलता के साथ ही आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की संलग्नता में वृद्धि की सम्भावना है।

3. आर्थिक क्रियाओं में श्रमिकों का असमान वितरण

प्रदेश के वृहत् नगरीय केन्द्रों में जहाँ एक ओर आर्थिक क्रियाओं में पुरुषों एवं

महिलाओं दोनों की संलग्नता अपेक्षाकृत न्यून है वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्रियात्मक वर्गों में उनका वितरण अत्यधिक असमान है । कतिपय क्रियाओं में श्रमशक्ति का अधिकांश भाग लगा हुआ है तो अन्य क्रियाओं में श्रमिकों का अल्पांश ही कार्यरत है । जनगणना 1981 के अनुसार प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में श्रमशक्ति का औसतन 3.02 प्रतिशत कृषक तथा 2.34 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं । गृह उद्योग में 7.37 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं, और शेष 87.27 प्रतिशत अन्य विविध क्रियाओं में संलग्न हैं। विभिन्न क्रिया वर्गों में श्रमिकों के असमान वितरण के अधिक स्पष्टीकरण हेतु जनगणना 1971 के समंकों का प्राश्रय लिया जा सकता है जिसमें समस्त क्रियाओं को अपेक्षाकृत अधिक उपवर्गों (9 वर्गों में) में विभक्त किया गया था ।

जनगणना 1971 के अनुसार प्रदेश के 66 वृहद् नगरों की श्रमशक्ति का 4.88 प्रतिशत प्राथमिक क्रियाओं में और 2.31 प्रतिशत निर्माण कार्यों में संलग्न था । गृह उद्योग में 7.18 प्रतिशत तथा विनिर्माण उद्योगों में 20.33 प्रतिशत श्रमिक संलग्न थे । इसी प्रकार कुल श्रमशक्ति का 21.89 प्रतिशत व्यापार एवं वाणिज्य में, 11.40 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में, तथा 32.01 प्रतिशत सेवाओं में संलग्न था । इससे स्पष्ट है कि विभिन्न क्रिया-वर्गों में श्रमिकों के वितरण में अधिक असमानता है । अधिकांश नगरों में विभिन्न क्रियाओं का समुचित विकास भी नहीं हुआ है जबकि अनेक नगर एक या एक से अधिक क्रियाओं में विशिष्टीकरण रखते हैं और वहाँ शेष क्रियाओं का विकास नहीं हुआ है । उदाहरणार्थ, 1971 में मऊनाथभंजन, टाण्डा और वाराणसी के कुल श्रमशक्ति का क्रमशः 62.34, 46.38 तथा 23.97 प्रतिशत गृह उद्योग में कार्यरत था जबकि प्रादेशिक औसत 7.18 प्रतिशत था । इसी प्रकार मोदीनगर के श्रमशक्ति का 68.71 प्रतिशत, फिरोजाबाद के श्रमशक्ति का 56.18 प्रतिशत तथा गाजियाबाद के श्रमशक्ति का 32.57 प्रतिशत विनिर्माण उद्योगों में कार्यरत रहा । मुगलसराय, झाँसी तथा गोरखपुर के कुल कार्यशील जनसंख्या का क्रमशः 53.44, 30.32 तथा 26.54 प्रतिशत परिवहन एवं संचार में संलग्न था जबकि प्रादेशिक औसत मात्र 11.40 प्रतिशत रहा। यद्यपि नगरों में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास अपेक्षाकृत सन्तुलित होता है किन्तु इस क्रिया-वर्ग में संलग्न श्रमिकों के प्रतिशत में भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है । हाथरस, मुजफ्फरनगर तथा एटा में क्रमशः 28.80, 28.41 एवं 28.37 प्रतिशत श्रमिक

व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न थे जबकि इन्हीं क्रियाओं में मोदीनगर (8.71 प्रतिशत) मऊनाथ भंजन (11.07 प्रतिशत), सम्भल (12.56 प्रतिशत), रुड़की (12.57 प्रतिशत) और टाण्डा (13.51 प्रतिशत) में 15.00 प्रतिशत से कम श्रमशक्ति लगी हुई थी। इसी प्रकार विविध सेवाओं में कुल श्रमशक्ति का अधिकतम 70.36 प्रतिशत (रुड़की) से न्यूनतम 10.72 प्रतिशत (मऊनाथ भंजन) तक पाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अधिकांश नगरों में कुछ विशिष्ट क्रियाओं का विकास अधिक हुआ है और फलतः अन्य क्रियायें अल्पविकसित ही रह गयी हैं।

4. उच्च निर्भरता-अनुपात

जनगणना 1981 के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में संयुक्त रूप से 72.90 प्रतिशत जनसंख्या किसी भी आर्थिक क्रिया में कार्यरत नहीं है और जीविका हेतु परिवार के कर्मी सदस्यों पर आश्रित है। निर्भरता अनुपात कतिपय नगरों में 75.00 प्रतिशत से भी अधिक है जैसे बलिया (76.68), गाजीपुर (76.14), आजमगढ़ (75.49), देवरिया (75.41), मैनपुरी (75.15) और मुगलसराय (75.05)। पुरुष जनसंख्या में आश्रितों का प्रतिशत 52.79 है किन्तु इलाहाबाद, झाँसी, इटावा, जौनपुर, बुलन्दशहर, हापुड़, बाँदा, मुगलसराय, आजमगढ़, उरई, बलिया, गाजीपुर, मैनपुरी, देवरिया और एटा में 55.00 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गैरश्रमिक तथा आश्रित है। वृहद् नगरों में अधिकांश (96.86 प्रतिशत) महिलायें अनर्जक होने के कारण परिवार के अन्य कार्यशील व्यक्तियों पर आर्थिक रूप से आश्रित पायी जाती हैं। कतिपय नगरों में 98.00 प्रतिशत से भी अधिक महिलायें आश्रित हैं। मुरादाबाद, सम्भल, मुगलसराय, चन्दौसी, शामली, देवबन्द, हाथरस, आगरा और शाहजहाँपुर इसी प्रकार के नगर हैं जहाँ महिलाओं में निर्भरता अनुपात अधिक है।

5. कतिपय नगरों में कृषि कार्यों की प्रधानता

कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं बल्कि अनेक लघु नगरों में भी कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इतना ही नहीं कतिपय मध्यम और वृहद् नगरों में भी जिसके चतुर्दिक उपजाऊ कृषि भूमि है, कार्यशील जनसंख्या का उल्लेखनीय प्रभाग कृषकों

तथा कृषि श्रमिकों के रूप में कार्यरत है । उत्तर प्रदेश में 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 20 नगरों में कुल कार्यशील जनसंख्या का 10 प्रतिशत से अधिक और 8 नगरों में 15 प्रतिशत से अधिक कृषक तथा कृषि श्रमिक के रूप में विविध कृषि कार्यों में संलग्न हैं। सम्भल, फतेहपुर और उन्नाव में 20 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों से ही सम्बद्ध है । इसी प्रकार बहराइच, देवबन्द, नगीना, रायबरेली और ललितपुर नगरों की कार्यशील जनसंख्या में 15 प्रतिशत से अधिक कृषक और कृषि श्रमिक हैं । उल्लेखनीय है कि इन नगरों का पर्यावरण ग्रामीण और नगरीय पर्यावरण के मिश्रित स्वरूप को प्रकट करता है । ऐसे नगरों की आकारिकी, गृह प्रकारों, जीवन पद्धति, व्यवसायों आदि पर ग्रामीण छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है ।

6. व्यवसायों पर सामाजिक तथ्यों का प्रभुत्व

उत्तर प्रदेश में जहाँ ग्रामीण व्यवसायों के चयन में जाति, धर्म, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, मान्यताओं आदि का अभी भी नियन्त्रण है वहीं इसके नगरीय केन्द्रों पर भी इन सामाजिक तथ्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है । व्यवसाय के चयन पर जाति एक प्रभावशाली कारक है । नगरों में शिक्षा के प्रसार से सामाजिक परम्पराओं तथा मान्यताओं में उल्लेखनीय ह्रास के बावजूद अभी भी व्यवसाय पर जातीय परम्परा की अमिट छाप देखी जा सकती है । कृषकों में अधिकांशतः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा कुछ पिछड़ी जातियाँ जैसे अहीर, कुर्मी, कोइरी, काछी आदि हैं जबकि कृषि श्रमिकों में अधिकांशतः अनुसूचित जातियां हैं जिनके पास निजी भूमि या जीविका के अन्य साधन नहीं हैं । अशिक्षित एवं अकुशल होने के कारण ये लोग प्रायः कृषि कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य करके मजदूरी प्राप्त करते हैं । चर्म उद्योग में अधिकांश अनुसूचित (मुख्यतया चमार जाति के व्यक्ति ही संलग्न हैं ।

गृह उद्योग में हथकरघा उद्योग एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण उद्योग है जिसका संचालन अधिकांशतः मुसलमानों (मुख्यतया जुलाहों, धुनियों) द्वारा किया जाता है । मुसलमान जनसंख्या-बहुल नगरों में गृह उद्योग में हथकरघा एवं शक्ति चालित करघा उद्योग का विकास अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । मऊनाथ भंजन और टाण्डा इसके विशिष्ट उदाहरण हैं । इसी प्रकार विभिन्न वणिक जातियाँ मुख्यतया व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाओं

में संलग्न हैं और अधिकांश पूँजीपति इसी समुदाय के लोग हैं । कायस्थ जाति के अधिकांश व्यक्ति विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक, भूराजस्व, शैक्षिक आदि क्रियाओं में संलग्न पाये जाते हैं ।

जातीय एवं आर्थिक उपरोक्त परम्पराओं तथा प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अन्यान्य सामाजिक मान्यतायें पुरुषों तथा महिलाओं के व्यवसायों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और साथ ही घरेलू कार्यों में निपुणता हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें आर्थिक कार्यों से दूर रखा जाता है । महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर जाकर कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता । पुरुषों को वाह्य कार्यों के लिए तथा महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिससे घरेलू कार्य प्राय: महिलाओं को करने पड़ते हैं । यहाँ तक कि कामकाजी महिलाओं को भी अधिकांश घरेलू कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं । अत: आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं का योगदान या तो अत्यल्प है या नगण्य है ।

8.2 सुझाव

मानवीय तथ्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिकर्ता है जो किसी प्रदेश के आर्थिक विकास को अग्रसर करता है । अत: मानव शक्ति कभी भी न तो खोयी जानी चाहिए और न ही कम आँकी जानी चाहिए बल्कि इसका उपयोग किसी न किसी भाँति अवश्य ही किया जाना चाहिए । किसी प्रदेश की जनता तभी समृद्ध एवं धनी हो सकती है जबकि वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से संलग्न होकर जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनोपार्जन करने में समर्थ होती है । वास्तव में, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मानव श्रम वह आर्थिक संसाधन होता है जिसके सकारात्मक एवं उपयुक्त प्रयोग से आर्थिक विकास को गति मिलती है । कोई भी विकास आयोजना जिसमें मानव संसाधन का यथोचित प्रयोग नहीं होता है वह आर्थिक रूप से उप-इष्टतम तथा सामाजिक रूप से अनुपयुक्त होती है क्योंकि इससे सर्वसाधारण (जनसमूह) को अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण प्रदान करने के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है ।[6] एक आदर्श एवं पूर्ण व्यावसायिक प्रतिरूप के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह

पुरुष हो या स्त्री, अपनी योग्यता एवं क्षमता के पूर्ण विकास हेतु सुअवसर प्राप्त कर सके । अतः आवश्यकता है उपलब्ध मानव शक्ति को आर्थिक क्रियाओं में व्यक्ति की योग्यता तथा रोजगार की आवश्यकताओं के अनुसार इस ढंग से नियुक्त करने की जिससे कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक स्त्री-पुरुष को रोजगार प्राप्त हो सके । रोजगार नीति सहित आर्थिक विकास का लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त किया जाना चाहिए कि पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि जनता की अधिकतम समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति की यही आधारशिला है ।

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों की व्यावसायिक संरचना तथा नगरीय अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के विश्लेषण के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आर्थिक विकास में श्रम-प्रधान तकनीक द्वारा बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है । किन्तु ग्रामीण प्रवास द्वारा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर नियंत्रण भी परमावश्यक है क्योंकि इसके अभाव में नगरीय बेरोजगारी और निर्धनता पर अंकुश लगाना अत्यन्त कठिन होगा । ग्राम्य क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास के विविध रोजगार-परक कार्यक्रमों को तत्परता से लागू किया जाना भी अनिवार्य है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरों में विद्यमान व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु कतिपय आवश्यक उपायों की चर्चा की गयी है ।

1. <u>नगरीय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण</u>

उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में आठवें दशक में 60.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सातवें दशक में यह वृद्धि 30.68 प्रतिशत रही । इस प्रकार प्रदेश में नगरीकरण की गति तीव्र है । नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कई प्रकार से हो रही है - 1. नगरों की जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि (जन्म और मृत्यु का अन्तर), 2. नवीन नगरों का अभ्युदय, और 3. ग्रामीण-नगरीय प्रवास द्वारा । नगरीय जनसंख्या वृद्धि की समस्या नवीन नगरों के अभ्युदय द्वारा नहीं है बल्कि नगरों में जन्मदर की अधिकता तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केन्द्रों की ओर जनसमूह के स्थानान्तरण के कारण है । अतः प्रदेश के नगरीय केन्द्रों विशेषरूप से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में जनसंख्या

वृद्धि पर नियंत्रण हेतु दोनों प्रकार के उपाय अपेक्षित हैं - 1. जन्मदर में कमी लाना, और 2. ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोकना ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ (1951) में उत्तर प्रदेश की 45.21 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में तथा 9.03 प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय श्रेणी के नगरों में निवास करती थी किन्तु 1981 जनगणनानुसार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या के क्रमशः 51.40 तथा 12.44 प्रतिशत प्रभाग का निवास पाया गया है । ये तथ्य प्रदेश में महानगरीकरण की प्रवृत्ति के द्योतक हैं जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तथा लघु नगरीय इकाइयों से जनसमूह का स्थानान्तरण वृहत् नगरों की ओर होता है । उल्लेखनीय है कि यदि नगरीय जनसंख्या की वर्तमान वृद्धिदर में ह्रास नहीं होता है तो इस शताब्दी के अन्त तक उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 5 करोड़ से अधिक हो जायेगी जो 1981 की तुलना में 2.5 गुना से अधिक होगी । किन्तु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार अवसरों के वृद्धि के लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं । अतः नगरीय केन्द्रों की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण समय की अनिवार्य आवश्यकता है ।

नगरों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अर्थात् जन्मदर की अधिकता पर नियंत्रण हेतु विविध प्रकार के परिवार,नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इस दिशा में जन-जागरण द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है । यद्यपि परिवार नियोजन के प्रति जनता जागरूक हो रही है और परिवार को सीमित करने का प्रयास भी करने लगी है किन्तु इसकी गति अभी अत्यन्त मन्द है । आशा है निकट भविष्य में जन्मदर में उल्लेखनीय ह्रास हो सकेगा जिससे जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि में कमी आयेगी जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, नगरों में जनसंख्या वृद्धि का प्रबल कारक ग्रामीण क्षेत्रों से जनता का नगरीय केन्द्रों की ओर स्थानान्तरण है । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, रोजगार के अभाव, मजदूरी की निम्नदर, विभिन्न नगरीय सेवाओं जैसे अस्पताल, उच्च शिक्षण संस्थाओं, मनोरंजन के साधनों आदि के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष नगरीय केन्द्रों के लिए स्थानान्तरित होते हैं जिससे विविध प्रकार की नगरीय समस्यायें विकसित होती हैं । इस प्रकार ग्रामीण स्थानान्तरण से नगरीय बेरोजगारी एवं निर्धनता में वृद्धि के साथ ही मलिनबस्तियों का अभ्युदय होता है जो नगरीय

जीवन के लिए एक अभिशाप बन जाती हैं । अतः ग्रामीण-नगरीय स्थानान्तरण को नियन्त्रित किया जाना परमावश्यक है । इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि तथा आर्थिक विकास के साथ ही वहाँ विभिन्न नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा जिससे ग्रामीण-दबाव में निश्चित ही कमी आयेगी ।

2. श्रमप्रधान नगरीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु इनका पूर्ण विकास अभी नहीं हो सका है जो प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है । देश के अन्यान्य भागों की भाँति यहाँ भी सम्पत्ति तथा कार्यावसरों का वितरण समान नहीं है जिसके कारण प्रदेश की बहुसंख्यक जनता निर्धनता के कुचक्र में फँसी हुई है । इन परिस्थितियों में लघु पूँजी के निवेश से अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजनायें आर्थिक विकास हेतु विशेष कारगर होंगी । इस दिशा में श्रमप्रधान आर्थिक क्षेत्रों के विकास हेतु यथासम्भव प्रयास किये जाने चाहिए । इससे पूँजी के विकेन्द्रीकरण और रोजगार वृद्धि - दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ हो सकेगी । प्रदेश में वृहत् पैमाने के उद्योगों के स्थानीकरण के कारकों - औद्योगिक खनिजों एवं शक्ति संसाधनों के अभाव, भारी पूँजी की कमी आदि के कारण बड़े कारखानों के विकास हेतु भौगोलिक - आर्थिक दशायें कम उपयुक्त हैं । इसके विपरीत भारी जनशक्ति के साथ ही कृषि उपजों से विविध प्रकार के कच्चे माल उपलब्ध हैं जिनका उपयोग लघु औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय रूप से किया जा सकता है । जनसंख्या की अधिकता के कारण जहाँ एक ओर सस्ता श्रम उपलब्ध है वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की विकट समस्या भी है जिसका समाधान श्रमप्रधान आर्थिक क्रियाओं के विकास द्वारा ही हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश के वृहत् नगरीय इकाइयों में लघु एवं गृह उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावनायें हैं । वाराणसी, मऊनाथ भंजन, टाण्डा, मिर्जापुर, अमरोहा, मुरादाबाद, इटावा, सम्भल, ललितपुर, अलीगढ़, जौनपुर आदि नगरों में लघु उद्योगों का उल्लेखनीय विकास हुआ है जहाँ अभी और विकास सम्भावित है । मऊनाथ भंजन की 62.78 प्रतिशत तथा टाण्डा की 39.30 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या गृह उद्योगों में कार्यरत है । इसी प्रकार 6 अन्य नगरों में यह अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक है । मऊनाथ

भंजन और टाण्डा में सूती वस्त्र उद्योग लघु उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जहाँ विविध प्रकार के सूती कपड़े हस्तकरघों तथा शक्ति करघों द्वारा तैयार किये जाते हैं। यहाँ वस्त्रों की छपाई, रंगाई, तैयारी आदि की इकाइयों को स्थापित करके रोजगार में वृद्धि की जा सकती है । इसके साथ ही सूती वस्त्रों के साथ ही सेंथिटिक वस्त्रों के लघु कारखानों में वृद्धि द्वारा स्थानीय माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार किये जा सकते हैं जिससे रोजगार तथा आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि होगी । इसी प्रकार वाराणसी में रेशमी वस्त्रों विशेषरूप से साड़ियों के निर्माण, सोने के धागे का कार्य एवं जरी के परम्परागत रोजगार में भी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा बढ़ोत्तरी की जा सकती है । वैसे तो प्रत्येक नगर में विभिन्न प्रकार की लघु औद्योगिक इकाइयाँ सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती हैं किन्तु जिन नगरों को जिस कार्य में विशिष्टता प्राप्त है वहाँ उसी प्रकार के कार्यों से सम्बद्ध औद्योगिक इकाइयों के विकास की सम्भावनायें अधिक प्रबल होती हैं क्योंकि वहाँ उक्त कार्य में कुशल श्रमिकों की सुलभता होती है जो अन्यत्र कठिनाई से प्राप्त हो पाती है । इस संदर्भ में सूती वस्त्र के लिए मऊनाथ भंजन, टाण्डा, वाराणसी, अमरोहा; दरी निर्माण के लिए मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी ; कम्बल बनाने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद ; चाकू, छुरे, कैंचियों आदि के लिए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ; काष्ठ उद्योग के लिए बरेली, देहरादून, नगीना, अमरोहा, हाथरस ; ताले के लिए अलीगढ़; चिकन (कढ़ाई आदि) के लिए लखनऊ ; पीतल व कलई के बर्तनों के लिए मुरादाबाद, शामली, हापुड़, हाथरस, मिर्जापुर ; बीड़ी व सिगरेट (तम्बाकू) के लिए आगरा, कानपुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, सहारनपुर प्रसिद्ध नगरीय केन्द्र हैं जहाँ इन उद्योगों से सम्बद्ध अन्यान्य इकाइयों के विकास की सम्भावनायें हैं जिसका मूलाधार वहाँ उपलब्ध पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति तथा परम्परागत व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं लगाव है ।

कतिपय वृहद् नगरों में स्थापित वृहद् कारखानों में प्रयुक्त सामग्रियों को पूरक एवं सहायक उद्योगों के रूप में तैयार किया जा सकता है जिनकी स्थापना स्थानीय तथा निकटवर्ती नगरों में सफलतापूर्वक की जा सकती है । इसी प्रकार वृहद् पैमाने के कारखानों में निर्मित पदार्थों के उपयोग से उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण हेतु लघु उद्योगों का विकास नगरीय केन्द्रों पर किया जा सकता है । इस प्रकार सूती वस्त्र कारखानों

के निकट सूतों की रंगाई, छपाई, तैयारी, कपड़े की सिलाई, कढ़ाई आदि से संबंधित कार्यों ; चीनी मिलों के समीप अलकोहल तथा कागज एवं गत्ता उद्योगों ; मोटर एवं साइकील उद्योगों के पास उनके छोटे उपकरण एवं पार्ट्स निर्माण के उद्योगों के विकास सुगमतापूर्वक किये जा सकते हैं ।

स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चेमाल पर आधारित विविध उद्योग जैसे पर्वतीय एवं समीपवर्ती नगरों में काष्ठ एवं फर्नीचर उद्योग; मैदानी कृषि प्रदेश में स्थानीय कृषि उपजों पर आधारित चावल, आटा, दाल, तेल, गुड़ एवं खांडसारी, टाट पट्टी एवं सुतली आदि उद्योग ; समीपवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध फलों के रसों को निकालने तथा उनके परिरक्षण उद्योग आदि लघु पूँजी से उपयुक्त नगरीय केन्द्रों पर स्थापित किये जा सकते हैं जिससे स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा नगरीय एवं प्रादेशिक अर्थव्यवस्था में सुधार । इसी प्रकार विभिन्न नगरीय केन्द्रों पर माँग - आधारित उद्योगों को गृह उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है । विविध प्रकार की सूती, रेशमी एवं ऊनी सामग्रियाँ जैसे, लुंगी, धोतियाँ, साड़ियाँ, तौलिये, चादरें, कम्बल, शाल-दुशाले ; खाद्य सामग्रियाँ जैसे बेकरी, बिस्कुट, दालमोट आदि; कृषि उपकरण; साइकिल एवं स्वचालित वाहनों के मरम्मत एवं पार्ट्स निर्माण, प्लास्टिक के खिलौने तथा दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ; जूते, चप्पल, अटैची निर्माण ; लोहे की ग्रिल आदि के निर्माण का कार्य लघु औद्योगिक इकाइयों के रूप में किया जा सकता है ।

नगरीय अर्थतंत्र के औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्षेत्रों - व्यापार, परिवहन, विविध सेवाओं आदि में भी रोजगार वृद्धि की बड़ी सम्भावनायें हैं जिसके लिए उन्हें आधुनिक ढंग से परिमार्जित करने की आवश्यकता है । परिवहन सुविधाओं के विकास से अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी विकास की गति तीव्र होगी और रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे ।

3. रोजगार-परक शिक्षा

नियोजन काल में साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । देश के अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में पाठशालायें, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है जिससे प्रादेशिक शैक्षिक स्तर में

काफी वृद्धि हुई है । जनगणना 1981 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 27.16 प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 23.06 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 45.88 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मुख्यत: सामान्य शिक्षा के प्रसार से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़ी संख्या में शिक्षित युवक तैयार हुए हैं जो केवल सफेदपोश कर्मी बन सकते हैं । किन्तु सामान्य शिक्षा प्राप्त इन समस्त युवकों के लिए उनके लिए उपयुक्त रोजगार का सर्वथा अभाव है जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वह स्वयं बेरोजगारों, समाज एवं सरकार सभी के लिए चिन्ता का विषय बन गयी है क्योंकि इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जिससे अनेक प्रकार की आर्थिक-सामाजिक समस्यायें उत्पन्न होती जा रही हैं । इसके विपरीत वर्तमान वैज्ञानिक-तकनीकी युग में आधुनिक यंत्रों के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की बड़ी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है । अत: नगरीय बेरोजगारी कम करने तथा अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रोजगार-परक व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता है जिससे आधुनिक यंत्रों के संचलनार्थ प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मियों को सुलभ कराया जा सकेगा । इसके साथ ही सामान्य शिक्षा विशेषरूप से उच्चशिक्षा को चयनित बनाने की भी आवश्यकता है । इस प्रकार शैक्षिक बेरोजगारी में ह्रास होगा तथा आर्थिक स्तर में उत्थान होगा । इसके लिए नगरों में पॉलिटेक्नीक एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं की स्थापना एवं विकास पर विशेष बल देने की आवश्यकता है । इसके साथ ही विभिन्न आधुनिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए । इस दिशा में चिकित्सा, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन आदि कार्यों में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को तैयार करके बेरोजगारी में कमी और आर्थिक स्तर में उन्नयन किया जा सकता है ।

4. व्यावसायिक गतिशीलता

आर्थिक उन्नयन हेतु नगरीय श्रमशक्ति में अन्तरा एवं अन्तर-व्यावसायिक गतिशीलता परमावश्यक है । अन्तरा-व्यावसायिक गतिशीलता के अन्तर्गत एक ही व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं कार्यानुभव के द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि तथा उनकी पदोन्नति एवं व्यावसायिक विशिष्टीकरण को सम्मिलित किया जाता है । इससे आर्थिक उत्पादन में वृद्धि तथा श्रमिकों के जीवन-स्तर में उत्थान होता है जो

नगरीय अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाता है । अन्तर-व्यावसायिक गतिशीलता से आशय श्रमिकों के एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानान्तरण से है । श्रमिकों की कार्यक्षमता के पूर्ण उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और फलत: उनके पारिश्रमिक में भी बढ़ोत्तरी सम्भावित होती है । अत: श्रमिकों को अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक वाले व्यवसायों में संलग्नता हेतु प्रयास करना चाहिए । कृषि, निर्माण कार्य आदि में संलग्न अकुशल श्रमिकों को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक प्राप्त हो पाता है जिससे उनका जीवन स्तर निम्न होता है । यदि वे सामान्य प्रशिक्षण द्वारा अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक प्रदान करने वाले कार्यों में संलग्न हो जायें तो उनकी आय एवं स्तर में वृद्धि हो सकेगी। इसके लिए श्रमिकों में उन्नत आय एवं जीवन-स्तर हेतु नवीन कार्यों को सीखने तथा अपनाने की इच्छा एवं तत्परता अनिवार्य होती है । नगरीय केन्द्रों में उपव्यवसायों द्वारा भी श्रमिकों की आय में वृद्धि हो सकती है । इससे कुछ सीमा तक बेरोजगारी भी कम हो सकती है । किन्तु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कभी-कभी उपव्यवसायों में श्रमिकों की व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि वे मुख्य व्यवसाय में अपने कार्यों एवं कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते । नगरों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है जहाँ विविध प्रकार के कार्यावसर उपलब्ध होते हैं और इन कार्यों में संलग्नता हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है । अत: अपनी कुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि करके श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीलता उत्पन्न हो सकती है जो नगरीय अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में सहायक होगी ।

5. <u>पूरक ग्रामीण विकास</u>

ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय केन्द्र परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होते हैं । नगरीय केन्द्र आत्मनिर्भर इकाई के रूप में स्थित नहीं होते बल्कि यहाँ सम्पन्न होने वाली अनेक क्रियायें ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित होती हैं । एक ओर नगरीय क्रियाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल तथा श्रम की आपूर्ति होती है और दूसरी ओर नगरीय सेवाओं तथा वस्तुओं का सम्भरण नगरीय जनों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हो है । नगरीय इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वस्तुओं के एकत्रण एवं वितरण केन्द्र के रू में कार्य करती हैं ।

उत्तर प्रदेश विशेषरूप से पूर्वी जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता तथा बेरोजगारी एवं जीवन की अन्यान्य आवश्यक सुविधाओं जैसे शिक्षा, मनोरंजन आदि के अभाव में ग्रामीण दबाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग गावों से नगरों के लिए प्रतिवर्ष स्थानान्तरित होते हैं। इससे नगरीय केन्द्रों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और अनेक नगरीय समस्यायें - बेरोजगारी, निर्धनता, मलिन बस्तियाँ आदि उत्पन्न होती हैं जिससे नगरीय जीवन-स्तर एवं जीवन पद्धति में ह्रास होता है। नगरों में जनाधिक्य के कारण आवास एवं जीविका के साथ ही अनेक प्रकार की सामाजिक - आर्थिक समस्यायें इतनी भयंकर हो जाती हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के केन्द्र समझे जाने वाले नगरों का ग्रामीणीकरण होने लगता है। अतः ग्रामीण-नगरीय स्थानान्तरण पर नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि वे सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जायें जिसकी खोज में ग्रामीण-जन नगरों की ओर पलायन करते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही शिक्षा, यातायात, मनोरंजन, विद्युत, पेयजल आदि आवश्यक सुविधाओं के प्रसार की नितान्त आवश्यकता है। कृषि प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार एवं सुधार तथा परिवहन सुविधाओं में वृद्धि और बाजार केन्द्रों के विकास द्वारा अधिक मुद्रादायिनी फसलों तथा शाक-सब्जियों के उत्पादनों, मत्स्य, कुक्कुट एवं सुअर पालन, डेरी उद्योग आदि को प्रोत्साहित एवं विकसित करके नवीन रोजगार उत्पन्न किये जा सकते हैं। नवीन वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीक का प्रयोग करके विविध उत्पादनों में वृद्धि द्वारा ग्रामीणजनों की आय एवं जीवन स्तर में उत्थान किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिए और साथ ही मनोरंजन के आधुनिक साधनों का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाना चाहिए। यही वे सार्थक तरीके हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय केन्द्रों की ओर पलायित होने वाले जन-समूह को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विक से नगरीय केन्द्रों को पर्याप्त कच्चे माल तथा कुशल श्रम की प्राप्ति होगी और साथ ही ग्रामीण जीवन स्तर में वृद्धि से नगरों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत में वृ होगी जिससे नगरीय अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं सम्पन्न हो सकेगी।

6. सामाजिक प्रावरोधों का समापन

भारत के अन्य अनेक भागों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी व्यवसायों के निर्धारण में जाति एवं धर्म की निर्णायक भूमिका होती है । व्यक्ति के व्यावसायिक चयन में जाति एक प्रभावशाली कारक है । यद्यपि नगरीय केन्द्रों में जाति प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम प्रभावी होती है किन्तु यहाँ भी इसका प्रभाव जनसंख्या के जन्म, मृत्यु एवं स्थानान्तरण के साथ ही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रियाओं पर भी होता है । व्यवसायों के चयन में जातीय अवरोध अभी भी काफी शक्तिशाली हैं । सवर्ण जातियों से सम्बद्ध सदस्य प्राय: उन कार्यों को नहीं कर सकते जिन्हें सामाजिक दृष्टि से निम्न तथा पिछड़ी जातियों के लिए समझा जाता है । इसी प्रकार अधिकांश घरेलू कार्य महिलाओं के लिए सुनिश्चित होते हैं जैसे भोजन पकाना, बच्चों का लालन-पालन एवं परिवार के अन्य सदस्यों की देख-रेख, सफाई आदि । विविध कार्यालयों एवं सेवाओं में कार्यरत महिला कर्मियों को समाज में यथोचित स्थान नहीं प्राप्त होता और उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है । बालिकों की शिक्षा पर बालकों की भाँति ध्यान नहीं दिया जाता और व्यावसायिक शिक्षा तो सामान्यतया बालकों के लिए ही मानी जाती है । इससे आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त कम है । इसी प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक अवरोध व्यक्ति के व्यवसाय-चयन के सम्मुख आते हैं जो बेरोजगारी में वृद्धि तथा आर्थिक ढाँचे को कमजोर बनाते हैं ।

अत: उत्तर प्रदेश के नगरीय केन्द्रों के आर्थिक विकास तथा व्यवसाय सम्बन्धी अनेक समस्यायों के निराकरण हेतु व्यावसायिक चयन में इस प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं एवं परम्पराओं को जिस भी प्रकार हो सके समाप्त करने की नितान्त आवश्यकता है । आशा है शिक्षा के प्रसार तथा औद्योगीकरण में वृद्धि के फलस्वरूप निकट भविष्य में इन सामाजिक प्रावरोधों में क्रमिक ह्रास हो सकेगा जिससे सामाजिक - आर्थिक विकास को नवीन गति एवं दिशा प्राप्त होगी ।

संदर्भ

1. Maurya, S.D. : Urban Environment Management - A Functional Study, Chugh Publications, Allahabad, 1988, p. 356.

2. उत्तर प्रदेश में विकास का नया दौर - योजनागत विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ 4.

3. वही, पृष्ठ 4-5.

4. मौर्य, साहबदीन : "भारतीय नारी-स्वतंत्र अस्मिता में बाधाएँ", प्रतियोगिता पीयूष, मासिक पत्रिका, फरवरी 1988, इलाहाबाद, पृष्ठ 75.

5. वही

6. Narayan, P.L. : "Role of Industries in the Sixth Plan", Margin, Vol.11, No. 1, 1978, pp. 69-70.

-------::0::-------
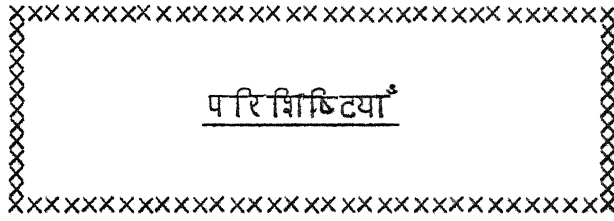
परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1

शब्दावली

अकर्मी/गैर श्रमिक	:	Non-workers
अनर्जक	:	Non-earner
अर्जक	:	Earner
अन्य कर्मी/अन्य श्रमिक	:	Other worker
अवरोही क्रम	:	Descending order
आरोही क्रम	:	Ascending order
आश्रित/निर्भर	:	Dependent
कर्मी/श्रमिक	:	Worker
कार्यशील/क्रियाशील जनसंख्या	:	Working population
कार्यात्मक/क्रियात्मक	:	Functional
कार्यात्मक पदानुक्रम	:	Functional hierarchy
कार्यात्मक वर्ग	:	Functional group
कार्यात्मक विशिष्टीकरण	:	Functional specialisation
कार्यात्मक श्रेणियाँ	:	Functional categories
कुटीर उद्योग	:	Cottage industry
केन्द्रीयता सूचकांक	:	Centrality index
कृषक/कास्तकार	:	Cultivator
कृषि	:	Agriculture
कृषि श्रमिक/खेतिहर मजदूर	:	Agricultural labourer
क्रिया-वर्ग	:	Activity group
गुणात्मक	:	Qualitative
गृह उद्योग/पारिवारिक उद्योग	:	Household industry
जनसंख्या	:	Population
जनांकिकीय	:	Demographic
नगर	:	Town/city
नगरीकरण	:	Urbanisation
नगरीकरण का स्तर	:	Level of urbanisation
नगरीय अधिवास	:	Urban settlement
नगरीय केन्द्र	:	Urban centre
नगरीय घनत्व	:	Urban density
नगरीय समूह	:	Urban Agglomeration
नगरीय श्रेणी/वर्ग	:	Urban class/Group
निर्माण कार्य	:	Construction
पर्यावरण	:	Environment

परिमाणात्मक/मात्रात्मक	:	Quantitative
पुरुष	:	Male
प्राथमिक क्रिया	:	Primary activity
भण्डारण/संग्रह	:	Storage
महिला/स्त्री	:	Female/Women
माध्य/औसत	:	Mean/Average
मानक/प्रमाप विचलन	:	Standard deviation
मुख्य कर्मी/श्रमिक	:	Main worker
लिंगानुपात	:	Sex-ratio
व्यक्ति	:	Person
व्यवसाय	:	Occupation
व्यावसायिक श्रेणी/वर्ग	:	Occupational category/group
व्यावसायिक संरचना	:	Occupational structure
विनिर्माण	:	Manufacturing
विशिष्टीकरण/विशिष्टीकृत	:	Specialisation/specialised
विविध क्रियायें	:	Multi-activities
वैयक्तिक पर्यावरण	:	Personal environment
सहचर	:	Correlates
सहसम्बन्ध	:	Correlation
सहसम्बन्ध गुणांक	:	Co-efficient of Correlation
समाश्रयण समीकरण	:	Regression equation
समाश्रयण रेखा	:	Regression line
सामान्य	:	Ordinary/Normal
साक्षरता	:	Literacy
सीमान्त कर्मी/श्रमिक	:	Marginal worker
श्रम-विभाजन	:	Division of labour
श्रम-शक्ति	:	Labour fource

---::o::---

परिशिष्ट-2 (अ)

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में कुल जनसंख्या, मुख्य कर्मी, सीमान्त कर्मी और अकर्मी (1981)

क्र0 सं0	नगरों के नाम	कुल जनसंख्या			मुख्य कर्मी		सीमान्त कर्मी		अकर्मी	
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कानपुर	1639064	908707	730357	432733	17855	628	138	475346	712364
2.	लखनऊ	1007604	550106	457498	262250	17045	1472	180	286384	440273
3.	वाराणसी	797162	432848	364314	199179	11111	398	505	233271	352698
4.	आगरा	747318	402353	344965	192214	6459	268	169	209871	338337
5.	इलाहाबाद	650070	358943	291127	157141	9518	321	156	201481	281453
6.	मेरठ	536615	290370	246245	144500	7155	281	103	145589	238987
7.	बरेली	449425	242405	207020	115001	4935	348	210	127056	201875
8.	मुरादाबाद	345350	185855	159495	92754	2447	82	56	93019	156992
9.	अलीगढ़	320861	171829	149032	77237	3038	48	232	94544	145762
10.	गोरखपुर	307501	167845	139656	70111	3963	197	153	97537	135540
11.	सहारनपुर	295355	158752	136603	77118	2880	84	50	81550	133673
12.	देहरादून	293010	162560	130450	82346	6369	628	268	79586	123813
13.	गाजियाबाद	287170	160382	126788	82040	4187	27	26	78315	122575
14.	झाँसी	284141	150079	134062	63546	7609	661	1269	85872	125184
15.	शाहजहाँपुर	205095	110108	94987	52534	1706	208	145	57466	93136
16.	रामपुर	204610	108024	96586	55308	2295	177	116	52539	94175
17.	फिरोजाबाद	202338	109569	92769	53120	1952	31	14	56418	90803
18.	मुजफ्फरनगर	171816	91656	80160	42355	1576	58	19	49243	78565
19.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	160796	88288	72508	45491	1748	16	48	42781	70712
20.	मथुरा	159498	86449	73049	42412	1871	53	85	43984	71093
21.	हरद्वार	145946	80302	65644	37945	1685	26	27	42331	63932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	फैजाबाद	143167	80952	62215	38662	2625	147	364	42143	59226
23.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	127787	68879	58908	33238	1804	247	66	35394	57038
24.	अमरोहा	112682	59589	53093	27652	1921	33	267	31904	50905
25.	इटावा	112174	59798	52376	26707	2067	24	28	33067	50281
26.	सम्भल	108232	57816	50416	23839	617	23	25	29954	49774
27.	जौनपुर	105140	56077	49063	24266	1941	88	222	31723	46900
28.	बुलन्दशहर	103436	55346	48090	24671	1128	36	83	30639	46879
29.	हापुड़	102837	55068	47769	25386	1199	1	13	29681	46557
30.	सीतापुर	101210	55574	45636	27649	1480	10	9	27915	44147
31.	बहराइच	99889	53020	46869	24499	931	9	12	28512	45926
32.	बदायूँ	93004	49882	43122	23243	963	26	52	26613	42107
33.	हाथरस	92962	50385	42567	23317	843	12	7	27066	41717
34.	रायबरेली	89697	49392	40305	24157	1467	48	424	25187	38414
35.	पीलीभीत	88548	47608	40940	22999	1005	41	1	24568	39934
36.	मोदीनगर	87655	48427	39238	24016	915	3	3	24408	33320
37.	मऊनाथभंजन	86326	45368	40958	20497	6716	186	2066	24685	32176
38.	फतेहपुर	84831	45393	39438	20520	1334	109	259	24764	37845
39.	रुड़की	79076	47528	31548	26409	950	24	21	21095	30577
40.	हल्द्वानी-काठगोदाम	77300	42472	34828	20891	988	276	94	21305	33746
41.	उन्नाव	75983	40965	35018	19189	870	104	142	21672	34006
42.	बाँदा	72379	39663	32716	17508	922	233	300	21922	31494
43.	गोण्डा	70847	38798	32049	17841	724	21	-	20936	31325
44.	बस्ती	69465	38034	31431	17027	1235	87	116	20920	30080
45.	मुगलसराय	69224	37971	31253	16680	5580	8	5	21283	30667
46.	हरदोई	67259	36763	30496	16986	823	7	32	19770	29641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	खुर्जा	67119	35698	31421	16740	720	3	43	18955	30658
48.	चन्दौसी	66970	35901	31069	16658	561	24	11	19219	30497
49.	आजमगढ़	66523	36024	30499	14850	1096	123	236	21051	29167
50.	उरई	66397	36539	29858	15315	565	41	51	21183	29242
51.	बाराबंकी	62216	34188	28028	16645	707	–	4	17543	27317
52.	बलिया	61704	33396	28308	13356	772	176	82	19864	27454
53.	कासगंज	61402	32812	28590	14811	601	12	81	17989	27908
54.	लखीमपुर	61003	32694	28309	15019	662	9	5	17666	27642
55.	गाजीपुर	60725	32420	28305	13292	976	109	110	19019	27219
56.	मैनपुरी	58928	31635	27293	14075	528	18	20	17542	26745
57.	बिजनौर	56713	30276	26437	13778	779	75	29	16423	25629
58.	ललितपुर	55756	29653	26103	13590	1397	41	163	16022	24543
59.	देवरिया	55720	30406	25314	12858	723	56	65	17492	24526
60.	नजीबाबाद	55109	29098	26011	13806	590	154	164	15138	25257
61.	टाण्डा	54474	28743	25731	13714	2125	132	858	14897	22748
62.	एटा	53784	28679	25105	12527	307	1	56	16151	24537
63.	शामली	51850	28259	23591	13652	424	–	5	14607	23162
64.	काशीपुर	51773	27854	23919	13193	558	57	52	14605	23309
65.	देवबन्द	51270	28214	23056	13244	326	8	86	14962	22644
66.	नगीना	50405	26827	23578	13031	492	64	795	13732	22291

स्रोत : Census of India 1981 : Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.

परिशिष्ट-2 (ब)

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के नगरों में मुख्य कर्मियों का वृहत् कार्यात्मक-वर्गों में वितरण (1981)

क्र० सं०	नगरों के नाम	कृषक		कृषि श्रमिक		गृह उद्योग		अन्य कर्मी	
		पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ	पुरुष	स्त्रियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कानपुर	7916	350	5375	718	15630	712	403812	16075
2.	लखनऊ	2427	68	3788	189	13987	712	242048	16076
3.	वाराणसी	3825	137	2486	285	43833	3073	149035	7616
4.	आगरा	1420	24	1803	42	14119	402	174872	5901
5.	इलाहाबाद	2704	157	3254	495	6727	786	144456	8080
6.	मेरठ	2585	73	3307	379	13300	836	125308	5867
7.	बरेली	2252	65	1142	13	5974	454	105633	4403
8.	मुरादाबाद	2177	29	803	15	7220	158	82554	2245
9.	अलीगढ़	1763	41	1208	61	7639	258	66627	2675
10.	गोरखपुर	2157	83	1851	104	5514	317	60589	3259
11.	सहारनपुर	1026	34	675	17	3886	180	71531	2649
12.	देहरादून	825	73	1067	105	1108	214	79346	5977
13.	गाजियाबाद	1789	68	1542	80	2200	165	76509	3874
14.	झाँसी	1608	294	698	159	3692	1801	57548	5355
15.	शाहजहाँपुर	2807	43	2870	52	3309	234	43448	1377
16.	रामपुर	2527	29	679	12	3914	546	48188	1708
17.	फिरोजाबाद	264	7	174	3	1857	235	50825	1707
18.	मुजफ्फरनगर	1108	17	698	29	1637	120	38912	1410
19.	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	2495	45	2370	46	3002	386	37624	1271
20.	मथुरा	416	12	231	44	1602	117	40163	1698
21.	हरद्वार	456	4	1825	45	1047	70	34617	1566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	फैजाबाद	2306	161	2084	302	2100	156	32172	2006
23.	मिर्जापुर-विन्ध्याचल	745	63	1003	313	6101	327	25389	1101
24.	अमरोहा	1780	32	875	54	3938	945	21059	890
25.	इटावा	747	13	466	2	2946	1162	22548	890
26.	सम्भल	5098	40	4754	107	3087	90	14900	380
27.	जौनपुर	2133	156	1107	171	2318	299	18708	1315
28.	बुलन्दशहर	963	10	583	16	1156	131	21969	971
29.	हापुड़	1004	7	1383	263	968	145	22031	784
30.	सीतापुर	948	9	429	14	1161	149	25111	1308
31.	बहराइच	2791	110	1730	52	969	74	19009	695
32.	बदायूँ	2035	21	779	30	630	79	19799	833
33.	हाथरस	338	2	247	2	1489	173	21243	666
34.	रायबरेली	2165	132	1640	163	1034	75	19318	1097
35.	पीलीभीत	1152	25	325	6	563	96	20959	878
36.	मोदीनगर	387	5	56	6	997	30	22576	874
37.	मऊनाथभंजन	623	64	353	62	11027	6058	8494	532
38.	फतेहपुर	3712	232	1434	341	1041	59	14333	702
39.	रुड़की	292	4	116	3	350	36	25651	907
40.	हल्द्वानी-काठगोदाम	289	40	158	13	463	37	19981	898
41.	उन्नाव	2418	23	1983	53	797	49	13991	745
42.	बाँदा	1589	28	838	30	1092	137	13989	727
43.	गोण्डा	926	17	628	55	365	33	15922	619
44.	बस्ती	958	38	1210	209	669	36	14190	952
45.	मुगलसराय	1050	24	1069	124	552	28	14009	404
46.	हरदोई	1019	38	632	21	620	21	14715	743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	खुर्जा	976	32	652	68	819	49	14293	571
48.	चन्दौसी	1114	30	250	16	684	51	14610	464
49.	आजमगढ़	675	86	263	22	1061	98	12851	890
50.	उरई	1309	22	631	39	356	26	13019	478
51.	बाराबंकी	951	8	544	10	1356	174	13794	515
52.	बलिया	815	62	536	123	703	52	11302	535
53.	कासगंज	787	14	684	14	881	129	12459	444
54.	लखीमपुर	498	9	244	17	778	19	13499	617
55.	गाजीपुर	819	120	342	25	1139	137	10992	694
56.	मैनपुरी	956	5	398	3	661	44	12060	[illegible]76
57.	बिजनौर	956	17	663	23	459	67	11700	672
58.	ललितपुर	1670	142	427	90	1483	366	10010	799
59.	देवरिया	733	23	385	78	532	27	11208	595
60.	नजीबाबाद	543	8	566	4	1024	157	11673	421
61.	टाण्डा	409	21	409	63	4956	1268	7940	773
62.	एटा	306	1	136	–	190	17	11895	494
63.	शामली	554	11	852	35	420	22	11826	356
64.	काशीपुर	831	9	425	11	391	166	11545	372
65.	देवबन्द	1473	16	820	19	620	38	10331	253
66.	नगीना	1239	20	1048	5	507	133	10237	334

स्रोत : Census of India 1981 : Uttar Pradesh, Part II-B, Primary Census Abstract.

परिशिष्ट 3
FURTHER READINGS

A. BOOKS

Agrawal, A. and Narayan, S. : The State of India's Environment 1984-85, Second Citizens Report, Centre for Science and Environment, New Delhi, 1985.

Ambedkar, B.R. : The Untouchables, Amrit Book Co., Delhi, 1948.

Asthana, B.N. and Srivastava, S.S. : Applied Statistics of India, Chaitanya Publishing House, Allahabad, 1972.

Bansal, S.C. : Town-Country Relationship in Saharanpur City Region- A Study in Rural-Urban Interdependence Problems, Sanjeev Prakashan, Saharanpur, 1975.

Basham, A.L. : The Wonder that was India, Sidgwick and Jackson, London, 1967.

Bhopegamage, A. : Delhi - A Study in Urban Sociology, University of Bombay, 1957.

Bose, A. : Urbanization in India - An Inventory of Source Materials, Academic Books, Ltd., New Delhi, 1970.

Brigs, G.W. : The Chamars, Associated Press, Calcutta, 1920.

Carter, H. : The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London, 1975.

Chandna, R.C. and Sidhu, N.S. : Introduction to Population Geography Kalyani Publishers, New Delhi, 1980.

Davis, K. : Population of India and Pakistan, Princeton University, Princeton, 1951.

Desai, A.R. : Introduction to Rural Sociology, Bombay, 1959.

Desai, A.R. and Pillai, S.D. (eds) : Slums and Urbanization, Popu-

Dore, R.P. : City Life in Japan, Routedge and Kegan Paul, London, 1958.

De Souza, V.S. : Social Structure of a Planned City Chandigarh, Orient Longman, New Delhi, 1968.

Eyles, J. : Social Theory and Social Geography, OUP, London, 1977.

Fox, R.G. : From Zamindar to Ballot Box - Community Change in North Indian Market Town, Cornell University Press, Dhaca, 1969.

Garnier, J.B. and Chabot, G. : Urban Geography, Longmans, Green & Co. Ltd., London, 1967.

Geddes, P. : Cities in Evolution, Williams Norgate, London, 1949.

Ghosh, S.K. : Muslim Politics in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1987.

Ghurye, G.S. : Cities and Civilization, Popular Prakashan, Bombay, 1962.

Gibbs, J.P. (ed.) : Urban Research Method, D. Van Nostrand Co., New York, 1961.

Gist, N.P. and Halbert, L.A. : Urban Society, Thomas Y. Crowell Company, New York, 1965.

Gupta, Sumitra : Social Welfare in India, Chugh Publications, Allahabad, 1988.

Hagget, P. : Locational Analysis in Human Geography, Edward, London, 1977.

Hauser, P.M. and Schnore, L.F. (eds.) : The Study of Urbanization, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1965.

Jain, Devaki (ed.) : Indian Women, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, 1975.

Johnson, J.H. : Urban Geography, Pergamon Press, Oxford, 1981.

Kay, G. : A Social and Economic Study of Fort Rosebery, Lusaka, 1960

Lowry, J.H. : World City Growth, Edward Arnold, London, 1977.

Madan, T.N. and Saran G. (eds.) : Indian Anthropology, Asia Publishing House, Bombay, 1962.

Mahalingam, T.V. : South Indian Polity, University of Madras, Madras, 1975.

Majumdar, R.C. : Corporate Life in Ancient India, Calcutta, 1922.

Mandal R.B. and Sinha, V.N.S. (eds.) : Recent Trends and Concepts in Geography, Vol. 3, Concept Publishing Company, New Delhi, 1980.

Mathew, P.M. : Women's Organization and Women's Interests, Ashish Publishing House, New Delhi, 1986.

Maurya, S.D. (ed.) : Women in India, Chugh Publications, Allahabad 1988.

—— (ed.) : Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publication, Allahabad, 1989.

—— (ed.) : Population and Housing Problems in India (2 vols.), Chugh Publications, Allahabad, 1989.

Maurya S.D. and Gayatri Devi : Social Environment of India, Chugh Publications, Allahabad, 1989.

Meadows, P. and Mizxuchi, E.H. (ed.) : Urbanism, Urbanization and Change - Comparative Perspectives, Addison Wesley Publishing Company, U.S.A.

Mehta, A.B. : The Domestic Servant Class, Popular Book Depot, Bombay, 1960.

Morris, R.N. : Urban Sociology, Allen and Unwin, London, 1968.

Pahl, R.E. (ed.) : Readings in Urban Sociology, Pergamon Press, Oxford, 1968.

—— Pattern of Urban Life, Longmans, London, 1970.

Pati, R.N. : Population, Family and Culture, Ashish Publishing House, New Delhi, 1987.

Puri, B.N. : Cities of Ancient India, Meenakshi Prakashan, Meerut, 1966.

Ramamani, V.S. : Tribal Economy - Problems and Prospect, Chugh Publications, Allahabad, 1988.

Rao, M.S.A. (ed.) : Urbanization and Social Change, Orient Longman, New Delhi, 1970.

Rayappa, H. : Backwardness and Welfare of Scheduled Castes and Tribes in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1966.

Shafi, M. : Land Utilization in Eastern Uttar Pradesh, Aligarh Muslim University, Aligarh, 1962.

Shah, A.M. : Society in India, Social Sciences Association, Madras 1956.

सिंह, ओम प्रकाश : नगरीय भूगोल, तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, 1979.

Singh, H.H. : Kanpur - A Study in Urban Geography, Varanasi, 1972.

Singh, Pramod (ed.) : Ecology of Urban India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1987.

—— (ed.) : Urban Environmental Conservation, Ashish Publishing House, New Delhi, 1990.

Singh, R.L. : Banaras - A Study in Urban Geography, Nand Kishore and Brothers, Varanasi, 1955.

Singh, U. : Allahabad - A Study in Urban Geography, B.H.U., Varanasi, 1966.

Sovani, N.V. : Urbanization and Urban India, Asia Publishing House Bombay, 1965.

Srivastava, S.K. : Social Class and Family Life in India, Chugh Publications, Allahabad, 1985.

Stacy, M. : Tradition and Change - A Study of Bombay, Oxford University Press, Oxford, 1960.

Thomas, P. : Indian Women Through the Ages, Asia Publishing House, New Delhi, 1964.

UNESCO : Handbook for Social Research in Urban Areas, Paris, 1964.

Verma, S.S. : Urbanization and Regional Development in India, Chug Publications, Allahabad, 1989.

B. ARTICLES

Alexander, J.W. : "Location of Manufacturing - Methods of Measurement", A.A.A.G., Vol. 48, 1958, pp. 26-20.

Alexander, J.W. and Lindberg, J.B. : "The Measurement of Manufacturing - Co-efficient of Correlation", Jl. Regl. Sc., Vol.3, No. 1, 1961, pp. 71-81.

Axelrod, M. : "Urban Structure and Social Participation", American Social Review, Vol. 21, 1956, pp. 13-18.

Adyanathya, N.K. : "Women's Employment in India", International Review, July, 1954.

Basu, T.K. : "Functional Classification of Urban Settlements in Singhbhum District, Bihar - A Geographic Appraisal", Geographical Review of India, Vol. 37, No. 2, 1975, pp. 165-168.

Berry, B.J.L. : "Functional Ecology of Calcutta", American Journal of Sociology, 1969.

Bhatt, G.S. : "The Chamars of Lucknow", Eastern Anthropologists, Vol.8, Sept-Nov., 1954, pp. 27-41.

Bose, A. : "Urban Characteristics of Towns in India - A Statistical Study", Indian Journal of Public Administration, Vol. 14, No.3, 1968.

Bhattacharya, B. : "Factors Determining the Central Functions and Urban Hierarchy in North Bengal", Geog. Review of India, Vol. 14, No.4, 1972, pp. 327-38.

Browning, H.L. and Gibbs, J.P. : "Some Measures of Demographic and Spatial Relationship among Cities", Urban Research Methods, New Delhi, 1966, pp. 450-59.

Brush, J.E. : "The Hierarchy of Central Places in South-Western Wisconsin", Geographical Review, Vol. 43, 1953, pp. 380-402.

Carol, H. : "The Hierarchy of Central Functions within the City, A.A.A.G., Vol. 50, 1960, pp. 419-438.

Chakraborty, S.C. : "On Identifying a Multi-functional Mix", Geog. Review of India, Vol. 32, No. 1, 1970, pp. 1-13.

Chapin, F.S. (Jr.) : "Activity Systems and Urban Structure - A Working Scheme", Jl. of Inst. of American Planners, Vol. 34, 1968, pp. 11-18.

Chatterjee, A. : "Changes in the Sturcture of Labour Force and Income in India during 1961-71", Indian Journal of Regional Science, Vol. 3, No. 1, 1975, pp. 69-86.

Chatterjee, A.B. and Roy, P.N. : "A Spatial Analysis of the Changing Livelihood Strudture Around Calcutta", National Geographical Journal of India, Vol. 19, No. 2, 1973, pp. 92-97.

Chaturvedi, R.P. : "Trends of Urbanization in Bundelkhand Region", National Geographer, Vol. 20, No. 2, 1985, pp. 129-140.

——— : Socio-Economic Status of Women in Bundelkhand Region", in Maurya, S.D. (ed.) : Women in India, Chugh Publications, Allahabad, 1988, pp. 139-155.

Chaudhury, A.R. : "Caste Occupation in Bowanipur, Calcutta", Man in India, Vol. 44, No. 3, 1964, pp. 207-220.

Davies, W.K.D. : "The Ranking of Service Centres - A Critical Review", Trans. Inst. Brit. Geogr., Vol. 40, 1966, pp. 51-65

Davis, K. : "The Origin and Growth of Urbanization in the World", American Journal of Sociology, Vol. 60, 1955.

Devi, Gayatri : Growth and Structure of Population in Eastern Uttar Pradesh", in Maurya S.D. (ed.) : Population and Housing Problems in India, Vol. 2, Chugh Publications, Allahaba 1989, pp. 30-49.

———: "Tribals of India", in Maurya, S.D. (ed.) : Population and Housing Problems in India, Vol 1 Op.cit., pp. 254-268.

Devi, Gayatri and Maurya, R.S. : "Place of Household Industry in Occupational Structure of Cities of Uttar Pradesh", in Maurya, S.D. (ed.) : Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad, 1989, pp. 118-136.

De Souza, V.S. : "Caste Occupation and Social Class in Chandigarh", in Rao, M.S.A. (ed.) : Urban Sociologyof India, Orient Longman Ltd. New Delhi, 1974.

Eckler, A.R. : "Occupational Changes in U.S.A. (1850-1920)",Review Economics and Statistics, Vol. 12, 1930, pp.77-87.

Galater, M. : "Law and Caste in Modern India", Asian Survey, Vol.3, No.2, 1963.

Garrison, W.L. and Marble, D.F.: "The Spatial Structure of Agricultural Activities", A.A.A.G., Vol. 47, 1957.

Giri, D.: "Trends in the World's Agricultural Population", Geography, Vol. 56, No. 4, 1971, pp. 320-24.

Ghosal, K. : "Market Places and Market Areas", National Geographer, Vol. 7, 1972, pp. 85-94.

Gupta, A. : "Silk Industry of Varanasi" Indian Geographical Journal, Vol. 46, No. 1 & 2, 1971, pp. 25-34.

Herbert, J. and Stevens, B. : "A Model for the Distribution of Residential Activities in Urban Areas", Journal of Regional Science, Vol. 2, 1960, pp. 21-36.

Hullur, S.I. : "Some Aspects of the Distribution of People engaged in Transport and Communication in Mysore State", Deccan Geographer, Vol.11, No. 1 & 2, 1973, pp. 18-27.

Jain, N.G. : "Urban Hierarchy and Telephone Service in Vidarbha (Maharashtra)", N.G.J.I., Vol. 17, Nos. 2 & 3, 1971, pp. 134-137.

Kumar, A. and Sharma, N. : "Spatial Arrangement and Degree of Specialization of Urban Centres", Geog. of India, Vol. 36, No. 2, 1974, pp. 120-128.

Lal, R. : "The Impact of Industrialization in Lower Ghaghra - Gandak Doab", Deccan Geographer, Vol. 12, No.1, 1974, pp. 105-124.

Mathur, V.K. : "Occupational Composition and its Determinants", Journal of Regional Science, Vol. 10, No.2, 1970, pp. 25-33.

Maurya, R.D. : "Role of Women in Agriculture of Uttar Pradesh", in Maurya S.D. (ed.) : Women in India, Chugh Publications, Allahabad, 1988, pp. 189-203.

Maurya, R.S. : "Women Education in India", in Maurya, S.D. (ed.), Women in India, Op.cit., pp. 61-73.

Maurya, S.D. : "Characteristics of Indian Urbanization", in idem (ed.) : Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad, 1989, pp. 1-22.

———: "Urban Economic Base - Concept and Application", in idem (ed.) : Urbanization and Environmental Problems, Op.cit., pp. 70-95.

Maurya S.D. and Devi, Gayatri : "Trends of Urbanization in Uttar Pradesh", National Geographer, Vol. 19, No.1, 1984, pp. 37-47.

मौर्य, साहबदीन एवं देवी, गायत्री : "उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना/, भू-संगम, अंक 2, संख्या 1, दिसम्बर 1984, पृष्ठ 57-64.

Mayer, H.M. : "Making a Living in Cities - The Urban Economic Base", Journal of Geography, Vol. 68, 1969, pp. 70-87.

Mukerjee, A.B. : "Levels of Urbanization in Uttar Pradesh", Geog. Review of India, Vol. 35, No. 1, 1973, pp. 31-42.

———: "Female Participation in Agricultural Labour in Uttar Pradesh - Spatial Variations, 1961", National Geographer, Vol. 6, 1971, pp. 13-18.

Mukherjee, M. (Mrs.) : "Agricultural Towns of Bihar", Geographical Review of India, Vol. 31, No. 3, 1969, pp. 65-66.

——— : "Trade Towns of Bihar", Geographical Knowledge, Vol. 3, No. 1 & 2, 1970, pp. 1-14.

——— : "Household Industry Towns of Bihar", Geographer, Vol.17, 1970, pp. 41-51.

——— : "Transport Towns of Bihar", Indian Geographical Journal, Vol. 64, Nos. 3 & 4, 1969, pp. 42-51.

Munsi, S.K. : "The Nature of Indian Urbanization - A Review", Geog. Review of India, Vol. 37, No.4, 1975, pp. 287-299.

Nelson, H.J. : "Some Characteristics of the Population of Cities in Similar Service Classifications", Economic Geography, Vol. 33, 1957, pp. 95-108.

Pathak, C.R. : "Spatial Variation in Urban and Industrial Growth in India", Indian Journal of Regional Science, Vol. 7, No.1, 1975, pp. 1-10.

Patil, S.R. : "Occupational Pattern of Urban Settlements in Mysore State", Geographer, Vol. 20, No.2, 1973, pp.98-115.

Preston, R.E. : "The Structure of Central Place Systems", Economic Geography, Vol. 47, No. 2, 1971, pp. 136-155.

Premi, M.K. : "Student Workers in the Age-Group 5-14 : A Socio-Demographic Analysis", Manpower Journal, Vol. 8, No. 4, 1973, pp. 68-84.

Rajpurohit, A.R. : "Classification of Indian Cities by Occupation Pattern", Arth Vijyana, Vol. 15, No. 1, 1973, pp. 101-103.

Reddy, N.B.K. : "Occupational Pattern in the Urban Settlements in the Krishna-Godavari Deltas", Bombay Geographical Magazine, Vol. 18, No. 1, 1969, pp. 7-26.

Saxena, N.P. : "Occupational Structure, Population Size and Central Place Considerations Regarding Urban Centres in India, Geographical Observer, Vol.3, 1967.

Sen Gupta, J.K. : "Agriculture and Industry in a Less Developed Economy", in T. Barna (ed.) : Structural Inter-dependence and Economic Development, London, 1963, pp. 67-102.

Sharma, K.N. : "Occupational Mobility of Caste in a North Indian Village", South-Western Journal of Anthropology, Vol.17, 1961, pp. 146-164.

Sharma, K.D. : "Female Participation in Rural Agricultural Labour in North India",Manpower Journal,Vol.8,No.4,1973,pp.52-57.

Singh, H.D. : "Dynamics of Population Dependency in Eastern U.P.", National Geographer, Vol. 16, No. 2, pp. 127-136.

——— : "Occupation - A Conceptual Framework", in Maurya, S.D.(ed.): Population and Housing Problems in India, Vol. 1, Chugh Publications, Allahabad, 1989, pp. 106-128.

——— : "Determinants of Occupation - A Case Study of Eastern Uttar Pradesh", in Maurya, S.D. (ed.) : Population and Housing Problems in India, Op.cit., pp. 129-160.

Singh, J. and Rai, J.P. : "Role of Transportation in Spatial Organization of Economy in Developing Countries", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 10, 1974.

——— : "Impact of Sugar Industry on the Space Economy of U.P.", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 11, No. 1, 1975, pp.1-11.

Singh, J.P. : "The GADIS Towns of North-East India - A Study in Population Growth and Occupational Structure", N.G.J.I., Vol. 15, Nos. 3 & 4, 1969, pp. 235-241.

Singh, K.N. : "Changes in the Functional Structure of Some Small Towns in Eastern Uttar Pradesh", Indian Geog., Vol. 6,1961, pp. 21-40.

Singh, Onkar : "The Trends of Urbanization in Uttar Pradesh", N.G. J.I., Vol. 13, 1967, pp. 141-157.

Singh, O.P. "Towards Determining the Hierarchy of Service Centres- A Methodology for Central Place Studies", N.G.J.I., Vol.17, No. 4, 1971, pp. 165-177.

——— : "Functional Morphology of Service Centres in Uttar Pradesh", Deccan Geographer, Vol. 12, No. 1, 1974, pp. 38-47.

——— : "Some Basic Principles for Functional Classification of Towns - A Critical Review", N.G.J.I., Vol. 23, Nos. 3 & 4, 1977, pp. 195-199.

Singh, R.L. : "Gorakhpur - A Study in Urban Morphology", N.G.J.I., Vol. 1, 1955, pp. 1-10.

———: "Ballia - A Study in Urban Settlement", N.G.J.I., Vol. 2, 1956, pp. 1-6.

——— : "Mirzapur - A Study in Urban Geography", Geographical Outlook, Vol. 1, 1956.

——— : "Faizabad-cum-Ayodhya", N.G.J.I., Vol. 4, 1958, pp. 1-6.

Singh, R.N. and Sahab Deen : "Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U.P. - A Case Study of Trade and Commerce", Indian Geographical Journal, Vol. 56, No. 2, 1981, pp. 55-62.

——— : "Primary Activities in the Urban Centres of Eastern U.P.", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 17, No. 1, 1981, pp.42-51.

——— : "Transport and Communication in the Occupational Structure of Urban Centres in Eastern U.P.", Geographical Review of India, Vol. 44, No. 3, 1982, pp. 69-80.

——— : "Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U.P. - A Case Study of Manufacturing", The Deccan Geographer, Vol. 20, No. 1, 1982, pp. 183-197.

——— : "Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U.P. - A Case Study of Services", University of Allahabad Studies, Vol. 13, Nos. 1-6, 1981, pp. 37-52.

——— : "Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U.P. - A Case Study of Construction", University of Allahabad Studies, Vol. 14, Nos. 1-6, 1982, pp. 27-41.

Singh, R.N. and Maurya, S.D. : "Functional Classification of Towns- A Case Study of Eastern Uttar Pradesh", in Maurya, S.D. (ed.) Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad, 1989, pp. 137-175.

Singh, R.B. : "Industrial Classification and the 'Export Base' - A Functional Relationship and an Explanation", N.G.J.I., Vol. 15, Nos. 3 & 4, 1969, pp. 167-168.

Singh, U. : "Banaras", Indian Geographical Journal, Vol. 36, 1952, pp. 26-33.

——— : "Demographic Structure of Allahabad", N.G.J.I., Vol. 4, 1958, pp. 163-188.

——— : "KAVAL Towns - Functional Aspects of Urban Centres in Uttar Pradesh", N.G.J.I., Vol. 8, Nos. 3 & 4, 1962.

——— : "The Character of Urbanization in U.P.", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 9, 1973, pp. 1-12.

Tiwari, C.B. : "Sugar Industry in Eastern U.P. – A Plea for Redistribution", Deccan Geographer, Vol. 7, No.1,1969,pp.41-47.

——— : "Changing Industrial Complex in Southern Upland of Mirzapur", Geographical Knowledge, Vol. 2, No. 1, 1961, pp. 59-62.

Tiwari, P.S. : "Functional Pattern of Towns in Madhya Pradesh", N.G.J.I., Vol. 14, 1968, pp. 41-54.

Torodo, M.P. : "A Model of Labour Migration and Urban Employment in Less Developed Countries", American Economic Review, Vol. 59, 1969, pp. 138-148.

Ullman, E.L. : "The Role of Transportation and the Bases for Interaction", in Thomas, W.L. (ed.) : Man's Role in Changing the face of the Earth, 1956, pp. 862-880.

Vasantha, V. : "Occupational Structure of Women in India", Indian Geographical Journal, Vol. 50, No. 2, 1975, pp. 8-13.

Vallace, W.H. : "Freight Traffic Functions of Anglo-American Railroads", A.A.A.G., Vol. 53, 1963, pp. 312-331.

Wheeler, J.O. : "Trip Purposes and Urban Activity Linkage", A.A.A.G., Vol. 62, 1972, pp. 644-654.

Wilkinson, H.R. : "The Maping of Census Returns of Occupations and Industries", Geography, Vol. 37, 1952.

Wirth, L. : "Urbanization as a Way of Life", American Journal of Sociology, Vol. 44, 1938.

———::o::———